

अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी

RAJASTHAN C. C. A. RULES, 1958 **WITH CONDUCT RULES, 1971**

*Disciplinary Proceedings Against
Government Servants And Its Remedies*

इस पुस्तक में.—*राजस्थान सी. सी. ए. रूल्स 1958

**राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971

***हाई बोर्ड्स एवं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के नज़ीरो सहित

****राजस्थान सरकार के निर्देश

द्वारा :

गोविन्द नारायण माथुर

बी. ए. एल. एन. बी., एडवोकेट

1980

प्रकाशक :

श्रीकृष्ण बुक डिपो

चौड़ा रास्ता—जयपुर

प्रकाशक :

बाफना बुक डिपो

चीडा रास्ता-जयपुर ।

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

संस्करण 1980

मूल्य : पैंतीस रुपये ।

मुद्रक :

1. एस० एन० प्रिन्टर्स-जयपुर

2. जनता प्रेस-जयपुर

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958
(राजस्थान सी. सी. ए. रूल्स)

अनुक्रमणिका

1. ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

पृष्ठ

i-iii

भाग 1—सामान्य

नियम	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	4
2. निर्वचन	4-6
3. नियमों का लागू होना	16
4. फरार द्वारा विशेष उपबन्ध	20
5. किसी विधि या फरार द्वारा प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण	21

भाग 2—वर्गीकरण

6. सिविल सेवाओं का वर्गीकरण	22
7. राज्य सेवा में	23
8. अधीनस्थ सेवा में	23
9. लिपिक वर्गीय सेवा में	24
10. चतुर्थ श्रेणी सेवा में	24
11. प्रविष्टियों में परिवर्तन	24

भाग 3—नियुक्ति प्राधिकारी

12. समस्त नियुक्तियों सरकार द्वारा	25
------------------------------------	----

भाग 4—निलम्बन

13. निलम्बन	26
-------------	----

भाग 5—अनुशासन

14. शास्त्रियों के प्रकार	46
15. अनुशासनिक प्राधिकारी	76

पृष्ठ	नियम
16. बड़ी शास्तिया लगाने की प्रक्रिया	82
17. छोटी शास्तिया लगाने की प्रक्रिया	133
18. सयुक्त जाच	142
19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया	143
20. सरकार के धलावा अन्य अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाएँ आदि	152

भाग 6—अपील

21. सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की अपील नहीं होगी	153
22. निलम्बन के आदेशों के विरुद्ध अपील	154
23. शास्तिया लगाने के आदेशों के विरुद्ध अपील	154
24. अपीलनीय आदेश को पारित करने वाला प्राधिकारी	159
25. अपीलों के लिए परिसीमा	159
26. अपील का रूप तथा अन्तर्वस्तु	160
27. अपील प्रस्तुत करना	161
28. अपीलों को रोक रखना	162
29. अपीलों का परिपण	164
30. अपीलों पर विचार	164
31. अपील में दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन	171

भाग 7—पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

32. प्राधिकारी जिसके पास नियम 14 में विनिर्दिष्ट शक्तियाँ	171
33. राज्य सेवानो के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में आदेशों का पुनर्विलोकन	174
34. राज्यपाल की पुनर्विलोकन सम्बन्धी शक्तियाँ	175

भाग 8—प्रकीर्ण तथा अस्थायी

35. निरसन तथा व्यावृत्ति	179
36. सदेहों का निराकरण	181
37. कतिपय अधिकारियों के विशेष उपबन्ध	181
अनुसूचियाँ एवं प्रपत्र	1-72
राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971	1-14

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील)

नियम, 1958

ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि

भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक समय में किसी राजकीय सिविल कर्मचारी की सेवा में बहाल रखना मुख्यतः फ़ाउन अर्थात् राजमुकुट (बादशाह) की 'प्रसन्नता' अथवा 'प्रसाद' पर निर्भर था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ़ इन्डिया अधिनियम, 1919 की धारा 96 बी के अनुसार भी फ़ाउन (बादशाह सत्तामत्) के कर्मचारी अपने पद पर राजमुकुट के प्रसाद पर्यन्त ही कायम रह सकते थे परन्तु उक्त धारा की उप-धारा (1) में यह प्रावधान था कि किसी सिविल सेवा के कर्मचारी का उसकी नियुक्त करने वाले पदाधिकारी से नीचे के स्तर का कोई प्राधिकारी बरखास्त नहीं कर सकेगा। धारा 96 बी की उप-धारा (2) द्वारा सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इन्डिया इन-कौंसिल को यह अधिकार भी प्रदान किए गए कि वह सिविल सेवाओं का नियमन तथा वर्गीकरण करे, उनके भर्तों के तरीके एवं सेवा की शर्तों और तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में नियम बना सके। इस प्रकार सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम सन् 1920 के दिसम्बर महीने में बनाए गए और उनका पुनः प्रकाशन भारत सरकार के राज-पत्र में 21 जून, 1930 को हुआ। उक्त नियमों से सिविल कर्मचारी के कुछ बचाव का प्रावधान धारा 55 में यह किया गया कि जब तक कि किसी सिविल कर्मचारी को उसकी प्रस्तावित बरखास्ती, नौकरी से हटाए जाने या पदावनति (demotion) करने की कार्यवाही के लिए आधार बताते हुए, नोटिस नहीं दिया जावे और जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जावे तब तक इस प्रकार की कोई सजा नहीं दी जावे। परन्तु किसी सरकार का कर्मचारी को किसी फौजदारी अदालत या सैनिक अदालत (Court martial) द्वारा दोषी करार दिए जाने के फलस्वरूप उक्त सजाएँ दिए जाने पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता था।

परन्तु ऊपर बताई गई सुरक्षा की स्थिति प्रिवी कौंसिल ने राधाचारी बनाम सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट¹ और वैकट राव बनाम सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट² के मामलों में दिए गए फैसलों से ग़ुन्य कर दी। प्रिवी कौंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि सिविल सेवाओं के वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील नियम कानूनी प्राधिकार के अन्तर्गत बनाए गए थे, फिर भी वह राजमुकुट (बादशाह) पर उनके विवेक में किसी को बरखास्त करने पर, रोक नहीं लगा सकते और उक्त नियमों के उल्लंघन में किसी कानूनी न्यायानुसंगत विनाश दावा पैदा नहीं हो सकता। प्रिवी कौंसिल ने इन नियमों को राजमुकुट द्वारा माथारण

1. AIR 1937 P C 27.

2. AIR 1937 P C 31.

16. बड़ी शास्तिया लगाने की प्रक्रिया	82
17. छोटी शास्तिया लगाने की प्रक्रिया	133
18. संयुक्त जाच	142
19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया	143
20. सरकार के अलावा अन्य अनुशासन प्राधिकारी द्वारा दी गई आज्ञाएँ आदि	152

भाग 6—अपील

21. सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की अपील नहीं होगी	153
22. निलम्बन के आदेशों के विरुद्ध अपील	154
23. शास्तियाँ लगाने के आदेशों के विरुद्ध अपील	154
24. अपीलनीय आदेश की पारित करने वाला प्राधिकारी	159
25. अपीलों के लिए परिसीमा	159
26. अपील का रूप तथा अन्तर्वस्तु	160
27. अपील प्रस्तुत करना	161
28. अपीलों को रोक रखना	162
29. अपीलों का परिपण	164
30. अपीलों पर विचार	164
31. अपील में दिये गये आदेशों का कार्यान्वयन	171

भाग 7—पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

32. प्राधिकारी जिसके पास नियम 14 में विनिर्दिष्ट शक्तियाँ	171
33. राज्य सेवादों के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में आदेशों का पुनर्विलोकन	174
34. राज्यपाल की पुनर्विलोकन सम्बन्धी शक्तियाँ	175

भाग 8—प्रकीर्ण तथा अस्थायी

35. निरसन तथा व्यावृत्ति	179
36. सदेहों का निराकरण	181
37. कतिपय अधिकारियों के विशेष उपबन्ध	181
अनुसूचियाँ एवं प्रपत्र	1-72
राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971	1-14

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील)

नियम, 1958

ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि

भारत में अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक समय में किसी राजकीय सिविल कर्मचारी की सेवा में बहाल रखना मुख्यतः फ़ाउन अर्थात् राजमुकुट (बादशाह) की 'प्रसन्नता' अथवा 'प्रसाद' पर निर्भर था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया अधिनियम, 1919 की धारा 96 बी के अनुसार भी फ़ाउन (बादशाह सलामत) के कर्मचारी अपने पद पर राजमुकुट के प्रसाद पर्यन्त ही बायम रह सकते थे परन्तु उक्त धारा की उप-धारा (1) में यह प्रावधान था कि किसी सिविल सेवा के कर्मचारी का उसको नियुक्त करने वाले पदाधिकारी से नीचे के स्तर का कोई प्राधिकारी बरखास्त नहीं कर सकेगा। धारा 96 बी की उप-धारा (2) द्वारा सेनेटरी ऑफ स्टेट फॉर इन्डिया-इन कौंसिल को यह अधिकार भी प्रदान किए गए कि वह सिविल सेवाओं का नियमन तथा वर्गीकरण करने, उनके भर्तों के तरीके एवं सेवा की शर्तों और तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में नियम बना सके। इस प्रकार सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम सन् 1920 के दिसम्बर महीने में बनाए गए और उनका पुनः प्रकाशन भारत सरकार के राज-पत्र में 21 जून, 1930 को हुआ। उक्त नियमों से सिविल कर्मचारी के कुछ बचाव का प्रावधान धारा 55 में यह किया गया कि जब तक कि किसी सिविल कर्मचारी को उसकी प्रस्तावित बरखास्तगी, नौकरी से हटाए जाने या पदावनति (demotion) करने की कार्यवाही के लिए आधार बताते हुए, नोटिस नहीं दिया जावे और जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जावे तब तक इस प्रकार की कोई सजा नहीं दी जावे। परन्तु किसी सरकारों कर्मचारी को किसी फौजदारी अदालत या सैनिक प्रदालत (Court martial) द्वारा दोषी करार दिए जाने के फलस्वरूप उक्त सजाएँ दिए जाने पर यह प्रतिवन्ध लागू नहीं होता था।

परन्तु ऊपर बताई गई सुरक्षा की स्थिति प्रिवी कौंसिल ने गणपतचारी बनाम सेनेटरी ऑफ स्टेट¹ और बंकट राव बनाम सेनेटरी ऑफ स्टेट² के मामलों में दिए गए फैसलों में दूर कर दी। प्रिवी कौंसिल ने निर्णय दिया कि यद्यपि सिविल सेवाओं के वर्गीकरण, नियन्त्रण और भर्तों के नियमों का प्राधिकार के अन्तर्गत बनाए गए थे, फिर भी वह राजमुकुट (बादशाह) पर उसके अधिकार के अन्तर्गत बरखास्त करने पर, रोक नहीं लगा सकते और उक्त नियमों के अन्तर्गत के किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने का विनाशकारी पद नहीं हो सकता। प्रिवी कौंसिल ने इन विवादों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में

1 AIR 1937 PC 27.

2. AIR 1937 PC 31.

पथ प्रदर्शन की हिदायतें मात्र माना। इसका नतीजा यह हुआ कि उक्त नियमों के उल्लंघन में किसी सिविल कर्मचारी को बरखास्त करने या हटाये जाने पर, उसको किसी दीवानी अदालत में चाराजोई करने का अधिकार नहीं रहा। किन्तु वह शासकीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता था।

गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1935 बनते समय कानून की ऊपर बनाई गई स्थिति को ध्यान में रखा गया। अतः सिविल कर्मचारियों से सम्बन्धित धारा 240 में उप-धारा (1) में 'प्रसाद पर्यन्त' का उल्लेख पुनः दोहराया गया और सन् 1919 के अधिनियम की धारा 96 बी द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध फिर से लगाये गये, परन्तु उप-धारा (3) ने सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों की धारा 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया। तदनुसार, पंजाब प्रदेश बनाम ताराचन्द और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रदेश बनाम मूरज नारायण³ में फेडरल अदालत ने निर्णय दिया कि पीडित सिविल कर्मचारी सरकार के विरुद्ध दावा लाने का हकदार है, जिसमें दोषमय बरखास्तगी की तिथि से चढ़ा हुआ वेतन पाना भी शामिल है।

किन्तु प्रिवी कौंसिल ने हाई कमिशनर बनाम साल⁴ के फैसले में फेडरल कोर्ट के निर्णय को अमान्य करार दिया और तय किया कि यदि किसी सिविल कर्मचारी को धारा 240 की किसी भी उप-धारा के उल्लंघन में नौकरी से बरखास्त किया जाता है, तो उसका उपचार वही है, अर्थात् ऐसी घोषणा का कि बरखास्तगी का आदेश शुन्य तथा प्रभावहीन है और वादी दावा प्रस्तुत करने की तिथि से वह का सदस्य कायम रहा, परन्तु वह चढ़ा हुआ वेतन तथा हर्जाना नहीं पा सकेगा। उक्त निर्णय का कारण यह बताया गया कि राज्यमुकुट की अवकृति (Tort) के अधीन हर्जाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि राजमुकुट के अधीन नौकरी वादशाह सलामत की कृपा पर निर्भर है।

अब उल्लेखनीय बात यह है कि जब हमारा सविधान प्रभावशील हुआ तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवी कौंसिल के निर्णय अमान्य करार दिये और फेडरल कोर्ट के निर्णय को पुनः स्थापित कर दिया। बिहार राज्य बनाम मन्दुन मजीद⁵ में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि धारा 240 की उप-धारा (2) या (3) का उल्लंघन होता है, तो पीडित सिविल कर्मचारी को हक है कि वह कानूनी उपचार मागे जिसमें सरकार के खिलाफ बरखास्तगी की तिथि से चढ़े हुए वेतन की दिशे भी सम्मिलित है।

तत्पश्चात्, सन् 1957 में केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, कंट्रोल और अपील) नियम बनाए गए जिन्होंने सन् 1930 का पुराना कानून विस्थापित कर दिया।

सन् 1965 में नये केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण कंट्रोल और अपील) नियम बनाये गये जा 1 दिसम्बर, 1965 से लागू हुये और जिनसे 1957 के नियम निरस्त कर दिये गये।

राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय नियमों की रूपरेखाानुसार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 प्रचलित किये, जा 7 मई, 1959 से लागू हुये। ये नियम

3 AIR 1947 F. C 23 तथा AIR 1949 F C 112

4 AIR 1948 P C 121

5. (1954) S C R 786

सर्वोत्तम न्यायालय ने इस फैसले¹ के अनुरूप हैं कि रिटायर होने की प्राप्ति प्राप्त करने पर सिविल कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति करना कोई शास्ति या सजा नहीं है।²

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, सविधान क अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जारी किए गए हैं और आज तक भी किसी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं बनाये गये। इक्कीस वर्ष के पश्चात भी इसका कोई अधिनियम नहीं बना, यह प्रश्न सम्बन्धित प्राधिकारियों से ही पूछा जाना चाहिये।

सविधान का अनुच्छेद 309 इस प्रकार है—

“309 सच या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें—इस सविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये समुचित विधान मण्डल के अधिनियम सच या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर सकेंगे।

परन्तु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान मण्डल के अधिनियम के द्वारा या अधीन उस लिये उपबन्ध नहीं बनाये जात तब तक यथास्थिति सच के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राष्ट्रपति को अथवा ऐम व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, तथा राज्य के कार्यों से सम्बद्ध सेवाओं और पदों के बारे में राज्य के राज्यपाल को अथवा ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह निर्देशित करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिये भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियमों के बनाने की क्षमता होगी तथा किसी ऐसे अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उस प्रकार निर्मित कोई नियम प्रभावी होगा।”

1 AIR 1954 SC 369 श्यामादान वि यू बी सरकार।

2 ILR (1961) 11 राजस्थान 371 राजस्थान वि राज्यपाल।

राजस्थान सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील)

नियम, 1958

प्राधिकृत पाठ¹

भाग-1 : सामान्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान सिविल सेवा के सदस्यों के वर्गीकरण और नियन्त्रण तथा ऐसी सेवाओं के सदस्यों द्वारा की जाने वाली अपीलों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं—

टिप्पणी

दिनांक 11 दिसम्बर, 1958 की उपरोक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल ने ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक (प्रतिबन्धात्मक वाक्य खण्ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बन गये हैं। माथा गुल राय विधान मण्डल की ऐसे नियम बनाने चाहियें। यह विदित नहीं है कि विधान मण्डल ने ऐसा क्यों नहीं किया और इतने लम्बे काल के बाद भी मामले को राज्यपाल पर क्यों छोड़ रखा है। कुछ भी हो, इन नियमों में कानून का बल है क्योंकि राज्यपाल ऐसे नियम बनाने तथा समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार उनमें उपयुक्त संशोधन करने के लिये सक्षम है।² अतः बदनीयता (malafides) के आधार पर इन नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती।³

परन्तु राज्यपाल का ऐसे नियमों के माध्यम से, संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा गारन्टीयुदा सार्वजनिक कर्मचारियों के अधिकारों को कम करने या उनमें कटौत करने का हक नहीं है।⁴

संविधान के अनुच्छेद 310 तथा 311 इस प्रकार हैं—

“310, सच या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि —(1) इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबन्धित अवस्था को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, जो सच की प्रतिरक्षा नवा या

- 1 विधि विभाग (विधि रचना सफ़ठन) की अधिसूचना GSR 76 दि 8 जून 1973 द्वारा प्रथम बार राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग)-1 दि 17 जुलाई 1975 में प्रकाशित। प्राधिकृत हिन्दी पाठ।
- 2 1973 (1) SLR 1053—विश्वनाथ वर्मा वि मध्यप्रदेश राज्य, AIR 1967 SC 1910—मनराम वि राजस्थान सरकार
- 3 1974 RLW 584 या 1974 WLN 647—अविनाश स्वप्न वि राजस्थान सरकार।
- 4 AIR 1972 SC 1429 पञ्जाब राज्य वि. मदनमिह और AIR 1964 SC 600, 1967 SC 1264, AIR 1966 SC 1442

अर्धनित सेना का या अर्धनित भारतीय सेना का सदस्य है, अथवा मध्य के अर्धनित प्रतिरक्षा में मध्यस्थता निम्नी पद को अथवा निम्नी अर्धनित पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रवाद-पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य की अर्धनित सेना का सदस्य है अथवा राज्य के अर्धनित निम्नी अर्धनित पद को धारण करता है राज्य व राज्यपाल के प्रवाद-पर्यन्त पद धारण करता है।

(2) इस बात के होने हूँ भी कि मध्य या राज्य के अर्धनित अर्धनित पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति पञ्चास्थिति राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल के प्रवाद पर्यन्त पद धारण करता है कोई मंडला जिला अर्धनित कोई व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेना या अर्धनित भारतीय सेना अथवा मध्य या राज्य की अर्धनित सेना का सदस्य नहीं है ऐसे निम्नी पद को धारण करने के लिए इस अधिनियम के अर्धनित नियुक्त होना है, यह उपर्युक्त कर सकेगी कि यदि पञ्चास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्धनित व्यक्ति निम्नी व्यक्ति को सेना को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझता है तो, यदि कारण की हृदय स्थापना की समझति म पक्षे उस पद का अर्थ कर दिया जाता है अथवा उसने द्वारा निम्ने मध्य निम्नी अवधार में समझ्युक्त कारणों के लिए उसम पद स्थित करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे प्रतिपत्ति दिया जावेगा।'

• 311 सच या राज्य के अर्धनित अर्धनित हैसियत में नौकरी में लगे हुये व्यक्तियों की पदस्थिति, पद से हटाया जाना, या पदस्थिति किया जाना - (1) जो व्यक्ति मध्य की अर्धनित सेना का या अर्धनित भारतीय सेना का या राज्य की अर्धनित सेना का सदस्य है, अथवा मध्य के या राज्य के अर्धनित अर्धनित पद का धारण करता है वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी में निम्ने निम्नी प्राधिकारी द्वारा पदस्थित नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जावेगा।

1[(2) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति नव तर पदस्थित नहीं किया जाएगा अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा अथवा पदस्थित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी जाँच जिसमें उसे अपने गिलाफ दोषारोपी में अवगत करा दिया गया है और उन दोषारोपी के सम्बन्ध में सुनवाई का सुनिश्चित अवसर दिया गया है, नहीं करनी जाती।

"परन्तु जहाँ ऐसी जाँच के पश्चात् इस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्तावना है वहाँ ऐसी शास्ति ऐसी जाँच के दौरान दिये गए माध्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति का प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अपील करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु यह और है कि यह खण्ड बड़ा लागू नहीं होगा -

(क) जहाँ कि कोई व्यक्ति ऐसे आधार के आधार पर पदस्थित किया गया या हटाया गया या पदस्थित किया गया है जिसके लिए दण्ड दोषारोप पर वह सिद्धोप हुआ है, या

(ख) जहाँ कि निम्नी व्यक्ति को पदस्थित करने या पद से हटाने या पदस्थित करने की शक्ति रखने वाले निम्नी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि निम्नी कारण में, जो उस प्राधिकारी द्वारा ज्ञेयवद्ध किया जावेगा यह सुनिश्चित रूप में व्यवहृत नहीं है कि ऐसी जाँच की जाये, या

(ग) जहाँ कि पञ्चास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि ऐसी जाँच की जाये।

(3) यदि उपर्युक्त प्रकार के किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या खण्ड (2) में निर्दिष्ट जैसी कोई जाच करना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नहीं तो उस प्राधिकारी या उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा जिसे उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद में हटाने अथवा पकिनच्युत करने की शक्ति प्राप्त है।”

ज्ञात रहे कि सविधान (क्यालीसवा सणोघन) अधिनियम 1974 द्वारा सविधान के अनुच्छेद 311 (2) में सणोघन कर दिया गया है, जिससे अनुसार उक्त उप अनुच्छेद की निम्नलिखित अन्तिम पंक्तियां खोपिन कर दी गई हैं।—

“और जहाँ ऐसी जाच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति आरोपित करना प्रत्यादिन है उहाँ जहाँ तक उसे प्रस्तावित शास्ति की बाबत अभिवेदन, किन्तु ऐसी जाच के दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर, करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।”

इसके साथ ही अनुच्छेद 311 (2) में प्रथम परन्तु जोड़ा गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित सजा के विरुद्ध सम्बन्धित कर्मचारी को अभिवेदन प्रस्तुत करने का नोटिस देना अब आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह दूसरा नोटिस देना सविधान के अनुसार अब जरूरी नहीं है, फिर भी इन नियमों के नियम 16 (10) (i) (ख) के अनुसार प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार कर्मचारी के पक्ष में अब भी कानूनन सुरक्षित है।

‘प्रसाद’ (Pleasure) का सिद्धान्त, अर्थात् यह सिद्धान्त कि राज्य के समस्त मित्र कर्मचारी अपना अपना पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त धारण करते हैं अभी तक विद्यमान है जैसा कि ऊपर दिए गए सविधान के अनुच्छेद 310 से विदित होगा। परन्तु सविधान के अन्य प्रावधानों में ऐसा से परास्तरणी, हटाए जाने तथा पदावनति करने पर प्रतिबन्ध लगा दिए हैं। निरकुश बाधबाही अब नहीं की जा सकती इसीलिये इन नियमों को बनाने की आवश्यकता हुई।

ये नियम केवल राज्य के सिविल सेवाओं के सदस्यों पर ही लागू होते हैं और यह सैन्य जल सैन्य या वायु सैन्य के सदस्यों पर तथा राजनैतिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होते जैसे कि राज्य के मंत्री (मिनिस्टर)। सविधान ने कुछ अन्य पद भी इन नियमों की परिधि में बाहर रक्ते हैं। उदाहरणतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यगण, जिन पर ‘प्रसाद’ का सिद्धान्त लागू नहीं होता। विशेष सचिव अर्थात् गतों पर नियुक्त व्यक्ति भी इन नियमों की पहुँच से बाहर हैं। किन्तु सविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रदत्त संरक्षण अर्थात् सार्वजनिक कर्मचारियों पर भी लागू है।¹

राजस्थान सरकार ने अनुशासन की कार्यवाहियों के विषय में आदेशों की पुस्तिका प्रकाशित की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस प्रकाशन को राजस्थान मित्र सेवा वर्गीकरण, नियन्त्रण और प्रणाली नियमों का पूर्ण माना जाना चाहिये।² इस विषय में राजस्थान सरकार का आदेश निम्नलिखित है —

राजस्थान सरकार का आदेश

अनुशासन की कायवाहिया में विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये वह राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम और अपील) नियम 1958 में पूर्ण विवरण सहित बाई गई है जिसका ज्ञान समस्त सरकारी अधिकारियों को तथा विशेषतः अनुशासन प्राधिकारियों को पूरी तरह होना चाहिये। किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ है कि या तो ऐसे मामलों को निपटाने हेतु नियमों तथा आवश्यक प्रक्रिया संबंधी अपेक्षताओं से परिचित होने के लिए उनको पर्याप्त समय नहीं मिलता अथवा वे इनको आवश्यक महत्व नहीं देते जिसका नतीजा यह होता है कि न केवल अनुशासन कायवाहिया और उनसे पारित अन्तिम आदेश अपील/नज़रस्तानी/निगरानी में तथा विभागीय जांच पूरी करने में विलम्ब के कारण कानूनी म्यादालयों द्वारा भी खारिज कर दिये जाते हैं परन्तु यह भी कि दोषी व्यक्तियाँ (delinquents) को भी अनावश्यक परेशानी होती है। अब यह पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता समझी गई जिसमें मूलाभूत नियमों के सदम के साथ आवश्यक प्रक्रिया की अपेक्षता बताई गई है और सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश तथा अधिसूचनाएँ सम्मिलित हैं। यह पुस्तिका राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम और अपील) नियम की पूर्ण मान है न कि उनका स्थान ग्रहण करने वाली। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं इस प्रक्रिया से शामिल नहीं होते हैं।

[अनुशासन कायवाहियों की पुस्तिका—(राजस्थान सरकार 1963 संस्करण अनुच्छेद (1))]

1 सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(क) इन नियमों का सक्षिप्त नाम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम और अपील) नियम, 1958 है।

(ख) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।¹

टिप्पणी

प्रारम्भ —नियम 1 का अनुच्छेद (ख) कहता है कि ये नियम तुरन्त लागू होंगे इसका अभिप्राय सरकारी गजट (राज पत्र) में प्रकाशन होना की तिथि में है। ये नियम राजस्थान राज पत्र प्रकाशक भाग 4 (ग) में दिनांक 7 मई 1959 को प्रकाशित हुए। इस प्रकार इस तिथि से ये प्रभावशील हुए।

2 निर्वाचन—जब तक सदस्य द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में—

(क) किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से निम्नलिखित में से जो भी उच्चतम प्राधिकारी हो वह अभिप्रेत है—

(1) जिस सेवा का सरकारी कर्मचारी उस समय सदस्य है उस सेवा में या जिस सेवा में सरकारी कर्मचारी उस समय सम्मिलित है उस सेवा की ग्रेड में नियुक्तियाँ करने के लिये मशकत प्राधिकारी, या

(2) जिस पद को सरकारी कर्मचारी उस समय धारण करता है उस पर नियुक्तियाँ करने के लिये सशक्त प्राधिकारी या

1 विज्ञप्ति सं F 18 (2) Appdt (A) 56 दिनांक—दिसम्बर 11, 1958, राजस्थान राजपत्र व भाग 4 (ग) दि 7-5-1959 में प्रकाशित एवं प्रभावशील।

- (3) वह प्राधिकारी जिसने सरकारी कर्मचारी को ऐसी सेवा, श्रेणी या पद, यथास्थिति, पर नियुक्त किया था, या
- (4) जहाँ मन्कारी कर्मचारी किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुये या अधिष्ठायी रूप से कोई अन्य स्थायी पद धारण करते हुये निरंतर सरकार के नियोजन में (सरकारी सेवा में) रहा है वहाँ वह प्राधिकारी जिसने उसे उस सेवा में या उस सेवा की किसी श्रेणी में या उस पद पर नियुक्त किया था :

परन्तु जहाँ सरकार ने या विभागाध्यक्ष ने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को अपनी शक्तियाँ सौंप दी हो तो नियम 23 (2) (क) (ख) के प्रयोजनों के लिये सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ही नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

- (स) 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,
- (ग) किसी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति लगाने के सवध में 'अनुशासनिक प्राधिकारी' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन उस पर ऐसी शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो,
- (घ) 'राज पत्र' से राजस्थान राज पत्र अभिप्रेत है,
- (ङ) 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है,
- (च) 'सरकारी कर्मचारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी सेवा के सदस्य है अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कोई सिविल पद धारण किये हुए है और उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति सम्मिलित है जो 'बाहरी सेवा' में है अथवा जिसकी सेवाय अस्थायी रूप से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन रख दी गई हो और किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी की सेवा का वह व्यक्ति भी जिसकी सेवाय अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार के अधीन रख दी गई है अथवा जो किसी सविदा के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सेवा में है, अथवा जो अन्य कहीं से सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुका है और राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजित कर लिया गया है, परन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो सध सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सिविल सेवा में है और राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर, सेवा कर रहा है वह उन्ही नियमों से शासित होना रहेगा जो उस पर लागू हो,
- (छ) ऐसे निम्नी विभाग के सम्बन्ध में जो सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, विभागाध्यक्ष से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अनुसूची 'क' में विभागाध्यक्ष विनिर्दिष्ट किया गया है, और उसमें वह विभागीय जाच आयुक्त भी सम्मिलित है जिसे सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के सम्बन्ध में 50/- तथा उमम अधिव राशि के खर्च के मामलों में जाच करने का कार्य सौंपा गया है,
- (ज) प्रत्येक ऐसे कार्यालय के सम्बन्ध में जो सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है, 'कार्यालयाध्यक्ष' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे अनुसूची 'ख' में कार्या-

लयाध्यक्ष विनिर्दिष्ट किया गया है और इसमें गवन विषयक जाच के मामलों का विशेषाधिकारी तथा सहायक आयुक्त, विभागीय जाच भी सम्मिलित है, जबकि विभिन्न विभागों से सम्बन्धित 50/- रु या उससे अधिक की राशि वाले गवन के मामलों में जाच का कार्य आयुक्त विभागीय जाच को सौंपा गया है,

(क) 'अनुसूची' से इन नियमों से सलग्न अनुसूची अभिप्रेत है,

(ख) 'सेवा' से राजस्थान राज्य की कोई सिविल सेवा अभिप्रेत है ।

व्याख्या:—जब किसी कानून में किसी शब्द या अभिव्यक्ति की परिभाषा प्रावधानित हो तो कहा वही भी वह शब्द या अभिव्यक्ति आवे, वहां उसका अर्थ तदनुसार ही लगाया जावे जब तक कि सदर्भ में कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो । अतः यहाँ हुई परिभाषा का अर्थ विषय के सदर्भानुसार तथा अधिनियम की योजना (scheme) तथा उसके उद्देश्य और कानून के अन्य प्रावधानों के अनुकूल लगाया जावे ।¹ हमें किसी शब्द या अभिव्यक्ति का ऐसा अस्पष्ट अर्थ नहीं लगाना चाहिए जो उसके सदर्भ विशेष से असंगत हो ।²

नियुक्ति प्राधिकारी —कोई प्राधिकारी जो किसी राज्य कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित चार श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में आता हो, वह उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा —

- (1) वह प्राधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी जिस वर्ग का तत्समय सदस्य हो उस वर्ग में नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो या सेवा के जिस ग्रेड में सम्बन्धित राज्य कर्मचारी आता हो, उस ग्रेड में नियुक्ति प्रदान करने का अधिकार रखता हो अथवा
- (2) वह प्राधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा तत्समय धारण किए हुए पद पर नियुक्ति करने की क्षमता रखता हो, अथवा
- (3) वह प्राधिकारी जिसने सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को उक्त सेवा या उक्त ग्रेड या उक्त पद पर नियुक्त किया हो, अथवा
- (4) यदि संबन्धित राज्य कर्मचारी, किसी अन्य सेवा का स्थाई सदस्य होते हुए, सरकारी सेवा में निरन्तर चल रहा है, तो वह प्राधिकारी जिसने उस, उस सेवा में, या उस सेवा के किसी ग्रेड में अथवा उस पद पर नियुक्त किया (जो ऐसे प्राधिकारियों में से सबसे ऊँचे पद (रैंक) का हो) उस विशेष मामले में नियुक्ति प्राधिकारी होना समझा जाएगा । यही नियम ऐसे सरकारी कर्मचारी पर भी लागू होगा, जिसने कोई अन्य स्थाई पद स्थाई रूप से धारण किया हो और जो अब राज्य सरकार के निरन्तर नियोजन में चल रहा है । अन्य शब्दों में, जिस प्राधिकारी ने उसे उक्त सेवा, या उस सेवा के किसी ग्रेड में या उस पद पर नियुक्त किया, वह उस कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

1 AIR 1958 Sc 353—हिन्दुस्तान लीवर लि वि दिल्ली प्रसाधन ।

2 AIR 1933 Pc 216

जब किसी राज्य कर्मचारी को किसी पद विशेष पर अन्तिम रूप से नियुक्त कर दिया गया हो और जब उसका पिछले मूल पद पर कोई पदाधिकार (lien) नहीं रहे, तो उसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसने उसे नए पद पर नियुक्त किया।¹

नियम 2 (क) में जोड़े गए परन्तुक को ध्यान में रखना चाहिए। इस परन्तुक के अनुसार जहाँ तब नियम 23 (2)(क) तथा (ख) के अधीन शास्ति लागू करने के आदेशों के विरुद्ध अपील सं सम्भव है, कोई अधीनस्थ अधिकारी (subordinate officer) जिस सरकार से या किसी विभागाध्यक्ष (Head of Department) द्वारा सुपुर्दे किए हुए अधिकार प्राप्त हो, वह नियुक्ति प्राधिकारी नहीं समझा जाएगा। ऐसे मामले में सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष (Head of Department) नियुक्ति प्राधिकारी होगा। तदनुसार, अधीनस्थ सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष कर सकेगा, और यदि आदेश नियुक्ति प्राधिकारी ने जारी किया हो, तो सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। गबन (embezzlement) के मामलों में विभागाध्यक्ष (Head of Department) की हैसियत से, विभागाध्यक्ष आचल्युक्त द्वारा दिए गए आदेश की अपील राज्य सरकार को होगी।

संविधान के अनुच्छेद 311 की व्याख्या नियुक्ति प्राधिकारी के सम्बन्ध में - चूंकि राजस्थान राज्य का गठन कतिपय राज्यों के विलीनकरण से हुआ, इसलिये पूर्वगामी राज्य से आए हुए व्यक्ति के बारे में उसकी नियुक्ति प्राधिकारी का पता लगाना कुछ जटिल कार्य है। ऐसे मामलों में किसी सेवारत कर्मचारी के विषय में यह ज्ञान करना आवश्यक नहीं है कि विलीनीकरण से पहले उसकी नियुक्ति किसने की थी। हमको बस यह मालूम करना है कि विलीनीकरण के पश्चात् राजस्थान में उसकी नियुक्ति किसने की। अतः संविधान के अनुच्छेद 311 की व्याख्या हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि सेवा से बरखास्तगी या हटाए जान की सजा किसी ऐसे अधिकारी द्वारा नहीं दी जा सकती जो एकीकरण (Integration) होने पर राजस्थान राज्य में उसे नियुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारी के निम्न स्तर का अर्थात् नीचे के पद का हो।² परन्तु जबकि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एकीकृत रूप में (integrated set up) में, उसने निलम्बित होने के कारण कभी हुई ही नहीं हो, तो हम यह ज्ञान करना होगा कि यदि वह निलम्बित नहीं होता तो उसकी नियुक्ति सम्मिलित स्वीकृत (integrated) राजस्थान में कौन करता, और उस मामले में वही अधिकारी उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा।³

नियुक्ति प्राधिकारी से ऊँचा तथा नीचे का अधिकारी - यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी उसके नियुक्ति प्राधिकारी से ऊपर के पद का है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। जबकि 'क' की नियुक्ति निष्पक्ष के पद पर, सरकार के सहायक सचिव श्रेय में अपने स्थान पर की, और उसकी वर्ग्यास्थगी का आदेश उप-आयुक्त न दिया, तो तदमीनारायण त्रि उडीमा सरकार⁴ में तब हुआ कि यह आदेश बंध या क्योंकि उप-आयुक्त निम्न-स्तर का नहीं था।

1 AIR 1956 इन हुआद 475-शरी अहमद वि डाकचानो के वरिष्ठ अधीक्षक (मुद्रित-नोट)।

2 AIR 1954 राजस्थान 207-जीन गमन वि राजस्थान सरकार।

3

4

इसी प्रकार, वन संरक्षण द्वारा नियुक्त व्यक्ति मुख्य वन संरक्षक द्वारा दण्डित किया जा सकता है, क्योंकि उससे सविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त की अवहेलना नहीं होती।* इसी तरह से, सरकार के सहायक सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सरकार के उप-सचिव द्वारा मनीषी से हटाया जा सकता है।¹

इसके विपरीत, जब कि पुलिस के एव गव-इन्स्पेक्टर (धानेदार) को महानिरीक्षक पुलिस ने नियुक्त किया था और बाद में उप-महानिरीक्षक के आदेशों के अन्तर्गत उसे बरखास्त कर दिया गया तो यह बरखास्तगी अ-संवैधानिक करार दी गई।² जबकि एक पुलिस धानेदार को, जिसकी नियुक्ति रत्नाम राज्य ने की थी, समयोपरान्त, मध्य भारत के उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने बरखास्त कर दिया, यह बरखास्तगी अवैध करार दी गई क्योंकि उप-महानिरीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न स्तर का था।³ एक व्यक्ति को कारागार के महानिरीक्षक ने नियुक्त किया था और उसकी बरखास्तगी का आदेश कारागार अधीक्षक ने कर दी, तो बरखास्तगी का आदेश सविधान के अनुच्छेद 311 (1) के उल्लंघन में होना निर्णीत हुआ। यद्यपि अपील में उक्त आदेश कारागार के महानिरीक्षक ने ने समोहित कर दिया, फिर भी प्रारम्भिक दशा में स्थित शेषाधिकार का अभाव सुधारा नहीं जा सका।⁴ जबकि प्रार्थी की नियुक्ति चीफ कमिशनर ने की थी और उसे हटाए जाने का आदेश, डिप्टी कमिशनर ने पारित किया तो यह निर्णय हुआ कि यह कार्यवाही सविधान के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिकूल थी।⁵ इसी प्रकार जब एक व्यक्ति को राज्य सरकार ने नियुक्त किया था और बरखास्तगी का आदेश कमिशनर ने पारित कर दिया तो यह बरखास्तगी सविधान के अनुच्छेद 311 (1) के उल्लंघन में की गई निर्णीत हुई।⁶ प्रार्थी की नियुक्ति डिप्टी कमिशनर के पद पर राजप्रमुख ने की थी। तत्पश्चात्, राजप्रमुख के सलाहकार (Adviser to the Rajpramukh) ने उसे अनिरिक्त सहायक कमिशनर के पद पर तैनात किया। यह आदेश गैर कानूनी करार दिया गया। यह तथ्य कि राज-प्रमुख न उससे अ-सहमत प्रवृत्त नहीं की, उनकी महमति होना नहीं मानी जा सकती।⁷

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला फतेहसिंह खोडा वि. "राजस्थान सरकार" में दिया है। इसमें यह साबित था कि प्रार्थी की पुलिस धानेदार (SIP) के पद पर महानिरीक्षक आरक्षी ने किया था स्थाई (confirm) परन्तु उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही का आदेश उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने दिया। उच्च न्यायालय ने तय किया कि चूंकि यह मामला परराष्ट्रगी या सेवा से हटाए जाने का नहीं था (बल्कि केवल पदावनति का था) इसलिए इसमें सविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन नहीं हुआ, परन्तु फिर भी यह कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 तथा 16 की अवहेलना में हुआ क्योंकि प्रार्थी के के विरुद्ध जांच प्रारम्भ करने के लिए महा निरीक्षण आरक्षी (I G Police) ने, राज्य सरकार की अनुमति से, उप-महानिरीक्षक आरक्षी को विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया था।

* AIR 1956 पटना-228.

1 AIR 1960 बलकृष्ण-सतीशचन्द्र गुप्ता वि प वगाल सरकार।

2 AIR 1964 मध्यप्रदेश 114-रामरत्न वि मध्यप्रदेश सरकार।

3 AIR 1957 मध्यप्रदेश 126-रामचन्द्र गोपाल राय वि उप-महानिरीक्षक, पुलिस।

4 AIR 1956 मद्रास 419-मोमामुन्दरम् वि मद्रास सरकार, तथा AIR 1956 मनीषुर 34.

5 AIR 1963 मनीषुर 51-अहमद हुसैन वि डिप्टी कमिशनर, मनीषुर।

6 AIR 1956 मध्यभारत 259-ए एम खान वि मध्य भारत सरकार।

7 AIR 1954 पेपम् 98

8. 1977 WLN 421

एक अन्य मामले, डा बी के गुप्ता वि भारत सरकार¹ में एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा उन ग्राम रहे रहने के लिए अयोग्य पाई गई। अतः उसके विरुद्ध कोई भी कलक (aspersion) प्रकट किए बिना उसे नौकरी से हटा दिया गया। यह कोई सजा नहीं हुई, इसलिए सविधान का अनुच्छेद 311 इसमें आकषिप्त नहीं हुआ।

जबकि सरकार ने अपन मुकद्दमों की पैरवी के लिए प्रार्थी वकील को एक निश्चित अवधि के लिए रखने के आधार (monthly retainer basis) पर नियुक्त किया, तो निम्न्य हुआ कि प्रार्थी और सरकार का पारस्परिक रिश्ता एक अवधिकल और वकील का था। प्रार्थी सिविल सेवा का कोई पद धारण नहीं करता था, इसलिए उसके हटाए जाने पर सविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं हुआ।²

शब्द 'पदच्युति' (dismissal) नौकरी से हटाना, (removal) या पक्तिच्युत (reduction in rank), जैसा कि इनका प्रयोग सविधान के अनुच्छेद 311 में हुआ है साफ़ तौर से दर्शाते हैं कि पदच्युति करने सेवा से हटान अथवा पक्तिच्युत करने व आदेश पर अनुच्छेद 311 तभी लागू होगा जबकि आदेश सजा के रूप में जारी किया गया हो। यदि नौकरी से पृथक् करना राजस्थान सभा नियमों के नियम 23 व के अधीन वेबल सजा की समाप्ति (termination simpliciter) मान है, तो यह अनुच्छेद 311 में प्रयोगित सेवा से हटाए जान (removal of service) के अन्तर्गत नहीं आया।

अतः बिना कलक लगाये किसी अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना एक साधारण सेवा समाप्ति की तारीफ़ में आता है जिस पर सविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता और यह सैद्धान्तिक अनिवार्यता कि हटाने का आदेश केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकता उपयोग में नहीं लाया जा सकता।³

सविधान के अनुच्छेद 311(1) के प्रयोजनार्थ किसी कर्मचारी को उसके पद पर पक्का (confirm) करने वाला प्राधिकारी उसका नियुक्ति प्राधिकारी है। इस प्रकार जबकि प्रार्थी को स्टाई रूप में आस्तविक नियुक्ति देने वाला पश्चिम रेलवे का डिप्टी चीफ़ एक्ज़ाक्ट्स ऑफिसर था तो वही अधिकारी प्रार्थी का नियुक्ति प्राधिकारी माना जायेगा। हरिश्चर वि भारतीय सच⁴ के मामले में डिबिजनल मैकेनिकल इंजिनियर न. जा कि डिप्टी चीफ़ एक्ज़ाक्ट्स ऑफिसर से नीचे व स्तर का पदाधिकारी था, ने प्रार्थी को सेवाच्युत करने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में डिबिजनल मैकेनिकल इंजिनियर द्वारा दिया गया आदेश खारिज किया गया।⁴

किसी कर्मचारी से सम्बन्धित सही नियुक्ति प्राधिकारी का पता लगाना भी एक गंभीर समस्या है। इस विषय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि सम्बन्धित प्राधिकारी के पदस्तर की जांच करनी चाहिए। 'यद्यपि सविधान का अनुच्छेद 311(1) यह प्रपक्षा नहीं करता कि सेवा से बर्खास्त करना या हटाना उसी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जिसने कर्मचारी की नियुक्ति की थी, फिर भी यह अवश्य निर्धारित किया गया है कि वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी से

1 1977 WLN 124

2 1976 WLN 519-रघुवीर सिंह वि राजस्थान सरकार।

3 1975 WLN 835-राज सरकार वि जयदीन चन्द्र।

4 1975 WLN 100

नीचे के स्तर या ग्रेड का कोई अग्रिमस्थ प्राधिकारी उसे सेवाच्युत करने या नौकरी में हटाने के लिए सज्ज नही है हालांकि यह नियमों के अधीन उसी प्रकार की नियुक्तियां प्रदान करत हतु सक्षम हो। अतः गणेशनारायण वि. राजस्थान सरकार¹ में जबकि अपील कर्ता की नियुक्ति प्राधिकारी डाकघरों का वरिष्ठ निरीक्षक अजमेर डिविजन था, उक्त कर्मचारी को उसने पद के सम्बन्ध में फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति पाली डिविजन के डाकघरों के अधीक्षक में जारी की जो कि उक्त कर्मचारों के वरिष्ठ अधीक्षक के पद से नीचे के स्तर का था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह ज्ञात करने के लिए कि आपा सेवा से हटाने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी में नीचे के पद का है या नही पद या ग्रेड उसका महत्वपूर्ण परीक्षण है। अतः अजमेर डिविजन के डाकघरों का वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी प्रथम के ग्रेड का र 400-1250 के वेतनमान का अधिकारी होने में पाली डिविजन के डाकघरों के अधीक्षक में जो कि श्रेणी द्वितीय में र 350-900 के वेतनमान का अधिकारी था, उच्चतर पद धारण करता था और पाली का अधीक्षक अजमेर के वरिष्ठ अधीक्षक से निम्न स्तर का था यद्यपि वह अधिकारों एवं कर्तव्यों की दृष्टि से उसके अधीनस्थ नही था।

लेमखन्द वि. भारतीय सघ² के तथ्य भिन्न हैं। इस मामले में, प्रार्थी, जो कि एक पुनर्नियोजित अस्थाई लिपिक था, निर्बल तथा अमृतोपजनक कारणों के आधार पर, अपनी नियुक्ति के नए स्थान पर जाने में विफल रहा। किन्तु, बिना अनुशासन कार्यवाही किए और उसे हटाने के आदेश में बिना कोई कारण बताए उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। अतः निर्णय हुआ कि उसके मामले में संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता।

कुलदीपसिंह तथा अन्य वि. भारतीय सघ³ में छ प्रार्थीगण, जो नेत्रों के कर्मचारी थे सेवा से हटा दिए गये अथवा बर्खास्त कर दिए गए क्योंकि वे सभी फौजदारी अदालत द्वारा दोषी सिद्ध हुए थे। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रदानत से दोष सिद्ध (conviction) होने मात्र से कोई सरकारी कर्मचारी आवश्यक रूप से सरकारी नौकरी में बने रहने की अर्हता (योग्यता) नहीं खोता और, इसके विपरीत, प्रोवेशन अधिनियम (Probation Act) का फलदा उसे अनुशासन कार्यवाही से अछूता नहीं रख सकता। दूसरा यह कि अपराध की किस्म कोई विशेष महत्व नहीं रखती क्योंकि अनुच्छेद 311 (2) में सभी प्रकार के दोषारोपण समाविष्ट है। इसके प्रतिरिक्त जब किसी राज्य कर्मचारी ऐसे आचरण के आधार पर जिससे फौजदारी दोषारोपण सिद्ध हुआ, पदच्युत या हटाया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (क) सजा देने वाले अधिकारों को चार्ज के विषय में और प्रस्तावित शास्ति के विषय दोनों दफा उसे नोटिस देने की आवश्यकता में मुक्त करता है।

अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (ग).—उपयुक्त मामले में,⁴ यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य कर्मचारी को बिना अनुशासनीय कार्यवाही किए और सजा देने का कारण प्रकट नहीं करने पर भी शास्ति इस आधार पर दी जा सकती है कि राज्यपाल को अतोपजनक विश्वास है कि कारण प्रकट करना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है। यदि उन परिस्थितियों को प्रकट करने से राज्य

1 1975 WLN 117

2 1975 WLN 202

3 1974 WLN 176

4 1974 WLN 175—कुलदीपसिंह वि. भारतीय सघ।

की सुरक्षा सनरे में पड़ती हो तो अवश्य ही उनको प्रवट करना जरूरी नहीं है परन्तु फिर भी संप्रति राज्य कर्मचारी को अपना पक्ष अभिव्यक्त करने की इजाजत दी जा सकती।

अर्थात्, कर्मचारी की सेवा समाप्त करना सजा नहीं है — जबकि एक अर्थात् कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच उसको चांजेंसीट देने और उसके उत्तर में उसके स्पष्टीकरण प्राप्त होने से आगे नहीं बढ़े, तो निर्णय हुआ कि बिना किसी प्रकार का कारण बताए, एक महीने के नोटिस पर उसकी सेवा समाप्त करने में सविधान के अनुच्छेद 311 की श्रियाशीलता आच्छेद नहीं हुई क्योंकि उसको नौकरी से प्रवक्त करने का आदेश एक अर्थात् कर्मचारी की मामूली सजा का समापन करना मान है।*

सविधान का अनुच्छेद 311 का विभाग के सिविल कर्मचारी का शासित नहीं करता। यह सिद्धान्त जीवनपुरी वि भारतीय सभ में प्रतिपादित किया गया। यह भी तय किया कि सविधान के अनुच्छेद 310 के अधीन "राज्यपाल के प्रसाद" की शक्ति, उदाहरणतः अनुच्छेद 311 के अन्वर्गन सजा देने की शक्ति अधीनस्थ अधिकारी को नहीं दी जा सकती।

परीक्षण के अधीन कोई कर्मचारी अपने पद पर अधिकार धारण नहीं करता — जो कर्मचारी परिक्षण (Probation) पर कार्य कर रहा हो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है और परिक्षणार्थी का अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सविधान का अनुच्छेद 311 उस पर लागू नहीं होता। यद्यपि परिक्षण काल की अवधि समाप्त हो गई हो, फिर भी जब तक उसे स्पष्ट पक्का नहीं किया जाये तब तक ऐसा कर्मचारी अर्थात् ही रहता।¹ अनुपयुक्तता के आधार पर किसी परिक्षणार्थी की सेवा समाप्त करना केवल में समाप्ति है न कि सजा। इस कारण से उस पर सविधान का अनुच्छेद 311 (2) लागू नहीं होता।²

जबकि एक कार्यवाहक जिला तथा मन भ्यायाधीन को उसके मूल पद पर वापस भेज दिया गया (Reverted), यह निर्णय हुआ कि केवल परिलाभो (emoluments) में कमी होना मात्र में आदेश को अधिकारी के विरुद्ध शासित लागू करने वाला नहीं माना जा सकता। स्थिति इससे भिन्न होगी यदि इसका परिणाम बरिष्ठता छोड़ना या उच्च पद पर पदोन्नति के भविष्य अवसर खूब करने जाना हो। कानून की यह स्थिति चंदरसिंह वि राजस्थान सरकार³ में प्रतिपादित की गई और यह कहा गया कि जिला एवं मन भ्यायाधीन के पद के लिए प्रार्थी की अनुपयुक्तता के आधार पर वापस मौलिक पद पर भेजना सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के उल्लंघन में नहीं है और प्रार्थी का उसके मौलिक पद पर वापस भेजने से पहले उसको कोई नोटिस देना भी अपेक्षित नहीं था।

अनिवार्य सेवा निवृत्ति: — किसी राज्य कर्मचारी की अनिवार्य सेवा निवृत्ति (compulsory retirement) उसके विरुद्ध कोई कानून लगाये बिना 'भेदभाव' की तारीफ में नहीं आता। यह सजा की तारीफ में भी नहीं आता, इसलिए इससे सविधान का अनुच्छेद 311 (2) अपेक्षित नहीं आता।

*1973 WLN 194 जीवनपुरी वि भारतीय सभ

1 1973 WLN 389—जिलासचिव मेठिया वि राज राज्य विद्युत मण्डल।

2 AIR 1978 SC 363—विमलराज गुप्ता वि हरियाणा सरकार।

3. 1972 WLN-8

ऐसे मामले में अदालत सचिवालय की फाइलों में यह तथ्य खोजने का कार्य नहीं कर सकती कि थाया ऐसे अनुमन्धान से कोई क्लर्क लगने का निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं। वतिपय मामला में अनिवार्य सेवा नियुक्ति सार्वजनिक हित में की जाती है और यदि रिटायर करने के आदेश में यह व्यक्त कर दिया जाय कि उस व्यक्ति को सार्वजनिक हित में रिटायर किया गया है तो इसमें कोई नुति नहीं होगी।

(ग) अनुशासन प्राधिकारी — नियम 2 (ग) में दी गई परिभाषानुसार किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में अनुशासन प्राधिकारी वह व्यक्ति है जो उसे शास्ति देने के लिए सक्षम हो। शास्तिमो का वर्णन नियम 14 में किया गया है। इस प्रकार ऐसा प्राधिकारी जो किसी राज्य कर्मचारी को नियम 14 में उल्लिखित कोई भी शास्ति देने में समर्थ हो वही उक्त राज्य कर्मचारी का अनुशासन प्राधिकारी है। वह उसका नियुक्ति प्राधिकारी भी हो सकता है या नहीं भी हो।

यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी का अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो वह केवल नियम 14 के अनुच्छेद (i) से (v) में उल्लेखित (लघु) शास्ति ही आरोपित कर सकता है। सेवा से हटाने या पदच्युत करने की कठोर शास्तिया केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकता है। नियम 15 अनुशासन प्राधिकारियों के अधिकारों तथा कार्यों के विषय में है। राज्य सेवाओं (State services) के लिए अनुशासन प्राधिकारी राज्य सरकार है या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त शक्तिधारी प्राधिकारी होता है। अधीनस्थ सेवाओं के लिए विभागाध्यक्ष अथवा सरकार की अनुमति से उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी होता है। लेखक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के लिए कार्यालयीय अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(घ) राज्य कर्मचारी:—राज्य कर्मचारी वह व्यक्ति है, जो—

- (i) किसी सेवा का सदस्य है, या
- (ii) राजस्थान सरकार के अधीन कोई अर्सेनिक (निविल) पद धारण किए हुए हो और इसमें निम्न लिखित व्यक्ति शामिल होंगे —

- (क) जो वैदेशिक सेवा में हो, या
- (ख) जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से किसी स्थानीय अधिकारी (उदाहरणतः नगर पालिका, पंचायत, राजकीय प्रतिष्ठान या निगम) को सुपुर्द की हुई हों, या
- (ग) किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के सेवा का कोई व्यक्ति जिसकी सेवाएं अस्थायी रूप से राजस्थान सरकार को सुपुर्द की हुई हो, या
- (घ) किसी सविदा (contract) पर सेवा में कार्य कर रहा हो, या
- (ङ) वह व्यक्ति जो किसी अन्य सरकार की सेवा से सेवा मुक्त हो चुका हो और जो राजस्थान सरकार के अधीन पुनः नियुक्त किया गया हो

परन्तु निम्न लिखित व्यक्ति राजस्थान सिविल (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधीन) नियमों के अधीन राज्य कर्मचारी नहीं हैं —

- (i) भारतीय सघ की अर्सेनिक सेवा का कोई व्यक्ति, या
- (ii) किसी अन्य राज्य की अर्सेनिक सेवा का कोई व्यक्ति—

जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर कार्य कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही उन पर लागू नियम, लागू हूँ।

सिविल (असैनिक) पद.—शब्द “सिविल पद” (या असैनिक पद) का प्रयोग अभिन्यक्ति ‘राज्य कर्मचारी’ की परिभाषा में किया गया है। राज्य के अधीन “सिविल पद” वह पद (post) है जिस पर राज्य सरकार का पूरा नियन्त्रण है और यदि सरकार चाहे तो उस पद का समाप्त कर सकती है। राज्य सरकार का सिविल पद पर निकटतम और अन्तिम नियन्त्रण (immediate and ultimate control) होना है।¹ इसके अनिरिक्त सिविल पद सैनिक पदों से विभिन्न है।² यद्यपि राज्य सरकार के अधीन किसी पदधारी को कोई वेतन नहीं दिया जाना हो, फिर भी उसे सिविल पद धारण करने वाला माना जाएगा।³ इसके विपरीत, केवल राजकीय निधियों से उसे रकम दी जाने या कतिपय प्रतिष्ठानों पर नियन्त्रण मात्र होन से, उन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्ति को भी स्वयं राज्य सेवा में अर्थात् सिविल पद धारण करने वाला नहीं माना जा सकता।⁴

निम्नलिखित व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन सिविल पद धारक की परिभाषा में नहीं आते.—

- (1) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का कर्मचारी,⁵
- (2) स्टेट सहकारी बैंक का कर्मचारी,⁶
- (3) राजकीय परिवहन निगम का कर्मचारी,⁷
- (4) नगरपालिका का कर्मचारी,⁸
- (5) जिता बोर्ड का कर्मचारी,⁹
- (6) पचायत का सचिव या अधिष्ठाता अधिकारी,¹⁰
- (7) सुधार न्यास का कर्मचारी,¹¹
- (8) सरकारी होजरी भिन्न में दैनिक वेतन पर काम करने वाला,¹²

1 AIR 1956 पटना 398 तथा AIR 1963 कलकत्ता 116

2 AIR 1955 नागपुर 175, AIR 1967 SC 844 आत्मान राज्य वि. कमल चन्द्रदत्त ।

3 AIR 1955 कलकत्ता 556

4 AIR 1959 ज. कश्मीर 26

5 AIR 1965 मद्रास 335 तथा AIR 1962 कलकत्ता 72.

6 AIR 1965 पटना 223 चतुर्नृज सहाय वि. केयरमैन, स्टेट सहकारी बैंक ।

7 AIR 1963 कलकत्ता 116, प्रफुल्ल कुमार मेन वि. कलकत्ता राज्य ट्रॉसपोर्टे कोर-पेरेशन ।

8 AIR 1958 जम्मू कश्मीर 6—बिशम्बर नाथ नेहरू वि. एच. एन. जम्मू तथा कश्मीर सरकार ।

9 AIR 1958 मद्रास 211 एव AIR 1957 पटना 333 रण नाथ मिश्रा वि. मन्नापति, जिला बोर्ड ।

10 AIR 1962 मध्य प्र. 50—रमण सिंह वि. मन्नापति, पचायत और समाज सेवा, इन्दौर ।

11. AIR 1958 इलाहाबाद 353—एम. ए. किदवाई वि. अध्यापक, सुधार न्यास ।

12 AIR 1956 जम्मू-कश्मीर—डी. एस. वादरा वि. आम्बे सचिव जेलों तथा वारि विभाग ।

- (9) किसी कम्पनी या नियम का कर्मचारी,¹
- (10) राज-भवन का माली,²
- (11) राज्यपाल के आनस्मिक कर्मचारीगण (contingency staff),³
- (12) गवर्नमेंट एडवोकेट,⁴
- (13) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मरदिय का अधिकारी,⁵ और
- (14) गांव का चौधरी।⁶

सिबिल सेवाएं—सिबिल सेवाओं के नियम में अनेक निर्णय हुए हैं। जी एम रामास्वामी वि महानिरीक्षण, पुनर्निर्माण, ममूर⁷ में सर्वोत्तम न्यायालय न सत्य किया कि परीक्षणार्थी (probationer) परीक्षण काल की अवधि समाप्त हो जाने पर स्वतः सेवा का स्थाई मद्रम्य नहीं बन सक्ता। इस फैसले का आधार लेते हुए बैंगाल चन्द्र सठिया वि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल⁸ में राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि परीक्षण पर नियुक्ति प्रार्थी अपने पद परीक्षण की प्रारम्भिक अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य करता रहा, फिर भी वह केवल समय गुजरने मात्र से तब तक स्थाई कर्मचारी नहीं बन सकता जब तक कि उस पर लागू नियम ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं करते कि परीक्षण का प्रारम्भिक काल समाप्त हो जाने पर वह अपने आप स्थाई हो जाएगा। इस प्रकार, यद्यपि परीक्षण की अवधि निम्नी आदेश द्वारा बढ़ाई नहीं गई है तथापि कर्मचारी परीक्षणार्थी के रूप में जारी रहता।

परन्तु जब कि अनुशासन प्राधिकारी न दापारोपी (delinquent) अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार ही नहीं किया और निर्णय की पुष्टि के कारण भी व्यक्त नहीं किए गए तो उसे सेवा से हटाने का आदेश दोषयुक्त करार दिया गया (भारतीय सच वि बी. के. इत्ता)⁹। इस विपरीत, एक अर्थाई कर्मचारी (प्रार्थी) की सेवाएं एक महीने का नोटिस देकर समाप्त कर दी गई, तो यह आदेश वैध माना गया।¹⁰ इसी प्रकार जब सेवा समाप्त करने के आदेश में यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी का कार्य सतोपजनन नहीं था तो निर्णय हुआ कि यह कोई कारण नहीं था और सेवा समाप्ति का आदेश उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुकूल था।¹¹

1 AIR 1963 कलकत्ता 421 AIR 1961 इलाहाबाद 502

2 AIR 1956 पटना 398—सहमी वि राज्यपाल का मिनीट्री सक्नेरी।

3 AIR 1955 वेपलू 25—वर्तारसिंह वि वेपलू सरकार।

4 AIR 1960 राजस्थान 138—राजस्थान सरकार वि भदन स्वरूप।

5 AIR 1959 त्रिपुरा 21—महेन्द्र लाल चक्रवर्ती वि भारत सचीय क्षेत्र त्रिपुरा।

6 ILR 1956 राजस्थान 355—शेरसिंह वि राजस्थान सरकार।

7 AIR 1966 मुंबई 175

8 1973 WLN 389

9 1973 WLN 663

10 1973 WLN 303—निशानाराम वि भारतीय सच।

11 1973 WLN 389

यहां यह स्पष्ट कर दें कि एक प्रशिक्षार्थी (apprentice) की नियुक्ति का साधारण आदेश उस किंसा स्टाई पद का अधिकार प्रदान नहीं करता ।¹ किसी भवा समाप्ति के आदेश का रूप निर्णायक (conclusive) नहीं होता । डिप्लूमन उसकी गहराइयों में जाकर तथ्य चाल कर सकती है ।²

जब किसी सिविन सेवा क सदस्य की जम नियि बिना जम नॉसि दिए बदल दी गई और उक्त परिवर्तन ज म सिवि क आधार उमकी सेवा निवृत्ति (retirement) का आदेश जारी कर दिया गया ता फमना हुआ कि सेवा स उमको रिटायर करना अवष था ।³

किसी विशेष विषय म किसी व्यक्ति की निपुणता सम्बन्धी क्षमता विश्व विद्यालय द्वारा आकी जानी चाहिए और उच्च न्यायालय को एमे विश्वविद्यालय सम्बन्धी ((academic matters) म दखल नहा करना चाहिए ।⁴

सविदा पर नियोजित व्यक्ति — साधारणतः सरकार नियुक्ति क आदेशानुसार नियुक्तिया करती है जिस कि कर्मचारी स्वाकार करता है । इनालिय सविधान क अनुच्छेद 309 क प्रधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत की गई सभी सिविन कर्मचारियों की नियुक्तिया क लिए सरकार और कर्मचारी क मध्य कोई सविदा (इकरारनामा) निष्पादिन करन की आवश्यकता नहीं पडती ।⁵ ऐसे मामल बानूनी निपमा से नियमित होते हैं न कि किसी पृषक सविदा स ।⁶ परन्तु सरकार अस्थाई कर्मचारियों स विशेष सविदा कर सकती है बानें कि एस इकरार का शर्तें सविधान के किसी प्रावधान का अवहनना नहीं करती हा ।⁷ लिखित शर्तों क विषय म सविधान का अनुच्छेद 299 प्रावधान करता है । सरकार तथा विशेष इकरारनाम पर नियुक्त कर्मचारी दोनों ही उनक द्वारा तय की गई शर्तों से माध्य हाग ।⁸ जब किसी अस्थाई कर्मचारी का एक निश्चिन अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो तो उक्त अवधि समाप्त होने पर उसकी नियुक्ति का समापन हा जायेगा और एक महीन क नोटिस की शोध आवश्यकता नहा हागे ।⁹ परन्तु कर्मचारी इकरार की पूरी अवधि तक कायरेत रहने का अधिकारी है ।¹⁰

किंतु जब एक राज्य दूसरे राज्य म सहमिनन (Accession) या विलय या विनीनीकरण या एकीकरण द्वारा सविनीन हा जाता है ता पूर्ववासीन सरकार और उनके कर्मचारियों के मध्य सेवा क समस्त इकरारनाम स्वतः समाप्त हा जात हैं और तत्पश्चात नो कर्मचारी सेवा म धन रहन का विकल्प नें वे नई सरकार द्वारा नाम की गई शर्तों पर रह सकेंगे ।¹¹

1 1974 WLN 112

2 1977 WLN 461

3 1977 WLN 551

4 1977 WLN 593

5 AIR 1953 पेपसू 196—वदी वि पपसू सरकार ।

6 AIR 1958 नगरत्ता 551—आर क चन्द्रत्ती वि प वमान सरकार ।

7 AIR 1955 इनाहवा—496—एम पी धीवास्व वि मालखार उतर प्रदेश

8 AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट—250 एम सी आनन्द वि भारतीय सध ।

9 AIR 1962 मनीपुर—52

10 AIR 1963 बम्बई—13

3 नियमों का लागू होना —(1) ये नियम निम्नाविक्त के सिवाय सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे.—

- (क) वे व्यक्ति जो भारत सरकार, अथवा बिन्ही भी राज्यों या सघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनियुक्ति पर हैं,
- (ख) वे व्यक्ति जो भारत सरकार के ऐसे औद्योगिक संगठनों में नियोजित हैं जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाए और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्थान्तर्गत कर्मचार हैं,
- (ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
- (घ) उपर्युक्त न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जो सविधान के अनुच्छेद 229 के खण्ड (2) के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शामिल होंगे,
- (ङ) राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो सावधान के अनुच्छेद 318 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शामिल होंगे,
- (च) वे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति तथा अन्य मामला के लिए, जो इन नियमों के अन्तर्गत आते हैं, तत्काल प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन, उक्त विधि के अन्तर्गत आने वाले मामला के सम्बन्ध में, विशेष उपबन्ध किया गया है,
- (छ) वे व्यक्ति, जो आवश्यक नियोजन में हैं,
- (ज) वे व्यक्ति जो एक महीने से कम की अवधि के नोटिस पर सेवान्मुक्त किए जा सकते हों, और
- (झ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य ।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी और सविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्ध के अध्वधीन सरकार, आदेश द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों के किसी वर्ग को, इन सब नियमों या इनमें से कुछ के प्रवर्तन से से अलग कर सकेगी ।

(3) यदि कोई सदेह उत्पन्न हो कि —

- (क) क्या ये नियम या इनमें से कोई भी नियम किसी व्यक्ति पर लागू होता है, या
- (ख) क्या कोई व्यक्ति जिस पर ये नियम लागू होते हों, किसी विशेष रूप से सेवा का सदस्य है,

तो ऐसा मामला सरकार के नियुक्ति विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय उन पर अन्तिम होगा ।

टिप्पणी

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 कतिपय अपवादों के साथ, राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं । “राज्य कर्मचारी” की परिभाषा नियम 2 के खण्ड (च) में दी गई है जो बताती है कि ये नियम, इन नियमों से सलग अनुसूचियों में निर्दिष्ट सभी कर्मचारियों पर लागू हैं ।

इस परिभाषा के विरुद्ध से स्विनि स्पष्ट होगी। इसने अनुसार राज्य कर्मचारी वह व्यक्ति है—

- I (i) जो किसी सेवा का सदस्य हो, अथवा
 - (ii) जो राजस्थान सरकार के अधीन कोई निविन (असैनिक) पद धारण करता हो
- और

II हमने निम्नलिखित सम्मिलित है —

- (i) वैदेशिक सेवा में आई ऐसी व्यक्ति, या वह जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी के पास प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर हो,
- (ii) कोई व्यक्ति जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा का हो और जो अर्थात् रूप से राजस्थान सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हो, अथवा
- (iii) सविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति, अथवा
- (iv) कोई रिटायर युवा सरकारी कर्मचारी जिसको राजस्थान सरकार के अधीन पुन नियुक्त किया हो।

निम्नलिखितों पर ये नियम लागू नहीं होंगे—

- (1) भारतीय सशस्त्र बल की निविन सेवाओं का कोई व्यक्ति, अथवा
- (2) वह व्यक्ति जो किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में होता हुआ राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर कार्य करता हो।

अन राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अर्पण) नियम किसी ऐसी कर्मचारी पर, किसी भारतीय सेवाओं के सदस्य पर आकस्मिक नियुक्ति पर कार्यरत किसी व्यक्ति पर या किसी ऐसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता जिसकी सेवाएँ एक माह से कम के नोटिस पर समाप्त की जा सकती हैं, या जिसके लिए कोई विशेष कानून या इतराणुमात्र विशेष शर्तें लागू होती हैं। इन अपवादों की विस्तृत सूची ऊपर नियम 3 के उपनियम (1) के अनुच्छेद (क) से (ख) में दी गई है।

(क) प्रतिनियुक्ति पर आया हुआ व्यक्ति—ऐसे समस्त व्यक्ति जो मूलतः भारत सरकार के कर्मचारी हैं भारत सरकार के या किसी अन्य राज्य सरकार के या मधीय क्षेत्र के कर्मचारी हैं परन्तु जिनकी सेवाएँ राजस्थान सरकार को सुपुर्द कर दी गई हैं, अपनी मूल सरकार के कानून में प्रणामित रहते न कि राजस्थान सेवा नियमों में। मध्यप्रदेश के एक पुत्रिम मन्त्र डम्पेक्टर को हैदराबाद में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया। जब उसने विरुद्ध हैदराबाद के कानून के अधीन उप अधीनस्थ पुलिस द्वारा जांच की गई तो वह निर्णय हुआ कि जांच पूर्वतः अनाधिकृत एजेंसी द्वारा संचालित की गई।¹

(ख) कर्मचार (workmen) जो सरकारी औद्योगिक संस्थानों में नियुक्त हों इन नियमों से प्रभावित नहीं होंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (घ) में कर्मचार की परिभाषा दी हुई है। यह परिभाषा उक्त प्रकार है—

‘बर्मकार’ से मेगा बोर्ड व्यक्ति (प्रशिक्षु सहित) अभिप्रेत है जो कि किसी उद्योग में कोई कौशल-पूर्ण या कौशलरहित शारीरिक, पदवेक्षणिय प्राविधिक या निविदा सम्बन्धी कार्य प्रवर्धन या पुरस्कार पर करने के लिए नियोजित है चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त या प्रवर्धित हों और इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवाद के सम्बन्ध में किसी बाधवाही के प्रयोजन के लिए ऐसा कोई व्यक्ति इसके अन्तर्गत आता है जो कि इस विवाद के सम्बन्ध में या ऐम विवाद के परिणामस्वरूप पदच्युत किया गया अलग किया गया या हटा दिया गया है, अथवा जिसकी पदच्युति, अलहदगी, या छटनी हानि का कारण ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है।

निम्नलिखित ‘बर्मकार’ के अन्तर्गत नहीं आते हैं —

- (क) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं सेना अधिनियम, हवाई-सेवा अधिनियम, या जन सेना (अनुशासन) अधिनियम द्वारा नियमित हो,
- (ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पुनिम या जैन में नियोजित हो,
- (ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्रबन्धकीय या प्रशासकीय क्षमता में कार्य कर रहा है,
- (घ) यदि निरोजक पर्यवेक्षणिय क्षमता के भीतर कार्य कर रहा है तो उसे अवश्य ही एक प्रबन्धकीय क्षमता के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए और इसके साथ ही उसे 500 रु प्रतिमास से अधिक का वेतन भी नहीं प्राप्त करना चाहिए।”

वे सभी व्यक्ति जो समय समय पर अधिसूचित किसी सरकारी औद्योगिक संगठनों में नियोजित हैं और जो ऊपर उल्लिखित परिभाषा के अभिप्राय से ‘वार्किंग’ (workmen) हैं, वे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों से शासित नहीं होंगे।

(ग) राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशः—ये नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होते, क्योंकि उनकी नियुक्ति सविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति करते हैं और केवल सविधान के अनुच्छेद 218 के साथ पठित अनुच्छेद 124 की प्रक्रिया द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। ये न्यायाधीश, हाई कोर्ट न्यायाधीश (मेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों से शासित होते हैं।

(घ) राजस्थान उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तथा बर्मकारीः—राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारी और बर्मकारीयण सविधान के अनुच्छेद 229 (2) के अधीन शासित होते हैं। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम उक्त अधिकारियों और बर्मचारियों पर लागू नहीं होते और हाई कोर्ट के उनके लिये 1956 में पृथक नियम बनाए। प्रद्योत कुमार वि चीफ जस्टिस ¹ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाई कोर्ट स्टाफ के सदस्यगण न्यायालय के चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) के नियन्त्रण में थे, जिसको उनके मामले निपटाने हेतु संबंधित अधिकार प्राप्त हैं।

निम्नोक्त ये नियम, G S R 27, अधिसूचना संख्या F 3 (40) ऐपोइन्टमेन्ट (A-III) 72 दिनांक 24 सितम्बर, 1973 (प्रकाशन तिथि 14-7-1975) द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा तथा राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होते हैं।

(ङ) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य—राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण भी राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमों से प्रभावित

नहीं होते। वे सविधान के अनुच्छेद 318 के अधीन बनाए गए विनियमों से शासित हैं।

(च) विशेष प्रावधानों के अधीन नियुक्त व्यक्ति — जब भी किसी व्यक्ति के लिये, किसी कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया हुआ हो, तो कानून का वही प्रावधान उसको शासित करेगा और उसके विषय में ये नियम लागू नहीं होंगे। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम राजस्थान पुलिस के अधीनस्थ मेवालों के पदों के मददगारों पर पुलिस अधिनियम के अधीनस्थ रहने, लागू होने हैं। अतः पुलिस अधिनियम में सेवा की शर्तों और शास्तियों के विषय में जिन प्रावधानों का अभाव है और जो मामले स्पष्ट पुलिस अधिनियम में नहीं आते वे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों द्वारा निपटाय जायेंगे। इस प्रकार ये नियम पुलिस अधिनियम के पूरक हैं।¹

(छ) आकस्मिक निपोजन वाले व्यक्ति — जो व्यक्ति आकस्मिक कार्य के लिये नियुक्त किये जाते हैं, वे इन नियमों के अधीन सिविल पद धारण करने वाले नहीं समझे जा सकते। ईनिक मजदूरी पर रखे जाने वाले अधिकारियों पर ये नियम लागू नहीं होते, जैसे कि डी डी टी छिड़कने वाले, गीमकाल में खस की टट्टियों पर पानी डालने वाले, माली, आदि।² परन्तु जहाँ ऐसे व्यक्ति नियमित बजट में समुचित स्वीकृत पदों पर काम करते हैं, वे आकस्मिक सेवा में नहीं समझे जायेंगे और इसलिये ये नियम उन पर लागू होंगे।

(ज) ऐसे व्यक्ति जो एक महीने से कम के नोटिस से सेवा से हटाए जा सकते हैं — जो व्यक्ति निरंतर अस्थाई आधार पर नियुक्त हो, यहाँ तक कि, जिनकी सेवा की शर्तों के अनुसार, एक माह से कम अवधि के नोटिस पर नौकरी से डिसचार्ज किये जा सकते हों, उन पर ये नियम लागू नहीं होते। जब एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा उसे आगे रखने के लिये उपयुक्त नहीं पाई गई, तो उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई। निम्नलिखित हूमा कि इस मामले में सविधान का अनुच्छेद 311 प्राकट्य नहीं होता और यह कि सेवा की समाप्ति वैध थी।³

बिना कलब लगाए किसी अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना केवल मान साधारण समाप्ति है और इस पर अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता।⁴ इसी प्रकार का एक फैसला केमचद वि भारतीय सघ⁵ में हुआ।

इसी तरह का एक अन्य मामला शकरलाल वि भारतीय सघ⁶ था। जबकि एक अस्थाई कर्मचारी की सेवा जो परीक्षण पर नियुक्त था, बिना नोटिस समाप्त कर दी गई, तो निम्नलिखित हूमा कि किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी और कथित आदेश सही था और ये नियम उस मामले पर लागू नहीं होते।⁷

1. AIR 1967 राजस्थान 414 — लोकमल वि अधीक्षक आरक्षी, AIR 1960 राजस्थान 56.

2. AIR 1966 पटना 328.

3. 1977 WLN 124 — डा. बी. के. गुप्ता वि. भारतीय सघ।

4. 1975 WLN 835 — राजस्थान सरकार वि जगदीश चन्द्र।

5. 1975 WLN 207

6. 1974 WLN 194.

7. AIR 1960 राजस्थान 517

(भ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य — राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधीन) नियम, 1958 अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर लागू नहीं होते, जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वैदेशिक सेवा, आदि। उन पर पृथक् नियम लागू होते हैं।

4. करार द्वारा विशेष उपबन्ध:—जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में, इन नियमों के किसी भी नियम से असंगत विशेष उपबन्ध का रखा जाना आवश्यक प्रतीत हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारी के साथ करार द्वारा ऐसे विशेष उपबन्ध कर सकेगा और तदुपरांत ये नियम उक्त सरकारी कर्मचारी पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जिन सीमा तक इस प्रकार बनाए गए विशेष उपबन्ध उनसे असंगत हों :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी मरफार के नियुक्ति विभाग के अनुरिक्त दूसरा कोई हो, तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा सरकार के नियुक्ति विभाग की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।¹

सरकार को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को किसी विशेष अनुबन्धन या शर्तों पर सेवा में नियोजित कर सके दशतें कि सविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन न हो।² इस प्रकार से नियुक्त कर्मचारी पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधीन) नियम लागू नहीं होंगे। परन्तु उसको सविधान (इकरार) की शर्तों के अनुसार सेवा से हटाया जा सकेगा, जिससे सविधान का अनुच्छेद 311 (2) आपतित नहीं होगा।³ ऐसे विशेष इकरार के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं:—

- (1) कोई विशेष प्रावधान करना जो इन नियमों के किसी प्रावधान से असंगत हो,
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं सरकार अर्थात् नियुक्ति विभाग नहीं है तो नियुक्ति विभाग में सरकार की पूर्वागामी अनुमति प्राप्त करना, और।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे इकरार से सविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होगा। परन्तु यदि सजा के रूप में उसे सेवा से बर्खास्त किया जायेगा तो सविधान का अनुच्छेद 311 नियामित हो जायेगा।

एक व्यक्ति की नियुक्ति इस शर्त पर हुई कि वह युद्ध के दौरान तथा उसके बाद 'यदि आवश्यकता हुई तो सेवा में रहेगा। ऐसे व्यक्ति को युद्ध के पश्चात् यदि किसी भी समय नौकरी से हटा दिया जावे तो उसे शिकायत करने का कोई कारण नहीं होना चाहिये।'⁴

जब एक राज्य अन्य राज्य में महामिलन (accession), विजय (Conquest), विलीनीकरण (merger) या एकीकरण (integration) द्वारा सवितीन (absorb) हो जाए तो पिछली सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य समस्त इकरार स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद, वे सभी व्यक्ति जो नए राज्य की सेवा में रहने का विवल्न ने, उन्हें नहीं गठित राज्य के द्वारा आरोपित अनु-

1 अधिमूचना सं 16 (9) नियुक्ति/O/59/ग्रुप III दिनांक 23-2 62 द्वारा जोड़ा गया।

2 AIR 1955 इन्दाहावाद 496—शारदा प्रसाद वि ए जी, यू पी।

3 AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 250—मनीषचन्द्र धानन्द वि भारतीय सघ।

4 AIR 1955 कलकत्ता 45.

बन्धो और शर्तों का पालन करना होगा।¹ परन्तु, इन नियमों का नियम 37 विशेष तौर से प्रावधान करता है कि जब किसी अधिकारी को एकीकृत योजना में किसी भी पद पर नियुक्त ही नहीं किया हो, तो वह राजस्थान में मिलने वाली उम्र इकाई (यूनिट) के नियमों से शासित होता रहेगा जिसमें वह प्रतिम नियुक्ति धारण करता था।

जब जिरा परिपद वे एक सचिव, (जो सेवा में स्थाई हो चुका था) की सेवा उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार, बिना किसी जाच के समाप्त कर दी गई तो निर्णय हुआ कि ऐसा करना वैध था।²

5. किसी विधि या करार द्वारा प्रदत्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षण— इन नियमों की कोई भी बात किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगी जिसका वह निम्नांकित आधारों पर हकदार है—

(क) उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, या

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के समय, उस व्यक्ति और सरकार के बीच अस्तित्वयुक्त किसी करार की शर्तों के द्वारा।

टिप्पणी

नियम 5 राज्य कर्मचारी को एक आश्रय या संरक्षण प्रदान करता है ताकि ये नियम—

(1) किसी प्रचलित कानून द्वारा या उसके अन्तर्गत, या

(2) कर्मचारी और सरकार के बीच, इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय चल रहा किसी करार की शर्तों द्वारा—

किसी राज्य कर्मचारी को उसके उचित अधिकारों या विशेषाधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। अतः पहले से ही अज्ञित अधिकारों को नए नियम नहीं छीन सकते।³

एक प्रश्न यह उठता है कि आया सरकार और निविन कर्मचारी कोई ऐसी सविदा निष्पादित कर सकते हैं जिनका नतीजा मजिबान द्वारा गारंटी किए गए अधिकारों में सशोधन के रूप में घटित हो जावे। सरकार वि. गजानन महादेव⁴ में मुख्य न्यायाधीश छागला ने निर्णय दिया कि सविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा प्रत्याभूत संरक्षण एक कानूनी अपेक्षा है और यह राज्य कर्मचारी के मागने पर निर्भर नहीं है। टी. मुनी स्वामी वि. मैसूर सरकार⁵ में यह तय किया गया है कि सविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा निम्न अधिकार में विधान मण्डल द्वारा बनाये गये किसी कानून द्वारा या राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा कोई कमी नहीं की जा सकती। राज्य कर्मचारी, नि. सदेह, कानूनी भ्यामालय में जाकर ऐसी घोषणा के लिए प्रार्थना कर सकता है कि उसकी वर्तमान या सेवा से हटाये जाने का आदेश शून्य तथा प्रभावहीन है और वह दावा प्रस्तुत करने की तिथि की सेवा का

1. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 228—अमरसिंह वि. राजस्थान सरकार।

2. 1971 Lab IC 1072

3. AIR 1953 पेपर्स 24, 1969 सुप्रीम कोर्ट 118, 1975 सुप्रीम कोर्ट 1116, 1972 सुप्रीम कोर्ट 628.

4. AIR 1954 बम्बई 351.

5. AIR 1964 मैसूर-250.

सदस्य बना हुआ है।¹ पुराना अंग्रेजी यह बानून कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राज-मुकुट के विरुद्ध चढ़े हुए वेतन का दावा नहीं ला सकता, अब भारत में लागू नहीं है। उसको भारत में सर्वधानिक बानून के प्रावधान द्वारा नकारा जा चुका है।²

भाग-2 : वर्गीकरण

6 (1) सिविल सेवाओं का निम्नांकित रूप से वर्गीकरण किया जायगा —

- (1) राज्य सेवाएँ,
- (2) अधीनस्थ सेवाएँ,
- (3) लिपिक वर्गीय सेवाएँ, और
- (4) चतुर्थ श्रेणी की सेवाएँ,

(2) यदि किसी सेवा में एक से अधिक ग्रेड के पद हों तो विभिन्न ग्रेडों के पदों को विभिन्न वर्गों में सम्मिलित किया जा सकेगा।

टिप्पणी

सिविल सेवाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित चार वर्गों में श्रेणीबद्ध किया गया है —

(i) राज्य सेवाएँ

इनमें से कुछ सेवाएँ इन नियमों में सहाय्य अनुसूची I में बताई गई हैं, उदाहरणतः —

- (क) राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा,
- (ख) राजस्थान प्रशासनिक सेवा,
- (ग) राजस्थान न्यायिक सेवा
- (घ) राजस्थान पुलिस सेवा,
- (ङ) राजस्थान लेखा सेवा,
- (च) राजस्थान सचिवालय सेवा।

उपरोक्त सेवाओं में सम्मिलित पदों को धारण करने वाले राज्य सेवाओं के सदस्य हैं। इस सूची को पूरा करने के लिए नियम 7 (क) तथा (ग) भी पढ़ें।

(iii) अधीनस्थ सेवाएँ

अनुसूची II में अधीनस्थ सेवाओं के सदस्यों की सूची दी गई है। इस सूची में नियम 8 के अनुच्छेद (क), (ख) तथा (ग) में उल्लेखित व्यक्ति जोड़े जावें।

(iii) लिपिक वर्गीय सेवाएँ

ये अनुसूची 3 में उल्लेखित निश्चित निपिकों के पद हैं और नियम 9 के अनुच्छेद (ख) तथा (ग) में बताये गये व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं।

1 AIR 1947 प्रीवी कोसिल 23

2 (1954) बिहार सरकार वि अब्दुल मजीद SCR 786

* अधिमूचना सख्या एफ 16 (9) नियुक्ति (ए) 59 थुप 3 दिनांक 23-2 62 द्वारा जोड़ा गया।

(iv) चतुर्थ श्रेणी सेवाएँ

ये निम्न श्रेणी की सेवाएँ हैं उदाहरणतः चपरासी, साईनिल सवार, जमादार, नाई, दफतरी, मिपाही, सफाई कर्ता, दजी, घोड़ी आदि । ये पद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधीन) नियमों से सलग्न अनुसूची 4 में तथा नियम 10 के अनुच्छेद (ख) व (ग) में निर्दिष्ट किए गए हैं ।

वर्गीकरण आदेशनक है क्योंकि भिन्न भिन्न वर्गों के अर्न्तगत कर्मचारी अपने अपने उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा नियन्त्रित होने हैं । ध्यान रहे कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग से उच्चतर है, द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग से उच्चतर है और तृतीय वर्ग चतुर्थ श्रेणी से ऊँचा है । ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण हैं । जबकि एक बाह्य चानक अभिनय सेवा का सदस्य है उस 60 वर्ष तक की आयु तक नौकरी से इस गत पहुँची से रखा गया कि वह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है । इन इन नियमों से सलग्न अधिसूचियाँ एमी गलतियों से बचने के लिए तथा सही वर्ग ज्ञात करने के लिये बनाई गई हैं । नियुक्ति विभाग न सरक्यूलर स F 8 (33) नियुक्ति (क)/55 दिनांक 26 मई, 1959 जारी कर के इस प्रकार की गलतियाँ न करने के लिए अधिकारियों को चेतावनी दी है । इस प्रकार का वर्गीकरण जो पहले से विद्यमान पदा की माध्यता पर आधारित है, अनुचित या मनचाही तरीके से बनाया गया, नहीं माना गया है ।¹ उचित वर्गीकरण से समान सरक्षण का अधिकार भग नहीं होता ।²

नियम 6 का उपनियम (2) विभिन्न ग्रेड्स में विभाजित पदों के बारे में है । एर ही सेवा में प्रत्येक ग्रेड हो सकते हैं और प्रत्येक ग्रेड में विभिन्न सेवाएँ सम्मिलित हो सकती हैं । मसलन, यदि सचिवालय सेवाओं में (i) सलकमन ग्रेड, (ii) ग्रेड प्रथम (iii) ग्रेड द्वितीय, (iv) ग्रेड तृतीय (v) ग्रेड चतुर्थ हैं, तो सलकमन ग्रेड और प्रथम ग्रेड राज्य सेवाओं में हो सकते हैं, ग्रेड द्वितीय अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित हो सकता है, ग्रेड तृतीय लेखक वर्गीय सेवाओं में सम्मिलित हो सकता है तथा ग्रेड चतुर्थ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में हो सकता है । इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी नियम 12 में निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

7 राज्य सेवा में निम्नलिखित होंगे:—

(क) अनुसूची (i) में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य ।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (i) में सम्मिलित पदों पर अधिष्ठायी हैमियत से कार्य करते हों, और जो किसी दूसरे सेवा के सत्रों के नहीं हों ।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकोकरण विभाग के नियमों के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक खण्ड (क) में निर्दिष्ट सेवाओं के सत्रों के पदों पर या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आचार पर नियुक्त किया गया हो ।

8 अधीनस्थ सेवा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे —

(क) अनुसूची (2) में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य ।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (2) में सम्मिलित पदों पर अधिष्ठायी हैमियत से कार्य करते हों और जो पद किसी दूसरी सेवा के सत्रों के नहीं हों ।

1. AIR 1963 मैसूर-203

2. AIR 1959 छावप्रदेश-251

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक खण्ड (क) में निर्दिष्ट सेवाओं के सर्वगों के पदों पर या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

9 लापक वर्गीय सेवाओं में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:—

(क) अनुसूची (3) में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (3) में सम्मिलित पदों पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य करते हो और जो पद किसी दूसरी सेवा के सर्वगों के नहीं हो।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक खण्ड (क) में निर्दिष्ट सेवाओं के सर्वगों के पदों पर, या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

10 चतुर्थ श्रेणी सेवा में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:—

(क) अनुसूची (4) में सम्मिलित सेवाओं के सदस्य।

(ख) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूची (4) में सम्मिलित पदों पर अधिष्ठायी हैसियत से कार्य करते हो और जो पद किसी दूसरी सेवा के सर्वगों के न हो।

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनका एकीकरण विभाग के नियमों के अनुसार उनका अन्तिम चयन होने तक, खण्ड (क) में निर्दिष्ट सेवाओं के सर्वगों के पदों पर या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया हो।

11 (क) सरकार, समय समय पर, अनुसूचियों की प्रविष्टियों में परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी।

(ख) जब कोई विद्यमान पद पर किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो तो ऐसा मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में भेजकर विनिश्चित कराया जाएगा।

टिप्पणी

सेवाओं का वर्गीकरण उपरोक्त भाग 2 में नियमबद्ध किया गया है। प्रत्येक सेवा की सम्पूर्ण सूची बनाई नहीं जा सकती क्योंकि अनेक पद समय समय पर नए बनाए जाते हैं या समाप्त किए जाते हैं। नियम 11 सरकार को ऐसा अधिकार प्रदान करता है जिसमें वह इन नियमों से सतत सूचियों में नए नाम जोड़ने या परिवर्तन करने में समर्थ हो सके। इसमें भिन्न किसी अन्य स्थिति का सामना करने के लिए, नियम 11 का उपनियम (ख) प्रावधान करता है कि यदि कोई पद किसी भी अनुसूची में दर्ज नहीं है, तो मामला सरकार के नियुक्ति विभाग में निर्णय हेतु भेजा जाएगा। कार्य दशना का वांछित स्तर सुनिश्चित करने के लिए सरकार वर्गीकरण के नियम बनाने हेतु कानूनन सक्षम है। हा मवता है कि वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप से सही या तर्क की दृष्टि से सम्पूर्ण न हो। ऐसी विनिश्चिताएँ जिनमें वर्गीकरण करना जरूरी हो, वास्तविक तथा मारभूत (substantial) और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उनमें सही एवं उचित सम्मन्ध रखने वाली होनी चाहिए।¹ अभिव्यक्ति

“सेवा का सदस्य” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इन नियमों के अधीन उक्त सेवा में स्थाई रूप में नियुक्त हो।¹ पूल-रचना (cadre) के अतिरिक्त किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति सम्बंधित सेवा की सदस्यता से बाहर होना नहीं माना जा सकता।²

भाग-3 नियुक्ति प्राधिकारी

12 (1) किसी राज्य सेवा में सम्मस्त नियुक्तियाँ सरकार द्वारा या इस विषय में सरकार द्वारा विशेष रूप से मणक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) किसी अधीनस्थ सेवा में सम्मस्त नियुक्तियाँ विभागाध्यक्ष द्वारा या इस विषय में सरकार की स्वीकृति से विभागाध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से मणक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

(3) किसी लिपिक वर्गीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सम्मस्त नियुक्तियाँ विभागाध्यक्ष द्वारा इस विषय में जारी किये गये नियमों एवं अनुदेशों के अध्वधीन कार्यान्वयाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी

विभिन्न सेवाओं व सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारियों की व्यवस्था नियम 12 करता है। राज्य सेवाओं में सभी नियुक्तियाँ राज्य सरकार करगी। पहले उपरक्त तीनों उपनियमों (1) (2) व (3) में शब्द ‘सम्मस्त’ और नियुक्तियाँ³ व मध्य शब्द प्रथम लिखा हुआ था। इसका तात्पर्य यह था कि पहले केवल प्रथम नियुक्ति प्रदान करने वाला ही नियुक्ति प्राधिकारी माना जाता था। परन्तु अब अधिमूचना सन्ध्या एक 16 (9) नियुक्ति ए/59 दृष्ट 3 दिनांक 23-2-62 द्वारा शब्द ‘प्रथम’ प्रत्यक्ष श्रेणी के लिये तोपित कर दिया गया है। अब अब राज्य सेवाओं में सम्मस्त नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा की जानी हैं और अधिनस्थ सेवाओं की मारी नियुक्तियाँ विभागाध्यक्ष करता है। लेखक वर्गीय सेवाओं में सभी नियुक्तियाँ कार्यान्वयाध्यक्ष करता है परन्तु नि सदेह वह सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये नियमों और निर्देशों से प्रभावित है। इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी सेवा में सम्मस्त नियुक्तियाँ विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये नियमों और निर्देशों का अनुसरण करते हुये कार्यान्वयाध्यक्ष करेगा। राज्य सरकार को यह भी अधिकार है कि वह उप नियम (1) के अन्तर्गत किसी अन्य अधिकारी को भी राज्य सेवाओं में नियुक्तियाँ करने के लिये अधिकार प्रदान कर सके। ऐसी व्यवस्था में, कथित अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी कहनाएगा। इसी तरह नियम (2) के अधीन विभागाध्यक्ष भी किसी अन्य अधिकारी को अधिनस्थ सेवाओं में नियुक्तियाँ करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और उस दशा में ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी कहनायेगा। परन्तु अधिनस्थ सेवाओं के मामले में एक बड़ी बात यह है कि हम प्रकार से अधिकार किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द करने में पहले विभागाध्यक्ष को राज्य सरकार व अधिकार सुपुर्द करने हेतु अनुमति पत्र ले लेनी चाहिए। लेखक वर्गीय सेवाओं तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के सम्बन्ध में कार्यान्वयाध्यक्ष नियुक्तियाँ करने का

1 1970 WLN 302-गोपानकृष्ण वि राजस्थान सरकार।

2 1970 WLN 302-उपराक्तानुसार।

3 अधिमूचना सन्ध्या एक 16 (9) नियुक्ति ए/59 दृष्ट 3 दिनांक 23-2-62 द्वारा शब्द ‘प्रथम’ हटाया गया।

अधिकार किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंप सकता तथा उसके लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों व हिदायतों का पालन होता रहे। यदि विभागाध्यक्ष कोई प्रविबन्ध आरोपित करे या कनिष्ठ पदों के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित करें या कार्यान्याध्यक्ष उक्त हिदायतों के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार यदि विभागाध्यक्ष ऐसी हिदायत जारी करे कि आगामी आदेशों तक कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तो कार्यान्याध्यक्ष तब तक कोई नियुक्ति नहीं कर सकेगा जब तक कि विभागाध्यक्ष नियुक्तियां करने के लिये नई हिदायत जारी नहीं करें।

विभागाध्यक्षों की सूची, अनुसूची (क) में दी गई है और कार्यान्याध्यक्षों की सूची अनुसूची (ख) में है, जो इन नियमों के साथ मलग्न हैं।

स्थाई करने वाला प्राधिकारी अर्थात् वह प्राधिकारी जो किसी परिक्षण में रूने गये कर्मचारी (Probationer) की नियुक्ति मूल पद पर परिक्षण की अवधि समाप्त होने पर स्थाई करे वही उक्त कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। वह अधिकारी जो किसी व्यक्ति को केवल मान परिक्षण (Probation) पर रखे, वह उसका नियुक्ति प्राधिकारी नहीं कहल जा सकेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा पर, (नियम 2-अनुच्छेद-क) की व्याख्या करते हुये हम इस परिभाषा पर पहले से ही चर्चा कर चुके हैं।

भाग-4 निलम्बन

13 निलम्बन—(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसके अधीन वह नियुक्ति प्राधिकारी है या सरकार द्वारा इस विषय में सशक्त कोई भी अन्य प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा:—

(क) जहां कि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही तबित है, या

(ख) जहां उसके विरुद्ध किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में अन्वेषण या विचारण हो रहा हो।

परन्तु जहां निलम्बन की आज्ञा नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर प्राधिकारी द्वारा दी गई है तो उक्त प्राधिकारी, उन परिस्थितियों की रिपोर्टें, जिनमें ऐसी आज्ञा दी गई थी, तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

*राजस्थान सरकार का निर्णय

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इन नियमों के नियम 14 में निर्दिष्ट लघु शक्तियों में से कोई शक्ति आरोपित करने के लिये सशक्त प्राधिकारी को, राज्य सरकार के कर्मचारी को निलम्बन करने का प्राधिकार प्रदान करती है।

(2) कोई राज्य कर्मचारी जो किसी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्यथा 48 घंटों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया हो, तो उसे हिरासत की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित किया हुआ समझा जायेगा और वह आगामी आदेश तक निलम्बन में रहेगा।

* अधिसूचना स, एफ 3 (9) नियुक्ति (अ) 62, दिनांक 10-9-62 द्वारा जोड़ा गया।

जब किसी निलम्बन आदेश में चल रहे राज्य कर्मचारी पर उसने विरुद्ध जारी की गई वर्खा-स्तगी या सेवा से हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या अपील करने के लिए लौटा दिया जावे, तो उस कर्मचारी का निलम्बन सेवा से वर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से पुनः जारी रहना समझा जायेगा और वह प्राणामी आज्ञा तक प्रभावशील रहेगा।

(4) जब किसी राज्य कर्मचारी पर सेवा से वर्खास्त करने, हटाये जाने, या अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने की शास्ति किसी कानूनी न्यायालय के फैसले द्वारा खारिज कर दी जावे या अन्य घोषित कर दी जाये या प्रभावहीन हो जावे और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए अनुशासन प्राधिकारी उन्हीं आरोपों पर जिनके आधार पर उसे वर्खास्तगी हटाये जाने या सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः दी गई थी, आगे जांच करना तय करे तो उक्त राज्य कर्मचारी वर्खास्तगी, हटाये जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित किया समझा जायेगा और प्राणामी आदेशों तक वह निलम्बन में चलता रहेगा।

(5) इस नियम के अधीन जारी किया गया निलम्बन का आदेश, किसी भी समय, उक्त आदेश देने वाले या देने वाले समझे गए प्राधिकारी द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा जिसका उक्त प्राधिकारी अधीनस्थ है।

राजस्थान सरकार के निर्देश

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका-अनुशासन कार्यवाहिदा, 1963 संस्करण, अनुच्छेद 4]

(1) प्रारम्भिक जांच के फल स्वरूप यदि यह समझा जावे कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसे अपने पद पर बने रहने देना सार्वजनिक हित में नहीं है या यदि कोई सरकारी कर्मचारी फौजदारी आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो, तो ऐसे दोषी (delinquent) को तुरन्त निलम्बित कर देना चाहिए। साधारणतः निलम्बन का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे वाले अधिकारी को नहीं देना चाहिए। परन्तु यदि सेवा की आवश्यकता (exigencies of the service) को कोई भिन्न कार्यवाही की तुरन्त जरूरत हो, तो निलम्बन का आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को आदेश की पुष्टि नियुक्ति प्राधिकारी से करवा लेनी चाहिए। हाल ही में राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने का प्राधिकार ऐसे अधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया है जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों के नियम 14 में निर्दिष्ट कोई भी लघु शास्ति लागू करने के लिये सक्षम हो। निलम्बन, आदेश की तिथि से या उससे पहले की किसी तिथि से प्रभावित नहीं करना चाहिये बल्कि चार्ज सुपुर्द करने की तिथि से होना चाहिये। (श्री प्रसाद, 1960 RLW 386), निलम्बन आदेश का प्रमाणिक मजमून (Standardized draft) परिशिष्ट में दिया गया है।

(ii) निलम्बन का आदेश देने वाले प्राधिकारी के लिये दोषी व्यक्ति को निर्वाह भत्ता देने की स्वीकृति भी देनी अपेक्षित है, जो अधिकधिक उसका आधा वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ता होगा।

[निर्वाह भत्ते पर राजस्थान सेवा नियमों का नियम 53 देखिये।]

* (iii) निलम्बित राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाच के लिये समय सारिका — निम्बन के अधीन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाच में निम्नलिखित समय सारिका निर्धारित की गई है —

- | | |
|---|---|
| (1) प्रारम्भिक इनक्वायरी (जाच) पूरी करना और अनुशासन प्राधिकारी को चार्ज व आरोपों के विवरण सहित रिपोर्ट प्रेषित करना । | 3 महीने |
| (2) प्रारम्भिक इनक्वायरी की रिपोर्ट की जाच करना और दोषी को चार्ज शीट देना । | 1 महीना |
| (3) दोषी द्वारा लिखित उत्तर देना । | कम से कम 3 सप्ताह और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने |
| (4) लिखित उत्तर की जाच और जाच अधिकारी की नियुक्ति | 2 महीने |
| (5) विभागीय जाच पूरी करना | 3 सप्ताह |
| (6) जाच रिपोर्ट (enquiry report) का परीक्षण | 2 सप्ताह |
| (7) कारण बताओ नोटिस जारी करना | 2 सप्ताह |
| (8) दोषी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रेषित करना | 3 सप्ताह |
| (9) कारण बताओ नोटिस के उत्तर की जाच और अंतिम आदेश जारी करना | 1 सप्ताह |

नोट — यदि किसी मामले में किसी विशेष अवस्था (stage) पर उपरोक्त समय सारिकानुसार कामवाही करने में कठिनाई हो, तो अनुशासन प्राधिकारी से किसी विशेष अवस्था (stage) पर समय बढान की अनुमति प्राप्त की जाएगी । यदि ऐसी कोई कठिनाईया अनुशासन प्राधिकारी को महसूस हो तो वह ऐसी अनुमति अपने अगल उच्च प्राधिकारी से प्राप्त करेगा ।

*राजस्थान सरकार के नीतिर्देश

मिबाय उन मामलों के जिनमें सरकारी कर्मचारियों को फौजदारी अपराध की तफ़्तीश या मुकदमा चालू होने के कारण निलम्बित किया गया हो निम्नलिखित सरकारी आदेश राज्य कर्मचारियों को निलम्बित करने के मामले में दृढ़ता से पालन करना चाहिए ।

(1) निलम्बन करने का रास्ता बहुत सावधानी से अपनाया जाना चाहिए और केवल तभी जबकि राजस्थान (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन निर्धारित किसी कठोर शांति दोषी कर्मचारी पर अन्ततः लागू करने की सम्भावना हो अथवा जब वह किसी फौजदारी जाच पर गिरफ्तार कर लिया गया हो ।

* नियुक्ति (ए-III) विभाग का सरखूनर स F 5 (43) नियुक्ति (ए/62 दिनांक 8-2-63 तथा सप्या एफ 2 (9) नियुक्ति (ए-III) 64 दिनांक 23-3-66

** म एफ 3 (28) ए ए-II/69 दिनांक 27 अप्रैल, 1970

(2) निलम्बन के सम्बन्ध में आदेश जारी करने से पहले, निम्नलिखित प्राधिकारी के सामने प्रारम्भिक रिपोर्ट और दायी कर्मचारी का कचन दोनों उपलब्ध होने चाहियें तब उपर्युक्त (1) का पालन कर मवे, वरानि बेचर प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर आदेश जारी करना सम्भवत इक-तरफा आधार पर होगा ।

(3) निलम्बन करने के पश्चात् समय सारिका के अनुसार कार्यवाही करने का प्रयास करना चाहिये ।

एक नया निर्देश निम्नानुसार है:—

राजस्थान सरकार का निर्देश

I * *राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ, जमाते इस्लामी और आतन्द मार्ग की गतिविधियों में भाग लेना:—आपातकाल (इमरजेन्सी) में लगाया गया प्रविष्य वापस ले लिया गया है ।

II ¹ कारण बताओ नोटिस पर निलम्बन:—विभागीय जाव के पश्चात् जब राज्य कर्मचारी को नियम 16 (10) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी हो, तो यदि वह पहले ही से निलम्बन में नहीं हो तो, उसे तुरन्त निलम्बित विषा जाना चाहिये ।

² राजस्थान सरकार का निर्देश

फौजदारी कार्यवाहिया चालू रहने की अवधि में या जूग के कारण गिरफ्तारी की कार्यवाही होने पर या किसी कानून के अधीन निवारक नजरबन्दी का प्रावधान करने वाले किसी कानून के (अर्थात् अब मौसा) के अन्तर्गत हिरासत के दरमियान निलम्बन ।

(क) जब किसी राज्य कर्मचारी को निवारक नजरबन्दी का प्रावधान करने वाले किसी कानून के अधीन या किसी फौजदारी अपराध या जूग के फलस्वरूप कार्यवाहियों में हिरासत में रखा जाता है और यदि हिरासत की अवधि 48 घण्टों से अधिक हो और यदि वह पहले से ही निलम्बित नहीं है, तो वह राजस्थान सिविन सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (2) के अनुसार भावी अद्वेष होने तक, हिरासत की निधि से निलम्बित होना सम्भवा जाएगा । जो राज्य कर्मचारी कैद की सजा भुगत रहा हो भी, इसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करने का फैसला विचाराधीन रहने पर उसके साथ भी इसी प्रकार का मन्क किया जाएगा,

(ख) जिन सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध, निम्नी फौजदारी आरोप पर कार्यवाही चालू हो पण्तु जिसे वास्तव में हिरासत में नहीं रखा गया हो (उदाहरणन जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति), वह राजस्थान सिविन सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों के नियम 13 (1) के अनुच्छेद (क) के अधीन मक्षम प्राधिकारी के आदेश से निनम्बित किया जा सकेगा । यदि चार्ज राज्य कर्मचारी के सरकारी पद से सम्बन्धित है या उसका नैतिक पतन (moral turpitude) का है, तो जब तक कि कोई अन्य रास्ता अपनाने के लिए विशेष कारण न हो तब तक निनम्बन का आदेश इसी नियम के अन्तर्गत दिया जाएगा

** मन्वा F 4 (1) कामिक/A-III/74 दिनांक 19-5-1977, 'लेखाविज्ञ' 1977 पेज 1

1 उपरोक्त अधिमूचना का 'लेखाविज्ञ' 1977 में पृष्ठ 257 पर प्रकाशित हुई ।

2 राज सेवा नियम विन 2 परिशिष्ट I-(II) वित्त विभाग मोसा स 2467-A (1) एक डी ए /नियम 53 I दिनांक 10-8-1959

(ग) जब किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध श्रृण के लिए गिरफ्तारी की कार्यवाही चालू की गई हो परन्तु जो वास्तव में हिरासत में नहीं लिया गया है, तो उसको राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधीन) नियम 1958 के नियम 13 (1) के अनुच्छेद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया जा सकेगा अर्थात् केवल तभी जब कि उसके विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करने का इरादा हो।

(घ) जब कोई राज्य कर्मचारी, जिसे अनुच्छेद (ख) में उल्लेखित परिस्थितियों में निलम्बित समझा गया है, बिना अनुशासन कार्यवाही किए पुनः स्थापित (re-instated) किया जाता है, तो निलम्बन काल का वेतन और भत्ता नियम 54 के अधीन नियमित किया जाएगा, अर्थात् यदि वह दोष से बरी किया गया है (या उसके विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही श्रृण के लिए थी नहीं थी) या यह साबित हुआ हो कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था जो उसके नियन्त्रण में बाहर थी या किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसको हिरासत में रखना पूर्णतः अनुचित करार दिया हो, तो मामला नियम 54 (2) के अधीन निपटाया जाएगा, अन्यथा नियम 54 (3) के अधीन तय किया जाएगा।"

नोट.—ऊपर नियम 54 का उल्लेख है, उससे अभिप्राय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 से है।

³ राजस्थान सरकार का निर्देश

यदि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्षों से अधिक समय से निलम्बित चला आ रहा है (और किसी कानूनी अदालत में उस पर फौजदारी मुकद्दमा नहीं चल रहा है) तो दो वर्षों की समाप्ति पर सक्षम प्राधिकारी तुरन्त निलम्बन आदेश का पुनः निरीक्षण करेगा। यदि उसे निलम्बन करने का आधार तब भी विद्यमान है, तो उसका निलम्बन जारी रहेगा, परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी (जो साधारणतया नियुक्ति प्राधिकारी होगा) यह अनुभव करे कि जिन आधारों पर उसे निलम्बित किया गया था वे अब मौजूद नहीं हैं अथवा यदि उक्त प्राधिकारी अनुभव करे कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनसे उस पुनः स्थापित करना जरूरी है, तो लिखित में कारण अभिलिखित करके उस राज्य कर्मचारी को पुनः स्थापित कर सकेगा। यह पुनः स्थापन विभागीय जाच के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा किन्तु जिस मामले में पुनः स्थापन किया गया है, निलम्बन की अवधि क्या समझी जाएगी इसका फैसला तभी किया जाएगा जब कि दोनों के विरुद्ध विभागीय जाच का अंतिम निर्णय हो जावे।

जाच प्रारम्भ होने के एक वर्ष पश्चात् जाच अधिकारी विभागाध्यक्ष के माध्यम से (जबकि जाच अधिकारी विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य हो) सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को सूचित करेगा कि जाच अमुक समय में समाप्त होगी सम्भव थी और पिछले विलम्ब और भविष्य में होने वाले विलम्ब का कारण बतलायेगा। तत्पश्चात् सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को हर तीन महीने प्रगति रिपोर्ट भेजी जाएगी। ऐसे मामलों का पुनर्निरीक्षण प्रशासन विभाग में किया जायेगा और उचित आदेश पारित किये जाएंगे। जब यह अनुभव किया जाये कि बिना पर्याप्त कारण के जाच में अत्यधिक विलम्ब हुआ है या विलम्ब के पीछे कोई बदनीयती का इरादा था, तो सम्बन्धित जाच

अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये नियुक्ति विभाग को लिखा जाना चाहिये।

जब किसी उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अथवा अदालती फॉर्मले के फलस्वरूप या अथवा यह जान हो कि किसी दोगी राज्य कर्मचारी को इसकारण से बरी किया गया है कि जाच अधिकारी या अनुशासन प्राधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए, यदि उन्होंने जानबूझ कर निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना की या घोर लापरवाही के कारण निर्धारित प्रक्रिया वा अनुसरण नहीं किया अथवा प्रक्रिया बदनीयता से भंग की गई।

जब किसी राज्य कर्मचारी को, जिसे मामले में जाच विचाराधीन होने से निलम्बन में रखा गया था, पुन स्थापित किया जाए तो पुन. स्थापित करने में सक्षम प्राधिकारी को आदेश में यह अवश्य ध्यक्त करना चाहिये कि निलम्बन काल का शुमार किस प्रकार किया जाएंगे तथा उस अवधि के लिये कितना वेतन एवं भत्ता दिया जाना है। यदि राज्य कर्मचारी पूरी तरह दोषमुक्त किया जाना है, तो वह पूरे वेतन व मंहगाई भत्ते का हकदार होगा। अन्य मामलों में उस अनुपात से वेतन तथा भत्ते अनुमन किये जायेंगे जितने सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे। पुनः स्थापन उस तिथि से प्रभावित होगा जिस तिथि को राज्य कर्मचारी अपने पद का यथा स्थान भार सभाले।¹

प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए, समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा हर वर्ष 15 जनवरी तक निम्नलिखित परिशिष्ट-2 में निर्धारित प्रपत्र पर वार्षिक नक्शा भेजा जायेगा जिसमें निलम्बित किये गये राज्य कर्मचारी तथा उनकी विभागीय जाच वा नतीजा दर्शाया जायेगा। यह नक्शा राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष देखनी है, इसलिये समय पर भेज देना चाहिए।

[राजस्मान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तक अनुच्छेद 4,]

परिशिष्ट-2

... .. विभाग

वर्ष के लिये निलम्बन में रले गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विषय में विचाराधीन विभागीय जाच के मामलों की अवस्था बतलाई गई है।

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम तथा पद	आया राजपत्रित अधिकारी है या अराजपत्रित	निलम्बन की तिथि	चार्ज शीट देने की ' तिथि	जाच करने के आदेश की तिथि
1	2	3	4	5	6
जाच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि	निरुपण तथा उसकी तिथि	कानूनी कार्यवाही की अवस्था, यदि कोई हो	विलम्ब के कारण	विशेष विवरण	
7	8	9	10	11	

टिप्पणी

निलम्बन का तात्पर्य:—शब्द 'निलम्बन' की परिभाषा इन नियमों में दी हुई नहीं है। परन्तु निलम्बन का मुख्य अभिप्राय राज्य कर्मचारी को अपने विशेषाधिकार का पद धारण करते हुये और सरकारी हैसियत से कार्य करने में दखल करने से है।¹ अन्य शब्दों में उसे अपने अधिकार प्रयोग करने से या सरकारी पद पर विशेषाधिकार रखने से रोका जाता है और उसे अस्थाई रूप से उसके कार्यों व विशेषाधिकार से अलग रखा जाता है।² निलम्बन वर्षास्तगी या सेवा से पृथक् करना नहीं होता, इसलिए वह सविधान के किसी प्रावधान को आक्रामित नहीं करता। कर्मचारी को उसके कर्तव्य-पालन से अस्थाई रूप में केवल रोका जाता है।³

ज्ञात रहे कि सरकार को मज्रा के रूप में निलम्बित करने का अधिकार नहीं है। निलम्बन का आदेश तभी दिया जाता है जब कि नागरिक कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जाच, या फौजदारी तफरीश या फौजदारी मुकद्दमा विचाराधीन हो। यह आवश्यक है ताकि सरकार और सम्बन्धित कर्मचारी दोनों उलझन की दशा (embarrassing situation) में बच सकें। निलम्बन काल में दोषी अधिकारी को पूरा वेतन नहीं दिया जाकर निर्वाह भत्ता प्रदत्त किया जाता है।⁴

मालिक बिना कोई कारण बताये अपने कर्मचारी को कह सकता है कि वह कार्य नहीं करे, परन्तु ऐसा आदेश बतौर मज्रा होना चाहिए, और इसीलिये मानिक को अपने कर्मचारी को पूरा वेतन का भुगतान करना होगा।⁵

निलम्बन न तो पदस्तर में पक्षिच्युत करना है,⁶ और न ही सेवा से हटाना है।⁷ अतः निलम्बन आदेश जारी करने से पहले दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है। ऐसा आदेश रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता।⁸ परन्तु मध्य प्रदेश वि. शमशुद्दीन⁹ में नागपुर उच्च न्यायालय ने एक भिन्न निर्णय दिया, जिसमें न्यायभूति बोस ने व्यक्त किया कि जब किसी व्यक्ति को निलम्बित किया जाता है तो उसकी राय में उसे उसकी पदपक्ति से गिरा दिया जाता है। परन्तु उसके बाद, कलकत्ता, उड़ीसा, मद्रास, मध्यभारत, पटना, आसाम, आन्ध्रप्रदेश, केरल आदि उच्च न्यायालयों ने नागपुर के निर्णय की पुष्टि नहीं की। अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने तय कर दिया है कि जाच का निर्णय विचाराधीन रहने, निलम्बन का आदेश, सविधान के अनुच्छेद 311 को आक्रामित नहीं करता।¹⁰

1. ए. आई. आर 1958 आन्ध्र प्रदेश 619—मोहम्मद आजम वि. हैदराबाद सरकार।

2. ए. आई. आर. 1964 सुप्रीमकोर्ट 72 तथा ए. आई. आर 1954 कलकत्ता-340.

3. AIR 1954 जम्मू-कश्मीर 14

4. AIR 1961 बनकला 225

5. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 823—भारत सरकार वि. टी. एन. घोष।

6. AIR 1958 राजस्थान 239—बट्टी प्रताप वि. राजस्थान सरकार, 1975 SLJ 333.

7. AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 246; (1974) 1 S L R-90.

8. 1977 Lab 1 C. (NOC) 105 (कलकत्ता)

9. AIR 1949 नागपुर 118

10. AIR 1957 सुप्रीमकोर्ट 246—मोहम्मद आजम वि. मद्रास सरकार।

निलम्बन प्राधिकारी — नियम 13 (1) के अनुसार निम्नलिखित प्राधिकारी निम्बन आदेश जारी करने का अधिकार रखते हैं:

- (i) नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त नियम 12 के अनुसार; अथवा
- (ii) कोई उच्चतर प्राधिकारी जिसका नियुक्ति प्राधिकारी अधिनस्थ है, अथवा
- (iii) कोई अन्य प्राधिकारी जिसको राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए शक्ति प्रदान की हो।

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार (अग्रिमूचना दिनांक 11 मिनम्बर, 1962), किसी राज्य कर्मचारी को निम्बन करने के अधिकार ऐम सक्षम प्राधिकारी को सुपुर्द कर दिए गए हैं जिसको यह अधिकार हो कि वह सम्बन्धित कर्मचारी को नियम 14 में निर्दिष्ट कोई लघु शक्ति से दण्डित कर सकते तामार्थ निन्दा, बेतन वृद्धि या पदोन्नति रोक देना, सचारी आर्थिक हानि को पूर्णतः या आंशिक रूप में बमूल करना, निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद आदि पर अवनत कर देना। यदि निम्बन करने वाला प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी को पद-पक्ति से नीचे का है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि मामले की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को भेजे।

सरकारी निर्देशन यह भी आज्ञा देना है कि निम्बन का प्रभाव किसी पिछली शक्ति से नहीं हो सकता और न आदेश की शक्ति में ही, बल्कि पद का भार सुपुर्द करने की तारीख में होगा।

राजकीय सेवाओं के लिए, राज्य सरकार निम्बन प्राधिकारी है। म्याई निर्देशानुसार, राजकीय सेवाओं के किसी सदस्य को निम्बन करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री को विशेष सचिव (DOP) के माध्यम से आदेश और अनुमति हेतु भेजना चाहिये।

निलम्बन प्राधिकारी, निम्बित व्यक्ति के जागजात को खटाई में डालकर हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। उसे नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से उसके रिपुट अनुशासन कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिये और यदि प्रथम दृष्टि में कोई (prima facie) आरोप नहीं बनता, तो उसे अपना आदेश वापिस लेना चाहिये। राजस्थान सरकार वि जगदीश चन्द्र¹ में तय किया गया है कि बिना अनुशासन कार्यवाही चलाए इनके समये तब निम्बन आदेश जारी रखना कि जिसमें सम्बन्धित अधिकारी की सेवाएं अन्तिम रूप से समाप्त हो गई, प्रकट करता है कि नियुक्ति प्राधिकारी उसके विरुद्ध ईमानदारी से कार्यवाही नहीं कर रहा था। अतएव राजस्थान सरकार ने विभागीय जांच के लिए एक समय मारिका निर्धारित करदी है, जो ऊपर दी जा चुकी है।² यदि निर्धारित समय मारिका के अनुसार किसी अवस्था में काम करना कठिन हो तो अनुशासन प्राधिकारी से समय बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए और यदि अनुशासन प्राधिकारी स्वयं ऐसी कठिनाई में हो, तो वह इसी प्रकार की अनुमति अपने अपने उच्चतर प्राधिकारी में प्राप्त करेगा।

नि सदेह उपर्युक्त निर्देशों के पालन नहीं करने से निम्बन का आदेश गैर कानूनी नहीं होगा, फिर भी जहां तक समय हो उनका अनुसरण करना ही चाहिये।^{*}

1 1976 Lab I c 385 (Rajasthan)

2. सरक्यूलर No F. 5 (43) Appts (A/52) दिनांक 8-2-63 और No F 2 (a) Appts (A-III) 64 दिनांक 26-3-66

* 1976 SCC (L & S) 155

नियोजक को मूल अधिकार होता है जिसमें कि वह अपने कर्मचारी को निलम्बित करने में सक्षम है। करीब करीब यह एक गंभीत अथवा छिपा हुआ अधिकार है और राज्य कर्मचारी ऐसे आदेश पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह उसकी सेवा की एक शर्त है।¹ फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि जब भी कोई विभागीय जांच चल रही हो तो कर्मचारी को निलम्बित किया ही जाय।² विभागाध्यक्षों और निलम्बित करने के लिए सशक्त अधिकारियों को, "किसी राज्य कर्मचारी को निलम्बित करने के मामले में अत्यन्त सावधानी और सतर्कता से कार्य करना चाहिए। साधारणतः निलम्बित केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो या चढ़ाने का विचार हो अथवा जबकि उसके विरुद्ध कोई पौजदारी मामला तफ्तीश में हो या मुकदमा चल रहा हो और दोषारोपण की गम्भीरता या अपराध ऐसा हो कि यदि यह साबित हो जाय तो बहुत सम्भव है कि वह उसकी सेवा से हटाये जाने या बर्खास्त करने में पराजित होगी।"³

'निलम्बन' के सम्बन्ध में आदेश जारी करने से पूर्व निलम्बन प्राधिकारी के सामने प्रारम्भिक रिपोर्ट और दोषी कर्मचारी का कथन दोनों होने चाहिए।⁴

विभागीय जांच के पश्चात् कारण बताओ नोटिस-ब्या निलम्बन आवश्यक है? — सरकार ने निर्देश जारी किया है कि विभागीय जांच के पश्चात् जब प्रस्तावित शास्ति के बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा हो तो नियम 16 (10) के अधीन दोषी कर्मचारी को, यदि वह पहिले से ही निलम्बित न हो तो निलम्बित कर दिया जाना चाहिए।⁵

आपातकाल में सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायत-ए इस्लामी तथा आनन्द माग की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यह प्रतिबन्ध 1977 में उठा लिया गया है।⁶

'विचार हो' — नियम 13 के अनुच्छेद 1 (क) अनुशासन कार्यवाही के सम्बन्ध में जो अभिव्यक्ति 'विचार हो' लिखी गई है उससे अभिप्राय यह निकलता है कि सम्बन्धित प्राधिकारी ने कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर विचार किया है और सोचा है और इस विषय में उपरन्ध सामग्री का निरीक्षण किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध प्रथम-बलोक्न में दुर्गचरण प्रतीत होता है जिससे नियमित जांच करना उचित है। उपनियम (1) के अधीन निलम्बन का आदेश बोलता हुआ आदेश होना चाहिए अर्थात् निलम्बन का कारण व्यक्त करते हुए होना चाहिए ऐसे आदेश में निरनुशता की वृत्ति नहीं आनी चाहिए क्योंकि निलम्बन के परिणाम गम्भीर होते हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को पूरे वेतन प्रनिष्ठा तथा श्वांति की हानि।⁷

1. 1977 Lab I C 73 (इनाहाबाद) पूर्णपीठ

2. 1971 Lab I C 973-डा एस अय्यर वि मैमूर सरकार

3. अधिसूचना स F 3 (28) AA-III/69 दिनांक 27-4-70 जो पूरा ऊपर दिया जा चुका है।

4. अधिसूचना स D 16633/59F 19 (28) Appointments (A) 60 दिनांक 17-3-60 जो पूरा ऊपर दिया जा चुका है।

5. अधिसूचना स F 9 (34) कामिग/A-III/74 दिनांक 19-5-77 जो लेखाविज्ञ 1977 में पृष्ठ 257 पर प्रकाशित हुआ।

6. उपरोक्तानुसार

7. 1975 Lab I C 1190-अर्शादअहमद वि जम्भू कश्मीर सरकार।

जांच के दौरान निलम्बन—का आदेश दोषी कर्मचारी के विरुद्ध चार्ज (आराप) निर्धारित करने से पूर्व या उसके पश्चात् किसी भी अवस्था में दिया जा सकेगा परन्तु केवल तभी जबकि तावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, सम्बन्धित प्राधिकारी इस मत का हो कि विभागीय जाच की उम्माद है या चल रही है। इन नियमों के अधीन निलम्बित करने की शक्ति कौनसी अवस्था में प्रयोग की जा सकती है वह सदैव प्रत्येक मामले के तथ्या एवं परिस्थितियों पर आधारित होगी।¹

निलम्बन से पूर्व नोटिस देना आवश्यक नहीं —किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन का आदेश देने से पूर्व उसे नोटिस देना आवश्यक नहीं है।² इसका कारण यह है कि निलम्बन केवल उसे पद से हट्टाई रूप में ध्वित करना मान है। यह सजा देने का कार्य अंतिम आदेश नहीं होता।³ जाच के दौरान या फौजदारी मुकदम के दौरान निम्बन सजा के बतौर निलम्बित करने से संवधा भिन्न है, जो कि एक अलग मामला है।⁴

स्वतः निलम्बन या अर्थात् समझा गया निलम्बनः—निम्नलिखित परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें नियम 13 के उप नियम (2) (3), तथा (4) के अनुसार सरकारी कर्मचारी को भविष्य के आदेश तक निलम्बित किया द्वारा समझा जायेगा —

- (i) जबकि सरकारी कर्मचारी को किसी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्यथा 48 घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, ता हिरासत में लेने की तारीख से, अथवा
- (ii) जबकि सेवा से बर्खास्तगी या हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश अपील या नजरसानी में निरस्त कर दिया गया हो और मामले को आगे जाच के लिए या आगे की कार्यवाही के लिए या अन्य किसी निर्देशों के साथ वापस भेजा गया हो। ऐसा निलम्बन बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश से जारी रहना समझा जाएगा, अथवा
- (iii) जबकि बर्खास्तगी, सेवा से हटाए जाने, या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति किसी कानूनी अदालत द्वारा खारिज कर दी गई हो या शून्य घोषित कर दी गई हो या शून्य हो गई हो और अनुशासन प्राधिकारी उन्ही मूल आरोपों के विषय में जिनमें राज्य कर्मचारी को पहले सजा देने का आदेश दिया गया था, फिर से जाच करना तय करे।

उपयुक्त परिस्थितियाँ में निलम्बन का कोई औपचारिक आदेश जरूरी नहीं है फिर भी सम्बंधित सरकारी कर्मचारी निलम्बन में रखा गया समझा जाएगा। मूर्य कुमार चटर्जी वि एस एन बनर्जी⁵ ने निर्णय दिया कि जिस अवधि में सरकारी कर्मचारी हिरासत में था जेल में बन्द रहा उस काल में स्वतः वह निलम्बन में होना समझा जाएगा। जबकि हिरासत में था जेल में रखा जान की अवधि के

1 1977 Lab I C 73—पूर्णपीठ निर्णय जिसने 1974 इनाहाबाद L J 282—जवाहरलाल भागव वि सरकार के निर्णय को ध्वित किया।
 2. AIR 1964 मद्रास 518
 3. AIR 1963 मणीपुर 28
 4. AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 787
 5. AIR 1955 कलकत्ता 365

लिए निलम्बन का कोई विधिष्ट आदेश आवश्यक नहीं था, परन्तु जिन दिनों वह वास्तव में हिरासत में या जेल में बंदरूद्ध नहीं था उस समय के लिए विधिष्ट आदेश आवश्यक था।

नियम 13 (3) और नियम 13 (4) के प्रभाव में राज्य कर्मचारी के लिए कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों अवस्थाओं में निलम्बन, वर्खास्तिगी, सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश से प्रभावशील होगा और आगामी आदेश तब जारी रहेगा।

हिरामन से छूटने के बाद, जैसे ही राज्य कर्मचारी बहाल आये, वह पुनःस्थापन (re-instatement) का हकदार होता है। अतः ऐसी रिहाई के बाद, यदि सम्बन्धित प्राधिकारी, जाच बिठाना तब करे तो उस कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा, अर्थात् पुनः स्थापन की आज्ञा जारी करने समय, साथ ही उसे निलम्बित करने का आदेश प्रदान कर सकेगा।¹

फौजदारी जाच या मुकदमा चालू रहने, फौजदारी कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे तब निलम्बन प्रभावशील रहेगा। अतः जैसे ही कर्मचारी के बर्ग होने या डिमिचार्ज होने के साथ इन कार्यवाहियों का अन्त हो वैसे ही निलम्बन आदेश स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा। इसलिए ऐसी मामलों के तुरन्त बाद सम्बन्धित राज्य कर्मचारी निलम्बन की तिथि से पूरा वेतन तथा भत्ता का हकदार हो जाएगा।²

साजे निलम्बन आदेश की आवश्यकता — जब किसी राज्य कर्मचारी का वर्गीकरण (Conviction) अपील में खारिज हो जाता है और जबकि निलम्बन का अन्तर्ग्रिह आदेश वापिस लिया जा चुका था, तो विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने में निलम्बनका पूर्व आदेश स्वतः पुनर्जिवित नहीं होगा।³

जब किसी कर्मचारी को उसके विरुद्ध विचाराधीन फौजदारी मुकदमे के कारण निलम्बित किया गया था तो अदालत द्वारा उसने पक्ष में बरी करने का फैसला होने पर, वह पुनः स्थापन का हकदार हो गया। दोषमोचन (Acquittal) की तिथि से उसके पुनः स्थापन के अधिनार पर हम कारण से कोई रखावट नहीं होगी कि उसने बरी करने के आदेश के विरुद्ध सरकार ने अपील दायर की है।⁴

ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए जिन्होंने विरुद्ध फौजदारी दोषारापण की कार्यवाहियां चली रखी हैं। परन्तु जो वास्तव में हिरामन में नहीं हैं (उदाहरण जमानत पर छूटा हुआ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन का स्पष्ट आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है। जबकि दोषारापण उसने सरकारी पद में सम्बन्धित है अथवा उगमें कोई नैतिक पनन सम्मिलित है, तो जब तब कि कोई भ्रष्ट रास्ता अपनाने के लिए विशेष कारण विद्यमान न हो तब तब नियम 13 (1) के अनुच्छेद (ख) के अधीन साधारणतः उसको निलम्बित करने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।⁵

सरकारी आदेश यह भी निर्धारित करते हैं कि जब किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध धृष्ट के कारण हिरासतारी की कार्यवाही शुरू की गई हो परन्तु जो वास्तव में हिरामन में नहीं गया गया हो तो उसको निलम्बित करने के आदेश नियम 13 (1) के अनुच्छेद (ख) के अधीन केवल तभी जारी

1. 1975 lab I C 1190 (जम्मू-कश्मीर) सर्जेंट महमद वि जम्मू-कश्मीर सरकार।

2. AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 787, 1976 lab I C 1503 (D II) चार पी बणू वि भारतीय मय।

3. 1976 lab I C 1503 (गण्ट पीठ)।

4. 1977 Lab. I C. 1325 (जम्मू तथा कश्मीर)

5. ऊपर उल्लिखित राजस्थान सरकार के आदेश।

कये जायेगे जब उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार हो ।

जब किसी राज्य कर्मचारी को जो अनुच्छेद (ब) में उल्लेखित परिस्थितियों में नितम्बन के अधीन समझा गया था बिना कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही किये पुनः स्थापित किया जाता है, तो उसका वेतन व भत्ते नितम्बन अवधि के दौरान राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 के अधीन नियमित किए जान चाहिये ।

यदि वह उससे विरुद्ध लगाये गये आरोपों में दोषमुक्त हो गया हो या यदि उसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही ऋण के लिये थी अथवा यह साबित हो जाए कि उसका दायित्व ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था जो उसके नियंत्रण के बाहर थी अथवा गिरफ्तारी पूर्णतः अनुचित निष्पत्ति की गई हो तो कर्मचारी का मामला राजस्थान सेवा नियमों के नियम 54 (2) के अधीन निपटाया जाएगा और यदि अन्यथा हो, नियम 54 (3) के अन्तर्गत ।

इसके विपरीत जबकि सरकारी कर्मचारी दोषी साबित हुआ हो और उस आधार पर उसे दण्डित किया गया हो, तो नितम्बन की अवधि में मुग्तान का मामला राजस्थान सेवा नियमों के अनुच्छेद (3) तथा (5) के अन्तर्गत तय किया जायेगा । ऐसे मामले में साधारणतः सेवा से गैर हाजरी सेवा की अवधि नहीं समझी जायेगी । भाषता तय करने से पहले दोषी कर्मचारियों को कोई नोटिस देना जरूरी नहीं है ।¹ परन्तु जब कि अधीन में राज्य कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था और उसे पुनः स्थापन करने का आदेश हुआ, फिर भी राज्य सरकार ने अधीन तय करते हुए आदेश दिया कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि और उसके व.प.म. नौकरी पर जान की तिथि के मध्य का काल विशेष प्रकाश के रूप में शुमार किया जायेगा, तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसे मामले में प्राचीन की प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था । चूंकि नववर्तन मन भ्यास कि राजस्थान सरकार² में ऐसे नोटिस का अभाव था इसलिए विधायी अधीन आदेश इस आधार पर खारिज किया गया कि उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया था ।

यहां राजस्थान सेवा नियमों का नियम 54 उद्धृत करना लाभकारी होगा ।

(1) 'नियम 54 (1)—पुनः स्थापन,—जब किसी राज्य कर्मचारी को जिससे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया था या शांति स्वरूप अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिया गया था या निवृत्त कर दिया गया था वह पुनः स्थापित किया जाना है तो पुनः स्थापित करने वाला सक्षम अधिकारी उस पर विचार करेगा और निम्न बिन्दुओं पर विनिश्चित आदेश प्रदान करेगा —

(क) काम में अनुपस्थिति के काल में या विश्राम वृत्ति धापु पर भेजा निवृत्त होने की तिथि को नितम्बन की अवधि, यथा स्थिति, में कर्मचारी को देने वाले वेतन व भत्तों के विषय में; तथा

(ग) आया उक्त अवधि काम पर रहने के काल में शुमार की जायेगी या नहीं ।

(2) जब ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह धारण करे कि राज्य कर्मचारी पूर्णतः दोषमुक्त हो गया है, अथवा नितम्बन के मामले में यदि नितम्बन पूर्णतः अनुचित था तो राज्य कर्मचारी को पूरा वेतन

1. 1977 WLN 245 —यजराजा सिंह वि. राजस्थान सरकार

2. 1974 WLN—877.

तथा महगाई भत्ता दिया जायेगा जिसका कि वह हक्दार होना, यदि वह शास्ति के रूप में सेवा से बर्खास्त या पृथक् या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त नहीं किया जाता या निलम्बन नहीं किया जाता, जैसी भी स्थिति हो।

(3) अन्य मामलों में, राज्य कर्मचारी को उस अनुपात से वेतन तथा महगाई भत्ता दिया जायेगा जैसा कि मक्षम प्राधिकारी निर्धारित करे।

(4) उप-खण्ड (2) के अधीन आने वाले मामलों में काम से अनुपस्थिति के समय को सभी प्रयोजनों के लिए कार्य पर ध्येयित किया गया समय समझा जायेगा।

(5) उप-खण्ड (3) के अधीन आने वाले मामलों में काम से अनुपस्थिति का समय काम पर ध्येयित किया गया काल तब तक समझा जायेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विशिष्टतः ऐसा निर्देश नहीं दे कि उक्त अवधि किसी विशेष प्रयोजन के लिये बिताई गई समझी जायेगी।

परन्तु शर्त यह है कि यदि राज्य कर्मचारी ऐसा चाहे तो उक्त प्राधिकारी निर्देश दे सकेगा कि कार्य से अनुपस्थिति का समय कर्मचारी के बकाया तथा स्वीकृत योग्य किसी प्रकार के प्रवकाश में परिवर्तित कर दिया जावे।”

वर्खास्ती के आदेश के साथ निलम्बन आदेश समाप्त हो जाता है; जब वर्खास्ती खारिज की जावे तो वह पुनर्जीवित नहीं होता—ग्राम प्रमाण गुणा विरुद्ध यू पी सरकार¹ में प्रार्थी, जो पहले निलम्बन में था उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था जिससे निलम्बन का आदेश समाप्त हो गया तथा प्रभावहीन हो गया। बाद में सिविल न्यायालय ने वर्खास्ती के कथित आदेश को अवैध घोषित किया। इसमें निर्णय हुआ कि सिविल न्यायालय से जो निलम्बन आदेश पहले से ही समाप्त हो चुका था वापस पुनर्जीवित नहीं हुआ।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भैरो प्रसाद वि राजस्थान सरकार² में भी यही सम्मति प्रकट की है, जिसमें यह कहा गया है:—

“न्यायालय द्वारा सेवा में वर्खास्ती का आदेश खारिज कर दिए जाने से, जाच के दौरान लागू पहले का निलम्बन आदेश बहाल नहीं होता। यह महत्वहीन है कि आया वर्खास्ती का आदेश, मामले के गुण-अवगुण पर खारिज किया गया था सावधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने से या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना के कारण निरस्त किया गया।”

ऐसे मामलों का सामना करने के प्रयास में, पूर्वगामी प्रभाव से ताजा निलम्बन आदेश जारी करने की भी न्यायालयों ने भर्त्सना की है और उसे अवैध ठहराया है।³ इस प्रकार के निर्णयों के फल स्वरूप भागत मन्कार तथा राजस्थान सरकार को भी नियमों में मशोधन करना पड़ा। कानून की सही स्थिति जयवंत राव वि. राजस्थान सरकार⁴ में भी निम्नानुसार स्पष्ट की गई है—

“जब कोई विभागीय जाच के दौरान दिया गया निलम्बन का आदेश बाद में दिये गये सेवा मुक्ति के आदेश में विलीन हो जाता है और तत्पश्चात सेवा मुक्ति का आदेश किसी बादूनी अशालत

1. AIR 1955 मुम्बई कोर्ट 600

2. ILR 1960 राजस्थान 952

3. 1957 RLW 587.

4. 1963 RIW 374

द्वारा या ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जावे, तो निलम्बन का आदेश पुनर्जीवित नहीं हो सकता क्योंकि वह वनई विद्यमान ही नहीं है और आगे स्थिति यह है कि कानूनी प्राविष्टि (Statutory Authority) के अभाव में, पूर्वकालीन प्रभाव से ताजा निलम्बन आदेश नहीं दिया जा सकता।¹

ऐसा एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने देवेन्द्र प्रताप नारायण राय शर्मा वि उत्तर प्रदेश सरकार² में प्रस्तुत हुआ, जिसमें निम्नलिखित निर्णय दिया गया —

“उच्च न्यायालय ने दावे में डिमी इस आधार पर जारी की कि शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया अनियमित थी और ऐसा निर्णय राज्य सरकार को उम्मीद विषय में, समिधान के अनुच्छेद 310 और 311 के प्रावधानों के अनुकरण में दूसरी जाच प्रारम्भ करने से नहीं रोक सकता। इसलिए, जब किसी सार्वजनिक कर्मचारी पर किसी जाच में शास्ति लागू करने का आदेश दीवानी अदालत द्वारा खारिज कर देने के पश्चात्, उसने बिम्बु आगे कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यद्यपि, उस कार्यवाही में जिसमें जाच का आदेश निरस्त किया गया था, सम्बन्धित सार्वजनिक कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के गुण-अवगुणों की छान बीन अभी नहीं हुई थी। यदि राज्य सरकार नई जाच के आदेश देने में सक्षम थी, तो कोई कारण नहीं है कि वह जाच के दौरान अपीलकर्ता को निलम्बन करने के लिए अक्षम रहे।³ परन्तु ऐसे मामले में निलम्बन का ताजा आदेश जारी करना चाहिए।

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1965 का नियम 12, राजस्थान (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों के नियम 13 के समान है। तब चर्चा वि. भारतीय सच⁴ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि “केन्द्रीय नियमों के नियम 12 (1) के अर्धीन वर्गीकरण के मूल आदेश की निषिद्धि से, राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया समझा जाएगा। परन्तु यह प्रावधान इस स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता कि पहले का आदेश प्रभावहीन था और अपीलकर्ता 25 मई, 1953 को सेवा का सदस्य था जब कि अपीलकर्ता ने पहला दावा दायर किया। निलम्बन का आदेश सरकारी कर्मचारी की सेवा का अंग नहीं करता। निलम्बन आदेश के बावजूद वह राज्य सेवा का सदस्य बना रहता है। जब 17 दिसम्बर, 1951 को वर्गीकरण का आदेश हुआ तो अपीलकर्ता की सेवा समाप्त हो गई। बाद में जब वर्गीकरण का आदेश विरुद्धित कर दिया गया तो अपीलकर्ता की सेवा पुनः जीवित हो गई और जब तक अपीलकर्ता को वर्गीकृत करने का अंश आदेश नहीं होता या अपीलकर्ता कि सेवा किसी अन्य तरीके में समाप्त नहीं की जाती तब तक अपीलकर्ता सेवा का सदस्य बना रहता और निलम्बन का आदेश उनकी स्थिति को किसी भी प्रकार में प्रभावित नहीं कर सकता। निलम्बन के आदेश का वास्तविक प्रभाव यह है कि यद्यपि वह सेवा का सदस्य बना रहा, तथापि उस काम करने की इजाजत नहीं थी और आगे यह भी कि, निलम्बन काल में उसे वेतन कुछ भत्ता मिला जिसे धामरौर से ‘निर्वाह भत्ता’ कहते हैं जो सामान्यतः वेतन में कम होता है वरन् उस वेतन और भत्तों के जिसे, यदि वह निलम्बित नहीं किया जाता तो पान का हृद्दार होता।”

1 1963 RLW 374

2 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1334 (1336)

3 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 687.

इसी फँसने में सर्वोत्तम न्यायालय ने तय किया कि जहाँ तक नियम 12 (4) (अर्थात् राजस्थान का नियम 13 (4) सविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) के अधीन प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, तथा तक वह आम जनता के हितों में एक उचित प्रतिबंध है। अतः यह नियम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता।

सर्वोत्तम न्यायालय के उपर्युक्त फैसले के बाद केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1965 में संशोधन किया जिसमें 'निलम्बन' से सम्बंधित नियम 10 के शब्दों में परिवर्तन किया परन्तु सिद्धान्त वही रहा। संशोधित नियम 10 सर्वोत्तम न्यायालय के सम्मुख एक ऐसा सवाल वि. भारत सरकार¹ में प्रस्तुत हुआ। इसमें निम्नलिखित है कि —

- (i) धू कि अधीनस्थता के विरुद्ध दिया गया निम्बन का पूरागामी आदेश उसको बर्खास्त करने समय समाप्त हो गया इसलिये उसका प्रभाव जारी नहीं रह सकता था। अतः बर्खास्तगी के बाद निलम्बन जारी रहना अवैध था।
- (ii) नियम 10 का उप नियम (4) (राजस्थान का नियम 13 (4)) किसी न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी विखण्डित करने तथा उसी आरोपों पर नई जांच बिठाने से निम्बित करने के नियम प्रावधान करता है। इस नियम के अन्तर्गत जबकि नई जांच के आरोप मूल जांच के आरोपों से भिन्न हों तो निम्बन नहीं किया जा सकता।
- (iii) बर्खास्तगी के आदेश से मानिक और नौकर का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इसलिए जब यह सम्बन्ध बर्खास्तगी द्वारा समाप्त हो जाता है तो निम्बन का पूरागामी आदेश न चल रहा जारी नहीं रहेगा।
- (iv) जब कोई प्राधिकारी अपनी शक्तियों के अधीन रहते कोई आदेश पारित करता है तो उक्त आदेश कब इस कारण में विफल नहीं हो सकता कि वह कानून के किसी अन्तर् प्रावधान के अधीन दिया हुआ था, यदि वह किसी अन्य कानून के प्रावधान के अन्तर्गत उसकी शक्तियों के भीतर था।

परन्तु यदि पुनः स्थापन या कोई आदेश विखण्डित किया जाता है तो सम्बन्धित दोषी सरकारी कर्मचारी निम्बन की अपनी पिछली स्थिति में लौट जाएगा।²

निलम्बन काल की अत्यधिक लम्बा करना सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है — ऐसे अन्यायों में हुए हैं जिनमें निम्बन काल अत्यधिक लम्बा हुआ जो मुक्त भोगी शोषी कर्मचारियों की बारम्बार शिकायतों का कारण बना। राजस्थान सरकार ने भी ऐसे मामलों में गंभीर मत धारण किया है जो नियुक्ति विभाग (A III) द्वारा जारी आदेश से F (61) (A) 62 दिनांक 19.12.1967 से स्पष्ट है। इस निर्देश को पूर्णतः ऊपर उद्यत किया जा चुका है। इस निर्देश के अनुसार मध्य प्राधिकारी को 2 वर्ष की निलम्बन अवधि समाप्त होने पर मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये।

अब राजस्थान सरकार न एक वर्ष से अधिक चल रहे निम्बन के मामलों का पुनरावलोकन

1 1974 SCC (L & S) 351

2 1976 SCC (L & S) 571 — बलदेव राज गुजराती वि. पञ्जाब व हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा राज्य वि. बलदेव राज गुजराती AIR 1976 SC 490

करने के लिये एक पुनर्वाचन समिति भी नियुक्त की है और विभागीय जाचो को जल्दी से निपटाने के लिए समय-समय पर पुनर्वाचन करने के निर्देश जारी किये हैं, देखिये—स F 9 (30) कार्मिक (A-III) 77 दिनांक 26 अगस्त, 1977 तथा स F 9 (30) कार्मिक (A-III) 77 दिनांक 29 अक्टूबर, 1977, और आदेश III F 9 (2) कार्मिक (A 3) 76 दिनांक 4 मई, 1977। तदनुसार, छ मास से अधिक समय से चल रहे निलम्बन के मामलों में, हर छ महीने पश्चात् उच्चतर प्राधिकारी ने अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।*

प्रत्येक जाच या मुकद्दमे की अवस्था (stage) और निपटारे के कारण दर्शति हुए वार्षिक विवरण पत्र भी प्रेषित करने पड़ते हैं। यदि यह पाया जावे कि किसी अनुशासन प्राधिकारी ने जानबूझ कर या लापरवाही से निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना की, जिसके कारण अदालती फैसले के फल स्वरूप या अन्यथा, निलंबित कर्मचारी का सेवा में पुन स्थापन हुआ, तो अनुशासन प्राधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। पुन स्थापन उस तारीख से प्रभावशील होगा जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए अपने स्थान पर अपने पद का भार ग्रहण करता है।**

निलम्बन आदेश निरस्त करना—नियम 13 का अनुच्छेद (5) निलम्बन आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को या उस अधिकारी को जिसकी प्राधिकृति के अधीन उक्त आदेश जारी किया जाना सम्भवा गया है, कथित निलम्बन आदेश निरस्त करने (revoke) की शक्ति प्रदान करता है। कार्यवाहियों की किसी भी अवस्था (stage) पर वह ऐसा कर सकता है अर्थात् जब भी वह आदेश निरस्त करना न्यायिक या उचित समझे। ऐसा वरिष्ठ अधिकारी भी जिसका निलम्बन प्राधिकारी मान्यता है, उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी किया गया निलम्बन आदेश निरस्त कर सकता है।

राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग के दिनांक 31 अक्टूबर, 1977 के आदेश द्वारा स्पष्ट किया है कि राज्य सेवाओं (State Services) के सदस्यों के लिए निलम्बन प्राधिकारी राज्य सरकार है। ऐसे मामले में निलम्बन का प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग के शासन सचिव द्वारा आदेश और अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव एवं मुख्य मंत्री को विशेष सचिव (DOP) के माध्यम से भेजा जाना चाहिये।

अनिश्चित निलम्बन आदेशः—निम्नलिखित कतिपय उदाहरण हैं, जिनमें निलम्बन आदेश अवैध ठहराए गए।

निलम्बन जिसका प्रभाव किसी निश्चयी तिथि से हो वह अवैध होगा।¹ निलम्बन या तो उस तारीख से प्रभावित होता है जिस दिन आदेश, सम्बन्धित कर्मचारी को पहुँचे,² या उस तारीख से जिस दिन वह अपने पद का प्रभार सुपुं करे।³ जब आदेश हस्ताक्षरित न हो अथवा जब उस पर ऐसे प्राधिकारी के हस्ताक्षर हो जिसको निलम्बन करने का प्राधिकार ही प्राप्त नहीं था तो ऐसा आदेश प्रभाव-

* 'लेखाविज्ञ' 1977 पृष्ठ 310

** 'लेखाविज्ञ' 1977 पृष्ठ 310

+ स एफ II (51) कार्मिक (AIII) दिनांक 31-10-1977

1 1963 RLW 374, 1973 SLJ 366

2 1964 SCR 733, ILR (1962) 15 (2) पत्राव 642, AIR 1970 S. C 214

3 1960 RLW 386 श्री प्रसाद वि राजस्थान राज्य

हीन हो जाएगा।¹ जब किसी राज्य कर्मचारी को ऐसी जाच के दौरान निलम्बित किया गया था जिसमें चार आरोप लगाये गये थे, जिनमें वह आरोप भी सम्मिलित था जिसमें वह दोषमुक्त किया जा चुका था, तो न्यायालय ने निलम्बन का आदेश अनियमित होना घोषित किया।² जब नैतिक पतन का कोई प्रश्न नहीं था तो निलम्बन करना अनावश्यक समझा गया। जब कर्मचारी को सेवा में कार्यरत रखने में कोई प्रशासनिक कठिनाई सम्भावित न हो तो उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, और निलम्बित करने की आवश्यकता नहीं रहती। किसी तकनीकी अनियमितता के कारण जाच के दौरान निलम्बित करना उचित नहीं है।³

निलम्बन के अन्तरिम आदेश के औचित्य का प्रश्न किसी न्यायिक अदालत में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि वह आदेश शास्ति के रूप में नहीं होता। वह सबिधान के अनुच्छेद 311 (2) के अन्तर्गत नहीं आता। निलम्बन करने का अधिकार और निलम्बन का औचित्य दो अलग-अलग मामले हैं। यह स्वीकारोक्ति कि सरकार प्रार्थी का निलम्बित करने के लिए सक्षम है यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि निलम्बन उचित था।⁴

बदनीयता से निलम्बन.—बदनीयता से निलम्बन करने की प्रवृत्ति की सदैव भर्त्सना की गई है। अर्शाद अहमद वि जम्मू-काश्मीर सरकार⁵ में न्यायालय नेपाया कि निलम्बन अनिश्चित लम्बे काल के लिए जारी रहा, उसे अवैध और नैतिकता की दृष्टि से अपमानजनक करार दिया गया। उसको बदनीयता से प्रेरित तथा कष्टदायक भी कहा जा सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीड़ित राज्य कर्मचारी को मुआवजा दिवाने के लिए चढे हुए वेतन पर 6% की दर से व्याज दिलवाया। उन्होंने अपना निर्णय AIR 1958 इलाहाबाद 246 और 1972 SLR 711 (जम्मू-काश्मीर) पर आधारित किया। इसके अनतिरिक्त, निलम्बन आदेश जारी करते हुए प्राधिकारी को ऐसा करने के कारण भी अभिलिखित करना चाहिये। आदेश न्यायिक तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त होने चाहिये। राजनैतिक दबाव के अधीन दिया गया निलम्बन का आदेश खारिज किया गया।⁶

निलम्बन के दौरान सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करना —यदि जाच चलू हो और दोषी राज्य कर्मचारी निलम्बन में हो और वह सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर ले तो वह स्वतः सेवा निवृत्त नहीं होगा। पहले, राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56 (ख) कर्मचारी का उन⁷ मामले में अन्तिम निर्णय नहीं होने तक रिटायर होने की अनुमति नहीं देना था। वित्त विभाग के मीमो सं F 7 क (22) F D—A/Rules/59 दिनांक 3-10-1960 के अनुसार अनुशासन कार्यवाही खतम होने से पहले कर्मचारी को रिटायर होने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी। परन्तु अब राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56 दिनांक 6-8-1963 में निरस्त कर दिया गया है। अन्तः नियम 210 (ग) लागू होता है जिसके अधीन मध्यम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, किसी कर्मचारी को सेवा से रिटायर होने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

1. AIR 1958 कलकत्ता 239

2. AIR 1961 मैसूर 37

3. 1967 SLR 636, 1969 Lab I C 1171

4. 1975 Lab I C 1190.

5. 1970 SLR 520.

निर्वाह भत्ता —

निलम्बन के अधीन राज्य कर्मचारी निर्वाह भत्ता तथा समय समय पर स्वीकृत कोई अन्य मुआवजा भत्ता भी पाने का हकदार है। राजस्थान सेवा नियमा का नियम 53 उस पर लागू होगा। यह नियम पाठक की सुविधा हेतु नीचे दिया जा रहा है:—

नियम 53 (1) — निलम्बित राज्य कर्मचारी निम्नांकित मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होगा:—

(क) निर्वाह भत्ते के रूप में अवकाश राशि के बराबर राशि जिसे वह कर्मचारी अर्द्ध-वेतन अवकाश पर रहने की स्थिति में प्राप्त करता, और उसके अतिरिक्त उक्त अवकाश वेतन पर आधारित महगाई भत्ता,

परन्तु शर्त यह है कि जब निलम्बन काल 6 मास* से अधिक हो गया हो, वह अधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया था या जो आदेश देन वाला समझा गया, 6 मास के पश्चात् निर्वाह भत्ते की राशि में निम्न प्रकार से परिवर्तन कर सकेगा

(i) निर्वाह-भत्ते की राशि उचित सीमा तक बढ़ाई जा सकेगी, जो प्रथम 6 मास की अवधि के लिए स्वीकृत निर्वाह-भत्ते से 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी, यदि कवित प्राधिकारी की राय में, निलम्बन की अवधि ऐसे कारणों से बढ़ गई हो जा प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी की वजह से नहीं हो, उसके कारण अभिलिखित किये जाएंगे,

(ii) निर्वाह-भत्ते की राशि उचित सीमा तक घटाई जा सकेगी, जो प्रथम 6 महिना* की अवधि के दौरान स्वीकृत निर्वाह भत्ते से 50% से अधिक नहीं घटाई जा सकेगी, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी की वजह से प्रत्यक्षतः बढ़ी, उसके कारण अभिलिखित किये जाएंगे,

(iii) महगाई भत्ते की दरें उपरोक्त उप-खण्ड (1) तथा (2) के अन्तर्गत देय निर्वाह भत्ते की बढ़ी हुई या घटी हुई राशि पर, यथास्थिति आधारित होगी।

(ख) कोई अन्य अतिपूरक भत्ता जो निलम्बन की तिथि की राज्य कर्मचारी को समय समय पर उसके वेतन पर देय था, यदि उक्त भत्ते उठाने के लिए निर्धारित शर्तों का पालन हुआ हो।

() जब तक राज्य कर्मचारी ऐसा प्रमाण-पत्र पेश नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, आधार, व्यवसाय या धन्ये में लगा हुआ नहीं है तब तक उसे उपनियम (1) के अधीन कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा,

परन्तु शर्त यह है कि राज्य कर्मचारी को वर्गान्तरी सेवा से हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति की दशा में, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 13 के उप नियम (3) या (4) के अनुसार ऐसी वर्गान्तरी या निष्कासन या अनिवार्य-सेवा-निवृत्ति की तारीख से जो निलम्बित किया गया अवधि निलम्बित बालू रहना दिया गया माना गया है और जो ऐसी अवधि के अवधि में उक्त प्रकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर, तो वह उतनी राशि

* शब्दावली "12 महीने के स्थान पर प्रतिस्थापन की गई, जो 9-6 1971"

तब निर्वाह-भत्ते एवं अन्य देय भत्ते प्राप्त करेगा, जो उसकी उस अवधि की अर्जित आय तथा निर्वाह भत्ते की राशि से कम पड़े जिसे वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त करता। जब कि देय निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्ते निरन्तर कर्मचारी द्वारा अर्जित अन्य आय के बराबर या उससे कम हों तो इस नियम का कोई प्रावधान उम्र पर लागू नहीं होगा, अर्थात् ऐसी दशा में उसे कोई निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि नहीं दिये जाएंगे।

स्पष्टीकरण

(1) 6 माह की अवधि उस दिन से गिनी जाएगी जिस तिथि को राज्य कर्मचारी निलम्बित किया गया।*

(2) निलम्बन प्राधिकारी को निर्वाह-भत्ते के भुगतान को रोकने का कोई स्व-विवेकाधिकार नहीं है। निलम्बित कर्मचारी को निरन्तर की अवधि में निर्वाह भत्ता देना ही होगा। किन्तु सक्षम प्राधिकारी, सवधित निलम्बित कर्मचारी के विरुद्ध, राजस्थान सिविल सेवा (CCA) नियम के अधीन, सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के मुख्यावास छोड़ने पर दूसरी जाच प्रारम्भ कर सकेगा।**

निर्वाह भत्ता रोकना:—निलम्बित दोषी राज्य कर्मचारी को देय निर्वाह भत्ता रोकना समुचित अवसर नहीं देना माना गया है।¹ निर्वाह भत्ता नहीं मिलने के कारण जब कोई राज्य कर्मचारी धनाभाव में जाच के लिए निश्चित तारीख पर अनुपस्थित रहा फिर भी जब जाच जारी रही तो वह जाच तथा उमम दिया गया निर्णय अवधि करार दिया गया।² इन निर्वाह भत्ता रोकने का निलम्बन प्राधिकारी को कोई अधिकार नहीं है (देखिये-उपरोक्त भीमो दिनांक 4 6 1970)।

निलम्बित कर्मचारी को अन्य सुविधाएँ:—निलम्बित राज्य कर्मचारी को विभागीय जाच में सवधित अवकाश सरकारी कामों की दशा में गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित होने हेतु तथा अन्य इसी प्रकार के अवसरों पर यात्रा करने पर पूरा यात्रा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा, (देखिए-राज यात्रा भत्ता नियम, 1971 का नियम 27)। वह चिकित्सक के अथवा चिकित्सा के नकद पत्रों की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में पाने का भी हकदार होगा। वह मकान किराया भत्ता उठाने का भी हकदार रहेगा तथा निलम्बन अवधि में सरकारी रिहायशी मकान खाली करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। उचित आयेदन के आधार पर उसे अपना मुख्यावास बदलने की भी अनुमति दी जा सकती और इसी प्रकार उचित अवधियों में विशेष परिस्थितियों में उसे मुख्यावास छोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जा सकती।³

प्रतिबन्ध.—राजस्थान सेवा नियमों के नियम 55 के अधीन निलम्बन काल में अवकाश की मांग अस्वीकार की जा सकेगी। बिना उचित अनुमति के वह मुख्यावास नहीं छोड़ सकता। उससे यह भी अपेक्षा की जा सकती कि वह प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी हाजरी अर्जित करवाए।

* F D मेमो स F 1 (44) F D (Ex Rules) 63 दिनांक 22-6-1964 द्वारा जोड़ा गया।

** F O मेमो स F 1 (32) F D (रूल्स) 70 दिनांक 6 4-1970 द्वारा जोड़ा गया।

1 1973 WLN (U C) 83 एम एन तीवाड़ी वि पचायत समिति आदरा।

2 AIR 1973 S C 1183 घनश्यामदास श्रीवास्तव वि मध्यप्रदेश सरकार।

3 राज सेवा नियमों के नियम 55 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार।

परन्तु समस्त दिन ठहर कर दफ्तर का कार्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता। सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में नियमित हजरती देने से मुक्ति भी प्रदान कर सकेगा।

यदि राज्य कर्मचारी पर कोई शास्ति लागू करना प्रस्तावित हो, तो ऐसे आदेश जारी करने से पहले कारण बताआ नोटिस देना आवश्यक है अथवा प्रावृत्तिक नियमों के विद्वानों के उल्लंघन के आधार पर आदेश अर्थ करार दिया जाकर विखण्डित किया जा सकता है।¹ यदि प्रस्तावित शास्ति का आदेश दोषी कर्मचारी को वित्तीय रूप में प्रभावित करता हो तो संबंधित व्यक्ति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उस पर भली भाँति विचार करने के बाद जारी करना चाहिए।²

निलम्बन काल का पूरा वेतन—निम्नांकित परिस्थितियों में, सरकारी कर्मचारी, निलम्बन काल के लिए पूरा वेतन प्राप्त करने का अधिकारी होगा—

- (1) जब वह, विभागीय जाच में उसके विरुद्ध लगाये गए आरोपों से दोष मुक्त किया जाकर सेवा में पुनःस्थापित किया गया हो।³
- (2) जबकि सरकारी कर्मचारी कानूनी अदालत द्वारा उस फौजदारी अपराध से डिस्चार्ज या बरी कर दिया गया हो जिसके विषय में उस पर मुकदमा चलाया गया था और जिसके कारण वह निलम्बित किया गया था। परन्तु सक्षम प्राधिकारी का विचार हो कि वह पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हुआ था या 'बाइज्जत बरी' नहीं किया गया था, तो वह उसके विरुद्ध विभागीय जाच प्रारम्भ करा सकेगा। यदि वह ऐसा करने में विफल हो तो संबंधित कर्मचारी निलम्बन की अवधि में पूरा वेतन पाने का हकदार होगा।⁴
- (3) जबकि राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए अपराध से बरी किया गया हो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा—आया वह साक्ष्य के अभाव में या मुकदमे की किसी प्रक्रिया के दृष्टिपूर्ण होने के कारण या उसे शक का फायदा दिया गया था या मामले के गुण-अवगुणों के आधार पर बरी किया गया। प्रत्येक दफ्ता में वह पूरे देय वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा। यह गुण अवगुणों पर या वा इन्जन बरी होने से प्रतिबन्धित नहीं है।⁵
- (4) जबकि कठोर शास्ति आरोपित करने का आदेश किसी कानूनी अदालत द्वारा या उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो।
- (5) जबकि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाच या फौजदारी मुकदमा वापिस ले लिया गया हो।⁶

1 AIR 1968 S C 240—गोपालकृष्ण नायडू वि. मध्यप्रदेश सरकार।

2 1971 RLW S C 546—बन्ध्यानाथ वि. भारतीय सच।

3 1978 RLT IV 29—मदननाथ कल्ला वि. राजस्थान सरकार।

4 1971 Lab I C 923 (गुजरात)—सर्पमिहजी, बीराजी राठी वि. गुजरात सरकार। AIR 1960 मद्रास 325, AIR 1966 बम्बई-नाशमि 278 तथा AIR 1963 उड़ीसा 73 भी देखिए।

5 1975 Lab I C 139 (कर्नाटक)।

6 AIR 1965 बनारस 281—ध्यामनाथ वि. भारतीय सच।

यदि पुनः स्थापित होने पर, प्राधिकारीगण राज्य कर्मचारी को निलम्बन की अवधि का चढ़ा हुआ वेतन भुगतान नहीं करें, तो वह देय राशि के निये सरकार के विरुद्ध दावा प्रस्तुत कर सकता है। विययदावा निलम्बन आदेश खारिज होने की तिथि को उत्पन्न होगा और उसी तारीख से उसके विरुद्ध म्याद (limitation) प्रारम्भ होगी।¹

उपयुक्त मामलों में निलम्बन अवधि में देय वेतन पर न्यायालय व्याज दिलाने का आदेश भी दे सकता है, यद्यपि ऐसे उपचार के लिए इस्तदुआ नहीं की गई हो।²

जब कि उस परीक्षारी मुद्दमे में, जिसके कारण राज्य कर्मचारी को निलम्बित किया गया था, वह दोषमुक्त (बरी) कर दिया गया, फिर भी निलम्बन स्वतः समाप्त नहीं होगा। उसे पुनः स्थापन करने का आदेश निलम्बन करने हेतु सशम प्राधिकारी को जारी करना होगा।³

भाग-5 : अनुशासन

14. शास्तियों के प्रकार—निम्नांकित शास्तियां ममुचित और पर्याप्त कारणों से, जिनको अभिलिखित किया जाएगा और जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित है, किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाई जा सकेगी, अर्थात्—

- [1] परिनिन्दा,
- [2] वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना,
- [3] लापरवाही से या किसी विधि, नियम या आदेश को भंग करने से सरकार को हुई प्राधिक हानि की उसके वेतन में से सम्पूर्ण या आंशिक रूप से बसूली,
- [4] निम्नतर सेवा, थ्रेड या पद पर अथवा निम्नतर काल वेतनमान में अथवा काल वेतनमान में नीचे के प्रक्रम पर अवतर कर देना, या पेंशन की दशा में नियमानुसार देय राशि में कमी कर देना,
- [5] अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,
- [6] सेवा से हटाया जाना जो कि आगे नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी।
- [7] सेवा से पदभ्यूति जो सामान्यतः भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी।

स्पष्टीकरण—(1) इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित शास्ति की कोटि में नहीं होगे:—

- [1] सेवा या पद या नियुक्ति के निवयनों से सम्बन्धित नियमों या आदेशों के अनुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में अग्रफल रहने पर सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोक देना,
- [2] किसी सरकारी कर्मचारी के दक्षता अवरोध पार करने में अयोग्य होने के कारण, उसे काल वेतनमान में दक्षता अवरोध पर रोकना,

1 AIR 1970 दिल्ली 185—भारतीय सघ। वि. जानसिंह, 1977 S.c (L & S) 232.

2 AIR 1964 आन्ध्र प्रदेश 491—आन्ध्रप्रदेश सरकार वि. मोहम्मद नुतबुद्दीन खां।

3 AIR 1957 इलाहाबाद 437—जगदीश चन्द्र वि. यू. पी. सरकार।

- [3] किसी सरकारी कर्मचारी को, उसके मामले पर विचार करने के बाद, ऐसी सेवा, ग्रेड या पद पर जिस पर पदोन्नति के लिए वह पात्र है, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैमियत से पदोन्नत न करना,
- [4] किसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी का निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर इस आधार पर कि उसे अवसर दिए जाने पर वह ऐसी उच्चतर सेवा, ग्रेड या पद के लिए अनुपयुक्त समझा गया है अथवा किसी प्रशासनिक आधार पर जो उसके आचरण से सम्बंधित नहीं है, प्रतिवर्तन कर देना,
- [5] किसी सरकारी कर्मचारी का जो परिवीक्षा पर किसी दूसरी सेवा, ग्रेड या पद पर नियुक्त किया गया हो, परिवीक्षाकाल में या उसकी समाप्ति पर नियुक्ति के निबन्धों या परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसरण में अपनी स्थायी सेवा, ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तन कर देना,
- [6] किसी सरकारी कर्मचारी को, उसकी अभिवृत्ति या सेवा निवृत्ति संबंधी उपबन्धों के अनुसार भविष्य सेवा निवृत्ति,
- [7] सेवा समाप्ति:—

- (क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी को, परिवीक्षाकाल में या उसकी समाप्ति पर उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या परिवीक्षा संबंधी नियमों या आदेशों के अनुसार,
- (ख) सविदा से अन्यथा किसी अन्य रूप में नियुक्त किसी अस्थायी सरकारी कर्मचारी की, नियुक्ति काल समाप्त होने पर,
- (ग) किसी करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी कर्मचारी की, उक्त करार के निबन्धनों के अनुसार,
- (घ) राजस्थान की एकीकृत इकाइयों में से किसी की भी सेवाओं के ऐसे सरकारी कर्मचारी की, एकीकरण नियमों के अनुसार राजस्थान राज्य की एकीकृत सेवाओं में से किसी में भी नियुक्ति के लिए चयन न होने पर या उनमें शामिल न किये जाने पर ।

स्पष्टीकरण—(2) किसी व्यक्ति की, जो राजस्थान की एकीकृत सेवाओं में किसी भी पद पर तदर्थ या अन्तिम आधार पर नियुक्त हो एकीकृत नियमों के अनुसार ऐसी किसी सेवाओं या पदों पर चयन नहीं किये जाने या उनमें शामिल नहीं किये जाने से अन्यथा किसी कारण से की गयी सेवान्युक्ति की, सेवा से हटाया जाना या पदच्युति यथा स्थिति, समझा जाएगा ।

टिप्पण—नियम 14 [7] के अधीन पदच्युति के कारण भावी नियोजन के लिए निरहंता केवल सरकार द्वारा ही अधित्यजित की जा सकती है यदि किसी मामले के गुण दोषों से ऐसा करना न्यायोचित हो ।

राजस्थान सरकार के निर्देश (1)

दण्ड—जो शास्तिया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियमन और अपील) नियम, 1958 के अधीन आरोपित की जा सकती है व नियम 14 में निर्दिष्ट हैं और वे किसी भी सही या पर्याप्त कारण से लागू की जा सकती हैं। शास्तियो की यह सूची पूर्ण है, और किसी अन्य स्वरूप या तरीके से शास्ति लगाना गलत होगा, उदाहरणतः वेतन रोकना, बिना वेतन के अवकाश स्वीकार करना जबकि दूसरे किस्म के अवकाश देय हैं, जुर्माना करना, आदि।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका—(राजस्थान सरकार) अनु० 17 (i)]

राजस्थान सरकार का निर्देश (2)

दण्ड का स्वरूप और उसकी मात्रा किसी विशेष मामले में कितनी होनी चाहिये वह उपलब्ध पूर्व निर्णयों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं अनुशासन प्राधिकारी द्वारा तय किये जाने चाहिये। मोटेतौर से, शास्ति इतनी उदार नहीं होनी चाहिये जिससे कि कार्य कुशलता और अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिले और इतनी कुर भी नहीं होनी चाहिये जिससे कि राज्य कर्मचारी को, यदि उसे सेवा में रखा जावे, तो उसकी नैतिकता तथा कार्यकुशलता में गिरावट आ जावे।

दोषों के कतिपय विनिष्टि मामलों में जैसे कि अप्राधिकृत तथा फर्जी यात्रा भत्ता बिन उठाना, सरकार ने 11/8-1960 को यह तय किया है कि बदनियती से यात्रा भत्ते की अधिक उठायी गयी राशियों के विचाराधीन मामलों में तीन ग्रेड क्षति वृद्धियाँ सचय प्रभाव से रोक दिये जाने का दण्ड दिया जाना चाहिये। भविष्य में यदि बदनियती से अधिक यात्रा भत्ता उठाने का प्रयास हो, तो सेवा से हटाये जाने या वर्तमानगी का दण्ड दिया जाना चाहिये। यात्रा भत्ता उठाने में किसी तकनीकी त्रुटि का मामला उसके गुण-अवगुण पर तय करना चाहिये।¹

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राजस्थान सरकार) 1963 संस्करण अनु० 17 (ii)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (3)

वेतन वृद्धियाँ रोकने के आदेश में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिये कि आया रुकावट सचयी प्रभावी है या नहीं।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका—राज० सरकार 1963 अनु० 17 (vii)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (4)

पदोन्नति रोकने के आदेश में कार्यकाल का उल्लेख स्पष्ट करना चाहिये अर्थात् आया वह स्थान रूप से है या अस्थायी रूप से किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये है।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राज० सरकार) 1963 अनु० 17 (viii)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (5)

सरकार को पहचानी गई ग्राथिक हानि के लिये दोषी कर्मचारी के वेतन से वसूली के आदेश के मामले में, दोषी कर्मचारी की स्थिति के अनुकूल सुविधाजनक विस्तार में वसूली की जानी चाहिये।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राज० सरकार) 1963 अनु० 17 (ix)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (6)

जब किसी राज्य कर्मचारी को निम्नतर सेवा, पद या निम्नतर समयमान (Time Scale) में पदावत किया जावे तो पदावतति का आदेश देन वाला प्राधिकारी यह अवधि निर्दिष्ट करे या नहीं भी करे जिस समय तक के लिए पदावतति प्रभावशील रहूगी। जब यह अवधि निर्दिष्ट हो, तो उक्त प्राधिकारी को यह भी उल्लेख करना चाहिये कि आया पूर्वावस्था की प्राप्ति पर पदावतति की अवधि भविष्य की बेतन वृद्धियों को स्थगित करने वाली होगी और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक। स्थाई स्वरूप का दण्ड उदाहरणतः निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद में स्थायी अवतति करना, साधारणतः टाल देना चाहिये, क्योंकि उनसे सम्बन्धित अधिकारी की अच्छा कार्य करने की प्रवृत्ति नष्ट होती है और नैतिकता का पतन होता है। अतः ऐसी पदावतति की अवधि निर्दिष्ट की जानी चाहिये।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका (राज० सरकार) अनु० 17 (iv)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (7)

अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड जो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 उपखण्ड (v) में उल्लेखित है, इसलिये बनाया गया है जिससे ऐसे मामलों के लिए प्रावधान हो सके जिनमें राज्य कर्मचारी को सेवा में जारी रखना अव्यक्ति सम्भवा गया हो परन्तु सेवा से हटाये जाने या वर्तमान की कठोरतम शास्ति लागू करना जिसके परिणाम स्वरूप पेंशन की हानि हो अधिक कठोर प्रतीत हो, सिवाय उन मामलों के जिनमें दोष वास्तव में बहुत गंभीर हो, उदाहरणतः सरकारी रकम का गबन नैतिक पतन वाले अपराध। जो प्राधिकारी-गण सेवा से हटाने या वर्तमान की शास्ति आरोपित करने के लिये सक्षम है वे अनिवार्य सेवा नियम की शास्ति लागू करने के लिये सक्षम हैं। जिन अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति किया जावे उन्हें ऐसी दर से पेंशन प्रदान की जा सकेगी जो उनकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि की स्वीकार योग्य पेंशन से दो तिहाई से कम नहीं हो तथा पूर्ण रोगातुर पेंशन (invalid pension) से अधिक नहीं हो। शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवा निवृत्ति राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने से भिन्न है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति मविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का आकर्षित नहीं करती, और इस कारण से राजस्थान सेवा नियम (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 में निर्धारित शास्ति आरोपित करने की प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होती, जब कि शास्ति के रूप में की गई अनिवार्य सेवा निवृत्ति मविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का आकर्षित करेगी और कठोर शास्तियों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 में प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, राजस्थान सरकार, 1963 अनुच्छेद 17 (v)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (8)

कानूनी अदानत द्वारा किसी राज्य कर्मचारी को दोषी ठहराए जाने पर वर्तमान का आदेश पारित करते समय, अनुशासन प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उक्त आदेश का प्रभाव आदेश की तिथि से किया जाना चाहिये न कि निलम्बन की तिथि से या दोषी करार दिये जाने (Conviction) की तिथि से। जब कि दोषी करार दिए जाने के फैसले के विरुद्ध अपील दायर

की गई हो, तो अनुशासन प्राधिकारी को वर्तमान की वापस देने से पहले प्रणीत-न्यायालय के निर्णय की भी प्रतीक्षा करनी चाहिये।

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963, राजस्थान सरकार अनुच्छेद 17 (vi)।]

राजस्थान सरकार के निर्देश (9)

सेवा की समाप्ति/अस्थाई/प्रतिस्थापित (officiating) कर्मचारियों का परावर्तन (Reversion):-

- (क) प्रतिस्थापन पर कार्य कर रहे राज्य कर्मचारी को पुनः उसके पढ़ने के पद पर परावर्तन (revert) करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देना कानूनन आवश्यक नहीं है परन्तु जब उसका कारण अमन्तोपजनक कार्य होना बनाना हो तो यह आवश्यक तथा वांछित होगा कि उसे कारण बताने का अवसर प्रदान किया जावे।
- (ख) यदि अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा दुराचरण या अनुकूलता के आधार पर समाप्त की जाती है तो सविधान का अनुच्छेद 311 (2) अल्पित होगा। किन्तु साधारण अनुशासन कार्यवाही के जरिये अस्थाई कर्मचारी की सेवा समाप्त करना जरूरी नहीं है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 (क) के अनुसार अस्थाई राज्य कर्मचारों की सेवा एक माह का नोटिस देकर अभी भी समाप्त की जा सकती है। इसलिए ऐसी समाप्ति के लिए कारण उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। चूंकि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23 (क) के अधीन अस्थाई राज्य कर्मचारियों की सेवा बिना कारण बताए और दुराचरण या अनुकूलता का उल्लेख किये बिना समाप्त की जा सकती है, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसने विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करे और सेवा समाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस तामील करवाएँ।
- (ग) यदि कोई नियुक्ति परीक्षण पर की गई हो तो परीक्षण काल में अमन्तोपजनक प्रगति के कारण सेवा समाप्त की जा सकती है और कारण बताने के नोटिस की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में, स्थाई नहीं करने के कारण बनाने की भी आवश्यकता नहीं है।

[राज सरकार की अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963, अनुच्छेद 17 (xi)]

टिप्पणी

जिस प्रकार ताजीरात हिन्द में विभिन्न प्रकार के दण्ड प्रावधानित हैं उसी प्रकार राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और प्रपील) नियम, 1958 में राज्य कर्मचारियों के लिये कतिपय शास्त्रिया निधारित की गई है। पुलिस कर्मचारी केवल इन नियमों से ही नहीं, वरन् पुलिस अधिनियम से भी शासित होते हैं, जिससे ऐसे दण्ड जो पुलिस अधिनियम से असंगत न हो, पुलिस के अधीनस्थ स्तर के अधिकारियों पर इन नियमों के नियम (I) (च) and पुलिस अधिनियम की धारा 2 के अधीन आरोपित किए जा सकते हैं।

भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 राजस्थान में 19 जुलाई, 1950 से लागू किया गया। पुलिस अधिनियम की धारा 7 जिसमें दण्ड का प्रावधान है, इस प्रकार है —

“सविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम राज्य सरकार बनावे, उनके अधीनस्थ रहते हुए, पुलिस के महा निरीक्षक, उप-महा निरीक्षक, सहायक महा-निरीक्षक एवं जिला अधीक्षक किसी समय भी अधीनस्थ पक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को जिसको

यह कर्तव्य में प्रिथिल, असावधान अथवा अनुपयुक्त समझे उसे सेवा से बर्खास्त, निलम्बित अथवा पदावनत कर सकते हैं अथवा निम्नलिखित शास्त्रियों में से कोई एक या अधिक किसी अधीनस्थ स्तर के पुलिस अधिकारी को जो नौकरी में असावधानी या सेवा में उपेक्षा करता हो अथवा अपने किसी कार्य द्वारा उसने अपने आपकी उक्त बाध के लिए अयोग्य होना प्रकट किया हो उसके विरुद्ध लागू कर सकता है, यथा (क) जुर्माना किसी घनराशि का जो एक महीने के वेतन से अधिक न हो, (ख) क्वार्टरों में नजरबन्दी जो पन्द्रह दिनों से अधिक अवधि की न हो ड्रिल, प्रतिरिक्त पहरा, बकान या अन्य डिउटी के साथ अथवा अलग, (ग) सदाचरण वेतन से बर्जित करना, (घ) किसी विशिष्ट पद अथवा विप्रेष उपलब्धि (रेम्पूनेशन) के पद से हटाना ।”

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और प्रवीण) नियम, पुलिस अधिनियम के पूर्ण हैं।¹ अतः अनुशासन प्राधिकारी इन नियमों के नियम 14 में बताई गई और पुलिस अधिनियम में निर्धारित कोई भी शास्ति लागू कर सकता है। जब कि एक पुलिस कर्मचारी ने स्थानान्तर आदेश का पालन नहीं किया और जब वह अवीक्षण आरक्षी के सम्मुख व्यक्तिगत उपस्थित हुआ, तो उसने वहीं पहनन से इन्कार किया और मुफ्ती में पना हुआ और अधिकारी के साथ हुंम्यहार किया। अतः स्थानान्तर के आदेश की अवज्ञा करने के कारण शास्ति आरोपित करने के प्रतिरिक्त, उसे पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अधीन बर्जित ड्रिल और बकान की डिउटी के साथ 14 दिन की क्वार्टरों में नजरबन्दी (quarter guard) की सजा भी दी गई। इस मामले में निर्णय हुआ कि बाद में उल्लिखित सजा, स्थानान्तर आदेश की अवज्ञा के कारण दी हुई सजा में अलग व स्वतन्त्र सजा थी।²

शास्त्रियों की पूरी सूची — नियम 14 में केवल सात प्रकार की शास्त्रियाँ गिनाई गई हैं जो राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकती हैं। यह सूची सम्पूर्ण है। इसलिये इन सात शास्त्रियों से भिन्न अन्य कोई भी शास्ति किसी भी रूप में नहीं दी जा सकती। वेतन का भुगतान रोकना, बिना वेतन अवकाश स्वीकार करना जबकि अन्य प्रकार का सर्वतनिक अवकाश कर्मचारी को देय है, जुर्माना करना आदि सजाएँ नियम 14 की परिधि से बाहर हैं, अतः आरोपित नहीं की जा सकती।

शास्ति केवल अनुशासन प्राधिकारी आरोपित कर सकता है:—नियम 14 में उल्लेखित कोई शास्ति या उससे पहले कारण बताओ नोटिस केवल अनुशासन प्राधिकारी ही दे सकता है। सविधान द्वारा प्रदत्त यह प्राधिकार समानान्तर रूप से किसी अन्य को संपुर्ण नहीं दिया जा सकता। जब कि राज्यपाल ने एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान न्यायिक सेवा के एक सदस्य के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में निहित अनुशासन प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रशासन न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को सौंप दी, तो कथित अधिसूचना अवैध घोषित की गई।³

सही एवं पर्याप्त कारण — नियम 14 में उल्लिखित कोई भी शास्ति बिना सही और पर्याप्त कारणों के किसी कर्मचारी पर लागू नहीं की जा सकती। यह नियम 14 का मुख्य तथा अनिवार्य भाग है। केवल सही एवं पर्याप्त कारण ही अनुशासन प्राधिकारी को सरकारी कर्मचारी पर

1. AIR 1967 राजस्थान 414—लौकमल वि. अधीक्षण आरक्षी।

2. उपरोक्तानुसार।

3. 1974 WLN 969 —मानन्दीताल वि. राजस्थान सरकार।

शास्ति आरोपित करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह सही तरीके से अभिलिखित तथ्यों पर आधारित है। यदि रेकॉर्ड पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अभियोग साबित नहीं या शह दत्त (माध्य) से निकाला गया निष्कर्ष स्पष्टतः विपरीत है तो शास्ति लागू करने का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर का होगा।¹ शास्ति लागू करने का आदेश बोलता हुआ आदेश होना चाहिये अर्थात् आदेश का पठन करने से की हुई कार्यवाही पूरी न्यायोचित प्रतीत होनी चाहिये¹ (एम शमशुद्दीन वि जम्मू व कश्मीर सरकार)।

अभिव्यक्ति, "सही एवं परित्याप्त कारण" की कोई परिभाषा नहीं है। यह सजा देने वाले प्राधिकारी के स्व विवेक पर छोड़ दिया गया है, जो दुराचरण की प्रकृति और गंभीरता तय करेगा।² उसे उन सही और परित्याप्त कारणों को अभिलिखित करना चाहिये जिनके आधार पर वह राज्य कर्मचारियों को दण्डित करना चाहता है।³ एक पुराने मामले में एक अधिकारी ने, अनुशासनात्मक मामलों को तय करने के लिये छापे हुए रुडिबन्ध प्रपत्र (S ereotyped printed form) प्रपना लिया था। इसमें निर्णय हुआ कि ऐसा करना इस प्रावधान का परित्याप्त अनुपालन नहीं था।⁴ नियम 14 ऐसा कोई पथ प्रदर्शन नहीं करता जिससे किसी कर्मचारी के दुराचरण का स्वरूप और उसके अनुरूप शास्ति निश्चित की जा सके। यह तो सम्बन्धित प्राधिकारी के स्वविवेक में निहित है।⁵ परन्तु यह स्वविवेक पूरी जाच और सार्वधानी के साथ प्रयोग में लाया जाना चाहिये। "अगर कोई गंभीर दुराचरण साबित था या नहीं" एक न्यायिक तनकी है और उस पर दीवानी अदालत खुद का निष्कर्ष निकाल सकती है।⁶

यदि प्रथमावलोकन से "सही एवं परित्याप्त" कारण प्रतीत हों तो उच्च न्यायालय, साधारणतः राज्य कर्मचारी पर कठोर शास्ति आरोपित करने के कारणों की छानबीन नहीं करता। परन्तु यदि किसी मामले में रेकॉर्ड से प्रत्यक्ष दिसता है कि आरोपित शास्ति के लिए न्यायसंगत सही एवं परित्याप्त कारण रेकॉर्ड पर विद्यमान नहीं है, तो उच्च न्यायालय इस आधार पर दखल कर सकता है कि दण्ड इस नियम के अनुरूप नहीं है।⁷

सरकारी निर्देश — चू कि नियम 14 द्वारा प्रदत्त स्वविवेक के अधिकार विस्तृत तथा अस्पष्ट हैं, इसलिये राजस्थान सरकार ने, अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963 के अनुच्छेद 17 (1) में कतिपय निर्देश दिए हैं, जो अपर उद्धृत किए गए हैं। इन निर्देशों⁸ के अनुसार, अनुशासन प्राधिकारी को उपलब्ध पहले के फ़ैमलों के तथ्यों और परस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिये। शास्ति इनकी उदार या दीनी नहीं होनी चाहिये जिससे कर्मचारी की अकुशलता तथा अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिले और इनकी क्रूर भी नहीं होनी चाहिये जिससे यदि कर्मचारी को सेवा में रखा जावे तो

1 1976 Lab IC 979 (जम्मू कश्मीर) (पूर्ण पीठ) एस शमशुद्दीन वि जम्मू कश्मीर सरकार।

2 AIR 1963 मध्य प्रदेश 115—मोविन्द राकर वि मध्य प्रदेश सरकार।

3 1971 WLN 560—रामगोपाल तेंवर वि भारतीय सच।

4 ILR 38 कलकत्ता 789

5 AIR 1958 उड़ीसा 96—धोरेन्द्रनाथ दाग वि उड़ीसा सरकार।

6 1973 SLJ 586—भारतीय मण वि पी एम मिश्रा।

7 1956RLW 531

8 नियुक्ति (A-III) विभाग के आदेश में F 20(32) नियुक्ति (A)60, ग्रुप-III दि 1-8-1960.

उसके मनोवर्षय और कार्य में कुशलता अर्थात् दक्षता की क्षति पहुँचे । उपरोक्त अधिमूचना में कतिपय उदाहरण भी दिए गए हैं ।

अच्छा हो, यदि राज्य विधान मण्डल विभिन्न प्रकार के दुराचरणों के लिए शास्ति का प्रचार और यात्रा निर्धारित करदे, तबकि अनुशासन प्राधिकारीगण अपने व्यक्तिगत मन की लहर तथा स्वच्छानुसार अग्रसर नहीं हो सकें और समान मामलों में सरकारी कर्मचारियों के साथ समान सख्त किया जा सके । ज्यादाती के कतिपय मामले नीचे बताए जा रहे हैं ।

- (क) नामान्तरण के कतिपय मामलों में एक पटवारी की कुछ अनियमितताएँ पाई गईं, परन्तु उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत चार्ज उठाना साबित नहीं था । इसलिए, राजस्व मण्डल ने उसके विरुद्ध पारित कर्मागमों का आदेश रद्द किया और उसे सचित प्रभाव से दो वेतन-वृद्धियाँ रोकने की शास्ति और बीच की अवधि को कार्यरत रहना मानने का आदेश दिया । ¹
- (ख) जबकि क्लेक्टर ने नियम 16 के अनुसार विस्तृत जाच किये बिना, एक बनिष्ठ लिपिका को, तीन माह तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण लघुसप्त वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी में पदावगत कर दिया, तो यह सजा अम्यायपूर्ण मानी गई, अतः कर्मचारी की अपील स्वीकार की गई और मामला वापस कार्यवाही हेतु भेजा गया । ²
- (ग) एक पटवारी को, तामीरान हिन्द की धारा 323 के अधीन साधारण चोट पहुँचाने की रिपोर्ट के कारण निलम्बित किया गया । मामला प्रोपेशन ऑफ़ ऑफ़ेंडर्स एक्ट की धारा 4 व 12 के अधीन कर्मचारी को छोड़ने के साथ समाप्त हुआ । हमपर क्लेक्टर ने निलम्बन अवधि में उसके आधे वेतन को जम कर देने की शास्ति आरोपित, की । क्लेक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व-मण्डल ने निर्णय दिया कि उक्त आरोप में कोई नैतिक-पगन या निष्ठाहीनता नहीं है, और उसके लम्बे काल तक निलम्बित रहने व परेशानी को देखते हुए उसे पूरा वेतन दिसवाया गया और उस पर केवल निन्दा की शास्ति लागू करके मामला समाप्त किया गया । ³
- (घ) जब यह स्थापित हुआ कि एक पटवारी अपने सर्वेस से अनुपस्थित रहा, और सरकारी बमूतियन में तथा पटवारी ने अपेक्षित वस्तुओं में कोई अभिप्राय नहीं ला तो क्लेक्टर ने उसे सेवा में हटाये जाने का कठोर दण्ड दिया यद्यपि आरोप साबित हुए थे, परन्तु वे इतने गम्भीर नहीं माने गये जितने कि इतना कठोर दण्ड दिया जावे । अतएव पटवारी की अपील स्वीकार की गई और शास्ति में संशोधन करके सचित प्रभाव में दो ग्रेड वेतन वृद्धियों को रोकने में परिवर्तित की गई । ⁴
- (ङ) जबकि एक राज्य कर्मचारी न चार्जशीट और कारण धनाने का नोटिस भेजने के पश्चात अपना स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया तो अनुशासन प्राधिकारी ने उसे सेवा में हटाये जान का आदेश पारित किया । उसमें निर्णय दिया गया कि चूँकि दोषी कर्मचारी ने

1. 1976 RRD 138

2. 1974 RRD NUC-102

3. 1976 RRD 452

4. 1974 RRD-NUC-108

उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए नियम 16 के प्रधीन जाच करना वानूनन आवश्यक था। अतः मामला जाच के लिए वापस भेजा गया।¹

(च) इसी प्रकार जबकि बोपाध्यक्ष ने एक लिपिक को उसके प्रतिवेदन पर बिना विस्तृत जाच किए तीन वेतन वृद्धियाँ राकने की शास्तियाँ लागू की तो आरोप साबित होना नहीं माना गया और शास्ति का आदेश निरस्त किया गया।²

(छ) जबकि एक राज्य कर्मचारी के विरुद्ध लगाया गया आरोप गम्भीर प्रवृत्ति का नहीं था तो कलेक्टर ने उसको एक वेतन वृद्धि रोकने और निलम्बन की अवधि में केवल तीन-चोलाई वेतन देने की शास्ति लागू की। अपील करने पर राजस्व मण्डल ने आदेश सशोधित किया क्योंकि कर्मचारी के विरुद्ध आरोप बहुत सघु होने की दृष्टि से, निलम्बन अवधि में वेतन में से कटौती करने का कोई उचित कारण नहीं था।³

(ज) अपील कर्ता की गोपनीय रिपोर्ट में एक रिमार्क यह था कि उसकी ईमानदारी शकाप्रद थी। इस पर कलेक्टर ने उसे नोटिस जारी किया परन्तु अपीलान्त अनुपस्थित रहा। कलेक्टर ने इन नियमों में प्रावधानित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उस पर एक ग्रेड वेतन वृद्धि बिना सिंचित प्रभाव से रोकने की शास्ति आरोपित की। इसलिए कलेक्टर द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वैध नहीं मानी गई।⁴

बोहरी शास्ति—इस बात पर मतान्तर है कि आया किसी राज्य कर्मचारी पर एक से अधिक शास्तियाँ एक साथ लागू की जा सकती हैं या नहीं। जबकि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह मत प्रकट किया है कि एक ही दोष पर बोहरी शास्ति लागू करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है,⁵ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक ही दुराचरण के लिए दो शास्तियाँ लागू नहीं की जा सकती।⁶

जबकि धोखे से नौकरी प्राप्त करना, नियोजन के दौरान दुराचरण में नहीं आता,⁷ मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि नौकरी पाने के लिए गलत जन्म तिथि पेश करना उसे नौकरी से हटाने के लिए 'सही और पर्याप्त कारण' है।⁸

जैसा कि ऊपर कहा गया है किसी कर्मचारी को दण्डित करने से पहले उस पर लगाये गये आरोप रिकॉर्ड पर सिद्ध होने चाहिए। एव मामले में जबकि आरोप साबित नहीं हुए (निन्दा) की शास्ति का आदेश सही नहीं माना गया।⁹ जबकि कारण बताओ नोटिस में अवज्ञा (अविनय) या अनुशासनहीनता की गतिविधियों से सम्बन्धित किसी आरोप का उल्लेख नहीं था, तो यह निर्णय

1. 1978 RRD-NUC-74
2. 1975 RRD-NUC-599
3. 1974 RRD NUC 121
4. RRD 1974-205.
5. 1974 SLJ-25
6. 1969 SLR-787.
7. 1973 Lab. IC 1267 (इलाहाबाद)
8. 1953 Lab IC 552 (मद्रास)
9. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट-156.

या कि इन आरोपों पर सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जा सकता।¹ नियम 14 में विहित शास्ति के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन करते हुए हम कुछ अन्य पैगलो का भी जिक्र करेंगे।

शास्तिमें का वर्गीकरण—नियम 14 में उल्लिखित शास्तियां दो वर्गों में खोलीबद्ध की गई हैं, यर्त् लघु शास्तिया और बडोर शास्तिया।

I लघु शास्तिया:—

- (i) निन्दा,
- (ii) बेतन वृद्धि पर रोक
- (iii) पदोन्नति पर रोक, और
- (iv) सरकारी आर्थिक हानि के कारण वसूली।

II बडोर शास्तिया.—

- (i) निम्नतर सेवा, थोडा या पद या नीचे के बेतनमान में अवतरति,
- (ii) अनुपालक पेशन पर अनिवाय सेवा निवृत्ति,
- (iii) सेवा से हटाना, और
- (iv) सेवा से बरखास्तगी।

यहा, नियम 14 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण का अध्ययन करना सामग्रद होगा, जिसके अनुसार निम्नलिखित कार्य इस नियम के अन्विषय न शास्ति नहीं माने जाएंगे—

- (i) सेवा नियमों या राज्य कर्मचारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में अनुनील रहने के कारण उसकी बेतन वृद्धियों पर रोक।
- (ii) अनुपयुक्तता के आधार पर दक्षता अवरोध (Efficiency Bars) पर तरकी रोक देना।
- (iii) किसी उच्चतर पद या बेतनमान में पदोन्नत नहीं करना।
- (iv) स्थानापन्न रूप में (officiating) पर काम कर रहे कर्मचारी को, उच्चतर सेवा, थोडा या पद के लिए अनुपयुक्तता के आधार पर या प्रशासनिक कारण से उसके मूल पद-स्तर पर वापिस भेज देना।
- (v) परीक्षण पर उच्चतर पद पर काम कर रहे कर्मचारी को वापिस उसके स्थाई पद पर परावर्तन (reversion) कर देना।
- (vi) नियम भेदाधि (superannuation) या रिटायरमेन्ट के नियमानुसार अनिवाय सेवा निवृत्ति।
- (vii) सेवा की समाप्ति—
 - (a) परीक्षण काल के दौरान या उसकी समाप्ति पर, या
 - (b) भत्याई कर्मचारी की, अब कि उसका नियुक्ति काल समाप्त हो जावे, या
 - (c) विशेष इतरार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी को, उसके इतरारनामे की शर्तों के अनुसार, या

(घ) राजस्थान में सम्मिलित होने वाले किसी इकाई के कर्मचारी की, जब वह एकीकृत राजस्थान में किसी सेवा के लिए नहीं चुना जावे या जिसका अवशोषण (absorption) नहीं हुआ हो ।

नतिपय व्यक्तियों पर परीक्षाएँ लागू करने सम्बन्धी सरकारी निर्णय के प्रोचिप की जाय प्रदालन नहीं कर सकती ।¹ अनुशासन प्राधिकारी कर्मचारी को दक्षता-अवरोध पर रोकने में समर्थ है और दीवानी प्रदालन इस अधिकार की जाच नहीं कर सकती और प्रशासनिक प्राधिकारियों के इस प्रकार के आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं मुमकती ।² अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दी गई दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति, नियुक्ति प्राधिकारी खारिज कर सकता है और सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर परीक्षा लागू कर सकता है ।³ परन्तु अब नए बेटनमानों में दक्षता अवरोध हटा दिए गए हैं, इसलिए भविष्य में दक्षता अवरोध पर बेवजह वृद्धियों रोकने का प्रश्न ही नहीं रहेगा ।

प्रक्रिया-लघु-शास्तिया आरोपित करने की प्रक्रिया नियम 17 में निर्धारित की हुई है और बठोर शास्तियों के लिए नियम 16 में प्रावधान है । निर्धारित प्रक्रिया का पालन दृढ़ता से करना चाहिए क्यों कि यह अपेक्षा 'कानूनी' और सविधान के अनुच्छेद 31(2) के अधीन आदेशात्मक (mandatory) भी है ।⁴

(1) निन्दा — यह राज्य कर्मचारी पर लागू की जा सकने वाली न्यूनतम शास्ति है जो करने योग्य कोई काम नहीं करने पर या अवांछित कार्य या टालने योग्य कार्य करने पर दया स्थिति, आरोपित की जा सकती है । निन्दा से अभिप्राय किसी अवांछित कार्य के करने पर या भूलचूक होने पर किङ्की देने या असम्मति प्रकट करने से है । निन्दा की शास्ति आरोपित करने के लिए लोक-सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है । जब लोक सेवा आयोग एक मामले में सिफारिश की कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, 'निन्दा' पर्याप्त सजा होगी, तो यह निर्णय हुआ कि सरकार के लिये यह बाध्य नहीं था कि वह लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर आलोचना करने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के लिए नोटिस जारी करे ।⁵ सर्विस बुक में दी गई प्रत्येक प्रतिकूल टिप्पणी 'निन्दा' नहीं होती । सर्विस बुक में प्रकित यह प्रत्युक्ति कि "सत्यशीलता सदेहप्रद है" (doubtful integrity) कबल एक सम्मति मानी गई न कि निन्दा या शास्ति ।⁶ गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल इन्प्राज यदि सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किया जावे तो वह 'निन्दा' का रूप धारण करलगी और जब सूचित नहीं किया जावे तो 'निन्दा' नहीं मानी जाएगी ।⁷

प्रत्येक चेतावनी (वार्निंग), जो निर्धारित तरीके से नहीं दी जावे वह 'निन्दा' नहीं है । परन्तु जब वह दुराचरण के कारण दी जावे और कर्मचारी के भविष्य पर विपरीत प्रसर डाले तो वो चेतावनी के भेद में निन्दा होगी ।⁸

1 AIR 1960 इलाहाबाद 484—मोहउद्दीन वि यू पी. सरकार ।

2 ILR 1960 राजस्थान 952—मैरो प्रसाद वि राजस्थान सरकार ।

3 AIR 1955 कलकत्ता 585—के बी माथुर वि एन सी चटर्जी ।

4 ILR 1957 राजस्थान 823, 1965 राजस्थान 108, 1958 राज 36

5 AIR 1961 MP 261 सी ए. डी सोजा वि मध्यप्रदेश सरकार ।

6 AIR 1961 कलकत्ता 164—ए आर नायक वि पश्चिम बंगाल सरकार ।

7 ILR (1965) 15 राजस्थान 664—थी नन्दन वि सरकार, AIR 1970 SC 2086 भी देखिए ।

8. 1969 SLR 24 (दिल्ली) एन. सिंह वि भारतीय सघ ।

जबकि दोषी कर्मचारी को दिया गया कारण बताने में नोटिस अस्पष्ट था जिससे वह उसका प्रभावशाली स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं कर सकता था तो निन्दा का आदेश रद्द किया गया।¹ प्राचीन सरकारी रकम बिना विवरित किए अथवा पचास वर्ष तक रखी तो उसके विनाश दिया गया निन्दा का दण्ड अनुमोदित किया गया। इसी प्रकार जब एक डाक्टर ने जिला मजिस्ट्रेट आपीसम के आदेश की नकल अवहलना की बरन् उसका प्रति भेदी भाषा का प्रयोग कर उसका अपमान किया, इस कारण से उस पर आरोपित निन्दा की शास्ति न्यायसंगत नहीं गई।² सविधान के अनुच्छेद 311 में निन्दा की शास्ति सम्मिलित नहीं है।³

(2) वेतन वृद्धि या उद्वेगित रोकना—यह नष्ट शास्ति का अन्य रूप है। इस शास्ति के लिए भी अधीनस्थ कर्मचारियों के मामलों में लोक सेवा आयोग में परामर्श करना आवश्यक नहीं है। परन्तु पदान्ति रोकने से पहले राज्य सरकार के मन्त्रियों के सामने या जोर सेवा आयोग की राय लेना जरूरी होगी। यह शास्ति सविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा निषेधित नहीं करती। परन्तु जब पहले से ही देय सरकारी रोजन के साथ कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर दी गई और सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का पालन नहीं किया तो यह शास्ति अवैध ठहराई गई।⁴

राज्य सरकार के निर्देशानुसार, वेतन वृद्धि रोकने का आदेश में यह निर्दिष्ट कर देना चाहिए आया स्वावट मचित प्रभाव से हाथी भयवा नहीं। इसी प्रकार पदान्ति रोकने के आदेश में भी उसके प्रभाव की अवधि उल्लिखित करनी चाहिए, अर्थात् अथवा स्थाई रूप से या अस्थायी निर्दिष्ट समय के लिए।

साधारणतः राज्य कर्मचारियों पर नष्ट शास्ति का आरोपित करने के प्रशासनिक आदेशों के औचित्य पर न्यायालय निर्णय नहीं देता है। परन्तु घोर अव्यवस्था के मामलों में न्यायालय को दखल करना पड़ा। जब कि एक राज्य कर्मचारी द्वारा 22 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात् विभागीय परीक्षा में पास नहीं होने के कारण उसकी वेतन वृद्धि रोक दी गई तो यह शास्ति अनुचित ठहराई गई।⁵ एक अन्य मामले में, जहाँ कि एक पहले से ही प्रदत्त अधिपत वन वृद्धि, सम्प्रतिष्ठन कर्मचारी को, अपना प्रतिवेदन देने का अवसर दिए बिना, रोक दी गई तो रोकने का आदेश खारिज किया गया।⁶ एक असाधारण मामले में एक सरकारी कर्मचारी की वेतन वृद्धि तीन वर्ष तक शास्ति के रूप में रोक दी गई क्योंकि भाषा विवाद पर सरकार के विरुद्ध उसने अपनी राय प्रकट की। अदालत ने यह आदेश इस आधार पर अवैध ठहराया कि वह आचरण नियमों से असंगत था और इससे अपेक्षा भी वह सविधान के अनुच्छेद 19 (2) का उल्लंघन करता था।⁷

1 AIR 1972 SC 2472—वी डी मुप्ता वि हरियाणा सरकार।

2 1970 SLR 185 (उड़ीसा) बी सनपथी वि उड़ीसा सरकार।

3 1971 Lab IC 1548 (आसाम) डा के पालीत वि शामन गविन

4 AIR 1954 अजमेर 22

5 AIR 1960 पंजाब 129—गुरदीप सिंह वि पंजाब सरकार।

6 1976 SLC (L & S) 118—पंजाब सरकार वि शामनाथ मुरारी।

7 1969 SLR 496 (पूण पीठ)—मण्डूकट्टम नय्यर वि केरल सरकार।

8 AIR 1966 SC 1387—डा बी के. आचारी वि मैसूर सरकार।

जबकि एक राज्य कर्मचारी की वेतन वृद्धियां रोकना का आदेश, उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का नतीजा अभिलिखित किये बिना जारी किया गया था, तो यह फैसला हुआ कि कारणों के अभाव ने अपील के अधिकार प्रदान किये और उमी आधार पर उक्त आदेश पारित किये गया¹। इस प्रकार किसी आदेश को वैध होने के लिए उसे वास्तव में हुआ लिखा जाना चाहिए अर्थात् उसमें आदेश देने के कारण व्यक्त करने चाहिए।²

सचित्त प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना—जबकि नियम 14 के अनुच्छेद (11) में उल्लिखित शास्ति वेतन-वृद्धि रोकना, एक लघु शास्ति है, परन्तु यदि उसके साथ अभिव्यक्ति सचिव प्रभाव से जाड़ा गया हो तो वह सेवा में पदानवती बन सकता है और इस प्रकार कठोर शास्ति में परिवर्तित हो जायेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ ने निर्णय दिया कि शब्द 'पदानवती' में वेतन वृद्धियां रोकना सम्मिलित है और यदि वह भविष्य में प्रभावित करने वाली हो तो वह, जहां तक वह कमचारी की उपलब्धियों (Emoluments) से सम्बन्धित है, उसकी उन्नति के वेग को रोकने के रूप में काम करने वाली होगी। यह मत लोगमन वि. सरकार³ में अभिव्यक्त किया गया। यह स्थिति भारत सरकार द्वारा जांच की गई और दिनांक 20-4-1968 को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और शरीर) नियमों में संशोधन किया गया जिससे जांच करना आवश्यक हो गया।

ऐसे मामलों में प्रशासनिक अंशों पर भी अदालतों ने प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त विस्तारित कर के लागू कर दिया है। एक दूसरे मामले—सी बीरा चौधुरा वि. मैसूर राज्य⁴—में निर्णय दिया गया कि, "आदेश यह विनिश्चित उल्लेख करता है कि वेतन वृद्धियां तीन वर्ष के लिए रोक दी गई हैं जो उसको भविष्य में तरक्की मिलने में प्रभावित करेंगी। अतः इसका नतीजा यह होगा कि जहां तक प्राप्ति सम्बन्धित है, वहां तक तीन वर्ष के लिए घड़ी की सुई पीछे खिसका दी गई है, मानो कि वह वेतन वृद्धियों के प्रयोजनार्थ सेवा में था ही नहीं। यदि इस आदेश का प्रभाव समयावधि वेतनमान में नीचे के स्तर पर गिराने का हो तो इसका अर्थ यह अवश्य हुआ कि नियमों में बताई गई वह एक कठोर शास्ति हो गई। ऐसी शास्ति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये नियमों से प्रतिकूल हो वह खारिज करने योग्य है। यह सम्मति दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीमती सुशीला दुग्गा वि. राज्यपाल⁵ में व्यक्त की। किन्तु उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गोविन्दचन्द्र राउट वि. उड़ीसा सरकार⁶ में यह निर्णय दिया कि वेतन वृद्धि रोकना एक लघु शास्ति है और 'वेतन मान में निम्न स्तर पर पदानवति' के समान कठोर शास्ति नहीं है। जैसे कि नियमों में उल्लिखित हैं, ये दोनों भिन्न भिन्न शास्तियां हैं। इससे वर्तमान में वेतन-मान में नीचे के स्टेज पर पदानवति होगी और भविष्य में लाभमय प्रगति के अवसर खोना नहीं।

पदानवति रोकना—पदानवति पर रोक लगाना भी एक लघु शास्ति है। यद्यपि पदानवति कोई

1. 1978 Lab IC 41 (खलकत्ता) (पूर्वपीठ)—टी आर पाण्डे वि. चीफ कमीशनर

2. 1970 SLR 732—डा० जी के तलवार वि. हरियाणा सरकार।

3. AIR 1967 राज 214

4. 1973 (1) SLR-241

5. 1977 Lab IC (NUC) 141

6. 1977 Lab IC 1684

अधिकार नहीं होता¹ फिर भी राज्य कर्मचारी को अधिकार है कि जब तक कि उसे शास्ति के रूप पदोन्नति में वंचित नहीं किया गया हो, जब तक उसके मामले पर विचार किया जावे।² इसलिए शास्ति के रूप में जिस किसी राज्य कर्मचारी की पदोन्नति रोक दी जावे तो ऐसा अवरोध लगाने में पहले, नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए।³ यह शास्ति बिना सही और पर्याप्त कारणों के लागू नहीं की जा सकती। अन्य शब्दों में, यह शास्ति आराधित करने में पूर्व रखाड़ पर दुराचरण का आराध साबित होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को पदोन्नति नहीं देना पदस्तर से अवनति करना नहीं है।⁴ परन्तु वह संविधान के अनुच्छेद 16 में विचारणीय राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर व समानता के सिद्धान्त के अन्तर्गत आती है। मैसूर सरकार वि सी आर शेषधारी⁵ में यह कहा गया है —

‘हमारी संविधान की योजना में मोटे तौर पर तीन विभाग विद्यमान हैं, नामार्थ—

- (अ) किसी पदाधिकारी को पदोन्नति देने का अधिकार कार्यकारीणी (सरकार) को है और न्यायिक अधिकार सरकार की कार्यवाही को नियन्त्रित या पुनरावलोकन कर सकेगी परन्तु इस हद तक कार्यवाही नहीं कर सकती मानो कि वह स्वयं ही कार्यकारीणी है।
- (ख) न्यायालय निदेशन जारी कर सकता है परन्तु उसकी कार्यन्विति कार्यकारीणी पर छोड़ देनी है।
- (ग) न्यायपालिका कर्मचारीयों को पदोन्नत या पदान्तरित नहीं कर सकती परन्तु सरकार के किसी गलत आदेश को खारिज कर सकती है या सही सिद्धान्तों पर पुनर्विचार करने के लिए आदेश दे सकती है।”

पदोन्नतियों के मामले में विचारण और नियुक्ति की परिधि में आते हैं।⁶ पदान्ति का मामला पूर्णतः प्राधिकारी के स्व विवेक पर निर्भर है और जब तक यह नहीं दर्शाया जावे कि किसी कानून या नियमों का उल्लंघन हुआ है तब तक उसे कानूनन चुनौती नहीं दी जा सकती।⁷ अतः जब कि प्रारम्भ में एक कर्मचारी का नाम पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया, परन्तु बाद में उसे सूचित किया गया कि वह इसके उपयुक्त नहीं है तो इससे अपने आप में कर्मचारी को पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हुआ।⁸ इसके विपरीत जबकि प्राचीन के प्रतिवेदन पर लोक सेवा आयोग की निरीक्षण के पश्चात् भी जब उसका नाम पदोन्नतियों की प्रस्तावित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया तो मना करने का सरकारी निर्णय अवैध तथा गलत घोषित किया गया।⁹

1 AIR 1962 SC 1704 और AIR 1968 SC 1113

2 AIR 1967 SC 1910—सन्नराम वि राजस्थान सरकार।

3 1973 SLJ 41—श्री नाथ वि मैसूर सरकार।

4 AIR 1958 राजस्थान-239

5 1974 SCC (L & S) 264

6 1965 RLW 388—मोहनलाल वि राजस्थान सरकार।

7 AIR 1959 मणीपुर 1—श्री बी सिंह वि पाठशाला निरीक्षण।

8 AIR 1959 मद्रास 270—एल बालकृष्णन वि उप-महा-निरीक्षण।

9 AIR 1964 पंजाब-302—के एल नन्दा वि पंजाब सरकार।

सेवाओं के एक सदस्य को अस्थाई रूप से एक उच्चतर पद पर कार्यवाहन के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया गया परन्तु उसके विरुद्ध शिष्यायते प्राप्त होने पर उसे एक वर्ष के लिए उसके मूल पद पर परावर्तन कर दिया गया और उसकी भावी पदोन्नति उसके ऊपर के अधिकारी की अच्छी रिपोर्ट पर निर्भर की। एक वर्ष की समाप्ति पर उसने अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा किया। न्यायालय ने इस आधार पर उसका दावा खारिज कर दिया कि राज्य कर्मचारी अधिकार के रूप में पदोन्नति पाने का हक्कार नहीं होता और जब वह एक बार नीचे की पक्ति में परावर्तन कर दिया जाता है तो उसकी पदोन्नति, पदोन्नतियों के नियमों द्वारा नियमित की जाएगी।¹ इसी प्रकार, जबकि पदोन्नति के मामले में प्राचीन को अनेक कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिस्पर्धित कराया गया (Superseded) तो वह अपना दावा लेकर न्यायालय में पहुँचा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके मामले पर सम्बन्धित प्राधिकारी ने यथाचित विचार किया था और उस पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझा इसलिए दावे के लिए कोई विनाश का दावा पैदा नहीं हुआ।² राजस्थान उच्च न्यायालय के एक अधिकारी श्री परमात्माशरण ने सहायक रजिस्ट्रार या मुख्य न्यायाधीश के सचिव के पद पर पदोन्नत करने के लिए इस आधार पर दावा किया कि उसके मामले पर पूर्णतया विचार नहीं किया गया। इस मामले पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत किसी भी नागरिक को समान अवसर से इन्कार नहीं किया जा सकता परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसे कुछ सुविधाएँ प्रदान की जावे। मुख्य न्यायाधीश को अधिकार था कि वह पदोन्नति के लिए सबसे उपयुक्त आदमी का चुनाव करता।³

जो व्यक्ति किसी अन्य विभाग में उप-नियुक्ति (ड्यूटेसन) पर चला गया हो तो उसके पदोन्नति के मामले में उसके मूल विभाग द्वारा उपयुक्त विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वह अपने पिछले पद पर प्राधिकार (lien) धारण करता है।⁴ कर्मचारी की वरिष्ठता पर तभी विचार किया जा सकता है जब कि वह अपने प्रतिस्पर्धी दावदारों के गुण तथा योग्यता में लगभग समान हो।⁵ अतः अगर रोय वि मध्यप्रदेश⁶ में निर्धारित यह तत्त्व किया गया है कि सरकार को पदोन्नतियों की तदर्थ या प्रस्तावित सूची तैयार करके प्रकाशित कर देनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति उनसे प्रभावित हो उनका अपना दावा प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

अनुसूचित जातियों/जन जातियों के पक्ष में आरक्षण करना संविधान के अनुच्छेद 16 (4) द्वारा प्रावधानित रामान बस्तर संभूत अधिकार का उल्लंघन नहीं करता⁷ तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य किया और यह मत अभिव्यक्त किया कि, 'आरक्षण की जो शक्ति राज्य को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन प्रदान की गई है वह राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त मामलों में न केवल नियुक्तियों के आरक्षण हेतु बल्कि चुनाव पदों के आरक्षण के लिए

1 AIR 1960 MP 216—बी सी तिवारी वि मध्य प्रदेश सरकार।

2 AIR 1962 SC 1704—बलकृष्ण उच्च न्यायालय वि ए के रोय।

3. 1963 RLW 246—परमात्मा शरण वि राजस्थान उच्च न्यायालय के, मुख्य न्यायाधीश।

4 1965 RLW 388—मोहनलाल वि राजस्थान सरकार।

5 AIR 1957 कश्मीर 29—एम एन गन्जु वि जम्मू व काश्मीर सरकार।

6 AIR 1964 मध्यप्रदेश—407

7 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 36—जिसमें AIR 1960 इलाहाबाद 454 का विपरीत किया गया।

प्रावधान करने के लिए भी प्रयोग कर सकेगी। हमारी सम्मति में इसका यह अभिप्राय सविधान निर्माताओं के इस आशय को प्रभावशाली बनाएगा कि पिछड़ी जातियों की प्रगति के लिए और समाजों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की प्राप्ति के लिए उचित सरक्षण रखा जाना चाहिए।”

(4) वेतन में वसूली — चौथी विस्म की लघु शास्ति कर्मचारी की नापरवाही या किसी कानून, नियम अथवा आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित सरकार को पहुँचाई गई हानि की क्षति पूर्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य कर्मचारी के वेतन में घटाने करने की है। यह कोई जुर्माना नहीं है, इसलिए वसूली की राशि वास्तविक नुकसान की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि दोगे इतनी राजकीय सेवाओं का सदस्य हो तो यह शास्ति लागू करने में पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा।

संवैधानिक सरक्षण — सार्वजनिक कर्मचारी को जो संवैधानिक सरक्षण प्रदत्त है वह उनकी अवहेलना किसी भी परिस्थिति में नहीं की जानी चाहिए। जबकि जिस प्रयोगशाला का प्रभारी अधीक्षक या उम्मेदवार चोरिया घटित हुई जिसमें उसे अवांछित व्यक्ति समझा गया। प्राधिकारियों ने निरपेक्ष तरीके से कार्यवाही की और निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण विधि बिना उसका दो महीने का वतन जवन कर लिया और उसे सेवा में हटा दिया गया। इसलिए, उक्त शास्ति का आदेश रद्द किया गया।¹

वेतन में वसूली की यह शास्ति इसलिए आवश्यक है कि राजकीय कर्मचारी ऐसे नापरवाही, अनानयानी या वर्चस्वी या किसी कानून, नियम या आदेश का उल्लंघन करने, से भयभीत रहे जिससे कि सरकार को हानि पहुँचे। उदाहरणार्थ, हम कम परिचानक के मामले को ले सकते हैं जो पात्रियों में कम सिद्धांत वसूल करे या ऐसा धालक जा यह जानने हुए कि गाड़ी में खराबी है उसे चलाता रहे जिसके फलस्वरूप कोई क्षति पहुँचे अथवा ऐसा मजान्ची जो सरकारी राशि को छुट्टे में छोड़ दे जिससे उसकी चोरी होने या आधी के भोके से उड़ जाने का परिणाम निकले। यदि कोई गोदाम कीपर या स्टोरकीपर या मरकारी लेखन सामग्री का प्रभागी अपने प्रभार की वस्तुओं को सावधानीपूर्वक नहीं रखे और कोई सामग्री दीमक वर्षा के पानी, चोरी आदि सारा नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वह ऐसी शास्ति का भागी होगा।

वित्तीय नियमों में भी वित्तीय सूचरित्र का एक मानक (स्टैंडर्ड) निर्धारित है, जिसका हड़ता से पालन करना अपने आप ही शास्ति से बचाने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक राज्य कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी सम्पत्ति की रक्षा उसी होजियारी तथा सनकता में करे जो वह अपनी निजी सम्पत्ति के विषय में करता है। यदि वह घोवाघड़ी या कपटपूर्ण तरीकों से जान बूझकर सरकार को हानि पहुँचावे तो वसूली की यह लघु शास्ति पर्याप्त नहीं होगी। उसे अधिक मगीन परिणाम भुगतने चाहिए।

वसूली का कोई आदेश जारी करने से पूर्व निम्नलिखित मध्य निर्धारित किए जाने चाहिए —

- (1) सरकार को पहुँचाई गई वास्तविक आर्थिक हानि,
- (2) उक्त हानि दोगे कर्मचारी की नापरवाही या किसी कानून, नियमों या आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित होनी चाहिए, और

(3) राजि के कम हानि की सीमा जो पूरण या आशित रूप में कमचारी से वसूल करनी है।¹

अतः जब कि यह नहीं कहा जा सकता कि हानि किसी विशिष्ट कमचारी के कारण ही घटित हुई तो उस दण्ड नहीं दिया जा सकता। तब कि प्रार्थी का यह कथन नहीं था कि वह पंक्ति व कामजो वगैरह का वर्गीकरण करता तो वह गनन वर्गीकरण के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता जिसके परिणाम स्वरूप सरकार का हानि हुई।² जोसफ धि केरन राज्य³ में यह माधोचित नहीं समझा गया कि जब स्टॉक में पड़ हुए गडू का वजन प्रार्थनिक कारणों (नमी) के कारण बढ़ गया तो सरकार ने उसका फायदा उठा लिया परन्तु जब प्रार्थनिक कारणों से ही (उदाहरणतः सूख) के कारण गेहूँ का वजन घट गया, तो सरकार ने इसका दायित्व गोद में वीपर पर ठहराया।

शास्ति नभी लागू की जानी चाहिए जब कि जाच की मारी औपचारिकताएँ पूरी करनी गईं हों और सम्बन्धित कमचारी को सामान्य में अपनी प्रतिबद्ध प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान दिया जा चुका हो।

राजस्थान सरकार के निर्देशनानुसार दोषी कमचारी से वसूली उसके भुगतान करने की सामान्य का ध्यान रखा हुआ सुविधाजनक किशो में की जानी चाहिए। यदि राज्य कमचारी के वजन से वसूली होने से पहले, कमचारी मेवा निवृत्त हो जाए तो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 के अन्तर्गत उसकी पे शन से वसूली की जा सकती है।

कठोर शास्ति

(1) पदस्तर से पदावनति — यह एक प्रकार की कठोर शास्ति है। इस तात्पर्य पद ने नीचे गिराना है अर्थात् सरकारी कमचारी को निम्नतर ग्रेड या निम्नतर पद, या निम्नतर घेतनमान में, या उसी वजन मान में नीचे की अवस्था (stage) में लगाना है अथवा देय पंशन में कम राशि पंशन के रूप में देने से है।⁴

दो प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसका नियम करण कि आया कोई पदावनति शास्ति स्वरूप है अथवा नहीं। पहला यह कि आया सम्बन्धित व्यक्ति को वह पद धारण करने का अधिकार है या नहीं दूसरा यह कि आया उस पदावनति का परिणाम सुविधान के अनुच्छेद 311 में प्रावधानित दण्ड के रूप में है अर्थात् अज्ञान लाभ की जन्ती या भावी पनोनति के अवसरों में हटाव या हटाना। इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हाँ में होने से पदावनति शास्ति के रूप में होने वाली समझी जाएगी। उपरोक्त सिद्धान्त सर्वोत्तम चायानन्द न प्रसिद्ध केम परशोत्तम लाल धीगरा वि भारतीय सच⁵ में निर्धारित किया। नियम 14 के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण (1) के उपखण्ड (iv) और (v) यह स्पष्ट करते हैं कि उच्च सेवा ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी राज्य कमचारी का प्रत्यावर्तन अनुपयुक्तता या प्रशासकीय आधार पर करना जो उसके आचरण से सम्बन्धित न हो शास्ति नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षण पर किसी अन्य मेवा ग्रेड या पद पर कार्य कर रहे राज्य कमचारी को परीक्षण अवधि में या अवधि की समाप्ति पर, उसकी

1 AIR 1955 VP 21 रामचरण वि विन्ध्य प्रदेश सरकार।

2 1975 Lab IC 1332 (पटना श्रीधर प्रसाद वि भारतीय सच)।

3 1973 (2) SLR 712

4 AIR 1958 मणिपुर 33—एन तोम्बी सिंह वि सरकार।

5 AIR 1958 मुम्बई नोट 36

नियुक्ति की अर्हता या परीक्षण सम्बन्धी आदेश या नियमों के अनुसार उसे वापिस उसकी स्थाई (मूल) सेवा, ग्रेड या पद पर प्रत्यावर्तित कर देना नियम 14 के अभिप्राय से शास्ति नहीं होगी। यहाँ शब्द "पदावर्ति" को उमरे तरतीकी अर्थ में समझना चाहिये, अर्थात् यह एक शास्ति है जो अनुशासन-हीनता या दुराचरण के कारण किसी राज्य कर्मचारी पर न मू की जा सकती है।¹ "पद-स्तर में अवर्ति" कर्मचारी की वर्तमान स्थिति में सम्बन्धित होनी चाहिए न कि किसी भावी सम्भावित स्थिति में। शास्ति के रूप में नीचे के पद पर या कम वेतन, भत्ता आदि उपलब्धियों पर पदावर्ति करना अधिनियम के अनुच्छेद 311 के अध्याय के अनुसार पक्षिभुत करना होगा।²

जब एक व्यक्ति जो ऊँचे पद पर प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर काम कर रहा था, मामूली तौर से वापिस उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, तो इसमें शास्ति का कोई तत्व या अंश नहीं है। परन्तु यदि पदस्तर में गिरावट शिक्काग्र और जाच के फल स्वरूप है, तो वह किसी अपराध या दुराचरण का दण्ड होगा और उससे उस कर्मचारी की भावी पदोन्नतियाँ रुक जाएँगी, इसलिए वह पद स्तर में पदावर्ति करना होगा।³

जब एक कर्मचारी का प्रत्यावर्तन इस कारण से कर दिया गया कि स्थाई पदाधिकारी उपलब्ध करा दिया गया था,⁴ या उपयुक्त योग्यता का आदमी मिल गया था, या अस्थायी पदोन्नति पाने वाला व्यक्ति उच्च पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया।⁵ तो निर्णय हुआ कि वह कोई दण्ड देने का मामला नहीं था। जबकि प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, जिसके लिए कि वह प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए भेजा गया था, उसे मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया, तो कोई शास्ति नहीं बनी।⁶ जब प्रतिनियुक्ति की अवधि में एक कर्मचारी निर्धारित परीक्षा में अनुनीर्ण रहा, जिससे उसको वापस उसके स्थाई पद पर भेजा गया, तो निर्णय हुआ कि यह भी कोई शास्ति का मामला नहीं था।⁷ जबकि प्रतिनियुक्ति की अवधि में चुनाव समिति ने कर्मचारी को उस पद के लिए नहीं चुना,⁸ अथवा प्रशासनिक कारणों से उसे उस पद पर नहीं रखा गया⁹ अथवा उपनियुक्ति पर कार्य कर रहे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट लगाये जाने के कारण उस वापस प्रत्यावर्तित कर दिया गया, तो प्रत्यावर्तन के इन सभी मामलों में कोई शास्ति सम्मिलित होनी नहीं मानी गई।¹⁰

1. AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 250-सनीश चन्द्र वि भाग्यीय सभ ।

2. ILR 1958 राजस्थान 134-बद्रीप्रसाद गुप्ता वि राजस्थान सरकार ।

3. AIR 1956-जी बी देशमुख वि मध्य भारत सरकार ।

4. AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 794-बम्बई राज्य वि एफ ए अग्र हिम ।

5. (1953) 58 CWN 128 विचोरेय वि मध्य प्रदेश सरकार, AIR 1952 नागपुर 288 और 1969 SLR 442-भारतीय सभ वि आर एस चावा ।

6. (1955) 59 CWN 859

7. AIR 1956 पटना 273

8. AIR 1965 केरल के एन चक्रम वि केरल सरकार ।

9. AIR 1960 पंजाब 65-हरद्वारमिह वि पंजाब सरकार ।

10. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट-36-पुरुषोत्तम लाल धीररा वि भारतीय सभ ।

निम्नलिखित मातृका में नी प्रत्यावर्तन करना भी शास्ति स्वरूप नहीं माना गया —

- (1) जबकि प्रशासनिक कार्यों में सम्पन्न पद सम्पन्न कर दिया गया ।¹
- (2) जबकि नये प्रकार के प्रशासनिक दायों के कारण प्रत्यावर्तन करना पड़ा ।²
- (3) जबकि कर्मचारी के विरुद्ध कोई बलक नहीं लगाया गया ।³

इसके विपरीत, प्रत्यावर्तन करना शास्ति स्वरूप माना गया जबकि कर्मचारी के विरुद्ध कोई बलक लगाया गया था,⁴ या नये उम्मीदवार का चुनाव कर लिये जाने के कारण कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति के पद से हटाया गया,⁵ या आपत्तीय प्रतिवेदन में प्रतिनियुक्त रिमाक होन के कारण⁶ या अनुशासनात्मक, लापरवाही और दुराचरण के आरोपों के आधार पर,⁷ या भ्रष्टाचार के आरोप पर जाच पूरी नहीं होन से पट्टा,⁸ या अनुपयुक्तता के कारण वेतन में कमी करने के साथ⁹ या प्रत्यावर्तन बदनीयता से जाच को मुविधाजनक बनाने के लिए किया गया प्रत्यावर्तन¹⁰ या जबकि एक प्रदेश में कर्मचारी को वेतन और भत्तों की जमीन या उमर भूत पद पर परिष्कृत की हानि हुई या जबकि उमर के भावी पदोन्नति के अवसर खत्म हो गये या स्थगित हो गये तो यह निर्णय हुआ कि आदेश को चाहे जैसा शास्ति विहीन रूप में दिया गया हो फिर भी उसकी परिस्थितियाँ बतानी थी कि वह शास्ति रूप का और सरकार ने निःसंदेह उस व्यक्ति का दंडित किया ।¹¹

हमारे प्रकार सेना-निवृत्त कर्मचारी की पेंशन में किसी कार्यवाहिकी आदेश द्वारा कमी नहीं की जा सकती क्योंकि पेंशन कोई अनुदान नहीं है और उस प्राप्त करना सम्पत्ति का अधिकार है ।¹²

अतः जब तक कि पेंशन पान वाले को अपनी प्रतिरक्षा के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाय तब तक पेंशन की राशि में कोई कटौती नहीं की जा सकती ।¹³ इस सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमावली नियम 170 का पठन करना लाभप्रद होगा । पेंशन में कटौती करना एक कठार शास्ति है जो तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि राजस्थान मिनिस्टर सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियमावली के नियम 16 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना से नहीं किया गया हो ।

- 1 1973 SCC (L&S) 560—एम आर पिन्लई वि केम्बल सरकार ।
- 2 1971 (1) SLR-164—गुर्देवसिंह वि पंजाब सरकार ।
- 3 1969 SLR-442—भारतीय सच वि आर एम धावा ।
- 4 1974 SCC (L&S)-124
- 5 1973 WLN 320—(जि सी भाटिया वि राजस्थान सरकार ।
- 6 1974 SCC (L&S) 124 यू पी सरकार वि गुधडसिंह ।
- 7 1973 SLC 302 (P&H) पंजाब राज्य वि मोहिन्दर सिंह ।
- 8 (1971) SLR 345 के एच फर्डिनस वि महाराष्ट्र सरकार ।
- 9 AIR 1970 SC 77 डी सी दाम वि भारतीय सच ।
- 10 AIR 1964 SC 423—पी सी बाघवा वि भारतीय सच ।
- 11 AIR 1958 SC 36—मी एल धीरारा वि भारतीय सच ।
- 12 AIR 1971 SC 1409—देवकीनन्दन प्रसाद वि बिहार सरकार ।
- 13 1976 SCC (L&S) 172 पंजाब सरकार वि इकबाल सिंह ।

राजस्थान सरकार ने अपनी पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहियों की हैण्डबुक में अनुच्छेद 17 (4) में विशिष्ट निर्देशन दिये हैं जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को नीचे की सेवा, ग्रेड या पद या निम्नतर वेतनमान में पदानवत किया जाता है तो सम्बन्धित प्राधिकारी को चाहिए कि वह साधारणतः स्थायी पदानवति नहीं करे क्योंकि उससे दोषी अधिकारी की नेक कार्य करने की प्रेरणा नष्ट होती है और उसका नैतिक पतन होता है। जबकि पदानवति की अवधि निर्दिष्ट की जावे, तो प्राधिकारी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि ग्रामा पूर्वस्थिति प्राप्त करने पर आया पदानवति की अवधि से भावी वेतन वृद्धि स्थगित होगी या नहीं और यदि है तो किस सीमा तक। इस विषय में नृपया राजस्थान सेवा नियमों के नियम 34 को भी पढ़िए।

(2) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति भी एक कठोर शास्ति है। साधारणतः, राजस्थान सरकार के समस्त असेनिक कर्मचारी उस माह की अंतिम तिथि को रिटायर होत हैं जिसमें वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने की दशा में 58 वर्ष और अन्य श्रेणी के होने की दशा में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, देखिए राजस्थान सेवा नियमों का नियम 56 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु 57 वर्ष है। सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर जब कर्मचारी को रिटायर किया जाता है तो वह राजस्थान सेवा नियमों की शर्तों के अनुसार, जिनके आधार पर उसकी नियुक्ति हुई थी, सेवा निवृत्त किया जाना है। अतः, इसमें शास्ति का कोई तत्व नहीं है। परन्तु सरकार को अधिकार है कि वह निम्नलिखित तरीकों से कर्मचारी को उक्त आयु प्राप्त करने से पहले रिटायर करदे —

- (1) नियम 16 तथा सविधान के अनुच्छेद 311 (2) में निर्धारित उपयुक्त जाव करने के पश्चात् शास्ति के रूप में सेवा निवृत्ति की जा सकती है, अथवा
- (2) पदों की कमी (Retrenchment) करने के लिए, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144 (2) के अधीन, जो कि एक प्रशासनिक मामला है। इस नियम के अधीन जब कोई राज्य कर्मचारी 25 वर्ष की अर्हता सेवा समाप्त कर लेता है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो बिना कोई कारण बताए उसे सेवा निवृत्त किया जा सकेगा, जो नियम 14 के स्पष्टीकरण (vi) के अनुसार शास्ति स्वरूप नहीं होगा क्योंकि वह कर्मचारी की सेवा की शर्तों के अनुरूप है, अर्थात् राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार है। वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 243 और 246 के अधीन पूरी सेवा निवृत्ति पेंशन प्राप्त करेगा।
- (3) 25 वर्ष का अर्हता सेवा समाप्त करने के पूर्व ही किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति की आयु से पहले इन आधार पर रिटायर किया जा सकेगा कि वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 228 के अधीन शारीरिक या मानसिक रोग के कारण असमर्थ हो गया है। ऐसा करना भी कोई शास्ति नहीं होगा और उसकी असमर्थता की तिथि से वह सेवा निवृत्ति पेंशन प्राप्त करेगा।

सेवा निवृत्ति के प्रयोजनार्थ राज्य कर्मचारी की आयु उसकी सेवा पुस्तिका (सक्रिय बुक) में दर्ज की गई जन्म तिथि के आधार पर तय की जाएगी। जबकि एक कर्मचारी ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि आयु का आधार मानी जाएगी और बिना किसी विपरीत शक्तिवाली सद्बत के इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

25 वर्ष की सेवा के पश्चात् अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश देने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जबकि ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो। इस विषय में, नियुक्ति विभाग के सरक्यूलर मर्या F-24 (55) नियुक्ति (A) 57 दिनांक 17-1-59 के अनुसार राजपत्रित अधिका-रियों के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार है। सरक्यूलर मर्या D 1273/60/F-24 (55) नियुक्ति (A) 57 दिनांक 22-2-60 के अनुसार निष्क्रिय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की पूर्वगामी अनुमति आवश्यक होगी।

सरकार की स्वीकृति-इसका साक्ष्य — कारोवारी नियम (Business Rules) का नियम 31 (vii) निर्धारित करता है कि किसी अधिकारी को बर्खास्त करने, सेवा स हटाने या अनिवार्य सेवा निवृत्ति करने का आदेश जारी करने से पूर्व, जबकि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो तो प्रस्ताव अनु-मति के लिए राज्यपाल व मुख्य मंत्री को पेश किए जाएंगे। श्रीपाल जैन व महानिरीक्षक आरक्षी राजस्थान¹ में न्यायमूर्ति बेरी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिया है —

“जब किसी राजपत्रित अधिकारी ने 25 वर्ष की अहंरता सेवा समाप्त करली हो उनके पश्चात् यह निर्धारित करने का कार्य कि आया उसे सार्वजनिक हित में सेवा निवृत्ति करना अपेक्षित है, राज्यपाल व मुख्य मंत्री ने स्वयं धारण करने के लिए आरक्षित कर लिया है। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा यह कार्य करने का अधिकार, चाहे वह कितना भी ऊँचा प्राधिकारी क्यों न हो कानून के अनुसार नहीं होगा।” इस मामले में सम्बन्धित पुत्रिस का सब-इन्स्पेक्टर सरकार द्वारा नियुक्त किया हुआ था और सरकार के नाम से ही वह अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति किया गया परन्तु वास्तव में उक्त आदेश मुख्य मंत्री व आगे राज्यपाल तक पहुँचा ही नहीं, इसलिए यह आदेश कानूनन गलत माना जाकर खारिज किया गया।

इस विषय में राजस्थान सरकार के निर्देश महत्वपूर्ण हैं जो ऊपर पूरे दिये जा चुके हैं।² तदनुसार सरकार का आग्रह यह है कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी कर्मचारी को सेवा में जारी रखना अवांछित प्रतीत हो और जबकि सेवा स हटाये जाने या बर्खास्तगी की कठोरतम शास्तिया उनके परिणामस्वरूप होने वाली पेन्शन की हानि का दृष्टिबोचर रखते हुए, तुर ममभी जावें, तो दैने मामले में अनिवार्यतः सेवा निवृत्ति की शास्ति दी जा सकेगी। परन्तु सरकारी रकम का भवन और नैतिक पतन के अपराध के मामलों को पूर्वकालीन सेवा निवृत्ति से ज्यादा संगत मजा दी जानी चाहिए। जो अधिकारी राज्य कर्मचारी को सेवा से हटान या बर्खास्त करने के लिए सक्षम हो वही उस अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति आरोपित कर सकेगा न कि कोई उससे नीचे का प्राधिकारी। इस प्रकार से रिटायर किए गये अधिकारियों को पेन्शन मजूर की जा सकेगी जो दोषी अधिकारी को स्वीकार योग्य पेन्शन से दो-तीहाई से कम नहीं तथा पूरी रोगातुर पेन्शन (invalid pension) से अधिक नहीं होगी। शास्ति के रूप में अनिवार्य सेवा निवृत्ति सर्विधान के अनुच्छेद 311 (2) को आवृत्ति करती है³ और इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील)

1 ILR 1961 राजस्थान 536

2 प्रशासनिक कार्यवाहिया की पुस्तिका, 1963

3 1961 RLW 298—मणाराम वि राजस्थान सरकार।

नियम 1958 में बठोर शास्त्रियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। आन्ध्रप्रदेश सरकार वि. एम. एन. निजामुद्दीन अलीवाँ¹ में निर्णय दिया गया कि जाच की अवस्था में तथा शास्त्रि प्रस्तावित करने की अवस्था में, दोनों समय सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा प्रतिवेदन पेश करने का अवसर प्रदान करने का अभाव रहने से सविधान का अनुच्छेद 311 (2) अतिक्रमित हुआ, अतः आदेश खण्डन करने योग्य माना गया। जाच विचाराधीन रहत समय से पूर्व रिटायर करना सेवा से वर्खास्तगी या हटाने के समान है और चूँकि सविधान में अनुच्छेद 311 (2) की अपेक्षानामों की पूर्ति नहीं की गई इसलिए आदेश निरस्त किया गया।² उसी प्रकार, जबकि जाच जारी रखने के बजाय, दापी कर्मचारी को समय से पूर्व रिटायर कर दिया गया तो विद्याधर मिश्रा वि. यू. पी. सरकार³ में तब हुआ कि उक्त सेवा निवृत्ति दण्ड स्वरूप थी और उससे सविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन हुआ।

एक राज्यपत्रित अधिकारी के पाम रु. 2440/- पाए गए। इस आधार पर प्राधिकारी ने यह कहते हुए उसको रिटायर कर दिया कि उक्त रकम उसकी आमदनी के अनुपात से काफी बड़ी थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उपरोक्त निष्कर्ष पूर्णतः अनुचित तथा अन्यायपूर्ण था, और अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश रद्द किया गया।⁴

इसके विपरीत जबकि राजस्थान सरकार ने एक आम आदेश जारी किया कि समस्त राज्य कर्मचारी जिन्होंने एक मई, 1949 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करनी है या 30 वर्ष की प्रहुरता सेवा पूरी करली है वे 1 मई, 1949 को सेवा निवृत्त हो जाएंगे। प्राचीन, को ज़िम्मे 1 मई, 1949 का 30 वर्ष की सेवा पूरी करली थी ऐसे अन्य कर्मचारी के साथ रिटायर कर दिया, प्राचीन ने अपनी सेवा निवृत्ति को इस आधार पर चुनौती दी कि उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया इसलिए वह जब तक 55 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करले तब तक नौकरी पर बने रहने का अधिकारी है। इस पर निर्णय दिया गया कि 55 वर्ष की आयु तक सेवा में रहना कोई अक्षय (indefeasible) अधिकार नहीं है, और यह कि सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं था।⁵ आगे अनेक मामलों में यह भी निर्णय हुआ कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अधीन सेवा निवृत्ति करना सविधान के अनुच्छेद 311, या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं करते।⁶

जब अनिवार्य सेवा निवृत्ति शास्त्रि के रूप में आरोपित नहीं की जाती, तो सम्बन्धित कर्मचारी की सुनवाई करना आवश्यक नहीं है। परन्तु जब यह शास्त्रि के रूप में हो, (जिसमें पदधारी द्वारा

1 AIR 1976 सुप्रीमकोर्ट 1964

2 1978 SLJ 88—इनाहाबाद—जी. एम. सीवाल वि. भारतीय सच।

3 1977 Lab IC 384 (इनाहाबाद)।

4 1973 (2) SLR—291.

5. ILR 1951 राज. 405 और ILR 1965 राज. 371—नेचनमन, मिश्री वि. हेनागम तथा गगाराम पुरोहित वि. राजस्थान सरकार।

6. RLW 1965—44—गोपालमल वि. राज्य, ILR 1962 राज. 69—कपूरचन्द वि. राजस्थान राज्य तथा ILR 1961 राज. 379—जी. धार पुरोहित वि. राजस्थान राज्य।

पहले से ही अर्जित लाभों की जल्दी सम्मिलित है) यह आवश्यक है कि दोषी कर्मचारी को प्रतिवेदन करने तथा अपने आप को बचाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जावे।¹

जयराम वि. भारतीय सघ² में एक भिन्न स्थिति उत्पन्न हुई, जबकि प्राथि ने खुद ने यह माग की कि वह 55 वर्ष की सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले रिटायर कर दिया जावे। जब उसने अपनी माग पर दबाव डाला, तो सरकार ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली और उसे सेवा निवृत्त होने से पहले 11 महीने व 25 दिन का अवकाश प्रदान किया। परन्तु उक्त अवकाश समाप्त होने से ठीक 10 दिन पहले उसने अपना विचार बदल लिया और पुन कार्य पर आने की इच्छा प्रकट की। इस घ्येय की प्राप्ति के लिए वह न्यायालय में पहुँचा। इस मामले में सर्वोत्तम न्यायालय ने फैसला दिया कि यह स्थिति पूर्णतः उसकी स्वयं की बनाई हुई थी। सरकार ने उसे रिटायर होन के लिए नहीं कहा था। अतः वह न्यायालय की सहायता प्राप्त करने का हक्दार नहीं था।

जब कि राज्य सेवाओं के किसी सदस्य को समय में पहले रिटायर करने का प्रस्ताव हो, तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा। निम्नलिखित मामलों में सेवा निवृत्ति की सेवा से हटाना माना गया और, इसलिये, सविधान का अनुच्छेद 311 (2) आक्षेपित हुआ —

- (1) जब कि राज्य कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेता था, या³,
- (2) जब कि वह असत्यवादी या अकुशल था,⁴ या
- (3) जब कि लोक सेवा आयोग की राय थी कि कर्मचारी के विरुद्ध आरोप मादित थे⁵ या
- (4) जब वह ऐसे व्यक्तियों के यहाँ आता जाता था जो कि विध्वंसक गतिविधियों (subversive activities) में भाग लेते थे⁶, या
- (5) जब उसे अनिवार्यतः अवकाश दिया गया जिसका अत आखिरकार उसकी सेवा निवृत्ति के रूप में हुआ⁷।

जब कि सरकार ने प्रार्थी का सेवा काल 11 महीने 20 दिन बढ़ा दिया, परन्तु कथित आदेश एक पक्षबाड़े के भीतर उठा लिया और प्रार्थी को उसने पद से मुक्त कर दिया गया, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा करने से पहले सविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिये था। ऐसे अवसर के अभाव में द्वितीय आदेश स्पष्टतः गलत था।⁸

परन्तु जब कि राज्य सरकार ने एक ग्राम अधिभूचना जारी करके, सार्वजनिक प्रशासन में

1. AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 369.
2. AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट 585
3. AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1160—वि. एस. मेनन वि. भारतीय सघ।
4. AIR 1954 सौराष्ट्र 146—सोभागचन्द एम. दोषी वि. सौराष्ट्र सरकार, एवं 1956 सुप्रीम कोर्ट 892.
5. AIR 1963 मद्रास 14—मद्रास राज्य वि. टी. के. जी. घय्यर।
6. AIR 1956 पेंपमू 19—सक्षमन सिंह वि. आई. जी. पुलिस।
7. AIR 1951 जम्मू-कश्मीर 60
8. AIR 1963 मैसूर 208—ने. शामा राव वि. मैसूर सरकार।

युक्तता बढ़ाने और सार्वजनिक हित के आधार पर सेवा निवृत्ति की आयु 58 से घटा कर 55 वर्ष की कर दी तो न्यायालय ने तय किया कि इससे अनुच्छेद 311 आक्रांत नहीं हुआ।¹

अनुपातिक पन्शन पर सेवा निवृत्ति एक बठोर शास्ति है। परन्तु बर्खास्तगी से बचने के लिए जब कि राज्य कर्मचारी ने स्वयं स्वच्छा से अनुपातिक पन्शन पर रिटायर होने का विकल्प लिया, तो फैसला हुआ कि इसमें जाच विठाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कर्मचारी ने दो बुराइयों में से कम हानिकार बुराई को चुना और वह उसके परिणामों में विजय था।²

(3) सेवा से हटाना—सेवा से हटाया जाना एक बठोर शास्ति है, परन्तु इससे राज्य कर्मचारी को पुनः सेवा में लिए जाने पर रोक नहीं लगती अर्थात् वह अनहित नहीं होता। राज्य सेवाओं के सदस्य पर यह शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोकर सेवा आयोग से परामर्श कर लेना चाहिए। यह शास्ति बर्खास्ती से भिन्न है क्योंकि बर्खास्तगी से साधारणतः कर्मचारी पुनः नियोजन के लिये अनहित (disqualified) हो जाता है।³

रेलवे के एक टी टी ई को सेवा से सही हटाया गया जब कि उसने कतिपय यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी।⁴ बिना अनुमति के कार्य से अनुपस्थिति या अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद भी काम पर नहीं आने से उक्त दण्ड दिया जा सकता है।⁵ जब कि एक पुलिस उप निरीक्षक को दैनिक रोजनाम में पर्जी इम्प्राज करने के कारण सेवा से हटा दिया गया तो ऐसा करना वैध निर्णीत हुआ।⁶ जब कि एक राज्य कर्मचारी ने व्यापार करना प्रारम्भ कर दिया जो कि राजकीय नियमों में प्रतिषूचन था तो उनको नौकरी से हटाया जाना सही ठहराया गया।⁷ जब कि रेलवे के परिसर में सभाएँ करना निषिद्ध था, फिर भी प्राची द्वारा ऐसी मीटिंग बहा करने पर उसे यह शास्ति दी गई तो अदालत ने उसे वैध माना।⁸ जब एक राज्य कर्मचारी ने नगरपालिका का चुनाव लड़ा, तो उसे नौकरी में निवासना मही था।⁹ स्थानान्तर होने पर काम पर नहीं जाने से,¹⁰ और टेरीफोन अवतन करने में अनियमितता के लिए¹¹ इसी प्रकार की शास्ति मही मानी गई।

1. AIR 1962 इनाहावाद 328—रामावनार पाण्डे वि यू पी सरकार।
2. AIR 1957 आगाम 77—आगाम सरकार वि एच बक्ष्मा।
3. AIR 1975 मुन्नीम कोट 1964 1975 ASR 370—मोहम्मद अब्दुल ननाम खों वि मफराज महमद याँ।
4. AIR 1971 इनाहावाद 246—भारतीय सघ वि ओ एस जोहरी 1970 SLR 874 (इनाहावाद)।
5. AIR 1966 मुन्नीम कोट 492—जयशंकर वि राजस्थान सरकार।
6. AIR 1961 मध्य प्रदेश 365—एन एन पाठक वि मध्य प्रदेश सरकार।
7. AIR 1971 निपुग 21—ए मी भीतम वि त्रिपुरा का अरबन ट्रस्ट।
8. AIR 1969 मुन्नीम वाटें 966—रेलव मण्डल वि निरजन सिंह।
9. AIR 1960 कनकता 283 एन एन बनर्जी वि वरिष्ठ डिप्टी ए जी।
10. 1971 SLR 730 (पान्द्र प्र) एन वाई स्वामी वि विदेनर राज्य विदेनर राज्य।

इसने विपरीत जब कि हड़ताल में भाग लेने का आरोप था, परन्तु यह माहित नहीं था कि हड़ताल सावजनिक शान्ति में बाधा डालने वाली थी, तो मेवा से हटाने का आदेश निरस्त किया गया।¹ जब कि प्रार्थी न अपने पिता का वश मीनो किया परन्तु कर्मचारी के विरुद्ध व्यापार या व्यवसाय करने का आरोप साबित नहीं हुआ, तो उनकी शान्ति का आदेश जारी किया गया।²

नियम 14 के स्पष्टीकरण 1 (vii) के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाहियाँ शान्ति स्वरूप नहीं मानी जाएगी :—

- (1) परीक्षण पर नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति, परीक्षण की अवधि में या उसके खतम होने पर, या
- (2) स्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति, नियोजन अवधि समाप्त होने पर, परन्तु यह सविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, या
- (3) किसी इस्तरार के अधीन नियोजित सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्ति, यदि यह समाप्ति उस इस्तरार की शर्तों के अनुसार है या
- (4) ऐसे राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति जो राजस्थान में सम्मिलित होने वाली किसी इकाई की सेवा में था और जिसका चुनाव या सविलीनीकरण सम्मिलित राजस्थान की किसी भी मेवा में एकीकरण के नियमों के अनुसार नहीं हुआ। परन्तु यदि उस किसी अन्य कारण से सेवा-मुक्त कर दिया हो तो वह सेवा से हटाया जाना या बर्खास्तगी, जैसी कि स्थिति हो, मानी जाएगी।

(1) परीक्षणार्थी की सेवा समाप्ति —जब कि एक 'अनीपचारिक' जांच केवल यह तय करने के लिए की गई कि शायद, किसी परीक्षणार्थी विशेष (Particular probationer) की सेवा में रखा जाव या नहीं और उसके बाद उसका सेवा से मुक्त करने का आदेश जारी हुआ, तो उससे उसके प्रति कोई बुरे परिणाम घटित नहीं हुए। ऐसे मामले में वह कर्मचारी सविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानानुसार पूरी जांच कराने का दावा नहीं कर सकता।³ परीक्षण पर रखने का प्रयोजन केवल यह होता है कि पदधारी के आचरण तथा योग्यता की जांच करनी जावे। परीक्षण की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी वह अधिकार रूप में स्थाई किया जाने का दावा नहीं कर सकता। स्थाई करने के स्पष्ट आदेश के अभाव में वह स्थाई किया जाना ममके जान का दावा नहीं कर सकता। इन विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने सुलवश सिंह⁴ व पञ्जाब सरकार⁵ में एक बिस्तृत निर्णय दिया है। यदि किसी परीक्षणार्थी को दुराचरण के कारण दण्डित किया गया हो तो सविधान के अनुच्छेद 311 (2) की अपेक्षाएं पूरी करनी आवश्यक होंगी जैसा कि पुरुषोत्तम लाल धीगडा वि. भारतीय सच में निरूपण हुआ था।⁶ अतः मामूली तौर से, ग्राम मामलों में परीक्षण पर रखे गए कर्मचारी को अपने पद पर

1 AIR 1964 पञ्जाब 143—एम एल कान्धारी वि भारतीय सच।

2 1967 ALJ 608—चन्द्र मिशर वि यू पी के ए जी।

3 AIR 1977 पञ्जाब व हरियाणा 7. 1977 Lab IC 345—विश्वनाथ गुप्ता वि हरियाणा सरकार।

4 AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट—1711

5 AIR 1958 सुप्रीमकोर्ट—36

बन रहने का कोई अधिकार नहीं है और वह परीक्षण की अवधि में बर्ती भी, लागू नियमों के अधीन रहते, हटाया जा सकता है।¹ कैलाश चन्द्र मेडिया वि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल² में, न्यायमूर्ति पी एन सिंघल ने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जी. एस. रामास्वामी वि आई जी पुलिम में दिए गए फैसले का अनुसरण करते हुए, मत प्रकट किया कि,—"परीक्षण अवधि की समाप्ति के पश्चात्, परीक्षणीयमाण (प्रोवेनर) स्वतः, सेवा के म्याई सदस्य की हैमियत प्राप्त नहीं करता, नि.सदेह, जब तक, कि जिन नियमों के अन्तर्गत उसे नियुक्ति मिली थी, उनमें ऐसा परिणाम स्पष्टतः प्रावधानित न हो। इसलिए, यद्यपि प्रोवेनर अपनी परीक्षण कालीन नियुक्ति के पद पर, परीक्षण की प्रारम्भिक अवधि से भी अधिक समय तक संचालित रहा हो तथापि केवल समय निकल जाने के आधार पर ही वह सेवा का हवाई सदस्य नहीं बन सकता जब तक कि उसका शामिल करने वाले सेवा के नियमों में यह साफ तौर से निर्धारित नहीं किया गया हो कि प्रारम्भिक परीक्षण काल बीत जाने के पश्चात् वह स्वतः, हवाई हो जाएगा।" उच्चतम न्यायालय ने एक बाद के मामले, कंदारनाथ, बहल वि पंजाब सरकार³ में और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मे एस्ट्रेमा वेटीज वि बि यू पी सरकार⁴ में भी यही मत धारण किया।

अनः परीक्षणार्थी (प्रोवेनर) को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों को आर्क्षित किए बिना परीक्षण की अवधि में वह बर्ती भी सेवा से हटाया जा सकता है।⁵ इसी फैसले में यह मत भी प्रकट किया गया कि जब पदमुक्ति के आदेश में कार्य 'अमनोपजनक' उल्लिखित था तो उसे बलक रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रार्थी की नियुक्ति की शर्तों में साफ उल्लिखित था कि यदि उसका काम 'अमनोपजनक' पाया गया, तो वह नोकरी से हटाया जा मनेगा। इसके, अनिदित, प्रार्थी की सेवा समाप्त करने का निर्णय लेने में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को किसी सारहीन असंबद्ध (irrelevant) तथ्यों ने प्रभावित नहीं किया, इसलिए यह मामला शक्ति के दुषपयोग का नहीं था। सेवा मुक्ति के आदेश की विरुद्ध जानने के लिए केवल आदेश का रूप पूर्णतः निष्कर्ष बनाने वाला नहीं था। यह सम्भव है कि आदेश दुराचरण के कारण बर्त्तामगी है परन्तु ऊपरी दिग्वासे से साधारण सेवा ममानि प्रतीत होती है। इसलिए टिक्खूनन जब चाहे तब आदेश के रूप के पीछे जाकर उसके तथ्यों की छानबीन कर सकती है। यदि वह इस मत पर पड़वे कि मात्र सेवा मुक्ति के भेप में आदेश दुराचरण के आधार पर बर्त्तामगी है तो उसे "कपटपूर्ण तरीके से शक्ति का प्रयोग" मानते हुए गारिज करना चाहिये।⁶

असाई राज्य कर्मचारी की सेवा समाप्ति-नियम 14 के स्पष्टीकरण (1)(vi) (क) के अनुसार बिग कर्मचारी को असाई रूप में बिना किसी सदिया के नियुक्त किया गया हो, उसकी सेवा, नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर, समाप्त की जा सकती है। उसे सेवा से हटाया जाना नहीं माना जायेगा।

1. AIR 1963 मुम्बई नोट 1552-गजेन्द्र भी उटर्जी वि नागनीय सप।

2. 1973 WLN 389, 1973 RLW 544.

3. AIR 1972 SC 873

4. FLR 1979 (38) 373.

5. 1973 WLN 389-कैलाश चन्द्र मेडिया वि राज गज विद्युत मण्डल।

6. 1977 WLN 461.

सतीशचन्द्र आनन्द वि. भारतीय सघ¹ में सर्वोत्तम न्यायालय न मत व्यक्त किया कि अस्थाई प्रकार के कार्यों के लिए, किसी अन्य नियोजक के समान, सरकार अस्थाई रूप में नियोजित कर्मचारियों के साथ सेवा की विशेष सविदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में जब कि अस्थाई सेवा अर्धस्थाई सेवा में परिवर्तित नहीं हुई हो तो ऐसे नियोजन की समाप्ति से कर्मचारी के किसी अधिकार का हनन नहीं होता और वह अपने आप में कोई दण्ड नहीं होता। अतः निम्नलिखित मामलों में अस्थाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति दण्ड-स्वरूप नहीं मानी गई और उससे सविधान का अनुच्छेद 311(2) आक्रामित नहीं हुआ :—

- (1) सेवा के पदों की संख्या में कमी करने से।²
- (2) कर्मचारी द्वारा धारण किये हुए पद की समाप्ति।³
- (3) सम्बन्धित सरकारी योजना का उन्मूलन।⁴
- (4) कर्मचारी वर्ग की समाप्ति।⁵
- (5) कॉलेज से किसी विषय को हटाना।⁶
- (6) जब कर्मचारी विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेता था।⁷
- (7) जब पद अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किया गया।⁸
- (8) जब कर्मचारी की पूर्ववालीन रिपोर्टें सतोषजनक नहीं थी।⁹
- (9) जबकि कर्मचारी पहले स मजायाप्ता था-जो सूचना बाद में ज्ञात हुई।¹⁰

केवल साधारण सेवा समाप्ति, जो राजस्थान सेवा नियमों के नियम 23(क) के अन्तर्गत आती है वह सविधान के अनुच्छेद 311 में प्रयोगित अभिव्यक्ति 'पद से हटाया जाना' के अन्तर्गत नहीं आती। अतः, राजस्थान सरकार द्वारा अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका 1963 अनु 17(xi) में दिये गये निर्देशानुसार, जो ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं, किसी अस्थाई राज्य कर्मचारी की सेवा किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है और ऐसी समाप्ति के कारण, उदाहरणतः दुराचरण या अनुशालता उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है।

इसके विपरीत, मयगुदा अवधि से पहले सेवा समाप्त करना दण्ड देने का कार्य करती है।¹¹ प्रारम्भ में प्रार्थी की नियुक्ति छ, महीने के लिए की गई थी। उसके बाद, समय समय पर यह अवधि बढ़ाई जाती रही और तत्पश्चात् आगे का कोई नियोजन काल निश्चित नहीं किया गया। अचानक,

1. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 250
2. AIR 1958 SC 419
3. AIR 1955 पटना 353
4. AIR 1957 पटना 555
5. AIR 1957 हैदराबाद-12
6. AIR 1965 इलाहाबाद-252
7. AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 232
8. AIR 1955 नागपुर-289
9. AIR 1965 केरल 19
10. 1965 RLW-7—ईश्वरी प्रसाद वि राज राज्य
11. AIR 1963 आसाम 94—एस बी निवारी वि भारतीय सघ।

एक दिन, लोक सेवा आयोग द्वारा नही चुने जाने के आधार पर, तत्कालिक प्रभाव से सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। इस मामले में निर्णायक हस्ता कि उपरोक्त परिस्थितियों में यह नही कहा जा सकता कि नियुक्ति निश्चित अवधि के लिए थी। अतः ऐसी अस्थाई नियुक्ति के लिए सविधान का अनुच्छेद 311 अप्रतिष्ठित है।¹

एक राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य स्थान पर किया गया, जिस आदेश का उसने पालन नही किया और चिन्तित करने के आधार पर रियायती छुट्टी (Privilege leave) के लिए आवेदन किया। उसने अवकाश में आगे बढ़ाया भी प्राप्त की, परन्तु अन्तिम अवस्था में, और अवकाश बढ़ाने के लिए दिया गया आवेदन नामज़ूर किया गया और उसे आदेश हुआ कि वह अपने वर्तमान-स्थल पर पद ग्रहण करें, अन्यथा उसकी नौकरी समाप्त होनी समझी जाएगी। इस मामले में फैसला हुआ कि उसकी सेवा का समापन दण्ड स्वरूप नही था और उससे सामान्य न्याय के सिद्धान्तों का प्रयोग अप्रतिष्ठित नही हुआ।² परन्तु, जतीन्द्र मोहन साहा वि निदेशालय, स्वास्थ्य, सेवाएँ³ में, कर्मचारी का सूचित किया गया कि उसको निरन्तर अनुपस्थिति के कारण और पूरा देय अवकाश खत्म होना के पश्चात्, उसकी सेवा समाप्त होनी समझी गई है। किन्तु उसकी सेवा समापन करने का कोई वास्तविक आदेश जारी नहीं हुआ। इसमें निर्णायक हस्ता कि सरकार उसकी सेवा समाप्त करने के लिए सहमत थी परन्तु तब तक वह राज्य कर्मचारी हाना समझा जाएगा और उसकी नियमों के अनुसार देय वेतन तथा उपलब्धियाँ (emoluments) मुफ्तान करने होंगे।

(iii) इकरार के अनुसार सेवा समाप्ति नियम 14 के स्पष्टीकरण (1) (vii) (ग) के अनुसार, शास्ति नही होगी। सरकार को अधिकार है कि वह अस्थाई कर्मचारियों के साथ भी सेवा की विशेष सविदा कर सके।⁴ परन्तु ऐसी सविदा की शर्तें सविधान के किसी प्रावधान को उल्लंघन करने वाली नही होनी चाहिए।⁵ सरकार भी ऐसी सविदाओं की शर्तों से बाध्य है।⁶ जब कि इकरार में एक निश्चित अवधि तय हो चुकी है, तो इस प्रकार के अस्थाई कर्मचारी की सेवा, अवधि के अन्त हान पर, समाप्त हो जाएगी। ऐसी दशा में एक महीने के नोटिस की आवश्यकता नही है। पहलु जब कि अवधि अनिश्चित है, तो एक मासिक का प्रश्न उठेगा।⁷ ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी ज़रूरी नही है। इकरार की शर्तों के अनुसार सेवा समाप्ति से कोई शास्ति नही होगी।⁸

इसके विपरीत जब कि नुराचरण के आधार पर जांच करने के पश्चात् कर्मचारी को हटाया जावे, तो सविधान का अनुच्छेद 311 लागू हो जाएगा, यद्यपि साधारणतः सेवा के इकरार के अनुसार, किसी भी पार्टी द्वारा एक महीने का नोटिस देना पर्याप्त था। सेवा समाप्ति का प्रश्न मामले की परिस्थितियों और आदेश के शब्दों से समझना चाहिए।⁹

1 AIR 1952 पेपर्स 148—ईश्वरदास नेहता वि पेपर्स सरकार।

2 AIR 1962 पटना 452—डा. परमानन्द वि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड।

3 AIR 1963 कलकत्ता 638

4 AIR 1955 इलाहाबाद 496 आरदा प्रसाद वि ए. जी।

5 AIR 1957 कलकत्ता 700 पतिल वाभन वीम वि कमीशनर।

6 AIR 1953 मुम्बई कोर्ट 250—सतीश चन्द्र वि. भारतीय सच।

7 AIR 1962 भुवनेश्वर 52—वीरम गौरीसिंह वि भारतीय गणतन्त्र।

8 AIR 1960 कलकत्ता 549—आर. घाघ वि दामोदर बेली कॉर्पोरेशन।

9 AIR 1957 इलाहाबाद 408—डा. मेनन वि डाइरेक्टर, हरियाणा वेलफेयर।

(iv) एकीकृत योजना में सेवा की समाप्ति के विषय में नियम 14 के स्पष्टीकरण (1) (vii) (घ) में खुलासा किया गया है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि कोई ऐसा कर्मचारी है जो राजस्थान में सम्मिलित होने वाली किसी इकाई की नौकरी में था परन्तु जिसका चुनाव या सविनोदीकरण सम्मिलित राजस्थान की किसी सेवा में एकीकरण के नियमों के अनुसार नहीं हो सका हो, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी और ऐसा करना शास्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(4) सेवा से बर्खास्तगी — बर्खास्तगी अंतिम तथा कठोर शास्तियों में से कठोरतम दण्ड है, क्योंकि आधारगत इसके दूरगामी परिणाम होते हैं, उदाहरणतः भावी नियोजन के लिए अयोग्यता, पेंशन की हानि, आदि। नियम 14 के नीचे दिये गये नोट के अनुसार भविष्य में नौकरी पर प्रतिबन्ध केवल राज्य सरकार द्वारा, मामले के गुण-भवगुणों को देखते हुए यदि उचित समझा जावे तो हटाया जा सकता है। राज्य सेवाओं के सदस्यों के मामले में यह शास्ति आरोपित करने से पहले अनुशासन प्राधिकारी द्वारा लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। यह शास्ति अनुशासन प्राधिकारी लागू कर सकता है। विभिन्न सेवाओं के लिए अनुशासन प्राधिकारी कौन है इसके लिए नियम 15 में प्रावधान है।

उक्त कठोर शास्ति लागू करने के लिए अनुशासन प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शन के लिये कोई निश्चित नियम नहीं है। यह उनके न्यायिक स्व विधिक पर निर्भर करता है। परन्तु वे पूर्वकालीन फैसलों से सहायता ले सकते हैं। सर्व प्रथम तो यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि शास्ति लागू करने से पूर्व सत्रिधान के अनुच्छेद 311 (1) और (2) की शर्तों का दृढ़ता से अनुसरण किया जावे। आमतौर से, न्यायालय किसी आरोप विशेष के लिये लागू की गई शास्ति के औचित्य पर नहीं जाते, परन्तु जांच के संचालन में अपनाई गई प्रक्रिया में त्रुटि होने के आधार पर शास्ति का आदेश बिलम्बित किया जा सकेगा।

कतिपय निर्णय इस प्रकार हैं —

सार्वजनिक धन का निजी उपयोग और कार्य से अनुपस्थिति,¹ रिश्वत लेना,² तथा कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही,³ गलत हिसाब रखना और सरकारी अभिलेखों में वाट-छाट करना,⁴ कर्मचारी के पाम आमदनी स्रोतों से अत्यधिक अनुपात से सम्पत्ति मिलना,⁵ विश्वविद्यालय के किसी राजकीय विद्यार्थी द्वारा परीक्षक के रूप में कार्य करत हुए रिश्वत स्वीकार करना,⁶ रिश्वत की मांग करना,⁷ बाबिल दस्तन्दाजी पुलिस की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं करना,⁸ ये सब ऐसे मामले हैं जिनमें सेवा से बर्खास्तगी की कठोरतम शास्ति लागू करना उपयुक्त है।

1. AIR 1962 आसाम-28

2. 1970 SLR (173) (रास्थान)

3. AIR 1965 मैसूर-283.

4. AIR 1962 केरल-43

5. AIR 1962 आसाम 17 तथा AIR 1970 गुजरीम कोर्ट-1255

6. AIR 1970 गुजरात-97.

7. AIR 1956 मद्रास-613.

8. AIR 1970 गुजरीम कोर्ट 1255

इसी प्रकार बुकिंग ऑफिस में टिकटें गायब होने से,¹ भ्रष्ट व्यक्ति की सहायता करके उसकी 55 रु सरकारी कोष से दिलवाने के लिए² नाजायज तौर से वृक्ष उखाड़े जाने पर रिपोर्ट नहीं करने के कारण,³ जो सरकारी सम्पत्ति कर्मचारी के प्रभार में थी, उसकी पर्याप्त सुरक्षा नहीं करने के कारण चोरी हो जाने के आधार पर,⁴ ऐसा व्यवहार करना जो अधिकारी के लिए शोभनीय न हो,⁵ नौकरी की परिधि के बाहर ऐसा दुराचरण जो अत्यन्त अनैतिक हो,⁶ कर्तव्यपालन में विफल होने के कारण तथा किसी स्त्री के साथ शैरकानूनी सम्पर्क बनाने के आधार पर तथा सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग करने व किसी के साथ पक्षपात करने एवं पर्जों यात्रा भत्ता विल प्रस्तुत करने कारण,⁷ रिश्वत प्राप्त करना तथा अपने नियन्त्रण तथा क्षेत्राधिकार के जगल से लकड़ी प्रबंध रूप से ले जाने में सहायता देने के कारण,⁸ और पाठशालाओं के जिला निरीक्षक का महिला अध्यापिकाओं के साथ व्यक्तिगत अनैतिक सम्बन्ध के आधार पर,⁹ बर्खास्तगी का दण्ड देना न्यायोचित ठहराया गया ।

जबकि एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दुर्य्यवहार का आरोप स्थापित हुआ और उसे सेवा में बर्खास्त कर दिया गया तो यह निर्णय हुआ कि दण्ड के औचित्य का विषय न्यायालय से सम्बन्धित नहीं था ।¹⁰ किन्तु एक अन्य मामले में अनुशासन प्राधिकारी (कलेक्टर भिलवाड़ा) ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को बर्खास्त करना प्रस्तावित किया, और तदनुसार, उसे नोटिस जारी किया परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् उसे कर्तव्यपालन में लापरवाह पाया गया और उस पर सचित प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियां रोकने की शास्ति लागू की । परन्तु राजस्व मण्डल के अध्यक्ष ने इन नियमों के नियम 32 के अधिकारों का उपयोग करते हुए, प्रार्थी को शास्ति बढ़ाने का नोटिस देने के पश्चात्, उसके स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए शास्ति को कठोर बना कर उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया । प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार को की गई अपील भी विफल हो जाने पर, वह सविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय में पहुँचा । प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि एक गवाह गौरीशंकर के साथ उसको जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया और उसका बयान भी उसकी उपस्थिति में अभिलिखित नहीं किया गया, इस कारण से अध्यक्ष डा.ग. गौरीशंकर की गवाही पर आधारित होना गलत था । इस दलील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति श्री डी पी गुप्ता ने निर्णय दिया कि गौरीशंकर ने कथित बयान, एक अन्य दोषी कर्मचारी के विरुद्ध, अन्य जांच अधिकारी के समक्ष प्रार्थी के पीछे पिछे दिया था, जिस पर प्रार्थी को जिरह करने का कतई कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ।

1. AIR 1960 केरल-224

2. AIR 1966 पंजाब-175

3. AIR 1967 मध्य प्रदेश-207.

4. AIR 1967 बम्बई-332.

5. AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट-679.

6. 17 M.D. 536.

7. 1971 ALJ 324.

8. AIR 1964 केरल-87.

9. 1971 ALJ-324

10. 1977 WLN 645-राजस्थान सरकार वि. दानमल ।

भीलवाडा कलेक्टर द्वारा प्रार्थी पर आरोपित शास्ति को कठोरतम बनाने के लिए इस प्रकार के बयान का आधार नहीं लेना चाहिए था। अतः राजस्व मण्डल द्वारा जारी किया गया नोटिस तथा शास्ति का आदेश और राज्य सरकार द्वारा पारित अ देश भी खारिज किया गया।¹

15 अनुशासनिक प्राधिकारी:—(1) राज्य सेवाओं के लिए, सरकार या सरकार द्वारा उस विषय में विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी अधीनस्थ सेवा के लिए विभागाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, और त्रिपिण्ड र्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के लिए कार्यालयीय अध्यक्ष नियम 14 में निर्दिष्ट सभी शक्तियां देने के लिए प्राधिकृत होंगे।

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियुक्ति और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल प्रशामी न्यायाधीश या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिवक्ता द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश को, उपर्युक्त नियमों के अधीन विहित शास्तियों में से सेवा से हटाये जाने तथा पदच्युति की शास्ति के सिवाय, कोई शास्ति,* [राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा और] राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं।

(2) जिन राज्य सेवाओं के संबंध में, जिनमें नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंपी गयी हो, परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के अतिरिक्त शास्ति लगाने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

राजस्थान सरकार का निर्देश

“ऊपर बताई गई शक्तियां दो श्रेणियों में विभाजित की गई हैं, नामार्थ कठोर तथा लघु और प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक प्रक्रिया प्रावधानित की गई है। ऐसा संविधान की अपेक्षाओं का पालन करने के लिए किया गया है। दो कठोर शास्तियां, अर्थात् सेवा से बर्खास्ती और हटाये जाने की लागू करने के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को ऐसा कोई भी प्राधिकारी बर्खास्त या सेवा से नहीं हटा सकेगा जो वास्तव में उसको नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से अधीनस्थ स्तर का था। यह सर्वमान्य सरक्षण कानूनी नियमों द्वारा छीना नहीं जा सकता। ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ कौन है यह ज्ञात करने के लिए औपचारिक दस्तावेज का अवलोकन करना बाधित होगा। यदि विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति स्थाई रूप से किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरण कर दिया गया हो तो वह केवल अन्य विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ही बर्खास्त या सेवा से हटाया जा सकेगा।² परिश्रमार्थी (प्रोवेशनर) हो तो, इसका भूल नियुक्ति के विषय में स्थाई करने वाला प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से ऊपर के दर्जे के प्राधिकारी पर भी उस व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने के लिए कोई रोक नहीं है। परन्तु

1 1975 WLN 8 हमने लाल वि राजस्थान सरकार।

*विज्ञप्ति में GSR 27 में F 3 (4) App'ts (A III) 72 दिनांक 24 सितम्बर 1973 द्वारा मशोधित जो राजस्थान राजपत्र दि 17 अप्रैल, 1975 में पृष्ठ 30-31 पर प्रकाशित हुई।

2 AIR 1967 राजस्थान 148.

माधारण उच्च प्राधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें नियमों के अधीन उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का कर्मचारी का हक मारा जाता है। एवं दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु इस विषय में ध्यान देने योग्य यह है कि किसी भी दोषी कर्मचारी को पूर्ववासीन प्रभाव से, सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जा सकता।”

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहीयो की पुस्तिका 1963 अनुच्छेद 17 (III)]

टिप्पणी

नियम 15 अनुशासन प्राधिकारियों की शक्ति के विषय में है। नियम 2(ग) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी पर शास्ति लागू करने के सम्बन्ध में “अनुशासन प्राधिकारी” वह प्राधिकारी है, जो उस पर उक्त शास्ति लागू करने में सक्षम हो। अभिव्यक्ति ‘नियुक्ति प्राधिकारी’ की परिभाषा नियम 2(क) में दी गई है और उसकी शक्तियां नियम 12 में उल्लेखित हैं। नीचे की तालिका विभिन्न वर्गों की सेवाओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासन प्राधिकारी और प्रत्येक श्रेणी के अनुशासन प्राधिकारियों द्वारा लागू की जा सकने वाली शास्ति बतायेगी :—

क्रमांक	सेवा की श्रेणी	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासन प्राधिकारी	शास्ति जो वह लागू कर सकता है
1	2	3	4	5
1.	राज्य सेवार्थ, राजस्थान न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त	(ग) राज्य सरकार अर्थात् राज्यपाल) (ख) सरकार द्वारा विशेषतः शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी	(क) राज्य सरकार (अर्थात् राज्यपाल) या (ख) सरकार द्वारा विशेषतः प्राधिकृत प्राधिकारी	नियम 14 में निर्दिष्ट सभी शास्तिमा।
2	अभिनव्य सेवाएँ	(क) विभागाध्यक्ष या (ख) विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेषतः प्राधिकृत प्राधिकारी	(क) विभागाध्यक्ष या (ख) विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार के अनुमोदन से विशेषतः प्राधिकृत प्राधिकारी	” ”
3	लिपिक वर्गीय सेवाएँ	कार्यालयाध्यक्ष, जो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देशों व नियमों के अधिनस्थ रहेंगे	कार्यालयाध्यक्ष	” ”
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	” ”	”	” ”

1	2	3	4	5
5	राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा तथा राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सदस्य	(क) राज्यपाल या (ख) राजस्थान उच्च-न्यायालय	राज्यपाल या राजस्थान उच्च न्यायालय का प्रशासनिक न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत न्यायाधीश ।	राज्यपाल नियम 14 में निर्दिष्ट समस्त शास्तिया लागू कर सकता है, परन्तु वह न्यायाधीश जिसको अनु-शासन प्राधिकारी की शक्तिया प्रत्या-वर्तित की गई हो वह सेवा से हटाने या बर्खा-स्तगी की शास्ती लागू नहीं कर सकता ।

राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा के सदस्यों पर शास्तिया आरोपित करने के विषय में आन्तरिकीय वि. राजस्थान सरकार¹ के मामले पर ध्यान देना उपयुक्त है । इस मामले में निम्नांकित बिन्दु तय किए गए —

- (1) यह कि संविधान प्रभावित होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायिक सेवा पर, अनुशासनीय नियन्त्रण पूर्णतः, 'उच्च न्यायालय' में निहित है, न कि किसी अन्य प्राधिकारी में
- (2) यह कि शब्द 'उच्च न्यायालय' से अभिप्राय मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से है जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे अर्थात् पूरा न्यायालय (संविधान का अनुच्छेद 216) अतः अकेला मुख्य न्यायाधीश या प्रशासनीय न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल द्वारा प्रत्यावर्तित कोई भी न्यायाधीश अथवा न्यायिक सेवाओं के किसी सदस्य के लिए वैध रूप से अनुशासन प्राधिकारी की भूमिका अदा नहीं कर सकता ।
- (3) यह कि एक अनेक न्यायाधीश द्वारा अनुशासन प्राधिकारी की हैसियत से की गई कार्यवाही का तत्पश्चात् सत्यापन या अनुमोदन राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या यहाँ तक कि पूरे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं किया जा सकता । संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा पहले से निर्मित प्राधिकारी के समानांतर कोई अन्य प्राधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता ।

अब ऐसे मामलों से निपटने के लिए पूरे राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 30 अक्टूबर, 1971 को निम्नलिखित सक्त्प ग्रहण किया है:—

“भारतीय सविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन सत्र न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण, जिसमें सत्र न्यायाधीशों के पदधारियों को तैनाती (प्रोविस्टिंग) और पदोन्नति और अवकाश स्वीकृति सम्मिलित हैं, उच्च न्यायालय में निहित हैं। अतः सत्र न्यायालयों तथा उसके अधिनस्थ न्यायालयों के पीठाध्यक्षों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित है, जो सविधान के अनुच्छेद 235 के अन्वय प्रावधानों तथा अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अधीनस्थ है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम, 1958, जो ऐसे मामलों के लिए वर्तमान में प्रावधान करते हैं, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये हैं और इसलिए वे, जहाँ तक सविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों से असंगत हैं, वहाँ तक सत्र न्यायालयों और उसके अधिनस्थ न्यायालयों के पीठाध्यक्षों पर लागू नहीं हो सकते।

“अनुच्छेद 235 के अधीन नियन्त्रण पूरे न्यायालय में निहित है, परन्तु चूँकि पूरे न्यायालय के लिए ऐसे मामलों में कार्यवाही करना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए उसमें द्वारा शक्तियों का निम्नलिखित पर्यावर्तन (डेलीगेशन) किया जाता है:—

×

×

×

×

प्रशासकीय न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनौपचारिक न्यायाधीश को अधिकार होगा कि वह न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सके और सेवा से हटाने या बर्खास्त करने के अतिरिक्त राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियम, 1958 के नियम 14 में निर्दिष्ट अन्य कोई भी शास्ति आरोपित कर सके।”

इस सम्बन्ध में सविधान के अनुच्छेद 311 (1) के प्रावधान का सदैव ध्यान रखना चाहिए जिसके अनुसार—

“जो व्यक्ति सभ की असेनिक सेवा का तो अलिल भारतीय सेवा का या राज्य की असेनिक सेवा का सदस्य है, अथवा सभ के या राज्य के अधीन असेनिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जावेगा।”

राजस्थान सरकार ने भी अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका में अनुच्छेद 17 (iii) द्वारा इस बिन्दु पर बल दिया है, जो ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। यह साफ बतला दिया गया है कि सर्वप्रधानिक सरक्षण कानूनी नियमों द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। यह सुझाव दिया गया है कि किसी दोषी पदाधिकारी के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी कीन है, यह निश्चित करने के लिए दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए। यदि किसी विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्ति व्यक्ति का तबादला स्थाई रूप से किसी अन्य महकमे में कर दिया गया हो तो उसकी बर्खास्तगी या सेवा से प्रवृत्तीकरण उक्त अन्य विभाग का केवल विभागाध्यक्ष ही कर सकेगा।¹ परिक्षणार्थी (Probationers) होने की स्थिति में कर्मचारी की मूल नियुक्ति के सम्बन्ध में उसको स्थाई करने वाला प्राधिकारी कर्मचारी का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। किसी कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने वाले से उच्चतर प्राधिकारी, नि सन्देह, सेवा से हटाने या बर्खास्तगी की सीमा तक असेनिक कर्मचारी को दण्ड दे सकेगा। परन्तु साधारणतः

उच्चतर प्राधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नियमा द्वारा प्रदत्त दोषी कमचारी का अपील करने का अधिकार मारा जाएगा। इस बात पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी दोषी कमचारी को पूर्ववर्तीन प्रभाव से सवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा। एवं और महत्वपूर्ण यह मुद्दा विचारणीय है कि जब नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासन प्राधिकारी अलग-अलग व्यक्ति हों तो अनुशासन कमचारी सवा से हटाने और बर्खास्त करने के विषय में अपनी शक्तियां लागू कर सकता है। सवा से हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही आरोपित कर सकेगा। उदाहरण के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सेनाओं के किसी सदस्य को केवल राज्य सरकार ही हटा सकती है या बर्खास्त कर सकती है और उससे नीचे का कोई प्राधिकारी नहीं कर सकता। इन्हीं सिद्धान्तों पर, यदि किसी अधिकारी के सदस्य के विषय में जिसको विभागाध्यक्ष ने नियुक्त किया था, परन्तु जिसकी जांच किसी प्रतिपादित (delegated) प्राधिकारी ने संचालित की थी तो अनुशासन प्राधिकारी उसके विरुद्ध सवा से हटाने या बर्खास्तगी के अलावा अन्य कोई शक्ति लागू कर सकेगा।

उप नियम (2) लोक सेवा आयोग से परामर्श—लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा—

(1) जबकि निम्नलिखितों में से कोई शक्ति किसी राज्य सेनाओं के सदस्य पर आरोपित की जा रही हो —

- (क) पदोन्नति रोकना,
- (ख) सरकार का पदुच ई गई कोई अधिक हानि की कोई पूर्णतः या आंशिक बसूरी,
- (ग) निम्नतर सवा ग्रेड या पद या निम्न वेतनमान में या उसी वेतनमान में नीचे के स्तर पर पदानवधि करना या नियमों के अधीन देय पेशन की राशि में कमी करना
- (घ) अनुपातिक पेशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,
- (ङ) सेवा से हटाना,
- (च) सेवा से बर्खास्तगी।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब राज्य सेनाओं के किसी सदस्य के विरुद्ध वेतन वृद्धि या राकने का ही प्रस्ताव हा तो लोक सेवा आयोग से परामर्श करना जरूरी नहीं होता।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस विषय पर मतभेद था कि आया सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) में निर्धारित लोक सेवा से परामर्श करना आदेशात्मक (मंडेटरी) है या केवल निर्देशात्मक (Directory) ताकि आयोग से परामर्श नहीं करने की दशा में शक्ति का आदेश अवैध नहीं हो। परन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यू पी सरकार वि. मोहनलाल¹ में दिए गये फैसले से मतभेद का समाप्ति हो गई है। यद्यपि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों में ऐसा प्रावधान है तथापि वह आदेशात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) के अधीन बनाया गया है।²

1 AIR 1957 सुप्रीमकोर्ट 912, यह भी देखिए —AIR 1962 सुप्रीमकोर्ट 1344—यू प्रार भट्ट वि. भारतीय सच।

2 AIR 1971 सुप्रीमकोर्ट 749 तथा AIR 1971 सुप्रीमकोर्ट 2004

यद्यपि उक्त प्रावधान केवल निर्देशात्मक है तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्राधिकारीण अपनी स्वेच्छा में जब चाहे तब इसकी अवहेलना कर सके। सभी मामलों में लोक लेबा आयोग से परामर्श करना चाहिए और उसका परिचाय केवल अपवादात्मक मामलों में ही किया जा सकेगा जिसके लिए वारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। नियमित रूप से इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।¹ आदर्शकुमारी भारती वि. के एन. मिन्हा² में यह तम किया गया है कि कार्यकारीणी सरकार को यह स्वतन्त्रता नहीं है कि वह पूर्णतः आयोग की अवहेलना करे और जहाँ नियमित रूप से नियम बने हुए हों, तो उनका पालन पूर्णतः किया जाना चाहिए।

विकास अधिकारियों के विरुद्ध लघु शास्तिया आरोपित करने के विषय में निम्नलिखित पृथक् तथा विशेष आदेश दिये गये हैं—

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(क III)

अधिसूचना सत्या प 9 (18) कार्मिक/क-III/77 जी एस आर 251, जनवरी 10, 1978-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 15 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इसके द्वारा—

- (1) कार्मिक विभाग की अधिसूचना सत्या एफ 3 (7) ए. ए. III 68 दिनांक 25-5-72 को प्रत्याहृत करती है (withdraws)।
- (2) सबधित कलक्टर, (जिला विकास अधिकारी) को उसके जिले में पदस्थापित विकास अधिकारी के विरुद्ध लघु शास्तिया अधिरोपित करने हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाहिया प्रारम्भ करने के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है। कलक्टर केवल 'परिनिन्दा' (निन्दा) तथा अनचाही (असहित) प्रभाव से केवल धृष्टिया (धो तक) रोकने की शक्ति अधिरोपित कर सकेगा : यदि वह यह महसूस करे कि दोषी अधिकारी के उत्तर का दृष्टि में रखते हुए, ऊपर विनिर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य लघु शास्ति के अधिरूपण की आवश्यकता है, तो वह निदेशक, सामुदायिक विकास को निर्देश (Reference) कर सकेगा, जिसे ऐसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी लघु शास्ति अधिरोपित करने की पूर्ण शक्तिया होगी।
- (3) यह आदेश देती है कि कोई विकास अधिकारी जिसके विरुद्ध ऊपर उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित करने सबधी कोई आदेश कलक्टर द्वारा दिया गया हो, निदेशक, सामुदायिक विकास को अपील कर सकेगा।

[राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दिनांक 19-1-1978 भ पृष्ठ 778 पर प्रकाशित।]

1. AIR 1957 पञ्जाब-97.

2. 1978 Lab I C-1049 (मध्य प्रदेश)

16, बड़ी शास्तिया लगाने की प्रक्रिया—(1) पब्लिक सर्वेंट्स (इन्क्वायरीज) एक्ट, 1950 के उपबन्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, किसी सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड [4] से [7] तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि यथाशक्य इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में जांच न कर ली गयी हो।

(2) अनुशासनिक प्राधिकारी जिन अभिकथनों के आधार पर जांच किया जाना प्रस्तावित है, उनके आधार पर निश्चित आरोप तैयार करेगा। ऐसे आरोप, अभिकथनों के विवरण के साथ, जिन पर वे आधारित हैं लिखित रूप में सरकारी कर्मचारी को समूचित किये जायेंगे और उससे ऐसे समय के भीतर जो कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय एक लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी जिसमें यह बतलाया जाएगा कि क्या वह सभी आरोपों को या उनमें से किसी की सत्यता स्वीकार करता है, उसको क्या स्पष्टीकरण देना है, या बचाव यदि कोई हो, करना है और क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है।

परन्तु जब दोषागोपित व्यक्ति द्वारा अपने बचाव के अनुक्रम में दिये किसी कथन या अभिकथन पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित हो तो कोई अतिरिक्त आरोप तैयार करना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस उप नियम तथा उप-नियम (3) में अभिव्यक्ति “अनुशासनिक प्राधिकारी” में वह प्राधिकारी भी सम्मिलित होगा जो इन नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी पर नियम 14 के खण्ड [1] से [3] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो।

(3) सरकारी कर्मचारी को अपने बचाव की तैयारी करने के प्रयोजनार्थ ऐसे सरकारी अभिलेखों का जिन्हें वह विनिर्दिष्ट कर निरीक्षण करने तथा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा दी जाएगी परन्तु यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में ऐसे अभिलेख उस प्रयोजन से सुमंगत नहीं है या उसे अभिलेख दिखलाना लोकहित के विरुद्ध है, तो अभिलिखित कारणों से ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा।

*[(4) बचाव के लिखित कथन की प्राप्ति पर या विनिर्दिष्ट समय में ऐसा कोई कथन प्राप्त न हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं ऐसे आरोपों के बारे में जो स्वीकार नहीं किये गये हैं, जांच कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो उस प्रयोजन के लिये ‘जांच बोर्ड’ या “जांच प्राधिकारी” नियुक्त कर सकेगा, और जो सरकारी कर्मचारी अपने बचाव के लिखित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार करले तो प्रत्येक आरोप के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।]

(4 क) यदि सरकारी कर्मचारी जिसने आरोप के किसी अनुच्छेद को बचाव के लिखित कथन में स्वीकार नहीं किया है या बचाव में कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया है,

*विज्ञप्ति सं GSZ 129 न एफ 3 (17) नियुक्ति (क 3) 67 दिनांक 5 अक्टूबर 1974 द्वारा प्रतिस्थापित एवं जोड़ा गया।

जाच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या अपने वचाव में कुछ कहना चाहता है और यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद के लिये दोषी होने का अभिवचन करता है तो जाच प्राधिकारी उस अभिवाक् को अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा—तथा उस पर सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।”

जाच प्राधिकारी सरकारी, कर्मचारी ने आगेप के जिन अनुच्छेदों के लिये दोषी होने का अभिवचन किया है—उनके बारे में दोषी होने का निष्कर्ष भेजेगा।]

(5) अनुशासनिक प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को आरोपों की जाच करने वाले प्राधिकारी (जिस इसमें इसके पश्चात् जाच प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के समक्ष आरोपों के समर्थन में मामले को प्रस्तुत करने के लिए नामजद कर सकेगा। सरकारी कर्मचारी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को सहायता से, अपने मामले को प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नामजद व्यक्ति कोई विधि व्यवसायी न हो या जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए ऐसी अनुज्ञा न दे दे।

स्पष्टीकरण—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ किसी लोक अभियोजक, प्रोसीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर या प्रोसीक्यूटिंग सर्व-इन्स्पेक्टर को विधि व्यवसायी माना जायगा।

1[(6) (क) जहां जाच के प्रारम्भ होने पर सरकारी कर्मचारी आरोपों का दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, जाच अधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से उपस्थित होने वाले प्रस्तुतकर्ता (प्रेजेंटिंग) अधिकारी को, साक्षियों की सूची तथा दस्तावेजों को 10 दिन में प्रस्तुत करने के लिये कहेगा जो इसके साथ ही उसकी एक प्रति सरकारी कर्मचारी को भेजेगा। जाच प्राधिकारी ऐसी सूची प्राप्त होने पर, सूची के अनुसार सुसंगत साक्ष्य को समन करेगा तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को मुरय-परीक्षा का और सरकारी कर्मचारी या उसके सहायक अधिकारी को जो भी उपस्थित हो, प्रति-परीक्षा का अवसर देते हुए साक्ष्य अभिलिखित करेगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी किसी भी विन्दु पर, जिस पर कि साक्षियों से प्रति-परीक्षा की जा चुकी है साक्षियों की पुनर्परीक्षा करने का हक्दार होगा, लेकिन किसी नये मामले पर जाच प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं। अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर, सरकारी कर्मचारी को साक्षियों की सूची तथा दस्तावेज, जो वह अपने वचाव में ऐसा चाहेगा, 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। जाच प्राधिकारी साक्षियों तथा दस्तावेजों की सुसंगति पर विचार करने के पश्चात् केवल सुसंगत साक्ष्यों तथा दस्तावेजों को ही समन करेगा तथा पक्ष-कारों को मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा। पुनर्परीक्षा का अवसर देते हुए, उनका साक्ष्य अभिलिखित करेगा तथा इसके पश्चात् साक्ष्य बन्द कर देगा। जाच प्राधिकारी दोनों पक्षकारों द्वारा बलाये गये साक्षियों तथा दस्तावेजों की सुसंगति पर विचार करेगा और

किन्ही साक्षियों या दस्तावेजों के समन करने से मना कर देने की दशा में वह इसका कारण लेखबद्ध करेगा। जाच प्राधिकारी भी न्याय के हित में पक्षकारों के साक्षियों से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जैसे वह ठीक समझे। पक्षकारों को भी वहस करने का अवसर दिया जायेगा।

टिप्पणी:—यदि सरकारी कर्मचारी, उप नियम (6) (क) में उल्लिखित सूचि में वर्णित साक्षियों के बयान की प्रतिलिपिया उपलब्ध कराने के लिये मौखिक अथवा लिखित में आवेदन करे तो जाच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतिलिपिया यथासंभव शीघ्र उपलब्ध करायेंगा जो किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम तीन दिन पूर्व तक उपलब्ध हो जानी चाहिये।]

²[6 (क-1) किसी व्यक्ति की गवाही जो औपचारिक रूप की है हलफनामे द्वारा दी जा सकेगी और सब न्यायोचित अपवादों के अधीन रहते विभागीय कार्यवाही में स्वीकार की जा सकेगी। जहाँ जाच प्राधिकारी यह उचित समझे कि किसी व्यक्ति को सम्मन भेजा जाकर उमका व्यक्तिगत रूप से बयान लेना चाहिये, या यदि कोई पक्षकार या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या दोषी अधिकारी, किसी गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर दे, तो ऐसे गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।]

(ख) जाच प्राधिकारी उसके द्वारा संचालित किये जा रहे या आशिक रूप से सुने गये, मामले में उचित तथा पर्याप्त कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, गवाही को बयान के लिए पुनः बुला सकेगा।

¹[(6) (ग) जाच प्राधिकारी आदेश के 10 दिनों के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो 10 दिन से अधिक का नहीं होगा, और जिसे जाच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किन्ही ऐसे दस्तावेजों की जो सरकार के कब्जे में हैं लेखित उप नियम (6) (क) में निर्दिष्ट सूची में वर्णित नहीं है, खोज या प्रस्तुतीकरण के लिये, नोटिस जारी करेगा।

टिप्पणी—सरकारी कर्मचारी, उन दस्तावेजों के सम्बन्ध में, जिनके लिये सरकार द्वारा खोज किए जाने या प्रस्तुत किये जाने की उसके द्वारा अपेक्षा की गई है, सुनगति उपदर्शित करेगा। जाच प्राधिकारी, दस्तावेजों की खोज करने या प्रस्तुत करने का नोटिस प्राप्त होने पर, उसे या उसकी प्रतिलिपियों को ऐसी तागोख तर दस्तावेज पेश करने की अध्यक्षता के साथ, जो कि अध्यक्षता में विनिर्दिष्ट की जाय, उस प्राधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा जिसकी अभिरक्षा और /या कब्जे में दस्तावेज रक्खे हुए है।

परन्तु जाच प्राधिकारी, ऐसे दस्तावेजों के लिये जो उसकी राय में, मामले से सुसंगत नहीं है, कारण अभिलिखित करते हुए अध्यक्षता करने से मना कर सकेगा।

अध्यक्षता की प्राप्ति पर, प्रत्येक प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यक्षता किये गये दस्तावेज हैं, उन्हें जाच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा,

2 अप्रापित हिन्दी अनुवाद—वि० स० F 3 (15) का/A III/72 GSR 81 (65) दिनांक 26-12-1973, राज० राजपत्र भाग 4 (ग) (1) दिनांक 7-2-1974 के पृष्ठ 135 (180) में प्रकाशित।

परन्तु अध्यक्ष क्षत दस्तावेजों की अभिरक्षा या उनका रज्जा रखने वाले प्राधिकारी का यदि अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से समाधान हो जाता है कि ऐसे दस्तावेजों में से सब या किन्हीं को प्रस्तुत करना लोकहित या राज्य सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह जाच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किये जाने पर जाच प्राधिकारी इसकी सूचना सरकारी कर्मचारी-को देगा और ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या खोज करने की अपने द्वारा की गई अध्यक्षता अध्याचन प्रत्याहर्ति कर लेगा ।)

1['(6) (घ) इन नियमों के नियम 18 के अन्तर्गत सयुक्त विभागीय जाच के मामले में या नियम 16 के अन्तर्गत जाच के मामले में यदि सरकारी कर्मचारी मुनवाई के लिए नियत तारीख को जिसकी कि उसे/उन्हे सूचना दी गई थी, बिना पर्याप्त कारण के उपस्थित होने में असफल रहता है/रहते हैं तो जाच प्राधिकारी ऐसी सरकारी कर्मचारी/कर्मचारियों की अनुपस्थिति में आगे जाच की कार्यवाही कर सकेगा ।']

2['(6-क) अनुशासनिक प्राधिकारी की आर स मामला समाप्त किये जाने से पूर्व, यदि यह आवश्यक प्रतीत हो, तो जाच प्राधिकारी, स्वविवेक से सरकारी कर्मचारी को दी गई सूची में समाविष्ट न किये गये साक्ष्य को पेश करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अनुज्ञा दे सकेगा या स्वयं ही नये साक्ष्य को मंगा सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा और ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारी को, यदि वह मांग करता है तो पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित और साक्ष्य की सूची की एक प्रति लेने तथा स्थगन के दिन और जिस दिन स्थगन हुआ उसको छोड़कर स्पष्ट तीन दिनों के लिए, जाच का स्थगन लेने का हक होगा । उन दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने से पूर्व, जाच प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का एक अवसर देगा । जाच प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को नया साक्ष्य पेश करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा, यदि उसको यह राय हो कि इस साक्ष्य को पेश करना न्याय के हित में आवश्यक है ।

टिप्पण—साक्ष्य के अन्तराल को भरने के लिए, नये साक्ष्य की अनुज्ञा न तो दी जायगी अथवा न वह मांगी जायगी और न ही कोई साक्षी पुनः बुलाया जायगा । इस प्रकार का साक्ष्य केवल तभी मंगाया जा सकेगा जबकि मूलतः प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो ।]

3['(6 ख) (क) जहाँ नियम 14 के खण्ड (1) (III) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम (किन्तु नियम 14 के खण्ड (4) से (7) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं, अनुशासनिक प्राधिकारी ने किसी आरोप का स्वयं जाच की है या जाच करवायी है और उस प्राधिकारी की, अपने द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर या अपने द्वारा नियुक्त किसी जाच प्राधिकारी के किन्हीं निष्कर्षों पर लिए गए निर्णय के आधार पर, यह राय हो कि

- 1 प्राविष्ट हिन्दी अनुवाद—वि स GSR 129 स F 3 (17) App'ts (A-III) 65 दि 9 अक्टूबर 1974 द्वारा सशोधित । राजपत्र में 10 अक्टू 1974 में प्रकाशित ।
- * प्राविष्ट हिन्दी अनुवाद—वि स GSR 129 स F 3 (17) App'ts (A III) 65 दि 9 अक्टूबर 1974 द्वारा सशोधित । राजपत्र में 10 अक्टू 1974 में प्रकाशित ।

नियम 14 के खण्ड (4) से (7) में विनिर्दिष्ट शास्तिया सरकारी कर्मचारी पर अभिरोपित की जानी चाहिए, वहा वह प्राधिकारा जाच के अभिलेख को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा जो अन्त में वर्णित शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो ।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको कि इस प्रकार अभिलेख अग्रप्रेषित किया गया है, अभिलेख पर के साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा या यदि उसकी राय हो कि साक्षियों में से किसी की और आगे अपीक्षा करना न्याय के हित में है, साक्षी को पुन बुला सकेगा और आगे साक्षी की प्रतीक्षा/प्रतिपरीक्षा तथा पुनर्परीक्षा कर सकेगा और सरकारी कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो इन नियमों के अनुसार उसे उचित प्रतीत हो ।

(7) जाच की समाप्ति पर, जाच प्राधिकारी प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष उनके कारणों सहित, अभिलिखित करते हुए जाच की रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि ऐसे प्राधिकारी की राय में जाच की कार्यवाही से मूलत तैयार किये गये आरोपों से भिन्न आरोप स्थापित हो, तो वह ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा परन्तु ऐसे आरोपों पर निष्कर्ष तब तक अभिलिखित नहीं किए जाएंगे जब तक कि सरकारी कर्मचारी ने उन्हें स्थापित करने वाले तथ्यों को स्वीकार न कर लिया हो या जब तक उसे उनके विरुद्ध अपना बचाव करने का अवसर न मिल चुका हो ।

(8) जाच के अभिलेख में निम्नांकित सम्मिलित होंगे —

- [1] उप-नियम (2) के अधीन सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध तैयार किये गये आरोप और उसको दिया गया अभिकथन विवरण,
- [2] उसके बचाव का लिखित कथन, यदि कोई हो,
- [3] जाच के अनुक्रम में लिया गया मौखिक साक्ष्य,
- [4] जाच के अनुक्रम में वह दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर विचार किया गया हो,
- [5] जाच के बारे में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जाच प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश, यदि कोई हो, और
- [6] प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष तथा उनके कारणों को बतलाने वाली रिपोर्टें ।

(9) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह जाच प्राधिकारी न हो तो जाच के अभिलेख पर विचार करेगा और प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

अनुशासनिक प्राधिकारी, जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करते समय, न्यायोचित तथा पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, मामले को उसकी और आगे जाच किये जाने/नये सिरे से जाच किये जाने के लिए, प्रतिप्रेषित कर सकेगा यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि पहले से की गयी जाच में किसी न किसी रूप में कोई कमी रह गई है ।

(10) [1] अपने आरोपों के निष्कर्ष का ध्यान रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि नियम 14 के खण्ड [4] से [7] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाई जानी चाहिये तो वह—

(क) जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति और जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जाच प्राधिकारी न हो तो वह अपने निष्कर्षों का, और जाच प्राधिकारी के निष्कर्षों में यदि उसकी कोई असहमति हो तो उसके सक्षिप्त कारणों सहित एक विवरण सरकारी कर्मचारी को देगा, और

(ख) उस पर लगाई जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख करते हुए और उससे विनिर्दिष्ट समय में ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए जो वह प्रस्तावित शास्ति के अवध में करना चाहे उसको एक नोटिस देगा परन्तु ऐसा अभ्यावेदन केवल जाच के दौरान पेश किये गये साक्ष्य पर ही आधारित होगा।

[2] (क) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, जाच का अभिलेख, खण्ड [1] के अधीन दिये गये नोटिस की एक प्रति के साथ तथा ऐसे नोटिस के प्रत्युत्तर में प्राप्त अभ्यावेदन सहित, यदि कोई हो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा।

(ख) आयोग की सलाह प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी से प्राप्त उपरोक्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, तथा आयोग द्वारा दी गई सलाह पर विचार करेगा और यह तय करेगा कि सरकारी कर्मचारी पर कौनसी शास्ति लगाई जाए यदि कोई लगाई जानी है, और मामले में समुचित आज्ञा देगा।

[3] ऐसे किसी मामले में जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी खण्ड [1] के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा और यह तय करेगा कि सरकारी कर्मचारी पर कौनसी शास्ति लगाई जाए, यदि कोई लगाई जानी है, तथा मामले में समुचित आदेश देगा।

(11) अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि नियम 14 के खण्ड [1] से [3] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति लगाई जानी चाहिए तो वह मामले में समुचित आदेश देगा।

परन्तु जिन मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, ऐसे प्रत्येक मामले में जाच का अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और ऐसी सलाह पर आदेश देने से पहले विचार कर लिया जाएगा।

(12) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश सरकारी कर्मचारी को समुचित किये जाएंगे और उसे जाच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भी दी जाएगी और जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, जाच प्राधिकारी न हो तो उसके निष्कर्षों का एक विवरण, जाच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के सक्षिप्त कारणों सहित, दिया जाएगा, यदि वे पहले उसको नहीं दिये गये हो और यदि आयोग द्वारा कोई

सलाह दी गयी हो तो उसकी एक प्रति भी दी जाएगी तथा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह स्वीकार न की हो तो ऐसी अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

तथापि जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति देना उन मामलों में आवश्यक नहीं होगा जिनमें नियम 14 के खण्ड [1] से [3] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी कर्मचारी पर लगाई जाय।

राजस्थान सरकार का निर्देश (1)

“प्रारम्भिक जांच आरम्भ करना —

- (i) जब किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई गंभीर दोष या दुराचरण का मामला उसके उच्च अधिकारी की जानकारी में लाया जावे जिसमें अनुशासन कार्यवाही की जरूरत हो, तो वह दोषों से परिचित किसी अधिकारी द्वारा, बिना किसी विलम्ब के प्रारम्भिक जांच करवाएगा।
- (ii) जिन मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप हो, तो विभागाध्यक्ष के मार्फत और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति की दशा में नियुक्ति विभाग के माध्यम से, मामले की छानबीन के लिए, यथा संभव शीघ्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त महा निरीक्षक आरक्षी (Additional Inspector General of Police Anti-corruption Department) को निर्देश भेजा जाएगा।
- (iii) सरतः प्रकृति के मामलों में जब कि अनुशासन प्राधिकारी तथ्यों की सच्चाई से अन्यथा सन्तुष्ट हो, तो प्रारम्भिक जांच का परित्याग किया जा सकेगा।
- (iv) प्रारम्भिक जांच के दौरान, सभी सारभूत दस्तावेज एकत्रित किए जावें और गवाहों के दायन लिखे जावें, और जहाँ तक संभव हो उन पर उन के हस्ताक्षर करना लिए जावें। दोषी कर्मचारी का लिखित कथन भी प्राप्त करना उचित होगा। उपलब्ध शहादत अभिलिखित करने और सारभूत दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात् प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी को उसके द्वारा जांच किए गए आरोपों की सत्यता या अन्यथा पर प्रपन निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिये। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में शिकायत, शहादत और निष्कर्ष भी सम्मिलित होगा, जिसे तीन महीने के भीतर आरोपों के विवरण और अभियोगों के भरोसे के साथ अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाना चाहिए।*

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट का परीक्षण — प्रारम्भिक जांच की रिपोर्टें प्राप्त होने पर, उस पर आगे कार्यवाही करने के विषय में निर्णय लेने के लिए, अनुशासन प्राधिकारी को रिपोर्टों का परीक्षण करना चाहिये। यदि अनुशासन प्राधिकारी को तसल्ली हो जाए कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध प्रथमावलोकन से कोई मामला नहीं बनता, तो वह कामजात दाखिल दफतर करने का आदेश दे सकेगा। किन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी की राय में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए प्रथमावलोकन से मामला बनता है, तो अनुशासन प्राधिकारी को आगे यह भी तय करना चाहिये,

* नियुक्ति (ए) विभाग (ए)—सरक्युलर स एफ 23 (36) नियुक्ति (A)/ 57 दिनांक 22 अगस्त, 1957।

के आया मामले में, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील), नियम 1958 के नियम 14 के खण्ड (i) से (ii) में निर्दिष्ट लघु शास्ति या खण्ड (iv) से (vii) में निर्दिष्ट बठोर शास्ति लागू करना वांछित हैं। लघु शास्ति होने की दशा में, दोषी कर्मचारी से नियम 17 (i) के अधीन केवल स्वैच्छिक मांगा जावे जब कि दूसरे किस्म का मामला हो तो, तो उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अधीन दोषी को नियमित रूप से चार्जशीट दी जाएगी।¹

[अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963 अनुच्छेद (2) और (3)]

राजस्थान सरकार का निर्देश (2)

अभियोजन (प्रोसिक्यूशन)

जब कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या जिला पुलिस या कोई अन्य प्राधिकारी नफ्तीश के फलस्वरूप किसी दोषी कर्मचारी पर फौजदारी मुकदमा (अभियोजन) चलाना चाहता हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी को तत्पश्चात् रिपोर्ट की जाच अत्यन्त सावधानी से करनी चाहिये और यदि मामले की मामूली पर जैसा भी उचित हो, या तो वांछित स्वीकृति दी जावे अथवा प्रस्वीकार कर दी जावे। किसी भी दशा में, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या जिला पुलिस से प्राप्त ऐसे निर्देशनों का निपटारा प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन में कर देना चाहिये।

यदि स्वीकृति प्रदान की जावे तो वह जहाँ तक संभव हो विस्तृत होनी चाहिए जिसमें उन तथ्यों का समावेश होना चाहिये जिनमें अभियोजन के लिए अपराध बना और उसमें विशिष्टतः यह उल्लेख करना चाहिए कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ने मामले पर स्वयं विचार किया है और यह भी कि वह प्राधिकारी विशेष स्वीकृति प्रदान करने के लिये सक्षम है। स्वीकृति का प्रपत्र परिशिष्ट में उपलब्ध है। (देखिए प्रपत्र सं 70)।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहियाँ पैरा 16]

राजस्थान सरकार का निर्देश (3)

अनुशासन कार्यवाहियों के मामलों का शीघ्रता से निपटारा :

सरकार ने समय-समय पर अनुशासन के मामलों को शीघ्रता से निपटारने की आवश्यकता और उपयुक्तता पर बल दिया है।

गहन के मामलों में विभागीय जांच:

स. 50/-से अधिक के धन सम्पत्ति के गहन के मामलों से सम्बन्धित उन विभागीय जाचों का शीघ्रता से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए, जो कि विभागाध्यक्षों के पास विचाराधीन हैं या ना भविष्य में उपपन्न हों, विभागीय जाच आयुक्त, राजस्थान को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।**

जिन मामलों में विभागीय तथा कानूनी दोनों कार्यवाहियाँ सम्मिलित हों, तो प्राग्भ में, विभागीय जाच करनी चाहिए और उसे पूरी की जाकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया जाना चाहिए। इससे दौरान पुलिस द्वारा मामले की नफ्तीश (फ्लेक्चिंग) जागी रह सकती है परन्तु

* नियुक्ति (A) विभाग सरकार F. 19 (38) नियुक्ति (A) 60 दिनांक 13-5-1960

** नियुक्ति (A) विभागीय आदेश सं. F. 19 (12) नियुक्ति (A)/59/ग्रुप III, दि. 26-10-1961.

अदालत में उसका चानान तभी पेश किया जाना चाहिए जबकि विभागीय जाच समाप्त हो गई हो और उसके फलस्वरूप दोषी को दण्डित किया जा चुका हो। सामान्य तौर से यही प्रक्रिया होनी चाहिए। किंतु ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें उपलब्ध साक्षी पर साफ तौर से दोषी के विरुद्ध अपराध बनता हो और कानूनी अदालत में उस दोषी करार दिए जान की पूरी संभावना हो। ऐसे मामलों में पहले से ही अभ्यपूदन मुकदमा दायर किया जा सकता है। किंतु अदालती मुकदम चल रहने के दौरान अभियोक्त पत्र धनाया जा सक्ता और कमचारी से निहित प्रतिवेदन भगवाया जा सकेगा तबि मुकदमे में दोष मिट होने बरी हान के पश्चात् तभी भी स्थिति हो मामला नियमित विभागीय जाच के लिए जाच अधिकारी को बचन सौंपा जाना बाकी रह जाए। अतः अधिनतर मामलों में विभागीय जाच पहल होगी और कुछ मामलों में मुकदमा पहल दायर होगा। इनमें से कौनसा रास्ता अपनाया जावे यह इस प्रकार के मामलों में निहित दोषी कमचारियों को राजकीय सेवा में वर्गास्त करने हेतु सत्यम प्राधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर होगा।*

विभागीय जाचा का गलत संचालन

जब उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष अपील/नजरसानी करने पर या किसी अशान्तो नियम व फल स्वरूप कोई मूल आदेश निरस्त करना पड़ और अपील/नजरसानी जाच प्राधिकारी या अनुशासन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित काय प्रणाली का पूरा पालन नहीं करने के कारण स्वीकार की गई हो तो गवनी करने वाले जाच प्राधिकारी/अनुशासन प्राधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त सरकारी आदेश में निर्धारित अनुशासन कायवाही की जा सकती जिसके लिये कि वह अवश्य जिम्मेदार है।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कायवाहिया अनुच्छेद 21 22 व 23]

राजस्थान सरकार का निर्देश (4)

अनुशासन कायवाही प्रारम्भ करने से पूर्व या उसके दौरान दोषी कमचारियों की सेवा निवृत्ति के मामलों में अनुसरणीय काय प्रणाली

यदि कोई दोषी कमचारी विभागीय जाच प्रारम्भ करने से पहले या उसके चाल रहने के दौरान सेवा निवृत्त (रिटायर) हो जाता है तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम और अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत उमक विरुद्ध कोई दण्ड की कायवाही नहीं की जा सकती। किंतु इस दोषी के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 के प्रावधानानुसार कायवाही की जा सकती है। किसी विभागीय या याचिक कायवाही में यदि कोई पेशन भोगी अपन सदाकान में जिसमें सेवा निवृत्ति के बाद पुन नियोजन का मेरा काग सम्मिलित है और दुराचरण का अपराध पाया गया हो या उमने अपने दुराचरण या लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक हानि पहुँचाई हो और उसकी पेशन या उसका कोई भाग स्थाई तौर से या किसी निम्नष्ट अवधि के लिए रोकना या बाधित वाना प्रस्तावित हो या सरकार को पहुँचाई गई आर्थिक हानि पूणत या आंशिक रूप से उमकी पेशन से वसूल की जानी हो तो इस नियम के अन्तर्गत कायवाही प्रारम्भ की जा सकती है बशर्ते कि—

(क) यदि एसी विभागीय जाच कमचारी के संचालन रहते उमकी सेवा निवृत्ति से पहले या पुन नियोजन के दरमियान प्रारम्भ नहा की गई हो तो

- (i) राज्यपाल की स्वीकृति के बिना शुरू नहीं की जाएगी;
- (ii) वह ऐसी घटना के विषय में होगी जो ऐसी कार्यवाही आरम्भ करने में अधिकाधिक चार वर्षों से पहले की नहीं हो, और
- (iii) जाच प्राधिकारी द्वारा एक ऐसे स्थान या स्थानों पर संचानित की जाएगी जिसके लिए राज्यपाल निर्देश दे और उस कार्य प्रणाली के अनुसार की जाएगी जो सेवा से वरखास्तगी के आदेश जारी करने के लिए लागू है,
- (ख) ऐसी न्यायिक कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा काल में, सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान आरम्भ नहीं की गई हो, तो वह खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) के अनुसार आरम्भ की गई हो, और
- (ग) अंतिम आदेश जारी करने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग में परामर्श लिया जाएगा।

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963 पैरा 19]

राजस्थान सरकार के निर्देश (5)

*दोपी कर्मचारियों द्वारा रेकॉर्ड का निरीक्षण.—राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और प्रवृत्ति) नियम, 1958 के अलावा, राज्य सरकार ने दोपी कर्मचारियों को रेकॉर्ड की नकले प्रदान करने तथा रेकॉर्ड निरीक्षण करने की अनुमति के लिए निम्न लिखित निर्देश निर्धारित किए हैं—

- (i) सरकारी रेकॉर्ड तक पहुंच असंभव नहीं है और अनुशासन प्राधिकारी एसी पहुंच (access) के लिए इन्कार कर सकता यदि उसकी मंमति में—
- (क) ऐसा रेकॉर्ड मामले से सुसंगत (relevant) नहीं है, और/अथवा,
- (ख) ऐसी पहुंच सार्वजनिक हित में बाधनीय नहीं है।
- (ii) किन्तु सरकारी रेकॉर्ड तक पहुंचने से इन्कार करने के अधिकार का प्रयोग बहुत कम होना चाहिए। सुसंगतता (सम्बन्धिता) का प्रश्न प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से देवना चाहिए और यदि कोई प्रतिरक्षा की ऐसी संभावित विचारधारा हो जिससे कोई दस्तावेज किसी भी प्रकार से सारभूत हो, तो यद्यपि प्राथम्यता करते समय अनुशासन प्राधिकारी को सुसंगतता साफ नहीं दिखती हो, तथापि उस तक पहुंचाने की प्राथम्यता प्रस्वीकार नहीं की जानी चाहिए।
- (iii) सार्वजनिक हित के आधार पर पहुंचने (access) से इन्कार करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब कि ऐसा विश्वास करने के लिए मही और पर्याप्त कारण हो कि उससे सार्वजनिक हित को स्पष्ट हानि होगी। इस प्रकार के मामलों संभवतः बहुत कम होने हैं, और यदि उक्त दस्तावेज का अभियोगों के सबूत में प्रयोग करने का इरादा हो और जाच बिठाई जाने की दशा में ऐसे दस्तावेज को जाच

प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना प्रस्तावित हो, तो सामान्यतः उसके सावजनिक हित में नहीं होने के आधार पर पहुचने (निरीक्षण करने) से अस्वीकृति का अवसर उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

- (iv) याद रखना चाहिए कि, दस्तावेजों तक पहुचने के लिए अनुशासन प्राधिकारियों द्वारा मनाई करना जब न्यायालय सही होना नहीं माने, तो गंभीर कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं। किसी भी दशा में, जब पहुच (access) अस्वीकार करना तय कर लिया हो, तो ऐसी अस्वीकृति विश्वस्त तथा ठोस होनी चाहिए और निश्चितः उसे लिखित में अभिलिखित करना चाहिए।
- (v) आरोपों के विवरण में जो अभियोग तथा तथ्य हो उनको साबित करने हेतु आधारभूत दस्तावेजों की प्रस्तावित सूची, दोषी कर्मचारी को चार्ज शीट के साथ ही या उसके पश्चात् यथा सभव शीघ्र दे देनी चाहिए। यदि कर्मचारी चाहे, तो सूची में उल्लेखित दस्तावेजों तक पहुचने (निरीक्षण) के लिए कर्मचारी को अनुमति दी जानी चाहिए।
- (vi) यदि दोषी कर्मचारी सूची में, सम्मिलित नहीं किए गए सरकारी दस्तावेजों के लिए प्रार्थना करे, तो उपयुक्त अनुच्छेदों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना साधारणतः, स्वीकार की जानी चाहिए।
- (vii) प्रारम्भिक जाच करने हेतु नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा तथ्यों का ठीक से पता लगाने की रिपोर्ट, प्रारम्भिक जाच करने के बाद की रिपोर्ट, जाबाना फौजदारी (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898) की धारा 173 की उप-धारा (1) अनुच्छेद (क) में निर्दिष्ट अन्वेषण के प्रतिरिक्त, पुलिस द्वारा अन्वेषण (तफतीश) करने के बाद की रिपोर्ट जो सरकार को या अन्य सक्षम प्राधिकारियों, अनुशासन प्राधिकारियों सहित, को प्रेषित की जाती हैं व ग्राम तौर से गोपनीय होती है, जो केवल सक्षम प्राधिकारियों की सन्तुष्टि के लिए होती है कि आया नियमित विभागीय जाच की या कोई अन्य प्रकार की कार्यवाही करना आवश्यक है। इन रिपोर्टों को राज्य कर्मचारी को दिखाना आवश्यक नहीं है।
- (viii) विभाग द्वारा संचालित प्रारम्भिक जाच में या पुलिस द्वारा किए गए अन्वेषण के दौरान अभिलिखित गवाहों के बयान —

ये बयान केवल जिरह (cross-examination) के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जा सकते हैं, और राज्य कर्मचारी को केवल उन गवाहों से जिरह के लिए कहा जाता है जिनके बयानों पर अभियोग या आरोपों के विवरण में दिए गए तथ्यों के सबूत के लिए आधार लेना प्रस्तावित है। जैसा कि कहा जा चुका है, सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को प्रारम्भिक जाच में या पुलिस की तफतीश में बयान लिए गए सभी गवाहों के बयानों तक पहुचने (access) की इजाजत देना जरूरी नहीं है और केवल उन्ही गवाहों के बयानों तक पहुचने देना चाहिए जिनको अभियोगों तथा आरोपों के विवरण में उल्लेखित तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य में पेश करना है। कतिपय मामलों में, राज्य कर्मचारी कुछ ऐसे गवाहान के बयानों की नकलें मांग सकते हैं जिन पर अनुशासन प्राधिकारी इस कारण से आधारित नहीं रहना चाहते कि कर्मचारी अपनी ओर से उन गवाहों को पेश करना चाहता है और जाच अधिकारियों के समक्ष उन गवाहों द्वारा पहले दिए गए बयानों की पुष्टि (corroboration) कराने के लिए उसको जरूरत है। चूंकि किसी व्यक्ति द्वारा गवाह के रूप में

पहले दिया गया बयान पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु स्वीकार्य नहीं होता, इसलिए उन बयानों तक पहुँचने की इजाजत अभयतापूर्वक अस्वीकार की जा सकती है। किन्तु कानून इस बात को मान्यता देता है कि यदि पिछला बयान उस समय/या उसके करीब दिया गया था जिस समय कि कोई तथ्य घटित हुआ और जब कि किसी कार्यवाही में उस व्यक्ति को उक्त तथ्य के बारे में गवाही देने के लिए बुलाया जावे, तो पिछला बयान पुष्टि करने के प्रयोजनों के लिए काम में लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में, पिछले बयानों तक पहुँचने (access) देना जरूरी होगा।

(ix) गवाहों के बयानों तक पहुँचने की अनुमति देने की अवस्था (stage),

गवाहों के बयानों की प्रतियाँ केवल जिरह करने के लिए ही काम में लाई जा सकती हैं और, इसलिए, नकलों की माग तभी की जानी चाहिये जब कि गवाहों को मौखिक जाच में बयानों के लिए बुलाया जावे। यदि ऐसी माग नहीं की जावे तो यही अनुमान लगाया जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नकलों की जरूरत नहीं थी। ऐसी नकलों का उपयोग किसी बाद की अवस्था में नहीं किया जा सकता क्योंकि इन बयानों पर अनुशासन प्राधिकारी भी विचार नहीं कर सकता। नकलें गवाहों का बयान लेने से पहले युक्त (reasonable) समय में, उपलब्ध करा देनी चाहिए। विभागीय जाच में साहाय्य अर्पित करने की अवस्था से पहले ऐसी प्रतिमाँ देने से कानूनन अवश्य इन्कार किया जा सकता है, परन्तु अपवादजनक मामलों में, यदि दोषी कर्मचारी बलपूर्वक आप्रग्रह करे, तो चार्ज-शीट के वे उत्तर में उसको लिखित प्रतिवेदन तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुशासन प्राधिकारी, अपने स्व-विवेक से, नकलें पहले देने की इजाजत दे सकेगा।

(x) दस्तावेजों की नकलें,

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और धनीत्व) नियम, 1958 के नियम 16 के उप-नियम (3) में दस्तावेजों की नकलें देने का कोई प्रावधान नहीं है। परिणामतः सामान्यतः से विभिन्न दस्तावेजों (documents) की नकलें देना आवश्यक नहीं है और केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि कर्मचारी को ऊपर उल्लेखित नियमों के अधीन दस्तावेज तक पहुँचने (निरीक्षण करने) की अनुमति दी जावे।

(xi) विभागीय जाच में लिखित सरकारी कर्मचारियों को जब सरकारी रिकॉर्ड देखने की अनुमति दी जाती है तो वह कभी कभी उनकी फोटो स्टेट प्रतियाँ लेने की इजाजत मांगते हैं। आम तौर से ऐसी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, खास तौर से जब कि कर्मचारी ऐसी प्रतियाँ किसी निजी (प्राइवेट) फोटोग्राफर के माध्यम से बनवाना चाहते हों क्योंकि उससे बाहरी लोगों की सरकारी रिकॉर्ड देखने का मौका मिलता है, जो वांछित नहीं है। किन्तु, यदि जिन दस्तावेजों की फोटो स्टेट प्रतियाँ मांगी गई हैं वे मामलों में अत्यन्त सारभूत हों (उदाहरणतः जब कि अभियोग का सबूत हस्तलिखित के सबूत पर निर्भर हो या दस्तावेज ऐसा हो जिसकी प्रामाणिकता विवादास्पद हो) तो अनुशासन प्राधिकारी खुद को उनकी फोटो स्टेट प्रतियाँ बनवा लेनी चाहिए और राज्य कर्मचारी को देनी चाहिए। ऐसे मामलों में जो इसी प्रकार के न हों (दिए हुए उदाहरण केवल मिसाल के तौर पर हैं और पूर्णतः नहीं हैं), इतना ही पर्याप्त होगा कि सरकारी कर्मचारी को सरकारी रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया जावे और उपर्युक्त नियमों के प्रावधानानुसार उमम से उद्धरण (extracts) लेने की अनुमति दी जावे।

[राजस्थान सरकार की अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, 1963, अनुच्छेद 11]

राजस्थान सरकार का निर्देश (6)

जाच अधिकारी की नियुक्ति :

जब नि निम्न प्रतिबन्धन के जाच दरम्य (या जब निर्धारित अवधि में या समय-समय पर बढ़ाई गई अवधि में कोई निम्न प्रतिबन्धन प्राप्त नहीं हान स दबनर्क बायबाही परता तय हुमा हा) और अनुशासन प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि कतिपय आरोपों के मूलत के लिए नियमित जाच प्रोशिन है, अवका आगेप गभीर प्रकार के हान स कोई कठार शास्ति अविरागित की जा मकनी है तो अनुशासन प्राधिकारी स्वयं ऐसे अभियो ॥ की जाच कर मवगा जा विवादास्पद हो, प्रयत्न इन प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, अपने निजी हस्ताक्षरों से कोई जाच अधिकारी या जाच मण्डल (Board of Enquiry) नियुक्त कर मवेगा । साम तोर से मण्डल नियुक्त नहीं किया जाता है और केरन बहुत गहन या उनमन भर मामलों में उसकी नियुक्ति प्रोशिन हा सकती है । जाच अधिकारी का चुनाव करने में आरोपों की गभीरता और दोषी कमचारियों के पद स्तर या उचित न्याय रचना के लिए । ऐसे अधिकारियों को जाच मुपुर्द नहीं की जानी चाहिए जिन स्वयं प्रारम्भिक जाच की हो या जिनमें पढ़ने तकियायन (विवाद-मिन्दुओं) पर अपनी निश्चित सम्मति प्रकट की हा । सामान्यतः जाच अधिकारी दोरी कमचारी से बरिस्ट व्यक्ति होता चाहिए और जो अपनी अवस्थाती और न्यायिकता (Fair Minded and Just) के लिए जाना जाता हो । जाच के दौरान यदि इस प्रकार ॥ नियुक्त जाच अधिकारी का स्थान स्तर हो जाता है, तो अन्य जाच अधिकारी की नियुक्ति का आदेश, निर्धारित प्रपत्र में अवश्य जारी करना चाहिए । जाच अधिकारी का स्थानान्तर होन पर और नए जाच अधिकारी की नियुक्ति होने पर दोरी कमचारियों को नए निरे में जाच करने की माग करने का कोई अधिकार नहीं है । जब तक कि किसी विशेष में मले में उसकी परस्थितियों को दृष्टिगोचर करने में जाच अधिकारी विशेषण मवाही पुन अभिलिखित करना तय नहीं करे तब तक उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है । नियुक्ति आदेश का मरीदा परिशिष्ट में (प्रपत्र न 7) दिजा गया है ।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुशासन बायबाहिया 1963, अनुच्छेद 9]

राजस्थान सरकार का निर्देश (7)

विभागीय प्रतिनिधि और दोषी अधिकारियों का प्रतिनिधि

- (i) अनुशासन प्राधिकारी जब जाच, जाच अधिकार को मुपुर्द करे तब या उसके बाद शीघ्र ही उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जाच अधिकारी के समक्ष अभियोग पत्र का मामला प्रस्तुत करने के लिए, मनोनीत करना चाहिये ।
- (ii) इसी प्रकार, दोरी कमचारी भी अपना मामला, अनुशासन प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किसी अन्य राज्य कमचारी की सहायता से प्रस्तुत कर मवेगा । किन्तु जब तक कि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति कोई वकील न हो (जैसा कि 1961 R L W 104, ए के व्यास के मामले में निर्णीत हुआ) अवका जब तक कि मामले की परस्थितियों का ध्यान रखते हुए कवित नियम के अधीन अनुशासन प्राधिकारी इजाजत न दे, तब तक राज्य कमचारी को अधिकार स्वरूप वकील द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने की माग करने का हक नहीं है ।

(iii) साधारणतः जाच में बचील उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये अन्यथा जाच सम्भवतः लम्बी हो जाएगी। ऐसी जाच में अभियोजित व्यक्ति को भी अधिकार स्वल्प यह हक नहीं है कि वह बचील द्वारा अपनी प्रतिरक्षा कराने की मांग करे। परन्तु किसी भी पक्ष से बचीलों की अनुज्ञा पर कोई निषेध नहीं है, और यह सदैव ध्यान में रक्खा चाहिये कि अभियोजित व्यक्ति को अपना बचाव करने का समुचित अवसर मिलना चाहिये। इसलिये, यदि मामला बहुत उलझन भरा और बठिन हो, या यदि अभियोजित व्यक्ति को उससे सम्बन्ध, बहुत दुविधा या परेशानी होगी, तो उसे कानूनी सहायता लेने की इजाजत दी जा सकती है (1957 आन्ध्र प्रदेश 414, 1958 इलाहाबाद 532 तथा 1961 बलकत्ता 1)। परन्तु इसकी इजाजत अत्यन्त अपवाद स्वरूपी परिस्थितियों में और उसका कारण लिखित में अभिलिखित करके देनी चाहिये।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहियाँ अनुच्छेद 12]

राजस्थान सरकार का निर्देश (8)

जाच अधिकारी के समस्त कार्य प्रणाली :

- (i) मौखिक जाच प्रारम्भ होने से पूर्व, यदि प्रतिरक्षा का लिखित प्रतिवेदन पेश किया जा चुका हो और यदि ऐसा प्रतिवेदन पेश नहीं भी किया गया हो, तो भी अभियोजित व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाना चाहिये कि वह अपना मौखिक बयान, अपने लिखित प्रतिवेदन के पूरक स्वरूप या उसके स्पष्टीकरण में या उसके बदले में तथा स्थिति, दे सके। यदि अभियोजित व्यक्ति अभियोग के विषय में कोई बयान देने से इन्कार करे तो बयान देने से इन्कारी अभिलिखित करनी चाहिये। किन्तु ऐसी इन्कारी में यह अनुमान नहीं लगाना चाहिये कि वह अभियोग की सत्यता स्वीकार करता है।
- (ii) मौखिक जाच में उन्हीं आरोपों/अभियोगों के विषय में गवाही मुनी जानी चाहिये जो स्वीकार नहीं किए गए हैं। जाच अधिकारी का गवाहों के बयान दोषी कर्मचारी की उपस्थिति में अभिलिखित करना चाहिये, जिसको उनसे जिरह (प्रतिपरीक्षा) का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। प्रारम्भिक जाच के दौरान लिए गए बयान विभागीय जाच की कार्यवाही का अंग नहीं बनते। यह बात सावधानी से ध्यान में रखी जावे कि अभियोग पक्ष के कबल उन गवाहों से जिनके बयान प्रारम्भिक जाच में लिए गए थे। जिरह करने का अवसर प्रदान करना, अपक्षताओं की पूर्ति नहीं करेगा। उक्त गवाहों के बयान फिर प्रारम्भ में अभियोजित अधिकारी की उपस्थिति में लिये जावे (कन्हैयालाल वि. राजस्थान सरकार, RLW 1958)

जिरह के दौरान विरोधाभास (Contradiction) के प्रयोजनार्थ, जाच प्रारम्भ होने से पहले, प्रारम्भिक जाच में अभिलिखित गवाहों के बयानों की मन्त्रे दोषी कर्मचारी को दी जा सकेगी। आरोपों में स्वयं शहादत देना और अपनी प्रतिरक्षा की दृष्टि में गवाह पक्ष करने की इजाजत दी जानी चाहिये। और इन गवाहों से विभागीय प्रतिनिधि या जाच अधिकारी जिरह कर सकेगा।

- (iii) साधारणतः अभियोजित व्यक्ति को अपनी दस्तावेजी शहादत, यदि कोई हो, उसके लिखित प्रतिवेदन के साथ पेश करने के लिए कहा जाना चाहिये, परन्तु ऐसी शहादत

को केवल इस कारण पर अस्वीकार नहीं करना चाहिये कि वह विलम्ब से प्रस्तुत हुई है। विलम्बित अवस्था में भी अभियोजित व्यक्ति द्वारा पेश की गई सारभूत शहादत का स्वीकार करना सदैव अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध काम में ली जाने वाली प्रस्तावित दस्तावेजी शहादत, कायदे से, शुरू की अवस्था में ही रिकॉर्ड पर स्थापित कर देनी चाहिए और साधारणतः ऐसी दस्तावेजों की सूची उसे चार्ज-शीट देने के साथ ही दे देनी चाहिए।

- (iv) सदम की सुविधा के लिए, अभियोग पक्ष के बयान लिए हुए गवाहों को त्रम से सहाय्य कर देना चाहिये, जैसे, P W 1, P. W 2, आदि, और प्रतिरक्षा के गवाहों को D W-1 तथा D W-2 आदि से। इसी प्रकार, अभियोग पक्ष द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजों को EX P-1, EX P-2, आदि और प्रतिरक्षा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को EX D-1, EX D-2, आदि चिन्हों से क्रमांकित करना चाहिये और ऐसे क्रमांकन के नीचे जाच अधिकारी को अपन हस्ताक्षर अवश्य करने चाहिये।
- (v) जाच अधिकारी किसी गवाह का बयान लेने से इस आचार पर इन्कार कर सकता है कि उसकी गवाही अभियोगों से सारभूत या आवश्यक सम्बन्ध नहीं रखती। उसे ऐसा करने के अपने कारण लिखित में रिकॉर्ड पर रखने चाहिये। यह स्वविवेक दोरी कर्मचारी के विपरीत अनियमितता से उपयोग में नहीं लाना चाहिये। साधारणतः किसी गवाह को बुलाने की प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिये। किन्तु जब ऐसा प्रतीत हो कि किसी गवाह विशेष को बुलाने की प्रार्थना क्लेशदाई है, या जाच को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने की नीयत से की गई है, तो ऐसी प्रार्थना अस्वीकार की जा सकेगी किन्तु उपर्युक्त अपेक्षा के अधीनस्थ कि ऐसी अस्वीकृति के कथित नियमों के नियम 16 (6) द्वारा अपेक्षित कारण अभिलिखित करने के बाद करनी चाहिये।
- (vi) गवाहों के बयान साधारणतः वृत्तान्त के रूप में (in the form of a narrative) अभिलिखित करने चाहिये। गवाहों को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। प्रत्येक गवाह के बयान में यह स्पष्ट संकेत होना चाहिये कि आया दोरी कर्मचारी ने उसके साथ जिरह की है या जिरह करने से इन्कार कर दिया है। जब (प्रत्येक) गवाह के बयान पूरे हो जावें तो उसके बाद उसे पढ़कर सुनाना चाहिये और गवाह तथा जाच अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिये। बयान पढ़कर सुनते समय यदि गवाह साक्ष्य के किसी भाग को सही होने से इन्कार करे, तो जाच अधिकारी, साक्ष्य में सुधार करने के बजाय, बयान पर गवाह द्वारा उठाई गई आपत्ति अंकित कर सकेगा जिसमें वह अपना 'रिमाक', जैसा वह उचित, समझे जोड़ सकेगा। याद रखना चाहिये कि जाच अधिकारी, किसी भी परस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंप सकता।
- (vii) राजस्थान अनुशासन कार्यवाहिया (गवाहों की तलबी तथा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण) अधिनियम, 1959 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अधीन जाच अधिकारी को अधिकार है कि वह गवाहों को उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सके चाहे गवाह राज्य कर्मचारी हो या निजी व्यक्ति। यात्रा भत्ता नियमों का नियम 34

(अथ, यात्रा भत्ता नियम 1971 का नियम 28) जाच अधिकारी के द्वारा निजी गवाहों को खर्चा देने का प्रावधान करता है जिनको बिना वह जाच के दौरान तनत्र करे।

(viii) दोनों पक्षों की ओर से गवाही अभिलिखित हो जाने के पश्चात्, दोषी कर्मचारी को अवसर प्रदान करना चाहिये कि यदि वह चाहे तो अपनी बहस सुनाए।

जाच के दौरान चार्ज-शीट से सुमात समस्त सम्भावी प्रश्न, जो जाच के आधार हो, पूछे जान की अनुमति देनी चाहिए। जो प्रश्न यद्यपि चार्ज-शीट से प्रत्यक्ष रूप के सुसंगत नहीं है तथापि यदि उनसे निर्णय तक पहुँचने में सुविधा की सम्भावना हो, तो प्रत्येक मामले में गुण-अवगुणों को देखत हुए, पूछे जान की अनुमति दी जानी चाहिए।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुशासन कार्यवाहिया (1963) अनु. 13]

राजस्थान सरकार का निर्देश (9)

जाँच समाप्त हो जाने पर, जाच अधिकारी को जाच की एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसमें प्रत्येक अभियोग पर पृथक्-पृथक् अपना निष्कर्ष कारणों सहित लिखना चाहिए। निष्कर्ष उपयुक्त कारणों पर आधारित होना चाहिए और दोनों पक्षों की शहान्त पर पूरा विचार करने के पश्चात् निकालना चाहिए। औपचारिक जाँच के रैपड पर जा सक्षम विद्यमान न हो उसे दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाई जा सकती। यदि जाच अधिकारी की राय में, जाच की कार्यवाही में मूलतः निर्धारित अभियोगों से कोई भिन्न अभियोग स्थापित हात है, तो वह ऐसे निष्कर्षों को अभिलिखित कर सकेगा, बशर्ते कि उक्त निष्कर्ष दोषी कर्मचारी द्वारा स्वीकारे गए तथ्यों पर आधारित हो और उनके विरुद्ध कर्मचारी को अपना बचाव करने का अवसर मिल चुका हो। ऐसे मामले में अनुशासन प्राधिकारी अभियोगों में मशौघन कर सकता है। जाच अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विशिष्ट कोई दण्ड प्रस्तावित करे और उसे प्रत्येक अभियोग के विषय में केवल अपने निष्कर्ष अभिव्यक्त करने तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए।

[राजस्थान सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया, 1963 अनु. 13 (ix)]

राजस्थान सरकार के निर्देश (10)

जाच अधिकारी के निष्कर्षों का परीक्षण .

जाच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अनुशासन प्राधिकारी को प्रत्येक अभियोग पर तथा जाच के रकड व निष्कर्षों के अभिलेख पर विचार करना चाहिए अर्थात् प्रत्येक अभियोग के विषय में जाच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमति या अग्रहमति। अनुशासन प्राधिकारी लिखित में कारण अभिलिखित करके जाच अधिकारी के निष्कर्षों से विभिन्न मन धारण सकता है।

[राज. सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहिया, 1963 अनुच्छेद 14]

राजस्थान सरकार के निर्देश (11)

निर्णय :

- (1) अभियोगों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासन प्राधिकारी इस सम्मति का हो कि कोई भी आरोप साबित नहीं हुए है, तो वह दोषी कर्मचारी को दोष

मुक्त कर सवेगा। राज्य कर्मचारी को लिखित में दोष मुक्त करने की सूचना भेजी जाएगी।

(ii) जाच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि अनुशासन प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुँचे कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 के उपखण्ड (i) से (iii) तक में निर्दिष्ट केवल कोई लघु शास्ति की ही अपेक्षा है, तो वह कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना मामले में उपयुक्त आदेश पारित कर सवेगा।

(iii) यदि अभियोगों के निष्कर्षों पर विचार करने से अनुशासन प्राधिकारी इस सम्मति का हो कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील), नियम 1958 के नियम 14 के अनुच्छेद (iv) तथा (v) तथा (vi) में निर्दिष्ट कोई बड़ी शास्ति अधिकारित की जानी चाहिए तो वह—

(क) दोषी कर्मचारी को जाच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रतिनिधि, अपने स्वयं के निष्कर्षों पर निर्णय और जबकि अनुशासन प्राधिकारी जाच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो ऐसी असहमति के कारणों सहित भेजेगा, और

(ख) और उसे एक नोटिस देगा जिसमें तदर्थ रूप से दण्ड की प्रस्तावना करते हुए उसे आदेश दिया जाएगा कि वह प्रस्तुत दण्ड के नतीजे के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन करना चाहे तो निर्दिष्ट अवधि में, उदाहरणतः 15 दिनों में, प्रेषित करे।

नोट:-जब अनुशासन प्राधिकारी स्वयं ही जाच प्राधिकारी हो तो भी उन्हीं औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।

(iv) कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, दोषी कर्मचारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए, और आयोग से परामर्श लेने के पश्चात्, जबकि ऐसा अपेक्षित हो, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध साबित अभियोगों की गम्भीरता और प्रकृति का ध्यान रखते हुए उपयुक्त शास्ति अधिकारित की जानी चाहिए। दण्ड की मात्रा निर्धारित करते समय अनुशासन प्राधिकारी दोषी कर्मचारी का पिछला रिकार्ड या पिछला दुराचरण केवल तभी विचाराधीन रख सकता है जबकि उसका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में कर दिया गया था और दोषी कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा अवसर दिया जा चुका था। (AIR 1954 काणपुर 90 तथा 1960 इलाहाबाद 270)।

(v) यदि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से प्रस्तावित दण्ड गम्भीर प्राकृति का हो, किन्तु उसके प्रतिवेदन पर सुनवाई करने के पश्चात् उससे हल्का दण्ड देने का निर्णय लिया जाये तो ताजा कारण बताओ नोटिस की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि उससे भारी दण्ड दिया जाना हो, तो ताजा कारण बताओ नोटिस देना जरूरी होगा।

(vi) अनुशासन प्राधिकारी द्वारा पारित अनिम आदेश राज्य कर्मचारी को भेजा जाएगा और अधिनस्थ सेवा एवं लिपिकवर्गीय सेवाओं के मामलों में उक्त आदेश सरकार को भी (सम्बन्धित) प्रशासनीय विभाग को प्रेषित किया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी सेवा के

मामलो में उसके ऊपर के प्राधिकारी को भी इस आशय से भेजा जाएगा कि इस प्रकार में पारित अंतिम आदेशों को प्रशासनीक विभाग अथवा उससे उच्च प्राधिकारी देख सकें और दण्ड की पर्याप्तता पर निर्णय ले सकें तथा यदि आवश्यक समझें तो उसकी नजरसानी कर के आदेश को सशोधित कर सकें ।

[राज. सरकार की पुस्तिका अनुशासन कार्यवाहीया 1963 अनुच्छेद 15]

टिप्पणी

असैनिक राज्य कर्मचारियों पर कठोर शास्त्रियाँ अधिरोपित करने के लिए नियम 16 विस्तृत कार्य प्रणाली निर्धारित करना है । सही तथ्या का पता लगाने के लिए और राज्य कर्मचारी को अपना पक्ष निवेदन करने तथा अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है ताकि न्याय किया जा सके । इस नियम में समय समय पर घनेक परिवर्धन तथा सशोधन किये गये हैं, अर्थात् दिनांक 16-7-63, 20-3-65, 16-6-65, 11-3-66 एवं अधिकतर 9-10-74 को जैसा कि ऊपर उद्धृत नियम के निचे दिये गये फुट नोटों में दर्शाया गया है । राज्य कर्मचारी माग कर सकता है कि उसके विरुद्ध जाच नियमों में निर्धारित तरीकों से की जाए न कि जाच प्राधिकारी के व्यक्तिगत मन की लहर तथा चपलता के अनुसार । यह सभी सम्बन्धितों के लिए एकसा प्रमाण (Standard) भी निर्धारित करता है ।¹

नियम 16 (1).—राज्य कर्मचारीयों के विरुद्ध जाच के लिए पूर्वकालीन ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक कर्मचारी (जाच) अधिनियम, 1850 लागू किया था । यद्यपि सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील), नियम प्रभावित हो चुके हैं, तथापि 1850 का कथित अधिनियम अभी भी कानूनी पुस्तकों पर विद्यमान है, परन्तु अब उसका उपयोग नहीं किया जाता है । किन्तु यदि सरकार चाहे तो, अब भी, जैसा कि उपनियम (1) में उल्लेख किया गया है, उपर्युक्त 1850 के अधिनियम के अनुसार कार्यवाही कर सकती है ।² सरकार के लिए यह एक सुविधा का मामला है आया कोई जाच वह इन नियमों के अधीन संचालित करे या सार्वजनिक कर्मचारी (जाच), अधिनियम, 1850 के अन्तर्गत ।³ सविधान के अनुच्छेद 311 (2) में निर्धारित प्रावधान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम के अधीन विभागीय जाच वा निचोड तथा रीड की हड्डी के समान है ।

नियम 16 (1) राज्य कर्मचारीयों पर नियम 14 के अनुच्छेद (iv) से (vii) में उल्लिखित सभी प्रकार की कठोर शास्त्रियाँ अधिरोपित करने के लिए लागू होता है, नामांश ।

- (iv) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर, या नीचे के वेतनमान में या उसी वेतनमान में नीचे के वेतन पर पदानुवर्ती अथवा पेंशन होने की दशा में नियमों के अधीन देय राशि से कम राशि तय करना,
- (v) अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,
- (vi) सेवा से हटाना, और या
- (vii) सेवा से बर्खास्तगी ।

1. AIR 1958 राजस्थान-1.

2. AIR 1956 पंजाब-58—कपूरसिंह वि. भारतीय सघ ।

3. AIR 1960 पटना-116—श्रीभुवननाथ वि बिहार सरकार ।

विभागीय जाच पर भारतीय माध्यम अधिनियम 1872 वास्तविक रूप में लागू नहीं है, परन्तु प्रतीत होता है कि यह नियम वनात समग्र उत्तर मोट मिट्टान रिषात मण्डल के ध्यात में प्रवेश था। हमने प्रतिरिक्त जाच की निर्धारित प्रतियां व साथ साथ प्राट्टिक न्याय के मिट्टानों का भी पालन किया जाना है। यह अद्वैत न्यायिक बायवाही है जिस पर प्राट्टिक न्याय के मिट्टान उत्तर ही लागू हो जाते हैं कि न्यायिक बायवाही पर और उनको निरस्त करने के लिए उद्देश्यम प्राप्त मासिना (Part of Certificates) द्वारा प्रायता की जा सकती है। परन्तु यदि प्राट्टिक न्याय के मिट्टान मूल रूप में पालन के लिए गए हैं तो किसी एक नियम के अनुपालन में विफल रहता बायवाही का शारिज करने के लिए परियाप्त नहीं है क्योंकि नियम 16 (1) में अभिव्यक्ति जहां तक संभव हो का प्रयोग किया गया है।¹ किन्तु प्राधिकारियों से प्राया की जानी है कि वे प्रशासनिक मामलों में भी बायवाही पक्षपातहीनता से बाय करेंगे।² अतः अतः एक गवाह या बयान प्रार्थी की अनुपस्थिति में अथवा मामलों के जान अधिकारी ने एक अथवा दोषी कमचारा के बग में अभिव्यक्ति कि और प्रार्थी का उक्त गवाह में जिरह करने का अधिकार भी नहीं दिया गया और फिर भी उक्त गवाह के बयान का आधार लेकर प्रार्थी की शास्ति में वृद्धि या घाटश दिया जा उच्च न्यायालय ने निष्णय दिया कि कथित आलेख न्यायिक नियमों के प्रतिबन्ध था।³ इसी प्रकार जय रवाड पर एका परियाप्त माहुर नहीं था जिससे यह साबित होता कि दोषी कमचारी ने अपन वनध्यों का पालन ठीक तरह से नहीं किया था यह फैसला हुआ कि एका निष्णय जो किसी गवाहन पर आधारित नहीं था बायम नहीं रखा जा सकता।⁴ परन्तु जब बायवाही नष्ट शास्ति के लिए नियम 17 के अधीन चालू की गई थी परन्तु उस पर अंतिम निष्णय नहीं हुआ और नियम 16 के अधीन जाच प्रारम्भ की गई तो तब हुआ कि ताजा जाच करने पर कोई रोक नहीं था।⁵

प्रारम्भिक जाच — किसी निम्निल कमचारी के विरुद्ध अभियोग निश्चित करने से पहले, तथ्या का पता लगान के लिए प्रारम्भिक जाच की जा सकती है। यह जाच वैधानिक है और कमचारी की अनुपस्थिति में स्वतः की जा सकती है।⁶ प्रारम्भिक जाच में नियमित जाच में कोई रखाव नहीं होगी।⁷ परन्तु सरकार को अधिकार है कि बिना प्रारम्भिक जाच के भी अभियोग निश्चित कर सके।⁸

राजस्थान सरकार ने प्रारम्भिक जाच के विषय में अनुशासन बायवाहियों की अपनी पुस्तिका के 1963 के सम्करण में अनुच्छेद (2 व 3) में निर्देशन जारी किए हैं जो ऊपर नियम की भाषा के नीचे दिए जा चुके हैं। इन निर्देशों के अनुसार जब किसी अधिकारी के ध्यान में किसी राज्य कमचारी के विरुद्ध ऐसा गम्भीर दोष या दुराचरण आवे या उसकी जानकारी में लाए जावें तो उसे

- 1 AIR 1960 राजस्थान 419—ए के ध्यास वि राजस्थान सरकार।
- 2 1974 WLN 245 रामशरण शर्मा वि राजस्थान सरकार।
- 3 1975 WLN 8—हृगन ताल वि राजस्थान सरकार।
- 4 1977 WLN 646—राजस्थान सरकार वि दान मन।
- 5 1977 WLN 421 फतेह सिंह लोढा वि राजस्थान सरकार।
- 6 1969 SLR 18—टी के सिंह वि बिहार सरकार।
- 7 AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 2037—आर सी शर्मा वि भारतीय सघ।
- 8 1969 RLW 579 = 1969 WLN 17—विश्वनाथ ताल गांधरा वि सरकार।

तुरन्त प्रारम्भिक जाच करानी चाहिए, जो चाहे वह स्वयं करे या दोषी कर्मचारों के ऊपर का कोई अधिकारी करे।

यदि कर्मचारों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हों, तो भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस के अतिरिक्त महा निरीक्षक को विभागाध्यक्ष के मार्फत तफ्तीश के लिए तुरन्त निर्देश भेज देने चाहिए, और यदि उक्त कर्मचारी की नियुक्ति सरकार न की थी तो नियुक्ति विभाग के माध्यम से उक्त अतिरिक्त महा निरीक्षक का मामले की ध्यानधीन करने हेतु लिखा जावे। उससे आगे की कार्यवाही अतिरिक्त महा-निरीक्षक पुलिस की सफाई प्राप्त होने के पश्चात् की जानी चाहिए।

परन्तु साधारण मामला में जबकि तथ्य सनोपजनक रूप से स्पष्ट हों तो प्रारम्भिक जाच की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रारम्भिक जाच के दौरान सभी उपलब्ध माध्यम और मुमकिन अभिलेख एकत्रित कर लेने चाहिए और भवाहो के बयान लिख जाँकर, यथासम्भव, उन पर उनके हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। यह भी उचित होगा कि, दोषी कर्मचारों का स्पष्टीकरण लिखित में प्राप्त कर लिया जाये। इससे बाद रिकार्ड निष्कर्षों सहित, आरोपों के विवरण और अभियोगों के साथ 3 माह के भीतर अनुशासन प्राधिकारी को समर्पित कर दिया जावे। तत्पश्चात् यह तय करना अनुशासन प्राधिकारी का कार्य है कि आया कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये जावें अथवा मामले में औपचारिक जाच संचालित की जाए, और यदि ऐसा निर्णय हो, कि आया जाच नियम 16 के अधीन कठोर शास्तियों के लिए या नियम 17 के अन्तर्गत लघु शास्तियों की जाच के तरीके से की जाए।

फौजदारी मुकदमा — राजस्थान सरकार ने यह भी निर्देशन जारी किए हैं कि जब भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या पुलिस विभाग या कोई अन्य प्राधिकारी किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अपने अन्वेषण के फलस्वरूप फौजदारी मुकदमा चलाना प्रस्तावित कर तो नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिए कि वह तथ्यों की रिपोर्ट का सावधानी पूर्वक अध्ययन करे और उस पर स्वयं सोच विचार करने के पश्चात्, या तो ऐसा मुकदमा दायर करने की अनुमति प्रदान करे या अस्वीकृति प्रकट करे। यदि मुकदमे के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए तो, स्वीकृति का आदेश कार्पी विस्तृत होना चाहिए जिसमें उन तथ्यों का विवेचन होना चाहिए जिनसे अपराध बना। ऐसा आदेश प्रपत्र 14 के अनुरूप होना चाहिए जो इस पुस्तक में अग्रज दिया हुआ है।

फौजदारी मुकदमे के साथ विभागीय जाच — फौजदारी मुकदमा तथा विभागीय जाच साथ साथ प्रारम्भ किए जा सकेंगे,¹ परन्तु न्यायालयों ने सम्मति प्रकट की है कि न्यायिकता तथा पक्ष-पातहीनता की दृष्टि से, जब तक कि फौजदारी मुकदमे का फैसला नहीं हो जाए, तब तक विभागीय जाच स्थगित रखी जाए। यह आवश्यक नहीं है कि फौजदारी अदालत का निर्णय जाच अधिकारी या अनुशासन प्राधिकारी पर बाध्यकारी हो।²

सविधान का अनुच्छेद 20 (2) प्रावधान करता है कि, “कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार में अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जाएगा”। यद्यपि यह प्रावधान विशिष्टतः वातूनी अदालत पर लागू है, तथापि इस प्रावृत्तिक नियम के सिद्धान्त रूप में माना है कि, “एक ही अभियोग के लिए किसी भी व्यक्ति को दो दफा परेशान नहीं किया जाना चाहिए”।³ यह निर्णय

1 AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 1210—भगतसिंह वि पंजाब सरकार।

2 1973 (2) SLR 564—काजीराम वि भारतीय सशस्त्र बल।

3 1973 SLC 180।

दिया गया है कि जब एक कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले की गई पूरी जानकारी दी गई हो, तो उन्होंने तथ्यों के प्रायोगिक पर उसे चार्ज-शीट दी जाकर विभागीय जांच करना कर्मचारी को परेशान करना होगा और प्राथमिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिबन्ध होगा।¹ जब एक कर्मचारी बिना अनुमति नाम से अनुपस्थित रहा जिसके कारण उसका वेतन काट लिया गया, तो वह अपने आप में स्वयं एक शास्ति थी। अतः वेतन से उसका कटौती करने के पश्चात्, प्राथमिक रीढ़ अनुपस्थित रहने के लिए उसे चार्ज-शीट नहीं दे सकते।² निष्पक्षता और न्यायिकता के सिद्धान्त पर उन्होंने अभियोगों पर नई जांच अनुचित होने से पुष्टि करने योग्य नहीं है।³ ऐसे मामलों में "रकावट का सिद्धान्त" (Principle of estoppel) भी लागू है, जिसके अनुसार दुबारा जांच अनुमति नहीं है।⁴ प्रतिकार कि नगरपालिका⁵ में न्यायालय और भी आगे बढ़ा है और सम्मति प्रकट की है कि एक पुरानी घटना की ताज़ा जांच में पुनः उठाकर, उसके आधार पर कर्मचारी को सेवा से हटाना बदनीयता की कार्यवाही में आता है। जो कुल्हाड़ी एक दफा दफनाई गई है उसे बार बार खोदकर नहीं निकालना चाहिये। एक प्रशासनिक मामले, यू पी सरकार वि मुघडतिह⁶ में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहरे दण्ड के विषय में यह सम्मति प्रकट की—“यदि आदेश की न्यायोचितता उसके (कर्मचारी के) चरित्रलेखा (रेकॉर्ड रॉल) में उसके विरुद्ध किए गए इन्फ्रिज से सदाभित है, तो यह न केवल दोहरी सज़ा का मामला बन गया बल्कि (सविधान के) अनुच्छेद 311 के उल्लंघन का भी मामला है। “... इस आलोचना को टालना असम्भव है कि प्रत्यावर्तन (reversion) के आदेश के देश में वस्तुतः यह एक सज़ा थी।” इसी प्रकार का मत द्वारकाचन्द वि राजस्थान सरकार⁷ में धारण किया जिसमें एक सिविल कर्मचारी के विरुद्ध दूसरी जांच धारम्भ कर दी गई थी यद्यपि वह पहले उसी अभियोग से दोषमुक्त कर दिया था। आदर्श सेवा मण्डल वि. उप निदेशक, शिक्षा विभाग⁸ में साफ तौर से तय, किया गया है कि जब एक दफा मामला समाप्त कर दिया गया हो और कर्मचारी को पुनः स्थापित (re-instated) किया जा चुका हो, तो दूसरी अनुज्ञान कार्यवाही अनुज्ञ नहीं है। एक अन्य मामले, शिखर चन्द सेठ वि दिविजनल मेकेनिकल एंजनीयर, पश्चिमी रेलवे⁹ में कर्मचारी को दीवानी अदालत में दोष मुक्त कर दिया था। इसलिए नाज़ी जांच का संचालन दूषित हो गया (vitiated)। इसके उपरान्त भी, प्राधिकारियों ने न्यायान्वय के निर्णय की प्रवृत्ति करना करते हुए, कर्मचारी को निलम्बित किया और तत्पश्चात् सेवा से बरखास्त कर दिया। जांच के दौरान निलम्बन भी दूषित करार दिया गया। अनुशासन प्राधिकारी का आदेश न्यायालय द्वारा जांच अधिकारी की अक्षमता के आधार पर और मामले के गुण अवगुण के आधार पर भी खारिज किया गया। ऐसी परिस्थितियों में ताज़ा जांच पर रोक लगवाने का निर्णय घोषित हुआ।

1 1972 Lab IC 1539 ILR (1973) 52 पटना 266 ।

2 1978 SLJ 456—अनवर खा वि भोगा प्रशासक ।

3 आसाम LR (1971) आसाम 281 ।

4 1975 Lab IC 1580 कलकत्ता, यह भी देखिए AIR 1958 मध्य प्र 413 ।

5 AIR 1961 मैसूर 181 ।

6 1974 SCC (L & S) 124 ।

7 AIR 1858 राजस्थान 138 ।

8 1978 SLJ (इलाहबाद) 138 ।

9 1970 RLW 83 AIR 1970 राजस्थान 210 ।

इसके विपरीत फर्हसिंह वि. राजस्थान सरकार¹ में, प्रारम्भ में नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई थी परन्तु उसके अन्तिम निर्णय से पहले, दोषी कर्मचारी को नियम 16 के अधीन नया नोटिस जारी किया गया और नवीन जाच प्रारम्भ की गई। निर्णय हुआ कि इस प्रकार से नई जाच की जाने पर कोई रोक नहीं थी। इसी मामले में ताजा चार्ज शीट देन में देर हुई क्योंकि सक्षम प्राधिकारी कौन है इस विषय में महानिरीक्षक आरक्षी और उप-महानिरीक्षक आरक्षी में मत-भेद था। न्यायालय ने तय किया कि विसम्भ का कारण स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए, नई जाच के लिए घातक नहीं है।

फौजदारी प्रदात का फँसला और ताजा जाच —जब कि विभागीय जाच के आरोप उस फौजदारी प्रदात के मुकदमे के विषय से भिन्न हो जिसमें कि राज्य कर्मचारी बरी हुआ, तो नई विभागीय जाच करने पर कोई रोक नहीं होगी यद्यपि², तथ्य वैसे ही हों³। जब कि फौजदारी प्रदात ने परित्याप्त शहादत के अभाव में मुल्जिम राज्य कर्मचारी को डिमिचार्ज कर दिया, फिर भी यदि अनुशासन प्राधिकारी के पास उससे बेहतर सबूत हो, तो वह उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चला सकेगा।⁴ जब कि मुकद्दमा केवल तकनीकी कारणों में, बिना उसके गुण-अवगुणों पर विचार किए बन्द कर दिया गया हो, तो यदि आरोपों के लिए सही तथा परित्याप्त आधार⁵ हो तो विभागीय जाच प्रारम्भ की जा सकेगी।⁶ फौजदारी प्रदात के निष्कर्ष अनुशासन प्राधिकारी को बाध्य करने वाले नहीं हैं।⁷ विभागीय जाच में एक पटवारी को सेवा से हटा दिया गया, उन्हीं अभियोगों पर फौजदारी प्रदात ने उसे बरी कर दिया। फिर भी निम्न हुआ कि बरी होने के आधार पर उसे सेवा में पुनः स्थापित किए जाने का अधिकार नहीं था।⁸

गबन के मामले —मभी विभागीय जाचों की कार्यवाहियों में अनावश्यक लम्बा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि विलम्ब न केवल न्याय देने से रोकता है, बल्कि कतिपय मामलों में किसी महत्वपूर्ण गवाह की मृत्यु हो जाने के कारण या समय गुजर जाने के स्मरण शक्ति क्षीण हो जाने से, दोषी कर्मचारी दोष मुक्त हो सकता है। परन्तु गबन के मामलों में तत्परता से कार्यवाही करना और भी आवश्यक है। राजस्थान सरकार ने इस आवश्यकता पर बल दिया है, और ₹ 50/- या उससे अधिक राशि या मूल्य की सम्पत्ति के गबन के मामलों का शीघ्रता से निपटारा कराने की दृष्टि से विशेष निर्देशन जारी किए हैं। इस प्रयोजन के लिए, राजस्थान के विभागीय जाच आयुक्त को विशेषतः विभागाध्यक्ष के अधिकार प्रदान किए हैं, देखिए—आदेश दिनांक 26-10-1961 तथा 6-2-1963, या ऊपर (निर्देशन सं 3) दिए जा चुके हैं।

जाच अधिकारियों और अनुशासन प्राधिकारियों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यवाही कि विभिन्न अवस्थाओं (stages) में, निर्धारित सारी श्रौ-

1 1977 WLN 421।

2 AIR 1962 उड़ीसा 125—राधाकान्त पटनायक वि. उड़ीसा सरकार तथा AIR 1956 पटना 228—वरमदेवसिंह वि. बिहार सरकार।

3 ILR (1975) कर्नाटक 895।

4 AIR 1955 पटना 328।

5 AIR 1962 SC-1334—देवेन्द्रप्रताप नारायणराय शर्मा वि. उत्तर प्र० सरकार।

6 1972 Lab IC 1453 (वम्बई)।

7 1974 Lab IC 553—(हरियाणा—पंजाब)।

चारिकताओं का मही पानन हुआ है। प्राकृतिक ाय और सविधान के सम्बन्धित प्रावधानों का भी यथाचित ध्यान रखना चाहिए। इस सम्बन्ध में नुटि या विपन्नता रहने से उनके दिए हुए फेंव

अपीन या नजरमानी में अथवा किसी कानूनी अदालत में सारिज किए जा सकते हैं और उस दशा में स्थाई सरकारी आदेशों के अनुसार प्राधिकारियों के विरुद्ध भी अनुशासन कायवाही की जा सकती है। (देखिए—राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कायवाही पर पुलिसका व अनुच्छेद 21 22 तथा 23)।

विभागीय जाच के दौरान सेवा निवृत्ति प्राप्ति करना—यदि कोई दोपी राज्य कमचारी विभागीय जाच प्रारम्भ करने से पूर्व या उसके चालू रहते सेवा निवृत्ति (रिटायर) हो जावे तो राजस्थान सिविन सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपीन) नियम 1958 के अधीन उस पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती। जब वह रिटायर हो जावे तो उसके विरुद्ध अनुशासन कायवाही का भी अंत हो जाएगा और तब सरकार उसे सेवा में रखने के लिए सशक्त नहीं रहेगी जिससे कि उस पर शास्ति लागू करने में संभव हो सके।¹ जाच करने के प्रयोजन से उसे सेवा में रखना उचित नहीं होता और उसके सेवाकाल में वृद्धि करना भी गैर कानूनी है।² यदि दोपी कमचारी का सेवा निवृत्ति तिथि में पहले विभागीय जाच पूरी नहीं की जा सकती हो, तो सही रास्ता रास्ता यह होगा कि उसे सेवा से निनम्बन कर दिया जावे (यदि वह पहले से ही निनम्बन में न हो) और जब तक विभागीय जाच में अन्तिम आदेश पारित न हो तब तक उस सेवा निवृत्त होने की अनुमति नहीं दी जावे।³ हान ही व एक में मल और पी नायर वि केरल राज्य विद्युत् मण्डल⁴ में करन उच्च न्यायालय ने निराव दिया है कि जो विभागीय कायवाही कमचारी के सेवा में रहते प्रारम्भ की गई थी वह उसे सेवा निवृत्त हो जाने के पश्चात् जारी नहीं रह सकती। पेगन व सम्बन्ध के सिवाय नौकरी में जारी रखना अवैध होगा। नि सदेह यदि कमचारी ने अपने सेवा काल या पुन नियोजन काल में सरकार का अपन दुराचरण या तापरावाही के कारण आर्थिक हानि पहुंचाई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति पूरण या आंशिक रूप में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 170 व अ तगत कमचारी की पणन से बन्नी जा सकती है परन्तु शन यह है कि —

(क) यदि उस सम्बन्ध में विभागीय कायवाही दोपी कमचारी व सवारन रहते या सेवा निवृत्ति व बाद पुन नियोजन की अवधि में प्रारम्भ नहीं की गई तो —

- (i) सरकार की स्वाहृति के बिना प्रारम्भ नहीं की जावेगी
- (ii) ऐसी किसी घटना या बिना व बार में नहीं होगी जो उक्त कायवाही शुरू करने में 4 वर्ष से अधिक पटन घटित हुई थी
- (iii) जाच ऐसे अधिकारियों द्वारा तथा ऐम स्थान या स्थानों पर संचालित की जाएगी जैसा कि राज्यपाल निर्देशन दे और ऐसी विभागीय कायवाही की काम प्रणाली

-
- 1 AIR 1958 राजस्थान 36—द्वाराचन्द वि राजस्थान सरकार।
 - AIR 1967 राजस्थान 82—नवनविज्ञार वि राजस्थान सरकार।
 - 2 AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 447—व नमान सरकार वि निपन्नाथ वागयी।
 - 3 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 214—पजाव राज्य वि भमीराम और
 - AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1737—भमीराम वि पजाव सरकार।
 - 4 FLR 1979 (38) 236।

के अनुसार की जाएगी जो किसी राज्य कर्मचारी की सेवा से बरखास्त करने के लिए निर्धारित है।

(ख) ऐसी कोई भी न्यायिक जाच, यदि कर्मचारी के सेवाकाल में, उसकी सेवा निवृत्ति से पूर्व या उसके पुनर्नियोजन काल में प्रारम्भ नहीं की गई थी, तो किसी ऐसी घटना या क्रिया के सम्बन्ध में प्रारम्भ नहीं की जाएगी जिसका समय जाच प्रारम्भ करने के पूर्व चार साल से अधिक गुजर चुका हो।

(ग) अन्तिम आदेश जारी करने से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना होगा।*

अनुच्छेद 311 (2) में संशोधन —अब, सविधान के अनुच्छेद 311 (2) में, सविधान (बयालीसव संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है, जो 3 जनवरी, 1977 से प्रभावशील हुआ है। इसके अनुसार दण्ड प्रस्तावित करने की अवस्था (stage) आने पर जो द्वितीय कारण बताओ नोटिस पहले दोषी कर्मचारी को देना अनिवार्य था वह प्रावधान वापिस ले लिया गया है। किन्तु राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों का नियम 16 (10) अभी तक प्रभावशील है जिसमें ऐसे द्वितीय नोटिस का कानूनी प्रावधान है परन्तु उसकी पुष्टि में पहले वाला सर्वैधानिक बल अब नहीं रहा है।

नियम 16 (2) —अभियोग तथा आरोपों का विवरण-पत्र निश्चित करना —कठोर शास्तियों हेतु विभागीय जाच की प्रथम अवस्था नियम 16 (2) में बताई गई है जो निर्धारित करता है कि ऐसे (क) आरोपों के आधार पर जिनकी जाच की जानी है, अनुशासन प्राधिकारी (ख) निश्चित अभियोग बनाएगा। ऐसे अभियोग, आरोपों के विवरण सहित लिखित में बनाए जाएंगे और दोषी राज्य कर्मचारी को एक नोटिस के साथ भेजे जायेंगे जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना लिखित प्रतिवेदन, ऐसी अधधि में भीतर पेश करे जो अनुशासन प्राधिकारी, नियम 16 (2) और 16 (3) के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट करे। जो प्राधिकारी नियम 14 के उप-खण्ड (i) से (iii) में निर्दिष्ट तथु शास्तिया लागू करने के लिए अधिकृत हो वह अनुशासन प्राधिकारी भी हो सकेगा। नियम 16 (2) के नीचे दिए गए परन्तुक के अनुसार जब कि अभियोगित दोषी व्यक्ति द्वारा उसकी प्रतिकक्षा के दौरान दिए गए अभिकथन या लगाया गए आरोप के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना प्रस्तावित हो, तो कोई अतिरिक्त अभियोग (चार्ज) बनाना आवश्यक नहीं होगा।

राजस्थान सरकार ने कतिपय आदेशों प्रपत्र अर्थात् प्रमाणिक मसौदों के फार्म बनाए हैं जो इन नियमों के अन्त में दिए गए हैं। प्रपत्र स. (3) जाच प्रस्तावित करने का मेमोरेण्डम है, प्रपत्र स. (4) अभियोग पत्र (चार्ज शीट) का है और प्रपत्र स. (5) आरोपों का विवरण तैयार करने के लिए है। भूत. जब भी नियम 16 (2) के अधीन कार्यवाही की जानी हो, तो उपर्युक्त तीन फार्मों का उपयोग करना चाहिए और ये तीनों भरे जाकर उस राज्य कर्मचारी के भेजने चाहिए जिसके विरुद्ध जाच बिठानी प्रस्तावित हो। दोषी कर्मचारी पर इनकी तामील या तो व्यक्तिगत रूप से प्रथवा रजिस्टर्ड डाक से करानी चाहिए और उसकी रसीद या पहुँच उक्त कर्मचारी के हस्ताक्षरों की प्राप्ति करनी चाहिए। यह नियम कोई निश्चित अधधि निर्धारित नहीं करता जिसमें दोषी कर्मचारी को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा जावे। मामान्यतः 15 दिन में कम समय नहीं दिया जावे। उपर्युक्त

*देनिए—अनुशासन कार्यवाही की राजस्थान सरकार की पुस्तिका 1963, अनुच्छेद 19।

सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर स्वयं अनुशासन प्राधिकारी को करने चाहिये और इनको किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अभियोग तथा आरोपों का विवरण जितना निश्चित और विशिष्ट हो सके उसका साफ शब्दों में लिखना चाहिए ताकि अस्पष्ट (Vague) होने के आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सके।¹ यहाँ शब्द 'अभियोग (चार्ज)' से अभिप्राय कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए किसी आरोप से है जो आवश्यक रूप से दण्ड संहिता के तत्त्वों की अर्थ में अपराधों के लिए बखाने 'घाज' नहीं होता।² मेमोरेण्डम औपचारिक चार्ज-शीट भी हो सकता है।³ आरोपों के विवरण या अभियोग पत्र में दीये कर्मचारी के विरुद्ध विद्यमान गहावत का संकेत मिलना चाहिए।⁴

राजस्थान सरकार वि. दानमल⁵ में एक अभियोग (चार्ज) इस प्रकार था —

'यह कि 7-2-53 को जब श्री एन एन- दीवान आई. पी एस ने आपको रोज़द सत्यापन करवाने के लिए कहा तो आपने साफ इन्कार कर दिया। इसलिए आपको पुलिस अधीक्षक के निवास स्थान पर ले जाया गया परन्तु वहाँ भी आपने इन्कार किया। अतः एम डी एम को बुलवाना पड़ा और बहुत ही हिचकिचाहट के बाद आपने उसे (रोकड़ पेटी का) छोड़ा। अतः भली भाँति जानते हुए, आपने पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक के आदेशों की अवमानना की और श्री दीवान के साथ ऐसा असोभनीय और अनुशासनहीनता व बदतमीजी का व्यवहार किया और पुलिस लाइन में तथा पुलिस अधीक्षक पाली के निवास स्थान पर और एस डी एम के सामने ऐसी अमर प्रश्लील भाषा का प्रयोग किया जो अविवेक (अवज्ञा) (insubordination) की तारीफ में आता है।'

दीये कर्मचारी की एक दलील यह थी कि अभियोग (विशेषतः उपर्युक्तचार्ज) अस्पष्ट (vague) था और उसकी अस्पष्टता से की गई जाच दूषित हो गई। यह व्यक्त किया गया कि जिस शब्दावली 'असोभनीय,' 'अनुशासनहीनता,' 'बदतमीजी,' 'ढीठपन,' 'अमर भाषा' का प्रयोग चार्ज में तथा आरोपों के विवरण में किया गया है वह अस्पष्ट है और रेस्पोंडेन्ट द्वारा वास्तव में उच्चारित किए गए शब्दों को चार्ज-शीट और आरोपों के विवरण में सम्मिलित करना चाहिए था। इस संबंध में उसने सुरयचन्द्र चक्रवर्ती वि. पश्चिम बंगाल सरकार (AIR 1971 सुप्रीमकोर्ट 752) आदि का आधार लिया। परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस केस को तथ्यों के आधार पर उनसे भिन्न होता माना। क्योंकि गवाह हसराम ने रेस्पोंडेन्ट द्वारा उच्चारित वास्तविक शब्दों को दुहराया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा विभिन्न स्थानों पर बोली गई वास्तविक शब्दावली की उसे जानकारी नहीं कराई गई थी। इस प्रकार न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट द्वारा उठाई गई अस्पष्टता की दलील ठुकरा दी। इसी प्रकार एक अन्य मामले में जब कि अभियोग पत्र में घटना का समय और स्थान के विशिष्ट उदाहरण तथा विवरण और शिकायतकर्ता के नाम और राज्य कर्मचारी विरुद्ध अधिरोपित बापों का उल्लेख था तो उसे नुटियुक्त नहीं माना गया।⁶

1 LIR 1962 राजस्थान 302 एवं AIR 1963 त्रिपुरा 20

2. AIR 1958 राजस्थान 1—कन्हैया लाल वि. राजस्थान सरकार।

3 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1589—वृष्ण चन्द्र टण्डन वि. भारतीय सच।

4 AIR 1972 कलकत्ता 27.

5 1977 WLN 645.

6 AIR 1956 सौराष्ट्र 14—मानुप्रसाद वि. सरकार।

इसके विपरीत, जब कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विशिष्ट अभियोग यह था कि उसने 367 बाहरी रेलवे लाइनो के पास जालसाजी में जारी किए, परन्तु 367 व्यक्तियों के नाम और आरोपित बाहरी रेलवे लाइनो के नाम प्रकट नहीं किए गए, तो निर्णय हुआ कि ऐसे अभियोग पर आधारित विभागीय जाच की संचालन-प्रक्रिया कानून के प्रतिबल थी।¹

अभियोगों के पत्र में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तावित शास्त्रि का उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे यह संकेत मिलेगा कि अनुशासन प्राधिकारी ने जाच संचालित करने से पहले ही दोषी कर्मचारी को दण्डित करने का मनस बना लिया है, जो सविधान के अनुच्छेद 311 की अवहेलना समझा जा सकता है।² परन्तु ऐसे मामले में भी, समस्त कार्यवाही विद्विष्ट कराने के लिए याचिका शास्त्रि आरोपित करने के अन्तिम आदेश पारित होने से पहले नहीं की जा सकती।³ यदि किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग एक से अधिक हों, तो जाच दूषित नहीं होगी।⁴ यदि पहले दी गई चार्ज-शीट के स्थान पर दूसरी चार्जशीट दी जावे तो इसमें कोई गलती नहीं होगी।⁵ आई. जी. पुलिस और डिप्टी आई. जी. पुलिस के मध्य, एक मामले में नियुक्ति प्राधिकारी के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण, दोषी कर्मचारी को ताजा चार्जशीट देने में देरी हुई। न्यायालय ने तय किया कि विलम्ब का कारण रेकॉर्ड पर स्पष्ट कर दिया गया था, इसलिए, वह ताजा जाच करने के लिए घातक नहीं था।⁶

आरोपों का विवरण —सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को आरोपों का विवरण (Statement of allegations) देने के लिए विशेष प्रावधान नियम 16 (2) में किया गया है, जिसको टालना या भूलना या तुच्छ समझते हुए छोड़ना नहीं चाहिए। सूर्यचन्द्र चक्रवर्ती वि. प. वगाल सरकार⁷ में जबकि आरोपों का विवरण दोषी कर्मचारी को नहीं दिया गया, तो उसे समुचित अवसर प्रदान करने से मनाई करना माना गया और उसे सवा में हटाने का आदेश रद्द किया गया। परन्तु कन्हूदलाल वि. राजस्थान सरकार⁸ के एक पुराने मामले में चार्ज-शीट स्वयं बहुत विस्तृत थी और उसमें वे सभी आरोप समाविष्ट थे जिन पर अभियोग आधारित थे और जाच अधिकारी ने अपने निष्कर्षों में उन से बाहर की किसी भी परस्थिति पर विचार नहीं किया। अतः प्रार्थी को आरोपों का विवरण नहीं देना केवल एक ऐसी अनियमितता मानी गई जिसमें मामले के गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।

लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नोटिस —चार्ज-शीट और आरोपों के विवरण के माध्यम दोषी राज्य कर्मचारी को एक नोटिस भी भेजना चाहिए जिसमें उसे अपना उत्तर पेश करने के लिए

1. AIR 1961 कलकत्ता 47—अमूल्य रतन वि. डिप्टी चीफ मेवेनिकल एन्जीनियर, और 1974 (1) SLR 285 और 1974 (2) SLR 466
2. AIR 1964 मद्रास 374—एस. मणिकम वि. पुलिस अधीक्षक।
3. AIR 1963 पटना 38—श्रीकांत उपाध्याय वि. भारतीय सघ।
4. AIR 1956 पंजाब 58—बपूर सिंह वि. भारतीय सघ।
5. AIR 1960 पंजाब 147—विनोद चन्द्र वि. भारतीय सघ।
6. 1977 WLN 421—फनेहमिह वि. राजस्थान सरकार।
7. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 275 : 1971 SLR 103.
8. AIR 1958 राजस्थान 1।

कहा जाए-अर्थात् वह अपना लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसमें व्यक्त करे कि आया वह अधिरोपित सभी या उनमें से कुछ अभियोक्तों की सत्यता को स्वीकार करता है और उसे क्या स्पष्टीकरण या प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, देनी है और यह भी बतावे कि आया वह व्यक्तिगत मुनबाई का अवसर चाहता है। उक्त नोटिस में एक अवधि निर्दिष्ट करनी चाहिए जिसमें दोषी कर्मचारी को अपना लिखित प्रतिवेदन प्रेषित करना है। ऐसे मेमोरेण्डम, नोटिस गृहित का आदर्श प्रथम परिशिष्ट 'क' में दिया गया है। राज्य कर्मचारी को अपना लिखित प्रतिवेदन पेश करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए। जब कि प्रार्थी को उत्तर पेश करने के लिए केवल एक दिन का समय दिया गया तो उसे नितान्त अपरिधान समझा गया¹ और यह फैसला हुआ कि कर्मचारी को समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।² साधारणतः 15 दिन से एक महीने तक का समय देना चाहिये।

आया कोई कार्यवाही बंद की जा सकती है ?

किसी सिविल कर्मचारी के विरुद्ध हो रही जाच को बंद करने के लिए सरकार सदैव स्वच्छन्द है।³ निर्देश (रेफ़रेन्स) करने के अधिकार के साथ उसको वापिस लेने का अधिकार जुड़ा हुआ है।⁴ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम राज्य कर्मचारी को यह अधिकार प्रदान नहीं करता कि वह ऐसा आग्रह कर सके कि जो जाच उसके विरुद्ध आरम्भ की गई है उसका अन्तिम निर्णय दिया जावे या अन्तिम निर्णय नहीं होने तक उसे सेवा में रखा जावे। नवल किशोर दुवे वि. राजस्थान सरकार⁵ में, प्रार्थी को नियम 16 के अधीन अभियोग-पत्र और आरोपों का विवरण दिया गया, परन्तु तत्पश्चात् कोई जाच नहीं की गई, और वह राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया गया। प्रार्थी की दलील यह थी कि उसे रिटायर करने में पहले उसने विरुद्ध आरम्भ की गई जाच पूरी की जावे। न्यायालय ने यह दलील प्रस्वीकार करते हुए फैसला दिया कि जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है या सेवा से रिटायर कर दिया जाता है वह सरकारी सेवाओं का सदस्य नहीं रहता। जैसे ही एक दफा सेवा निवृत्ति का आदेश प्रभावशील हुआ तब से ही वह सेवा से पदान्तरित, हटाया जाना या बर्खास्त नहीं किया जा सकता और इस लिए, उसके विरुद्ध कोई जाच नहीं की जा सकती।

नियम 16 (3) — दोषी कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए न्यायोचित अवसर प्रदान करने के लिए नियम 16 (3) में प्रावधान किया गया है कि वह सरकारी रेकर्ड का निरीक्षण कर सके और उनमें से उद्धारण ले सके। सिवाय निम्नांकित अपवादों के सामान्यतः उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी:—

- (1) यह कि ऐसा रेकर्ड इस प्रयोजन के लिए सुसंगत (सारभूत) (relevant) नहीं है, अथवा
- (2) यह कि ऐसे रेकर्ड तक पहुँचने (access) की अनुमति देना सावजनिक हित के प्रतिकूल है।

1 AIR 1961 कलकत्ता 628—गुधीर रजन वि पश्चिम बंगाल सरकार AIR 1965 पन्नाब 352

2 AIR 1958 राजस्थान 1—बन्हालाल वि राजस्थान सरकार।

3 AIR 1961 मध्य प्रदेश 293—एस एस पाण्डे वि मध्य प्रदेश सरकार।

4 AIR 1962 आन्ध्रप्रदेश 303—आर. मरकय्या वि अनुशासन कार्यवाहियों का ट्रिब्यूनल।

5 AIR 1967 राजस्थान 82

सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण करने और उनमें से उद्धरण लेने से इन्कार करने की सूचना देने का अनुशासन प्राधिकारी का आदेश परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र स 10 के प्रतिरूप होना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने अपनी अनुशासन कार्यवाहियों की पुस्तिका, सस्करण 1963 के अनुच्छेद 11 में उक्त विषय में विस्तृत निर्देश दिए हैं जो ऊपर दिए जा चुके हैं।¹

उपयुक्त निर्देशों में व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई सरकारी रेकार्ड जो केवल सरकार के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वह भी जिससे प्रतिरक्षा की कोई विचारधारा सम्भव बन सकती हो, उसके निरीक्षण के लिए दोषी कर्मचारी आवेदन करे तो उसे इजाजत दी जानी चाहिए। यद्यपि किसी दस्तावेज की सुसंगतता अनुशासन प्राधिकारी को आवेदन करते समय स्पष्ट नहीं हो तो भी आधारगत, अनुमति देनी चाहिए।

सार्वजनिक हित के आधार पर भी किसी दस्तावेज को दिखाने से इन्कार करने की शक्ति का प्रयोग भी बहुत सतर्कता व सावधानी से करना चाहिए। यदि यह बहुत सम्भव हो कि किसी दस्तावेज की आवश्यकता अभियोग साबित करने के लिए होगी, तो उसका निरीक्षण करने के लिए कर्मचारी को अनुमति देनी चाहिए। परन्तु जिन दस्तावेजों का दिखाना वास्तव में सार्वजनिक हित में नहीं है, उनको देखने की इजाजत बदापि नहीं देनी चाहिए। 'इन्कारी का आदेश विश्वस्त और ठोस होना चाहिए और लिखित होना चाहिए।'

प्रारम्भिक जाच करने वाले अधिकारी की सरकार को या अन्य प्राधिकारी को दी जाने वाली रिपोर्ट और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 173 की उप धारा (1) के अनुच्छेद (क) (जैसा कि वह 1974 के अधिनियम स 2 जारी होने से पहले स्थित था) की रिपोर्ट के अनिरिक्त जो रिपोर्ट अन्वेषण (तफतीश) के बाद पुलिस तम्भार करती है, वे आम तौर से गोपनीय होती हैं और उनको राज्य कर्मचारी को देखने देना आवश्यक नहीं है।

प्रारम्भिक जाच में या पुलिस अन्वेषण के दौरान लिए गए गवाहों के सभी बयानों की दोषी कर्मचारी को निरीक्षण करने की अनुमति देना जरूरी नहीं है। केवल उन्हीं गवाहों के बयानों का निरीक्षण करने की इजाजत देनी चाहिए जिनको अभियोगों तथा आरोपों के विवरण में उल्लेखित सध्यों को साबित करने के लिए माह्व में प्रस्तुत करना प्रस्तावित हो। लेकिन प्रारम्भिक जाच या पुलिस तफतीश के दौरान अभिलिखित किये गये बयानों की भाग विभागीय जाच के समय प्रस्तावित गवाहों से जिरह करने के लिए बो जा सकती है। अतः, राज्य कर्मचारी को केवल ऐसे गवाहों के बयान पढ़ने की अनुमति दी जानी चापिए न कि अन्य गवाहों के लिए जिनके लिए निरीक्षण करने की अनुमति अस्वीकार की जा सकती है। परन्तु उक्त प्रस्तावना में भी एक अपवाद है। यदि पहले का बयान उस समय या उसके आसपास अभिलिखित किया गया था जबकि घटना घटित हुई और बयान देने वाले व्यक्ति को किसी कार्यवाही में इसी बात के विषय में साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है, तो कानून महादय के अधीन पूर्ववालीन बयान का उसकी पुष्टि (Corroboration) के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य कर्मचारी को पूर्ववालीन बयानों का मुद्रायता

1 सरकार स F 3 (25) नियुक्ति (ए) 61/ग्रुप III दिनांक 14-2-1962 तथा इसी सहायक सरकार स 8-11-1962.

करने की इजाजत दी जानी चाहिए। कृष्णलाल गोदारा वि राजस्थान सरकार¹ में सम्मति प्रवृत्त की गई कि प्रारम्भिक जाच में लिए गए गवाहों के बयान विशेषाधिकार के दस्तावेज (privileged documents) नहीं होते क्योंकि उनसे कोई नाबजर्निक हित को हानि नहीं पहुँचती।

दस्तावेजों की नकलें

नियम 16 (3) में दस्तावेजों की नकलें देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, साधारणतः दोषी कर्मचारी को नकलें देना जरूरी नहीं है और इतना ही पर्याप्त होगा कि उसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने और उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति दी जाय। ध्यान रहे कि उद्धरण लेने के लिए केवल कच्ची पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है न कि म्याही, पेपरिंग पेंसिल का, या बॉन पॉइंट का। रेकॉर्ड का मुद्रायना करते वक्त दस्तावेजों पर किसी भी प्रकार का निशान लगाना निषिद्ध है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, बयानों का उपयोग केवल सम्बन्धित गवाहों से जिरह करने के लिए किया जा सकता है। अतः ऐसे बयानों की प्रतियाँ बनाए जायें जहाँ माग तभी करनी चाहिए जब कि उन गवाहों को गवाहों के लिए बुलाया गया हो। यदि नकलों के लिए आवेदन नहीं किया, तो यह समझ लिया जाएगा कि इस प्रयोजन के लिए नकलों को जरूरत नहीं थी। ऐसी प्रतियों का उपयोग किसी बाद की अवस्था में नहीं किया जा सकता, न ऐसे बयानों पर अनुशासन प्राधिकारी विचार ही कर सकता है। ऐसी प्रतियाँ सम्बन्धित गवाहों के बयान होने से पहले ख़ास समय में दी जानी चाहिए। गवाहों के बयान लेने से पहले की अवस्था में, नकलों के लिए दिया गया आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। परन्तु यदि दोषी कर्मचारी ऐसी प्रतियों के लिए आग्रह करे, तो अनुशासन प्राधिकारी अपने स्वविवेक में अनुमति दे सकता है ताकि कर्मचारी अभियोगों के उत्तर में अपना प्रतिवेदन उनके आधार पर तैयार कर सके।

कभी कभी दोषी कर्मचारी सरकारी रेकार्डों की फोटो-स्टेट नकल बनवाने की अनुमति के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि ऐसे दस्तावेज मामले में ठोस महत्व रखते हों (मसलन हस्तलिपि या हस्ताक्षरों का सङ्ग्रह) तो (सरकारी निदेश अनुसार) सही वक़्त यह होगा कि ऐसी फोटो-स्टेट नकलें सरकार स्वयं बनवाले और कर्मचारी को उपलब्ध करा दे क्योंकि किसी निजी फोटोग्राफर द्वारा फोटो खिंचवाने में बाहरी व्यक्ति को सरकारी रेकार्ड देखने का मौका मिलता है जो अनुचित है। अन्य प्रकार के मामलों में, जिनमें फोटो स्टेट नकलें अनावश्यक हैं, ऐसी अनुमति अस्वीकार की जा सकेगी।

अनुशासन प्राधिकारी, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट² और गोपनीय प्रारम्भिक जाच में लिए गए बयान³ व भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट⁴ का निरीक्षण करने और उनमें से उद्धरण लेने की अनुमति अस्वीकार कर सकेगा। यदि रेकार्ड महत्वपूर्ण हों, तो उसका निरीक्षण करने या नकलें देने, यथा स्थिति, की अनुमति दी जानी चाहिए अन्यथा राज्य कर्मचारी यह दलील कर सकेगा कि जिन सारभूत दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करने का उसे अधिकारी था उनके लिए जाच अधिकारी द्वारा

1 1969 WLN 17 1969 SLR 667

2 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 493—पंजाब सरकार वि सोधी मुखदेवसिंह।

3 AIR 1959 उड़ीसा 152—जामेश बुशी वि कलेक्टर गजम।

4 AIR 1957 पटना 357—पुनीतलाल साहा वि बिहार सरकार।

इन्वारी करने के कारण वह गवाहों से प्रभावशील तरीके से जिरह करने से वंचित रहा। इसकी प्रावृत्ति-व्याप के सिद्धान्त की अवहेलना माना जा सकता है।¹ जब कि राज्य कर्मचारी को महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं दिए गए, तो निर्णय हुआ कि उसे नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।² चाहे दोषी कर्मचारी ने लिखित उत्तर पेश किया हो या नहीं, उसे गवाहों का बयान लेने से पहले दस्तावेजों का मुआयना करने का हक है।³

प्रतिरक्षा की तैयारी—दोषी कर्मचारी को अपना बचाव पक्ष तैयार करने के लिए सरकारी रेकार्ड का निरीक्षण करने का हक अधिकार स्वरूप प्राप्त है। यह कानून द्वारा प्रदत्त एक अवसर है। यह अवसर वास्तविक होना चाहिए न कि विधि की खाना पुस्तिका, प्रभावशील होना चाहिए न कि दिवावटी और उसके बाद कर्मचारी के स्पष्टीकरण पर वायिक विचार किया जाना चाहिए।⁴

यात्रा भत्ता :

अनुशासन प्राधिकारी की अनुमति से, दोषी कर्मचारी, अपनी प्रतिरक्षा के लिए की गई यात्राओं के लिए यात्रा-भत्ता उठा सकेगा। जाच की कार्यवाही की तारीखों पर उपस्थित होने के लिए भी वह यही यात्रा भत्ता पान का अधिकार होगा जो वह साधारणतः नियमानुसूल पाने का हकदार है। निम्नस्वन की अवस्था से भी भत्ते की दरों में कोई अन्तर नहीं आएगा। इस विषय में राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों का नियम 27 (2) लागू होगा।

नियम 16 (4)—प्रावधान करता है कि यदि दोषी कर्मचारी उसके विरुद्ध अधिरोपित अभियोग या अभियोगों को स्वीकार करले तो अनुशासन प्राधिकारी इसी अवस्था (stage) पर प्रत्येक चार्ज पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और नियम 16 (10) से (12) के अनुसार अन्तिम निर्णय के लिए कार्यवाही करेगा। इससे प्रतिकूल, यदि प्रतिरक्षा के लिखित प्रतिवेदन में, सभी अभियोग स्वीकार नहीं किए जावें या निर्धारित अवधि में कोई ऐसा प्रतिवेदन पेश ही न हो, तो अनुशासन प्राधिकारी या तो दोषी द्वारा अस्वीकृत अभियोगों पर जाच स्वयं करेगा या उन की जाच मण्डल द्वारा या प्रपन स 7 के अनुसार नियुक्त जाच अधिकारी से करवाएगा। यह उप-खण्ड G S R स 129* के अधीन प्रतिस्थापित किया गया है। पहले स्वीकारे गए अभियोगों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं था। उप-खण्ड (4 क)* भी तथा जोड़ा गया है (उसी G S R स 129 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा)। नए उप-खण्ड 4 क के अनुसार, यदि दोषी कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा के लिखित उत्तर में चार्ज का कोई आर्टिकल स्वीकार नहीं करे, अथवा उमने कोई लिखित उत्तर पेश ही नहीं किया हो परन्तु जो स्वयं जाच प्राधिकारी के सम्मुख उपस्थित हो, तो जान प्राधिकारी उनसे पूछेगा कि आपका यह अपराधी है या कोई वरियत पेश करनी है और यदि इस स्टेज पर भी वह किसी अभियोग पर वह अपना दोष स्वीकार करले तो जाच अधिकारी उमना बयान अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा। ऐसे रेकार्ड पर वह उक्त राज्य कर्मचारी के हस्ताक्षर भी करवाएगा। जाच प्राधिकारी स्वीकारे गए अभियोग पर अपराधी होने का निष्कर्ष लिखेगा और जिन अभियोगों को राज्य

1 AIR 1961 मुंबई कोर्ट 1623—मध्य प्रदेश सरकार वि चिन्तामन मदनान्न बैजम्पादन।

2 AIR 1961 आन्ध्र प्रदेश 289।

3 AIR 1971 दिल्ली 133—नूरुलमिह वि एम आर यशी।

4 AIR 1970 केरल 65—दुर्गाहिम कुजा वि करल सरकार।

*स F. 3 (17) नियुक्ति (A III)/67 दि 9-10-74।

कर्मचारी ने स्वीकारा नहीं है उन के विषय में जाच करने के लिए प्रागे कार्यवाही करेगा। यदि वह अपना अपराध स्वीकार नहीं करे और प्रतिरक्षा प्रस्तुत करना चाहे, तो नियमों के अनुसार प्रागे जाच की जाएगी।

जब कि राज्य कर्मचारी ने साफ शब्दों में अपना दोष स्वीकार कर लिया हो और वह उसके विरुद्ध प्रचिरोपित अभियोग प्रणीकार करे, तो सिवाय नियम 16 के उप-नियम (9), (10) (11) तथा (12) के अधीन कार्यवाही करने के, और कोई प्रागे जाच करने की जरूरत नहीं होगी।¹ निष्कर्ष स्थापित करने के लिए दोष की स्वीकारोक्ति स्पष्ट और सदेह रहित शब्दों में होनी चाहिए। जब कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दोष की सदेह रहित स्वीकारोक्ति नहीं थी, तो उसके आधार पर उसके विरुद्ध पारित पक्षास्तमी के प्रादेश को विम्वृत जाच के अभाव में अत्यन्त दुर्बल माना।² जब कि प्रार्थी ने जाच की कार्यवाही में अपने आपको जाच अधिकारी की दया पर छोड़ दिया और दया की प्रार्थना के आधार पर अपनी पैरवी करन (भाभला भगडने) में इन्कार कर दिया, तो निर्णय हुआ कि उसको दी गई सजा बंद थी और उसका दिया गया अवसर कानूनन परियाप्त था।³ जब कि आरोपी की स्वीकृति अपवादरहित नहीं थी, जिसमें यह पक्ष प्रस्तुत किया गया था कि उसके द्वारा की गई अनियमितताएं ऐसी परिस्थितियों की वजह से हुईं जो कि उसके नियन्त्रण के बाहर की थीं, और जाच अधिकारी ने न तो प्रार्थी की प्रतिरक्षा के इस आरोप को रण्डित करने के लिए किसी गवाह का बयान लिया और न ही दोषी कर्मचारी को उसके स्पष्टीकरण में उल्लेखित विशेष परिस्थितियाँ साबित करने का मौका दिया और प्रतिरक्षा के इस भाग पर विचार ही नहीं किया, तो निर्णय हुआ कि जाच अधिकारी ने अपना दिमाग नहीं सगया और बिना किसी गहावत के प्रार्थी का अस्थायी दुर्व्ययोग (temporaty misappropriation) का दोषी मानकर वह अपने अर्ध-न्यायिक कर्तव्यों के पालन में विफल हुआ है। इससे प्राज्ञातिव न्याय क सिद्धान्त का गुना उल्लंघन हुआ है, इसलिए, उसका निष्कर्ष कायम नहीं रखा जा सकता।⁴

जाच अधिकारी की निपुक्ति—अनुशासन प्राधिकारी या तो स्वयं ऐसे अभियोगों की जाच कर सकेगा जिन्हें सम्बन्धित राज्य कर्मचारी ने अंगीकार नहीं किया है या वह जाच करने वाले प्राधिकारी जिसे आम तौर से 'जाच अधिकारी' कहा जाता है, कि निपुक्ति करेगा या एक जाच मण्डल का गठन कर सकेगा। जाच अधिकारी केवल तथ्यों का पता लगाने वाला प्राधिकारी होता है।⁵ प्राज्ञातिव न्याय के नियमानुसार, वह मामले में व्यक्तिगत रुचि रखने वाला या पक्षपातधारी नहीं होना चाहिए।⁶ वह खुले दिमाग का तथा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध पक्षपाती रख रखने वाला नहीं होना

1 AIR 1961 त्रिपुरा 1—रविन्द्र पोहन वि अरवन ट्रस्ट, त्रिपुरा।

AIR 1965 जम्मू-कश्मीर 53 तथा AIR 1963 बम्बई 121।

2 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1070—जे. पी. सक्सेना वि मध्य प्र सरकार, ILR (1963) 13 राजस्था 7 28।

3 AIR 1963 पंजाब 137

4 1972 Lab IC 734 (कलकत्ता)।

5 AIR 1964 आन्ध्र प्रदेश 407—अब्दुल रहीम वि चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर।

6 AIR 1964 गुजरात 139—ए एस राजकी वि डिविजनल अभियन्ता।

चाहिए।* एक अधीनस्थ अधिकारी को जाच प्राधिकारी के अधिकार सुपुर्द किये जा सकते हैं, परन्तु वह दोषी राज्य कर्मचारी के पद स्तर से ऊँचा होना चाहिए।¹ जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के विरुद्ध अधिरापित अभियोगों की जाच करने के लिए उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्त किया तो यह निर्णय हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मामले में स्वयं जाच करे और वह अन्य न्यायाधीश का यह कार्य सुपुर्द करने के लिए सक्षम था।² एक अन्य मामले में, भारत सरकार के सचिव ने एक राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग निघारित किए और डिप्टी हाई कमिशनर को जाच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया तथा कथित राज्य कर्मचारी को कहा गया कि वह अपने निश्चित प्रतिवेदन डिप्टी हाई कमिशनर द्वारा चुने गये जाच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। जाच अधिकारी ने अपने जाच की रिपोर्टें भारत सरकार को प्रेषित की और दोषी कर्मचारी को दूसरा नोटिस जारी करने के पश्चात् तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर, कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। हमने यह दलील दी गई कि भारत सरकार के सचिव का यह अधिकार नहीं था कि वह जाच अधिकारी का चुनाव करने की अपनी शक्ति किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द करदे। इस मामले में निर्णय किया गया कि वास्तव में कोई सुपुर्दगी निरुत्तल ही नहीं हुई। जो अधिकारी मामले में निर्णय देने का प्राधिकार रखता था वह उसकी सामग्री एकत्र करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता था। जब तक कि ऐसा प्राधिकारी मामले में चुनाव करने के अपने आवश्यक कर्तव्य का परित्याग नहीं करदे और एकत्रित की गई सामग्री पर स्वयं का दिमाग न लगाए और अपने खुद के निष्कर्षों पर न पहुँचे तो सामग्री एकत्रित करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करने हेतु आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।³ इसी प्रकार जबकि एक जाच समिति का गठन डिबिजनल अभियन्ता के स्थान पर सहायक अभियन्ता ने किया तो निर्णय हुआ कि जाच समिति द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मूल्यहीन नहीं थी तथा उस पर फायदाही की जा सकती थी।⁴ अनुशासन प्राधिकारी जाच संचालन का अधिकार किसी को सुपुर्द कर सकता है⁵ परन्तु जाच अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर जाच अधिकारी का कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकता।⁶ न तो जाच अधिकारी नया अभियोग लगा सकता है,⁷ और न ही किसी दण्ड की सिफारिश कर सकेगा।⁸

मैज-इन्स्पेक्टर पुलिस का पद अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित है और इन नियमों से मूलन अनुसूची II में उल्लिखित है। नियम 15 के अनुसार, विभागाध्यक्ष या राज्य सरकार के अनुमादन ॥ उसके द्वारा विशेषतः प्राधिकृत प्राधिकारी को हक है कि वह नियम 14 में बताई हुई सभी

* AIR 1956 कलकत्ता 661-ए आर. एस चौधरी वि भारतीय सघ।

1 AIR 1954 मुम्बई कोर्ट 285-प्रफुल्ल कुमार वि मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता।

2 1965 RLW-166

3 AIR 1968 दिल्ली 24-ए एम सेटी वि भारतीय सघ।

4 ILR 1961-राजस्थान-63-मदनसिंह वि भारतीय सघ।

5 AIR 1964 आन्ध्रप्रदेश 407-अनुन रहीम वि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।

6 AIR 1964 मध्य प्रदेश 318-मानन्द नारायण वि मध्य प्रदेश सरकार।

7 1964 मैसूर 221

8 AIR 1962 मुम्बई कोर्ट 1130

शास्तियां अधिरोपित कर सके। इस प्रकार, प्रार्थी मव इन्स्पेक्टर पुलिस से सम्बन्धित अनुशासन प्राधिकारी, विभागाध्यक्ष होने के नाते, आई जो पुलिस या न कि डिप्टी आई जो पुलिस। चूंकि डिप्टी आई जो पुलिस को राज्य सरकार के अनुमोदन में, प्रार्थी के विरुद्ध जाच प्रारम्भ करने के लिए आई जो पुलिस ने विशिष्ट अधिवृत्त नहीं किया था इसलिए, प्रार्थी को नियम 16 के अधीन चाज-शीट और आरोपों के साथ जारी किया गया नोटिस धर्वाच करार दिया गया और रद्द किया गया।¹ जाच प्राधिकारी का पद स्तर इन नियमों में दिए गए निर्देशानुसार होना चाहिए।² यह आवश्यक नहीं है कि जाच अधिकारी स्वयं शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी हो या उसके बराबर के पद स्तर का हो।³ जब कि पहले नियुक्त किए गए जाच अधिकारी का स्थानान्तरण जाच के दौरान हो जान के कारण उसके स्थान पर दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो दूसरे जाच अधिकारी द्वारा पूरी की गई जाच को दूषित होना नहीं माना गया।⁴ मुख्यगोष्ठ (शिकायतकर्ता) को या किसी ऐसे अधिकारी को जाच प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसकी रिपोर्ट पर जाच प्रारम्भ की गई थी।⁵ जाच अधिकारी व्यापारिक के समान होना है इसलिए उससे यह भाशा की जाती है कि वह पक्षपात रहित तरीके से अनुमनना रहित (with no attachments), खुले दिमाग में शालीनता से कार्य करे।⁶ जो मामला उसे जाच करने के लिए सुपुर्द हुआ है, उसमें वह व्यापारिक और गवाह दोनों नहीं हो सकता।⁷

राजस्थान सरकार ने निर्देश जारी किए हैं जिनमें परामर्श दिया है कि सामान्यतः जाच मण्डल का गठन नहीं करना चाहिए जब तक कि मामला बहुत जटिल और उलझन भरा न हो। जाच अधिकारी का चुनाव करने में आरोपों की गंभीरता और दोषी राज्य कर्मचारी के पद स्तर का खयाल रखना चाहिए। जाच ऐसे अधिकारी को सुपुर्द नहीं करनी चाहिए जिसने पुढे में प्रारम्भिक जाच की थी या जिसने पहले मामले के विवाद प्रस्त विन्दुओं पर अपनी सम्मति प्रकट की थी। जाच अधिकारी के कर्तव्य पालन करने हेतु ऐसे अधिकारी को चुनना चाहिए जो अपनी पक्षपात हीनता और न्यायिकता के लिए प्रसिद्ध हो। जाच चालू रहने जब एक जाच अधिकारी के स्थान पर दूसरा अधिकारी नियुक्त किया जावे तो उसकी नियुक्ति भी निर्धारित प्रपत्र स 7 द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी परस्थितियों में दोषी कर्मचारी को फिर से नई जाच प्रारम्भ करने की भाव करने का अधिकार नहीं है। जब तक कि किसी विशिष्ट मामले में, नव नियुक्त जाच अधिकारी, मामले की परस्थिति का वा देखत हुए, दुबारा गवाही लेना आवश्यक नहीं समझे, तब तक उसे ऐसा करना जरूरी नहीं है।

नियम 16 (5) —इस नियम के अधीन, अनुशासन प्राधिकारी किसी व्यक्ति को जाच अधिकारी के समक्ष अभिमोक्ष की पुष्टि में मामला प्रस्तुत करने अर्थात् पेश करने के लिए नियुक्त

- 1 1977 WLN 421—पतहसिंह लोढा वि. राजस्थान सरकार।
- 2 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 122—भारतीय सघ वि. जगजीत सिंह।
- 3 AIR 1960 आन्ध्रप्रदेश 473—मध्यप्रदेश सरकार वि. शार्दूल सिंह।
- 4 AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 1095—जनरल मैनेजर पूर्वी रेलवे वि. ज्वाला प्रसाद सिंह।
- 5 1956 कलकत्ता 662 व AIR 1955 पेपसू 127 और 1975 Lab IC 682 (इलाहाबाद)।
- 6 AIR 1958 पंजाब 327, AIR 1962 त्रिपुरा 15
- 7 AIR 1956 कलकत्ता 278—आशुतोष दास वि. प. बंगाल सरकार।

कर सकेगा। विरोधी पक्ष की ओर से दोषी राज्य कर्मचारी स्वयं अपने मामले की पैरवी कर सकता है या किसी अन्य राज्य कर्मचारी का चुनाव अनुशासन प्राधिकारी के अनुमोदन से कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए साधारणतः राज्य कर्मचारी को वकील नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, परन्तु यदि अनुशासन प्राधिकारी द्वारा अभियोगों की पुष्टि में पैरवी करने वाला व्यक्ति कोई वकील, पब्लिक प्रोसीक्यूटर या प्रोसीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर या प्रोसीक्यूटिंग सब-इन्स्पेक्टर हो, तो दोषी कर्मचारी का भी अधिकार होगा कि वह अपनी पैरवी वकील से करवा सके।

इसके अतिरिक्त यदि मामला इतना जटिल व उलझन भरा हो कि कर्मचारी के लिए अपनी प्रतिरक्षा ठीक तरह से करना कठिन हो, तो अनुशासन प्राधिकारी उसे वकील से सहायता लेने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।

प्रतिरक्षा में अन्य राज्य कर्मचारी (जिसे सहायक अधिकारी कहते हैं) की सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए —

- (1) प्रस्ताविन सहायता अधिकारी की लिखित स्वीकृति पेश करनी होगी।
- (2) प्रस्तावित सहायता अधिकारी को अपने स्वयं के उच्च अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- (3) उक्त सहायता अधिकारी ने दोषी कर्मचारी द्वारा पैरवी में सहायता लेने हेतु अनुशासन प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

राजस्थान सरकार ने निर्देशन जारी करके सलाह दी है कि अभियोजित व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए उपयुक्त अवसर मिलना चाहिए "इसलिए यदि मामला अत्यन्त जटिल और कठिन हो या जब कि अभियोजित व्यक्ति को संभवतः दुविधा का सामना करना पड़ेगा, तो उसे वानूनी सहायता लेने की इजाजत दी जानी चाहिए: (1957 आन्ध्रप्रदेश 414, 1958 इलाहाबाद 532 और 1961 कलकत्ता 1)।" परन्तु इसकी अनुमति अत्यन्त अपवाद स्वरूप परस्थितियों में दी जानी चाहिए और उसके कारण रेकॉर्ड में लिखित में अभिहित करने चाहिए।* किन्तु सरकार का आशय यह है कि सामान्यतः दोषी कर्मचारी को वकील की सहायता लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।†

अन्य राज्य कर्मचारी से सहायता लेने का राज्य कर्मचारी को अधिकार — यह एक वानूनी अधिकार है जिसको प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। सी एल मुक्तामणियम वि कस्टम क्लेक्टेडर¹ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह अधिकार आदेशात्मक (mandatary) है जो विधान के अनुच्छेद 311 के अधीन दी गई शारटी को नियमित करता है, क्योंकि राज्य कर्मचारियों को ग्राम सीर में वानूनी प्रशिक्षण नहीं होता। अतः दोषी कर्मचारी को प्रतिरक्षा का अवसर देने के लिए अन्य

* अनुशासन कार्यवाहियों की राजस्थान सरकार की पुस्तिका, अनुच्छेद 12.

† परिपक्वता न. F. 2 (35) Appts (A)/57 दिनांक 7-10-58; F. 23 (36) Appts (A) 57 दिनांक 17-10-58; न. D. 14340/F 23 (65) Appts A/57 दि. 7-10-58 और न. D. 14340/F 23 (65) Appts (C) 55 दिनांक 31-12-56

1. 1972 Lab, IC 10-49 (मुख्यम बोटें) : AIR 1972 SC 2178

राज्य कर्मचारी से मदद लेने की इजाजत दी जाती है। मभवत दोषी कर्मचारी अपना पक्ष स्वयं संचालित करने की सही मानसिक स्थिति में नहीं होता, उसकी धनसा, सहायता अधिकारी उससे अधिक विद्वान तथा कामकुशल हो सकता है। अतः न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि न्यायिक सुनवाई के इस अवशेष में प्रशासन दखल नहीं करे।¹ जब दोषी कर्मचारी द्वारा सहायता के लिए चुने गए व्यक्ति को किसी भी कारण से अनुमति नहीं दी जा सके तो अनुशासन प्राधिकारी को चाहिए कि वह किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करके उसे दोषी कर्मचारी को बहे।² भारतीय संघ वि अन्दुल कादर³ में तय किया गया कि जब, दोषी कर्मचारी को अपने पक्ष की प्रतिरक्षा करने के लिए अन्य राज्य कर्मचारी से सहायता लेने की अनुमति नहीं दी गई तो पक्षपत स्वन हो गया जिसके लिए किसी अन्य सबूत की जरूरत नहीं है और इस कारण से जांच दूषित हो गई।

वकील की सहायता — जैसा कि ऊपर बताया गया है साधारण तौर से दोषी कर्मचारी को अपने बचाव में पैरोकारी वकील से करवाने का अधिकार नहीं होता। इसलिए, इसके लिए मांगी गई अनुमति अस्वीकार करना उपयुक्त अवसर देने से इनकार करना नहीं होता।⁴ एक निरा बयान कि जांच अधिकारी ने दोषी कर्मचारी के मामले में प्रोमीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर से परामर्श लिया, जब कि रेकार्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं था जो यह सबन करता कि जांच अधिकारी ने प्रोमीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर से किसी भी प्रकार से सहायता ली, तो निर्णय हुआ कि गेमपो-डेंट को वकील से सहायता लेने का अधिकार स्वरूप हक कोई नहीं था।⁵

इसके विपरीत जब कि मामले के तथ्य जटिल हैं या उनमें कोई कानूनी मुद्दा समाविष्ट हो, या विषय तकनीकी हो या ग्राह्यत बहुत ज्यादा हो, तो वकील नियुक्त करने की अनुमति अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा क्योंकि दापी कर्मचारी को अपना बचाव करने का समुचित अवसर अस्वीकार कर दिया गया।⁶

एक राज्य कर्मचारी पर दुस्ययोग misappro priation) का अभियोग लगाया गया। उसने अपनी प्रतिरक्षा के लिए वकील नियुक्त करने की प्रार्थना की, परंतु अनुमति इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि प्रथम तो उसने जांच में भाग नहीं लिया जो इकतर्फी की गई और द्वितीय यह कि उस सेवा से हटा दिया गया है। इस मामले में निर्णय हुआ कि इस अस्वीकृति से नियम 16 (5) का उल्लंघन हुआ क्योंकि उसे अपने आप की प्रतिरक्षा करने का समुचित अवसर मना कर दिया गया।⁷ अब कि विभाग ने इन बातों पर विचार ही नहीं किया कि दायी मामले की परिस्थितियों में वकील की सहायता लेना वाजिब है या नहीं, तो अस्वीकृति का आदेश खारिज किया गया।⁸ जब

1 AIR 1970 कलकत्ता 545-भारतीय संघ वि एस बी विस्वास।

2. 1975 Lab IC 1140 (केरल)-एन पी पद्मनाभ व डाकस्तानो के अधीक्षक।

3. 1977 Lab IC 974 (बम्बई)

4 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1589-वृष्णचन्द्र टण्डन वि भारतीय संघ, AIR 1961 RLW-104 ए के व्यास वि राजस्थान सरकार।

5 1977 WLN 645 राजस्थान सरकार वि दान मल।

6 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1589-वृष्ण चन्द्र टंडन वि भारतीय संघ।

7. AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 2178

8 1978 Lab IC 654 मद्रास-एस वाई वैकटश्वरलु वि डाइरेक्टर जनरल।

कि अनुशासन प्राधिकारी को वरियत के लिए वकील की इजाजत हेतु प्रार्थना की जावे, तो दोपी कर्मचारी को ऐसी प्रार्थना पर समुचित विचार करना होगा। जब कि एक मामले में अनुशासन प्राधिकारी का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक प्रशिक्षित पुलिस प्रोसीक्यूटर या ए सी डी. की नियुक्ति की गई, तो यह तथ्य हुआ कि यद्यपि ऐसे सहायक अधिकारी को वकील नहीं कहा जा सकता, तथापि दोपी कर्मचारी को वकील की सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए यह एक अच्छा आधार था।¹ परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय ने फंसला दिया है कि स्पेशल पुलिस एसटैबलिशमेन्ट का सदस्य वकील की श्रेणी में नहीं आता।²

नियम 16 (6) (क)-साक्ष्य अभिलिखित करना.—यह नियम सशोधित रूप में जो एस आर 129 में एक 3 (17) नियुक्ति (ए-III)/67 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दोपी कर्मचारी को अपना पक्ष निवेदन करने के लिये सहायक रखने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, जाच अधिकारी के लिए आगे का कदम यह होगा कि वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से 10 दिन की अवधि में अपने गवाहों और अभिलेखों की सूची पेश करने और साथ ही उनकी प्रतियां दोपी कर्मचारी को देने के लिए कहेंगे। गवाहों की सूची प्राप्त होने पर, जाच अधिकारी सूची के अनुसार सारभूत गवाहों को तलब करेगा। तत्पश्चात्, जबकि गवाहान उपस्थित हों और दस्तावेज फाइल पर आजावें, तो वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अपनी गवाहों पर प्रारम्भ करने के लिये आदेश देगा। पहले वह प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को इजाजत देगा कि गवाह की मुख्य परीक्षा (Examination in Chief) करे, उसके बाद दोपी सरकारी कर्मचारी या उसके सहायक अधिकारी को गवाह से जिरह (cross examination) करने की अनुमति देगा। जब गवाह से जिरह पूरी हो जावे, तो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उसकी पुनः परीक्षा (Re examination) केवल उन बिन्दुओं पर कर सकेगा जिन पर जिरह में प्रश्न पूछे गए थे, परन्तु बिना जाच अधिकारी की अनुमति के कोई नया विषय नहीं ला सकेगा। इस प्रकार एक एक करके जब आरोपी की पुष्टि में प्रस्तुत किये गये सभी गवाहों की गवाहान अभिलिखित हो जावे, अर्थात् अभियोग पक्ष की गवाहान वस्तु होने के पश्चात् दोपी कर्मचारी को कहा जायेगा कि वह 10 दिन के भीतर अपने दस्तावेजों व गवाहों की सूची पेश करें। उसके बाद सूची के अनुसार सारभूत गवाहों को तलब किया जाकर प्रतिरक्षा की गवाहान प्रारम्भ की जायेगी। जिन दस्तावेज तथा रेकार्डों की दापी कर्मचारी ने माग की है वे अगर जाच में सारभूत हों तो जाच अधिकारी उसे भगवायेगा। दोपी कर्मचारी या उसका सहायक अधिकारी प्रतिरक्षा के गवाहों का मुख्य परीक्षण करेगा जिसके बाद प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उससे जिरह कर सकेगा और दोपी कर्मचारी उनकी पुनः परीक्षा केवल उन बिन्दुओं पर कर सकेगा जो जिरह में उठाए गये थे लेकिन कोई नया विषय नहीं ला सकेगा। इस प्रकार क्रमानुसार एक एक गवाहों की साक्ष्य समाप्त हो जाने पर वरियत की गवाही बन्द की जायेगी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि जाच अधिकारी किसी गवाह को बुलान या रेकार्डें भगवाने के लिये किसी पक्ष को मना करे तो वह उसके कारणों को रेकार्डें पर लिखेगा। जाच अधिकारी स्वयं भी किसी गवाह से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्याय की दृष्टि में वह उपयुक्त समझे। फिर बहस की अवस्था आ जायेगी जिसके लिये दोनों पक्षों को अवसर दिया जाएगा।

1. AIR 1972 मुंबई कोर्ट-सी एन मुद्रामणियम वि. कनेक्टर, बस्टम्भ, AIR 1973 SLR 7 SC ; 1974 Lab IC 1459 कनकता।
2. 1978 Lab IC (Noc) 47 (मद्रास) पी. एण्ड टी बोर्ड वि. एम ए हनुमन्थन।

यदि दोपी कर्मचारी लिखित में या मौखिक रूप से भी उपयुक्त गवाहों के प्रारम्भिक जाच में दिये गये बयानों की प्रतिया दिलाने का आवेदन करे तो जाच अधिकारी उसको ऐसी प्रतिया दिलवाएगा, जो प्रतिरक्षा साक्ष्य आरम्भ होने से कम से कम तीन दिन पहले दी जायेंगी।

राजस्थान सरकार ने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की अपनी पुस्तिका (1963) के अनुच्छेद 13 में इस विषय में विस्तृत निर्देश दिये हैं जो ऊपर दिये जा चुके हैं। इन निर्देशानुसार मौखिक जाच आरम्भ करने से पूर्व चाहे दोपी कर्मचारी ने अपना लिखित प्रतिवेदन प्रेषित किया हो अथवा नहीं, उसे मौखिक बयान देने का अवसर दिया जायेगा जिस वह अपने लिखित बयान के पूरक रूप में या उसके स्पष्टीकरण में, या उसने लिखित उत्तर दिया ही नहीं हो तो उसके स्थान में उपयोग कर सकेगा। यदि दोपी बयान देने से इन्कार करे तो यह तथ्य रिकार्ड पर लिखित कर लेना चाहिये। बयान देने से इन्कार करना आरोपी को स्वीकार करना नहीं माना जा सकता।

गवाहों के बयान दोपी कर्मचारी की उपस्थिति में लिये जाने चाहिये जिससे उसे जिरह करने का पूरा अवसर देना चाहिये। प्रारम्भिक जाच के दौरान लिये गये गवाहों का पूर्वकालीन बयान इन प्रयोजन को सार्थक नहीं करेगा क्योंकि ऐसा बयान विभागीय जाच का अंग नहीं होता। कर्मचारी की भोजवगी में ही बयान लेना आदेशात्मक है। कर्मचारी की पीठ पीछे उसकी अनुपस्थिति में पूर्व में लिये गये किसी बयान को दिखाया जाकर, उसी आधार पर कर्मचारी को उस गवाह से जिरह करने के लिये नहीं कहा जा सकता जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कन्हैयालाल वि. राजस्थान सरकार में¹ तय किया है। एक दूसरे मामले में जबकि किसी गवाह का बयान प्रार्थी की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया गया, जिससे जिरह करने का उसे कोई मौका ही नहीं था, फिर भी उस गवाह के साक्ष्य के आधार पर शास्ति कठोरतम बना दी गई तो यह नियम दृष्टा कि ऐसी शास्ति का आदेश न्यायिक नियमों के प्रतिकूल था और निरस्त करने योग्य था।²

जबकि प्रार्थी को जाच अधिकारी के कमरे से बाहर रखा गया और गवाह का मुख्य बयान कर्मचारी की अनुपस्थिति में लिखा गया तो यद्यपि उसे गवाह से जिरह करने की अनुमति दी गई, तथापि ऐसा करना जाच नियमों से विरुद्ध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल माना गया।³

साधारणतः दोपी कर्मचारी द्वारा किसी गवाह को बुलाने के लिये की गई प्रार्थना अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए। परन्तु जब ऐसा प्रतीत हो कि उक्त प्रार्थना परेशान करने के लिये या जाच को अनावश्यक रूप से लम्बी करने के दुरादे से की गई है तो प्रार्थना खारिज की जा सकेगी। ऐसी अस्वीकृति का कारण लिखित में अभिलिखित करना होगा।⁴ यह आदेशात्मक है।⁵

शहादत वृत्तान्त के रूप में अभिलिखित करनी चाहिये जैसे कि न्याय अदालतें आमतौर से लिखती हैं परन्तु इसमें महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में गवाहों को शपथ

1 1958 RLW-1,

2 1975 WLN-8—हसनलाल वि. राज सरकार।

3, AIR 1962 पंजाब 496, AIR 1963 पंजाब-399,

4 AIR 1962 राज 265, 1963 इलाहाबाद-94, 1968 सुप्रीम कोर्ट-158

5 1973 ASR 90—मोहम्मद युसुफ भली वि. आन्ध्र प्रदेश सरकार।

नहीं दिलाई जा सकती। गवाह का खर्चा जाच अधिकारी भुदा करेगा और यदि गवाह कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह राजस्थान यात्रा भत्ते के नियम 34 के अधीन यात्रा भत्ता उठा सकेगा।

गवाहों के बयान जाच अधिकारी को स्वयं लिखने चाहिए। यह कार्य वह किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द नहीं कर सकता। किन्तु जब गवाह में प्रश्न पूछे जा रहे हों तब साथ ही साथ जाच अधिकारी के लिखवाने पर श्रुतिलेख (dication) के रूप में जाच अधिकारी से सम्बन्ध कोई टक्का लिपिक या कोई अन्य लिपिक बयान लिख सकेगा। परन्तु जब मारी माखी दस्तावेजों थी और उससे दोषी कर्मचारी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा तो यह अनियमितता दोषभाजित (condoned) की गई।¹ अनुशासन प्राधिकारी स्वयं जाच कर सकेगा, जाच अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने से जाच दूषित नहीं होगी। जब दोषी कर्मचारी ने मौखिक जाच की माग ही नहीं की तो उससे समस्त कार्यवाही दूषित नहीं हुई।² किन्तु जाच अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह दोषी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विषय में उसकी अनुपस्थिति में निजी पूछताछ करे और उस निजी पूछताछ के आधार पर अपना निष्कर्ष देवे।³

चार्जशीट देने के वक्त ही दस्तावेजों और गवाहों की सूची कर्मचारी को दे देनी चाहिए। जब ऐसी सूचियाँ चार्जशीट के पश्चात् भी नहीं दी गई और कर्मचारी न अनुशासन प्राधिकारी के समक्ष और अपील के भीमों में भी कोई आपत्ति नहीं उठाई, तो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इन परिस्थितियों ने प्रार्थी को सर्वे सर्व प्रथम यह आपत्ति उच्च न्यायालय में रिट की कार्यवाहियों में उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।⁴

राजस्थान अनुशासनारम्भक कार्यवाहियाँ (गवाहों का ग्राह्वान तथा प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) नियम 1960 के अधीन दीवानी अदालत की तरह ही गवाहों की उपस्थिति बाध्य करने के लिए जाच अधिकारी सशक्त है। ये नियम इस पुस्तक के अन्त में दिए गए हैं।

जाच अधिकारी को इन नियमों द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का पालन दृढता से करना चाहिये। जबकि एक जाच अधिकारी ने न तो किसी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की और न ही राज्य कर्मचारी को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी से सहायता लेने में अनुमति दी और अधिकारी ने स्वयं सभी गवाहों से जिरह की, तो वह विभागीय कार्यवाही अवैध घोषित की गई।⁵

गवाहों का ग्राह्वान और दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण — जाच अधिकारी का यह वैधानिक कर्तव्य है कि सही समय पर पक्षकार द्वारा आवेदिन गवाहों को तनव करे और यदि वह इस मत का हो कि कतिपय गवाहों को कोई सारभूत माखी नहीं देनी है या जिनका नाम सूची में केवल जाच को किम्ब्वित करने या किसी प्रकार से परेखान करने की नीयत से सम्मिलित किया गया है, तो वह ऐसे गवाहों को बुलाने में इन्कार कर सकेगा। यह महत्वपूर्ण है कि उसे दोषी कर्मचारी के मामले में उदार तथा विशाल हृदय होना चाहिए क्योंकि जिस तथ्य को जाच अधिकारी मामले को सुसंगत नहीं समझता हो वह कर्मचारी के लिए सुसंगत हो जाए। अतः यदि प्रतिरक्षा के गवाहों को ग्राह्वान करने में इन्कार

1 1963 RLW-374-जगन्तराव वि राज सरकार।

2 Lab I C -1941 (ग्रान्धप्रदेश) पी रामैय्या वि क्लेक्टर, कुरनूल।

3 1974 SLJ 415-कृष्ण चन्द्र टंडन वि भारतीय सघ-AIR 1974 सुप्रीमकोर्ट-1589.

4 1975 WLN (U C) 320-सत्यनारायण वि राजस्थान सरकार।

5 1978 Lab I C 60 (कर्नाटक)-एल बी श्रीरामप्पी वि डिप्टी सपरिन्टेन्डेंट पत्रिस।

करने की शक्ति का प्रयोग जाच अधिकारी उपयुक्त सावधानी और सचेतता से नहीं किया गया तो वह सविधान के अनुच्छेद 311 में प्रावधानित प्रतिरक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के सिद्धान्त का उल्लंघन हो सकता है।¹ यह सिद्धान्त न्यायालयों में तथा न्यायाधिकरणों में समान रूप से लागू होता है। जब एव न्यायाधिकरण ने मुलजिम द्वारा आवेदित एव गवाह का इस आधार पर सम्मान करने से इनकार कर दिया कि मुलजिम की सहायता करने हेतु गवाहों को बुलाना उसका कर्तव्य नहीं है, तो न्यायालय ने फैसला दिया कि ऐसी अस्वीकृति न्याय के प्रत्येक सिद्धान्त और सदाचार के प्रतिशूल या।² यद्यपि जाच सवामन करने वाला अधिकारी न यह निष्कर्ष निकालता कि प्रतिरक्षा के कुछ गवाहों को बुलाया जाय किन्तु पुनिस अधीक्षण न पन्द्रह गवाहों के सम्मान करने से मना कर दिया और जाच अधिकारी ने दोरी कमचारी को उससे लिए अवसर प्रदान नहीं किया तो नियम हुआ कि अभिदोगी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा के प्रति पक्षपात किया गया है और इस कारण से उसने विरुद्ध पारित बर्खास्तगी का आदेश खारिज किया गया।³ इसी प्रकार मोहम्मद हसीद कि उप अधीक्षक पुनिस⁴ में दायी कमचारी को उसने गवाह सम्मान करने तथा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अवसर नहीं दिया तो यह निर्णय हुआ कि ऐसा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था।

नियम 16 [6 (क) (1)],—यह नियम अधिमूचना सम्पा 3 (15)/कामि/Α-III-72/G S R 81 (65) दिनांक 26 दिसम्बर 1973, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) (1) दिनांक 7 फरवरी 1974 को पृष्ठ 135 (180) पर प्रकाशित हुआ, के अधीन जोड़ा गया है। यह नियम शपथ पत्र (हलफनामा) द्वारा गवाहों लेने का प्रावधान करता है। परन्तु सभी प्रकार के गवाहों के बयान हलफनामों के रूप में ग्रहण नहीं किए जा सकते। केवल ऐसे गवाहों के बयान हलफनामों के रूप में लिए जा सकते हैं जिनकी माध्य निरी 'प्रीपचारिक किस्म' की हो जिससे कि विभागीय जाच में अनावश्यक विलम्ब कम किया जा सके। परन्तु जब भी दोरी राज्य कमचारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी इस पर आपत्ति उठाए और गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए माग करे तो उन व्यक्तिगत शहादत में बुलाना चाहिए। इसी प्रकार यदि जाच अधिकारी किसी ऐसे गवाह को व्यक्तिगत परीक्षण करना उचित समझे तो गवाहों के लिए सम्मान द्वारा बुलाया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति प्रीपचारिक किस्म की कोई परिभाषा दी हुई नहीं है। परन्तु किसी दस्तावेज को साबित करना या यह बयान देना कि वह हम न कला रिपोर्ट प्राप्त होने पर कला आदेश जारी किया, 'प्रीपचारिक किस्म' के उदाहरण के रूप में बताए जा सकते हैं।

नियम 16 (6) (ख) —आंशिक रूप से सुने गए मामले में गवाहों को दुबारा बुलाना — यह नियम अधिमूचना III F. 3 (5) नियुक्ति Α-III 65 दिनांक 11 मार्च 1966 द्वारा जोड़ा गया है यह जाच अधिकारी को अधिकार प्रदान करता है कि आंशिक रूप से किसी अन्य जाच अधिकारी द्वारा सुने गए मामले में जिस पर अध कार्यवाही उसे करनी है, वह गवाहों को पुनः परीक्षण के लिए बुला सके। परन्तु गवाह को पुनः बयान के लिए बुलाना हेतु सही तथा पर्याप्त कारण होने चाहिए जो लिखित में रिकॉर्ड पर रखे जावें। गवाह को पुनः बुलाने के लिए उपयुक्त दो शर्तें नियत हैं।

1 ILR 1962 राजस्थान-302-रमान द वि डिविजनल मेजेनिकल इंजिनियर।

2 AIR 1955 आन्ध्रप्रदेश 168, AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट 158

3 AIR 1958 इलाहाबाद 609-बुद्धसिंह वि उत्तरप्रदेश सरकार।

4 AIR 1957 इलाहाबाद 634.

नियम 16 (6) (ग) —इस नियम में ताजा संशोधन जी एम आर 129 सत्या F 3 (17) नियुक्ति (A III)/67 दिनांक 9 अक्टूबर 1974 को किया गया ताकि इस विषय में स्पष्टीकरण मिले कि जो दस्तावेज सरकार के कब्जे में हैं परन्तु जिनका उल्लेख उपनियम 6 (क) में संदर्भित नहीं किया गया है उनका अन्वेषण (discovery) तथा प्रस्तुतिकरण के लिए क्या प्रावधान हैं। से अपेक्षित दस्तावेजों के अन्वेषण या प्रस्तुतीकरण के लिए दोषी कर्मचारी का उक्त दस्तावेज की सगुता (relevancy) बतानी होगी। राजस्थान सरकार के निर्देशनों* के अनुसार सरकारी अभिलेखों तक पहुँचने (Access) का अधिकार 'असिमिन' नहीं है और यदि ऐसा अभिलेख मामले में सम्बन्धित नहीं है, तथा/प्रत्यक्ष उन तक पहुँचने की अनुमति देना सार्वजनिक हित में बाधनीय नहीं है तो उनके लिए अस्वीकृति दी जा सकती है। इसका साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि अस्वीकृति अधिकार का प्रयोग बहुत ही कम किया जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी दस्तावेज की सगुता अनुशासनिक प्राधिकारी का प्राथमिक परते समय स्पष्ट न हो परन्तु बाद में सम्भवतः तिरस्का की कोई विचारधारा उस दस्तावेज से उत्पन्न हो सकती है। अतः दस्तावेज तक पहुँचने की प्राथमिक अस्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक हित के आधार पर अस्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जबकि एनी अस्वीकृति के लिए समुचित तथा पर्याप्त आधार विद्यमान हो। ऐसे मामले बहुत ही कम मिलते हैं। यदि किसी दस्तावेज को राज्य कर्मचारी के विरुद्ध मूल में पेश करने का इरादा हो तो उस दस्तावेज का निरीक्षण करने की इजाजत नामजूर नहीं की जानी चाहिए। कुछ भी हो, अस्वीकृति के कारण लिखित में रिकॉर्ड पर होना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 162 (2) के अधीन सार्वजनिक हित के आधार पर किसी दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार माना है, परन्तु न्यायमूर्ति मुन्नाराय ने इस फैसले से अपनी अप्रहमति प्रकट की और सरकार के इस विभागाधिकार की मांग को उचित नहीं माना।**

नियम 16 (6) (घ) —(क) संशोधन GSR 129 स F 3 (17) नियुक्ति (A III) 67 दिनांक 9 अक्टूबर 1974 द्वारा हुआ। यह नियम दोषी कर्मचारी की या नियम 18 के अधीन समुक्त विभागीय जांच होने की दशा में एवं या अधिक कर्मचारियों की अनुपस्थिति में सम्बन्ध में है।

इकतरफा कार्यवाही —यदि सम्मन की तामील होने के बावजूद कोई दोषी अधिकारी जांच अधिकारी के सम्मुख अनुपस्थित रहे तो जांच अधिकारी इकतरफा कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा, परन्तु उसे यह बताना नियम 19 (ii) के अधीन लिखनी चाहिए कि नियम 16 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना वाजिब तौर से व्यवहार्य (practicable) नहीं है। इसी प्रकार की कार्यवाही समुक्त विभागीय जांच होने की दशा में करनी चाहिए जबकि सम्मन की साफ तामील हो जान के बावजूद एवं या अग्रिम दोषी कर्मचारी अनुपस्थित रहे। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जांच अधिकारी अपना निष्कर्ष बिना किसी जांच के अभिलेखित करदे, अर्थात् बिना किसी मौखिक या दस्तावेजी गवाहों के ही निश्चिन करे।¹ जबकि एक इकतरफा जांच में अनुसरण की गई प्रक्रिया

* प्रपत्र स F 3 (25) नियुक्ति A/61 ग्रुप III दिनांक 14-2-1962 एवं इसी सत्या का अन्य प्रपत्र दिनांक 8-11-1962

** AIR 1961 सुप्रीमकोर्ट 493—पंजाब सरकार वि सोबी सुखदेवसिंह।

1 1964 RLW 613—श्यामनारायण शर्मा वि भारतीय सच।

नियमों के अनुकूल नहीं थी, तो यह निर्णय हुआ कि कार्यवाही मनमानी होने के कारण कर्मचारी के विरुद्ध दोष साबित होने का निष्कर्ष अवैध था।¹

इकतर्फी कार्यवाही आरम्भ करने के लिए शर्तें—विभागीय जाच इकतर्फी अर्थात्, एक या अधिक दोषी कर्मचारियों की गैर हाजिरी में केवल तभी चन सजनी है जब कि—

(1) पेशी की तारीख और स्थान निश्चित किए जा चुके हैं और उनकी सूचना यथोचित तरीके से दोषी कर्मचारी या कर्मचारियों को दी जा चुकी है, और

(2) उक्त कर्मचारी पेशी की वधित तारीख को बिना किसी परियाप्त कारण अनुपस्थित रहे। शब्दावली “बिना किसी परियाप्त कारण के” नहीं जोड़ी गई है। यदि पेशी की तारीख और स्थान की सूचना दोषी कर्मचारी को नहीं दी गई हो, तो केवल इस आधार पर कि उसने बार्जशीट का उत्तर नहीं दिया, उसके विरुद्ध इकतर्फी कार्यवाही आरम्भ करना न्यायोचित नहीं होगा।²

अवमनात बीमार हो जाने या ज्यादा वर्षों से रास्ता भ्रमजाने, या ट्रेन या बस चूक जाने या सरकारी कार्य के लिए अधिकारी द्वारा रोक लिये जाने से तारीख पेशी पर गैर हाजिर रहने के परियाप्त कारण हो सकते हैं। जब कि निलम्बित दोषी कर्मचारी का निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया और जाच का स्थान उसके निवास स्थान से लगभग 500 मील दूर था इसलिए, धनाभाव के कारण राज्य कर्मचारी पेशी पर हाजिर नहीं हो सका तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुपस्थिति का परियाप्त कारण माना। अतः दोषी कर्मचारी की अनुपस्थिति में की गई कार्यवाही अवैध घोषित की गई।³ इसी प्रकार के कारणों पर मोहनलाल तिवारी वि. वचायत समिति, भादरा⁴ में जाच दूषित होना करार दिया गया।

इसके विपरीत, जब कि प्रार्थी जाच अधिकारी के समक्ष इस आधार पर उपस्थित नहीं हुआ कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, तो निर्णय हुआ कि सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी (रिमान्) हटवाने के लिए की गई निगरानी से जाच पर कोई रोक नहीं थी, इसलिए इसे समुचित अवसर नहीं देना नहीं माना जा सकता।⁵ जब कि पेशी स्थापित करवाने के लिए कोई परियाप्त कारण नहीं बताया गया और जाच सम्बन्धित कर्मचारी की अनुपस्थिति में चालू रही, तो इस मामले में इकतर्फी का आदेश अनुचित नहीं माना गया। इसके अलावा इकतर्फी आदेश निरस्त करने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब हुआ कि इस मामले में समुचित अवसर प्रदान करने की इन्कारि नहीं हुई।⁶

नियम 16 (6-अ).—अतिरिक्त या नहीं साथ, यह नियम जी. एम. आर. 129* दिनांक 9-10-1974 के अधीन जोड़ा गया है। यह नियम जाच अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह

1 AIR 1956 कलकत्ता 114—ए. पी. डी. गुप्ता वि. निदेशक प्रोक्वोरमेट।

2 AIR 1970 उड़ीसा-1—पूरनचन्द्र दास वि. चैयरमन स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी।

3 AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट—धनश्याम दाम श्रीवास्तव वि. उत्तर प्रदेश सरकार।

4 1975 WLN (U C) 83

5 1976 WLN (U C) 340—सुआलाल यादव वि. राजस्थान सरकार।

6 1975 WLN (U C) 299—गुहचरण सिंह वि. राजस्थान सरकार।

* III F 3 (17) नियुक्ति (A-III) 67 दिनांक 9 कदुवर, 1974.

दोपी कर्मचारी की दी गई सूची में जिन गवाहों के नाम नहीं लिखे हैं तो भी वह अपने स्वविवेक से उन गवाहों को उपस्थित करने की अनुमति प्रदान करदे, अथवा जांच अधिकारी स्वयं नई शहादत तलब कर सकेगा या किसी गवाह को पुनः बुलाकर उसके बयान पुनः ले सकेगा। परन्तु, ऐसे स्व-विवेक के प्रयोग पर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं जैसे कि:—

(1) ऐसी कार्यवाही का चरण (stage) अनुशासनिक प्राधिकारी के पक्ष की गवाही बन्द होने से पहले है। यदि यह अवस्था गुजर चुकी है तो जांच अधिकारी फिर नई शहादत बुलाने, आदि के लिए मक्षम नहीं रहेगा।

(2) ऐसा कदम केवल तभी उठाया जा सकता है जब कि ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, अन्यथा नहीं।

(3) सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा भाग की जाने पर उसे प्रस्तावित नई शहादत की सूची देनी होगी।

(4) उपर्युक्त नई शहादत पेश करने से पहले दोपी कर्मचारी को तारीख पेशी का स्वयं कम से कम तीन पूरे दिनों का भी देना होगा जिसमें स्वयं स्वीकार करने की तिथि और भागे की तारीख पेशी शुमार नहीं की जाएगी।

(5) रिकॉर्ड पर लिए जाने से पहले नए दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर दोपी कर्मचारी को दिया जाएगा।

(6) नई शहादत या किसी गवाह का पुनः परीक्षण, शहादत में रह गई किसी खामी का पूरा करने के लिए अनुमत्त नहीं होगा। किन्तु भूल साक्ष्य की कोई अन्तर्निहित भूल या त्रुटि को सुधारने के लिए ऐसा किया जा सकेगा।

(7) दोपी कर्मचारी को अनुमति दी जाएगी कि वह नए गवाहों से या पुनः बुलाए गए गवाहों से दीगर जिरह (further cross-examination) कर सके।

नियम 16 (6-ख).—कठोर शास्ति के लिए मामला आगे भेजना—यह नियम भी जी.एस. आर. 129, स F 3 (17) नियुक्ति (A-III) 67 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा जोड़ा गया है। जब कोई ऐसा अनुशासनिक अधिकारी जो सम्बन्धित राज्य कर्मचारी पर कठोर शास्ति अधिराजित करने की क्षमता नहीं रखता हो, इस सम्मति का हो कि उसके निष्कर्षों के आधार पर उस पर कोई शास्ति लागू करनी चाहिए, तो वह जांच का रिकॉर्ड ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी का भेजेगा जो कठोर शास्ति अधिराजित करने के लिए सक्षम हो। तदुपराल, उक्त कठोर शास्ति के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी, या तो पहले से रिकॉर्ड पर विद्यमान शहादत के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा, या यदि वह न्याय के हित में आवश्यक समझे, तो वह गवाहों को अतिरिक्त साक्ष्य के लिए (जिनमें जिरह और पुनः परीक्षण सम्मिलित है), वापिस बुला सकेगा और दोपी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम के अनुसार जैसी भी शास्ति उचित समझे वैसी अधिराजित कर सकेगा।

यह नियम केवल उन्हीं मामलों पर लागू होता है जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच स्वयं की हो और वह कठोर शास्तियाँ लागू करने के लिए प्राधिकृत न हो।

नियम 16 (7)—जांच की रिपोर्ट—जब जांच सम्पन्न हो जाये तो जांच अधिकारी को

जाच की एक रिपोर्ट बनानी होगी जिसमें उसे दोषी कर्मचारी पर लगाए गए प्रत्येक चार्ज (आरोप) पर अपना निष्कर्ष उल्लिखित करना होगा। उसे अपने निष्कर्षों की पुष्टि में ऐसे कारण देने होंगे जो ऐसे परिणामों का औचित्य बतावें। परन्तु यदि जाच अधिकारी जाच कार्यवाही के आधार पर ऐसे नतीजे पर पहुँचे कि कतिपय ऐसे आरोप स्थापित होते हैं जो दोगोपित कर्मचारी के विरुद्ध मूलतः निर्धारित आरोपों से भिन्न हैं तो वह ऐसे निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा वशतः कि सम्बन्धित कर्मचारी ने—

(1) उन तथ्यों को स्वीकारा है जिनसे नया आरोप बनता है, अथवा

(2) उसे उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा करने का अवसर मिला था।

नियम 16 (8)—जाच की रिपोर्ट—नियम 16 (8) में उन कागजात के नाम गिनाए गए हैं जो जाच के (रेकॉर्ड) में सम्मिलित किए जाएंगे और उनको यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार न अनुशासनिक कार्यवाही पर अपनी पुस्तिका 1963 (संस्करण) के अनुच्छेद 13 (ix) में इस विषय में निर्देशन दिए हैं। अतः स्मरण रहे, कि जब विभागीय जाच पूरी हो जावे, तो जाच अधिकारी को जाच की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। जान रिपोर्ट में जाच करने वाले अधिकारी को प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग अपना नतीजा (निष्कर्ष) लिखना चाहिए और प्रत्येक निष्कर्ष के लिए न्यायोचित कारण व्यक्त करने चाहिये। निष्कर्ष दोनों पक्षों द्वारा रेकॉर्ड पर साईं गई साक्ष्य पर भली भाँति विचार करने के बाद निकालने चाहिए। इस सिद्धान्त पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी तथ्य या सामग्री जो औपचारिक रूप में रेकॉर्ड में स्थित नहीं हो, उसका उपयोग दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। हाल ही के एक मामले राजस्थान सरकार वि दान माल¹ में, चार्ज स 1 का भाग (क) इस प्रकार था, “यह कि हेड कान्स्टेबल दान मल, जब कि वह पुलिस लाइन, पाली में लेखाकार लिपिक का कार्य कर रहा था, दिनांक 6-3-53 को कतिपय कर्मचारियों ने तरकासिक पुलिस अधीक्षक को ज्ञात की कि, यद्यपि उनका वेतन उठा लिया गया है, तथापि जब तक वे दानमल को पैसा देने को तैयार नहीं तक वह वेतन का वितरण करना नहीं चाहता।” इस मामले में न्यायमूर्ति श्री मोक्ष ने निर्णय दिया कि केवल इस कथन से कि कर्मचारी वर्ग के कुछ सदस्यों ने पिछले दो या तीन महीने से वेतन प्राप्त नहीं किया है, यह नतीजा नहीं निकलता कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायत सही थी या यह कि शिकायत करने वाले व्यक्तियों को, दानमल द्वारा अपना कर्तव्य पालन नहीं करने के कारण वेतन नहीं मिला। अतः दानमल के विरुद्ध चार्ज स 1 के भाग (क) का दोषी होने का जाच अधिकारी का नतीजा किसी भी शहान्त पर आधारित नहीं था और इसलिए यह निष्कर्ष स्थित नहीं रखा जा सकता।²

आरोपों को साबित करने का भार विभाग पर है। दृढ़ सकारात्मक सबूत का स्थान केवल अटकल बाजी या सदेह नहीं ले सकते।³

जबकि जाच अधिकारी के निष्कर्ष, सदेहों पर आधारित, पक्षपातयुक्त, मनमाने और अनुचित होने में पूर्णतः दूषित करार दिए गये थे, तो उसके बाद अनुशासनिक प्राधिकारी और अपनी

1 1977 WLN 645,

2 1973 SLJ 669 हरमन्दर सिंह वि पञ्जाब सरकार, AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 2535
भारत सरकार वि मोहन चन्द कलिता।

प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने पर भी, वे स्थिर नहीं रहे जा सकें।¹ सर्वोत्तम न्यायालय ने तय किया है कि जब कोई गहादत ही नहीं हो, या निष्कर्ष कुटिलता से निकाले गये हों तो उन्हें कायम नहीं रखा जा सकता। यह कानून की प्रत्यक्ष वृत्ति है जो याचिका द्वारा सुधारी जा सकती है, परन्तु गहादत पर पुनः विचार करना सम्भव नहीं है।² परन्तु एक अन्य मामले में यह निर्णय किया गया कि जब ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) ने अपने नतीजे सवाग्रो तथा अस्वीकृत साक्ष्य पर निर्धारित किए हों, तो उच्च न्यायालय, रिट याचिका में इस बात की जाच कर सकता है कि आया ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष सही है।³ इसके विपरीत यदि नतीजा साबित किये गये तथ्यों का बाजिब निष्कर्ष हो, तो उसे कुटिल (perverse) या सारभूत मामलों से अप्रुष्ट होना नहीं कह जा सकता।⁴ भगवत प्रसाद श्रीवास्तव वि मध्य प्रदेश सरकार⁵ में दोषी कर्मचारी को उपयुक्त अवसर अस्वीकार किया गया और बाहरी सामग्री शामिल की जब कि उससे भुकाबला करने के लिये कोई मौका प्रदान नहीं किया गया और सम्बन्धित प्राधिकारी को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति की सिफारिश करने का भी अधिकार नहीं था। अन्न न्यायालय ने ऐसे नतीजे को अनुचित माना।

नियम 16 (7) के अनुसार, दोषी होने का नतीजा मूल आरोपों से भिन्न आरोपों के विषय में भी दिया जा सकता बशर्त कि ऐसे नए आरोपों के विषय में राज्य कर्मचारी को उसकी प्रशिक्षा के लिए समुचित अवसर प्रदान किया गया हो। ऐसे आरोप पर लागू की गई शास्ति स्थिर रह सकती है।

जाच अधिकारी और अनुशासनिक अधिकारी दोनों को रैकड पर विद्यमान सामग्री पर अपना खुद का विभाग लगा कर निश्चित नतीजों पर पहुँचना चाहिए। हिचकिचाहट के साथ दिए गए और अपूर्ण फैसले प्रमोजन हीन होते हैं। वे व्यर्थ हैं।⁶

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार “जाच अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विशिष्टतः कोई शास्ति प्रस्तावित करे, और उसे प्रत्येक चार्ज के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करने तक सीमित रहना चाहिए।” जाच अधिकारी को ज्ञात करना चाहिए कि आया कोई आरोप विशेष साबित हुआ है या नहीं। उसे अपने प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में कारण अवश्य बनाने चाहियें। परन्तु अपने निष्कर्षों से साबित आरोपों पर उसे कोई शास्ति का मुद्दा देने की जरूरत नहीं है।⁷

नियम 16 (9)-अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्षों पर विचार—यह उपनियम केवल तभी लागू होगा जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच अधिकारी नहीं हों। अनुशासनिक प्राधिकारी का यह परम कर्तव्य है कि जाच के समस्त अभिलेखों का वह स्वयं अध्ययन करे और प्रत्येक आरोप पर अपने निजी नतीजे, उनकी पुष्टि में कारणों का उल्लेख करते हुए, रैकड पर

1 19/3 Lab 1c (NOC) 26 कर्नाटक एन नरसीमहिप्पा वि कर्नाटक सरकार।

2 AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 1103-मद्रास राज्य वि मुन्दरम।¹

3 1972 SLR 893.

4 1972 SLR 355-भारतीय सच वि मरदार बहादुर।

5 1978 SLJ 162 मध्य प्रदेश।

6 1975 Lab IC 73 (हिमाचल प्रदेश) ज्ञान सिंह वि हिमाचल प्रदेश सरकार।

7 AIR 1964 आन्ध्र प्रदेश 407-अब्दुल रहीम वि एक्सीक्यूटिव आफिसर तथा AIR 1958 राजस्थान 595

लगावे। उसे अपना मुँह बा दियाग लगाना चाहिए न कि जाच के विवरणों से अपने आपसे निर्लिप्त रहते हुए, केवल जाच अधिकारी की सम्मति का समर्थन कर दे। अनुशासनिक प्राधिकारी वाध्य है कि वह रेकॉर्ड पर स्थित सामग्री पर नैतिक सतर्कता से स्वयं विचार कर और निश्चित नतीजे पर पहुँचे। अन्यथा, अपूर्ण निष्कर्षों के बौद्धि प्रयोजन हासिल नहीं होगा और वह निरर्थक होगा।¹ यह आवश्यक नहीं है कि अनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी ने नतीजों से सहमत हो, और असहमति की दशा में, यदि वह सकारण यह विश्वास रखता हो कि जाच किसी विषय में अपूर्ण है तो मामले को प्रतिरिक्त जाच के लिए या फिर स नई जाच करने के लिए वापिस भेज सकेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास "सही और पर्याप्त कारण" होना चाहिए जो लिखित में अभिलिखित किए जाए। किन्तु रिकॉर्ड में जाच प्राधिकारी की केवल छोटी सी त्रुटि, जो उसकी निष्कर्षों के सार को प्रभावित नहीं करे जाच को दूषित नहीं कर सकती।²

नियम 16 (10) (i) प्रस्तावित शास्त्र का नोटिस—जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी अपने निष्कर्षों के आधार पर इस नतीजे पर पहुँचे कि दोषी कर्मचारी पर नियम 14 के अनुच्छेद (iv) में (vii) में उल्लेखित कोई कठोर शास्त्र अधिरोपित की जाए तो वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को जाच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा और उसके विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड सूचित करते हुए नोटिस देगा कि, यदि वह चाहे, तो (नोटिस में) निर्दिष्ट अवधि में, प्रस्तावित शास्त्र उसके विरुद्ध क्या नहीं लागू की जावे इसका कारण बताते हुए अपना प्रतिवेदन पेश करे। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाच अधिकारी नहीं है, तो वह अपने मुँह के नतीजे का विवरण भी, जाच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारण संक्षेप में बताते हुए (यदि ऐसा हो), भेजेगा। दोषी कर्मचारी अपने प्रतिवेदन में केवल अभिलिखित साक्ष्य पर निवेदन कर सकेगा।

राज्य कर्मचारी का अपना प्रतिवेदन तैयार करने तथा प्रेषित करने के लिए उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए, उदाहरणन पन्द्रह दिन का, जैसा कि सरकारी निर्देशनों में सुझाव दिया गया है।

इसके प्रतिकूल, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुँचे कि आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आरोप माहित नहीं हुआ है, तो वह उसे दोष मुक्त कर सकेगा और तदनुसार कर्मचारी को सूचित करेगा।

सविधान के अनुच्छेद 311 (2) में सशोधन—अब सविधान के ब्यालीसवें संशोधन 1976 द्वारा सविधान के अनुच्छेद 311 (2) में परिवर्तन किया गया है। प्रस्तावित शास्त्र के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस देने की आदेशात्मक व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। किन्तु राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों के नियम 16 (10) (i) के अधीन उक्त द्वितीय नोटिस देना फिर भी अनिवार्य है और इस नियम की पुष्टि में कानूनी बल अवश्य विद्यमान है। अतः उक्त संशोधन से पहले के सविधान के प्रावधान पर आधारित पूर्ववालीन अदालती पैगलो को अब तदनुसार समझना चाहिए।

जब कि जाच अधिकारी न कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों से उस दोष मुक्त कर दिया हो, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी न प्रतिकूल राय बनाई हो, तो उसे अपनी असहमति के

कारण व्यक्त करने चाहियें। ऐसे कारणों के अभाव में बर्खास्तगी का आदेश गलत होगा, क्योंकि नियम 16 (10) (i) आदेशात्मक है और इससे दोषी कर्मचारी अपनी प्रतिरक्षा प्रभावशाली तरीके से करने के समुचित अवसर से वंचित हो जायेगा। दोषी कर्मचारी को सूचित किये बिना उसके पिछले रेकार्ड पर विचार करने से, या आरोपी से असम्बन्धित बाहरी मामलों को निष्कर्षों का आधार बनाने पर, कर्मचारी के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति का आदेश दूषित हो जाएगा।¹

कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय—जबकि प्रार्थी को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई और कलेक्टर के निष्कर्षों की प्रति भी नहीं दी गई, तो फंसला हुआ कि जिन आधारों पर प्रार्थी को दण्डित किया जाना प्रस्तावित था उनके विरुद्ध कारण बताने का उसे समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया।² जबकि दोषी कर्मचारी को यह विदित हो नहीं हो कि उसके विरुद्ध क्या और कितना प्रयत्न सामला बनाया गया है, तो वह उसके विरुद्ध प्रस्तावित कठोर शास्ति लागू करने के विरुद्ध प्रभावशाली कारण बताने में असमर्थ रहेगा।³

जबकि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध एक से अधिक चार्ज (आरोप) थे और नोटिस में प्रत्येक आरोप पर पृथक् पृथक् शास्ति प्रस्तावित करने का मकन नहीं दिया गया, तो तब हुआ कि उक्त नोटिस अवैध नहीं था।⁴

अनुशासन प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि तदर्थ रूप से राज्य कर्मचारी पर शास्ति प्रस्तावित करने से पहले, अपने आप को सन्तुष्ट करे कि उनके विरुद्ध आरोप साबित हैं।⁵

जबकि निष्कर्ष अनिश्चित हो और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किए गए हों, तो उनके आधार पर नोटिस जारी करना अपरिपक्व (premature) होगा और उन पर पारित बर्खास्तगी का आदेश अवैध होगा।⁶

दोरी कर्मचारी ने प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जो अस्वीकार किया गया। फिर भी उसका उत्तर अनुशासनिक प्राधिकारी को शास्ति का आदेश देने से पहले प्राप्त हो गया, परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ने उस पर विचार नहीं किया। अतः के सदा-शिवय्या वि. जी एम. टेली कॉम⁷ में निर्णय दिया गया कि दोषी कर्मचारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त महत्वपूर्ण होता है जिस पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिये। इस प्रकार के विचार के अभाव में शास्ति का आदेश रद्द किया गया। जबकि द्वितीय कारण बताओ नोटिस के अभाव में दण्ड का आदेश निरस्त किया जाता है, तो फिर से नया मुकदमा चालू करना आवश्यक नहीं होता, इस प्रयोजन के लिये केवल ताजा कारण बताओ नोटिस तारीख करना पर्याप्त होगा।⁸

+ 1976 WLN (UC) 367—रामसहाय वि. राजस्व मण्डल।

1. AIR 1958 राजस्थान 153—नायूलाल वि. सरकार, AIR 1963 पंजाब 390.

2. AIR 1960 इलाहाबाद 543—यू पी सरकार वि. मालिगराम शर्मा।

3. AIR 1963 मध्य प्र 115—मोविन्द शर्कर वि. मध्यप्रदेश सरकार।

4. AIR 1960 उड़ीसा 37—के. जी मुखर्जी वि. सरकार।

5. AIR 1958 राज 153—नायूलाल वि. सरकार और AIR 1960 पंजाब सरकार वि. श्री. एन जोशी।

6. 1978 एम. एन. जे. 253 (आंध्रप्रदेश)।

7. 1963 भार एन डब्ल्यू 374—जयवन्त राज वि. राज सरकार।

जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि जाच अधिकारी की रिपोर्ट को देखने हुए और विशेषतः दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध साबित आरोपों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उसे बर्खास्तगी की सजा देना प्रस्तावित की जाती है, तो यद्यपि अनुशासनिक प्राधिकारी ने प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष कारण बताओ नोटिस में नहीं दिया था, तथापि उक्त नोटिस में कोई कमजोरी नहीं थी।¹

यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो, तो दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते समय उस अपना तथ्य निष्कर्ष उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा। ऐसे मामले में आदेश कारण सहित लिखना जरूरी नहीं है।² कारण बताओ नोटिस तभी जारी किया जाता है जबकि कर्मचारी के विरुद्ध प्रभावजनक से अपराध बनता हो और उस अवस्था में जो राय कायम की गयी है वह बलवत् तथ्य है। अन्तिम कायवाही दोषी कर्मचारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् की जाती है।³

जबकि दोषी कर्मचारी को सूचित प्रस्तावित शास्ति, कर्मचारी के प्रतिवेदन पर सुतवाई करने के पश्चात् वास्तव में ही गई शास्ति से कम बठोर थी, तो इससे सविधान के अनुच्छेद 311 (2) और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं होना माना गया।⁴

जबकि जाच का रेकार्ड जल कर भस्म हो गया और रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से पुनर्निर्मित नहीं हुआ, तो केवल जाच की रिपोर्ट के आधार पर ने दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। न्यायालय ने उक्त नोटिस को अवैध माना।⁵

मोहनलाल वि सरकार⁶ के मामले में कारण बताओ नोटिस में अविनय और अनुशासनहीन गतिविधियों (insubordination and indisciplined activities) का उल्लेख नहीं किया गया। इनलिने तय हुआ कि इन आधारों पर दोषी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जा सकता था। नसीरुद्दीन वि सरकार⁷ में भी कर्मचारी के विरुद्ध पारित बर्खास्तगी का आदेश अवैध माना गया क्योंकि उक्त आदेश कारण बताओ नोटिस के उत्तर में दिए गए प्रतिवेदन पर विचार किए बिना पारित किया गया।

नियम 16 (10) (ii) लोक सेवा आयोग से परामर्श तथा दोषी कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार

अनुशासनिक प्राधिकारी को चाहिए कि वह जाच का पूरा अभिलेख (रेकार्ड) दोषी कर्मचारी के

1. 1975 WLN 320 राज (यू सी)।

2. AIR 1963 मु बीट 1612-आसाम सरकार वि विमलकुमार पंडित, और 1977 मु नाट (एल. एण्ड एस) 151 ताराचन्द खत्री वि म्यूनिसिपल कार्पो)

3. 1976 Lab I C 1741 (गोहाटी) नन्द विश्वर वि ए पी बी राघवन।

4. AIR 1955 उड़ीसा 33, AIR 1970 उड़ीसा 81-बिद्रावन पाथी वि उड़ीसा राज्य, 1974 Lab I C 1068 (हिमाचल प्रदेश) पुनेलमिह वि डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग।

5. 1988 Lab. IC 1032 (हिमाचल प्र) छतर सिंह वि डिप्टी कमिश्नर, शिमला।

6. 1975 WLN (UC) 232

7. 1976 WLN (UC) 335

प्रतिवेदन के साथ लोक सेवा आयोग की मन्त्रणा के लिए भेजे। सभी मामलों में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। परन्तु लोक सेवा आयोग से ऐसी जाचो के बारे में परामर्श लेना आवश्यक है जो राज्य सेवाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में हों, जिनका कि नियुक्ति प्राधिकारी सरकार हो और नियुक्ति करने का अधिकार किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को नहीं सौंपा गया हो और जबकि दोरी कर्मचारी के विरुद्ध निन्दा और वेतन वृद्धि या रोकने की शास्तियों से भिन्न कोई अन्य शास्ति लागू करना प्रस्तावित हो। [दखिए नियम 15 (2) 1] अतः आयोग से परामर्श मांगा जाना चाहिए जबकि नियम 14 क अनुच्छेद (iii) से (vii) और अनुच्छेद (ii) के द्वितीय भाग में निदिष्ट कोई शास्ति आरोप करने का विचार हो जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

- (1) पदोन्नति रोकना;
- (2) सरकार को आर्थिक हानि पहुंचने की दशा में वेतन से वसूली करना,
- (3) निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद, आदि पर पदावनति करना,
- (4) अनुपातिक पेन्शन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति,
- (5) सेवा से हटाना, और
- (6) सेवा से बर्खास्तगी।

राजस्थान सरकार ने अनुशासनिक कार्यवाही पर लिखित पुस्तिका (1963) के अनुच्छेद 15 में इस विषय पर निर्देशन जारी किए हैं। इन निर्देशनों के अनुसार, अनुशासन प्राधिकारी को, कारण बताओ नोटिस के उत्तर में दोरी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उठाए गए विन्दुओं पर सावधानी-पूर्वक विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग से परामर्श लेने के पश्चात् जहां यह जरूरी हो, कर्मचारी के विरुद्ध साबित आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता का ध्यान रखते हुए, उचित शास्ति लागू करनी चाहिए। “दण्ड की मात्रा निर्धारित करते हुए, दोरी कर्मचारी के पिछले रेकॉर्ड या पूर्वकालीन दुराचरण पर विचार केवल तभी किया जा सकता है, जब कि उसका उल्लेख कारण बताओ नोटिस में कर दिया गया था और कर्मचारी को उसका स्पष्टीकरण देने के लिए पूरा अवसर दिया गया हो। (AIR 1954 नागपुर 90 और 1960 इलाहाबाद 270)।”

इन निर्देशनों में आगे यह भी कहा गया है कि दोरी कर्मचारी के प्रतिवेदन की सुनवाई करन के पश्चात् उसे मूलतः प्रस्तावित शास्ति से कोई हल्की शास्ति बिना नया कारण बताओ नोटिस जारी किए प्रदान की जा सकती है, परन्तु यदि उससे भारी सजा देनी हो, तो उसे ताजा कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक होगा।

लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आदेशात्मक नहीं है—सविधान का अनुच्छेद 320 (3) व्यवस्था करता है कि “यथा स्थिति, सच-लोक सेवा आयोग या राज्य-लोक सेवा आयोग से, ऐम व्यक्ति पर, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य की अर्सेनिक सरकार की अर्सेनिक हैमियत में काम कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयो से जो अभ्यावेदन या याचिकाएं सम्बद्ध हैं उनके सहित समस्त ऐसे अनुशासन विषयो पर..... परामर्श किया जायेगा।” अन्य शब्दों में, निमित्त कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनिक मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए। उक्त प्रावधान निदेशात्मक (directory) माना गया है न कि आदेशात्मक

(mandatory) जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने यू पी सरकार वि मनवोध लाल¹ में तथा अन्य मामलों में तय किया है। लोक सेवा आयोग कोई अपील प्राधिकारी नहीं है इसलिए उसकी राय मानना राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है (ए. एन डी सित्वा वि भारतीय सब)² अतः मन्वर लोक सेवा आयोग की राय मांग भी सबती है या नहीं भी मांगे और आयोग की राय स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

यद्यपि उक्त प्रावधान केवल निदेशात्मक है, तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राधिकारी-तग की मनमानी इच्छा के अनुसार इसे टाला जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि आदेशात्मक प्रावधान का पालन नहीं करने से कार्यवाही अर्बद्ध हो जाएगी, परन्तु निदेशात्मक प्रावधान के सम्बन्ध में उसका मोटे तौर से परिपालन पर्याप्त होगा और यदि यह भी नहीं किया जाय तो भी केवल इसी आधार पर कार्यवाही अर्बद्ध नहीं होगी। इसका अभिप्राय यह नहीं हुआ कि जिन प्राधिकारियों पर निदेशात्मक प्रावधान लागू हैं, वे उनकी अवमानना आदनन करते रहें। कार्यकारिणी सरकार ऐसी स्वच्छन्द नहीं हो सकती कि लोक सेवा आयोग की पूर्णतः अवहेलना करे। "नियमित कार्य प्रदर्शित बनाते हुए प्रावधान की पूरी अवमानना करना घोर अनुचित कार्य है।³ जब एन वार निदम बना दिए गए हो, तो उनका परिपालन अक्षरत तथा भूतत होना ही चाहिए।⁴

*राजस्थान सरकार के अधिशासी निर्देश —राज्य सभाओं के सम्बन्ध में, जिनमें नियुक्ति करने का प्राधिकार किसी अन्य प्राधिकारी को सुपुर्व किया हुआ नहीं हो, अनुशासनिक मामलों, जिनमें नजर सानी व अम्यावेदन (review and memorials) शामिल हैं, के विषय में आयोग की सम्मति प्राप्त करने के लिए, पत्राचार कार्मिक विभाग में राज्य सरकार के माध्यम से करना चाहिए और अधीनस्थ एवं अन्य सभाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से।

अनुशासनिक मामले

जब कोई अनुशासनिक मामला, जिसमें आयोग में परामर्श लेना आवश्यक हो, विचार के लिए सामने आए, तो सावधानी पूर्वक यह मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आया कागजात पूरे हैं तथा सही तरीके से लग हुए हैं, अनुशासनिक जाचों से सम्बन्धित मामलों में कि आया ऐसी जाचों से सम्बन्धित कागजाती प्रावधानों का परिपालन हो चुका है। यदि आवश्यक हो तो कागजात उस प्राधिकारी को जिसमें प्राप्त हुए थे, इस निर्देशन के साथ तौटा देने चाहिए कि कानूनी प्रावधानों का समुचित पालन किया जावे। ऐसा तत्काल कर देना चाहिए और उस 'स्टेज' पर मामले के गुण-दोष नहीं जाचने चाहिये। ऐसी जाच 'केस' आयोग से प्राप्त होने पर, यह देखन के लिए करनी चाहिए कि आया कोई अपवाद स्वरूप परस्थिति विद्यमान है जिससे किसी विषय में आयोग की सम्मति से भिन्न कार्य करने का औचित्य

1. AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 912,

2. AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1130, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 158, 1972 Lab. IC 1496 (आसाम), 1966 SLR 429—राम गोपाल चतुर्वेदी वि मध्य प्रदेश सरकार।

3. AIR 1957 पंजाब 97—दुर्गासिंह वि पंजाब सरकार।

4. 1978 Lab IC 1049 (मध्य प्रदेश) आदर्श कुमारी भारती वि के एन. सिन्हा तथा अन्य।

* राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श के विषय में अधिशासी निर्देशन (1972 संस्करण)।

गे। यदि भिन्न कार्य करना प्रस्तावित हो, तो, उसके कारण व्यक्त करने चाहियें और अंतिम निर्णय देने से पूर्व प्रायोग को अपनी सम्मति पर पुनः विचार करने का अवसर देना चाहिए।

जब प्रायोग की सम्मति मांगी जानी हो, तो जाच से सम्बन्धित समस्त सारभूत अभिलेख, मपीलें या मेमोरियल्स, यथा स्थिति, सही तरीके से व्यवस्थित करने प्रायोग को अवसर देने चाहिये। प्रायोग को निर्देशन निर्धारित पत्र पर, नियुक्ति विभाग के प्रीमो स F 16 (7) नियुक्ति (A) 00/III दिनांक 31-7-61 के अनुसार करना चाहिए। सरकार की ओर से मामले के गुण-दोषों पर राय अभिव्यक्त नहीं करनी चाहिए, और टिप्पणी पत्र या ऐसे अन्य कागजात जिन में मामले के गुण-दोषों का विवेचन हो, किसी भी दशा में लोक सभा प्रायोग को नहीं भेजने चाहिये। किसी भी दशा में, जिसमें अनुशासनिक मामले में प्रायोग की राय मांगी गई हो, वह पत्र, जिसमें प्रायोग के निष्कर्ष समाविष्ट हों, मामले के अभिलेखों का भाग बनेगा और सिवाय उसके उन प्रश्नों के जिनमें किसी सरकारी महकमे के विरुद्ध कड़ी टीका की गई हो, जो सम्बन्धित अधिकारी या अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।

सिवाय प्रपवाद स्वरूप परिस्थितियों के, निर्देशन के फल स्वरूप मामले में दी गई प्रायोग की सम्मति स्वीकार करनी चाहिए। जब किसी मामले विशेष में ऐसा अनुभव किया जावे कि प्रायोग की राय नहीं माननी चाहिए, तो प्रायोग को उसके कारण सूचित करना चाहिए ताकि वह अपनी राय पर पुन विचार कर सके। यदि प्रायोग की दुबारा सम्मति प्राप्त होने पर, उसे स्वीकार करने का विचार नहीं हो तो मामला, नियुक्ति विभाग को निर्णय हेतु भेजा जाएगा, जिसमें प्रायोग की राय स प्रसहमति के कारण भी व्यक्त किए जाएंगे।

सभी मामलों में, प्रायोग की सिफारिशों पर क्या अंतिम कार्यवाही की गई उसे (प्रायोग) को सूचित करनी चाहिए। सामान्यतः ऐसे पत्राचार की प्रतिष्ठा पृष्ठांकित करना पर्याप्त होगा जिनमें आदेश सूचित किए गए हों, सिफारिश की गई हो, या अन्य कार्यवाही की गई हो।

अनुशासनिक प्राधिकारी को कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार करना होगा—अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह दोषी सिविल कर्मचारी के प्रतिवेदन पर समुचित विचार करे। आरोप अर्थात् चार्ज के आधार पर, कर्मचारी के प्रतिवेदन पर विचार किए बिना शास्ति लागू करने से शास्ति का आदेश निरस्त किया जाना योग्य होगा।¹ “अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दोषी प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार नहीं करने से और अपने निष्कर्षों की पुष्टि में कारण अभिव्यक्त नहीं करने के फल स्वरूप सेवा से हटाने का विखण्डनीय आदेश दूषित हुआ है। यह आदेश इस कारण से भी दूषित है कि जाच अधिकारी के निष्कर्षों की जो अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वीकार किए, आह्वान द्वारा पुष्टि नहीं होनी।”² दुष्प्रयोग के एक अन्य मामले में, दोषी कर्मचारी ने कारण पत्राग्रा नोटिस पर अपनी आपत्ति पेश की थी। परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ने उन आपत्तियों पर विचार किए बिना, उसकी सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। अतः दण्ड का आदेश, कारण युक्त होना नहीं माना गया और इसलिये उसे अवैध करार दिया गया।³

1 AIR 1963 मुम्बई कोर्ट 1612, ILR (1973) कर्नाटक 1199।

2 1973 WLN 663—भारतीय सच वि. बी. के. दत्ता,

AIR 1972 राजस्थान 196—भारतीय सच वि. रामगोपाल।

3. 1925 SLJ 387—सरलोचनसिंह वि. पंजाब सरकार।

नियम 16 (11) लघु शास्तियो के अन्तिम आदेश — यदि किसी मामले में अनुशासनिक प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुँचे कि दोषी कर्मचारी पर नियम 14 के अनुच्छेद (i) से (iii) में निर्दिष्ट कोई लघु शक्ति अधिरोपित की जाए, तो वह मामले में उपयुक्त आदेश जारी करेगा। निःसन्देह, आदेश जारी करने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कि आयोग का परामर्श लेना आवश्यक हो, उसे साक़ सवा आयोग की राय पर विचार करना होगा।

नियम 16 (12)—अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों की सूचना — शास्ति अधि-रापित करने के आदेश की सूचना सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को निम्नलिखित अभिलेखों की प्रतियों के साथ दी जायेगी —

- (1) जाच अधिकारी की रिपोर्ट,
- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष, जबकि वह स्वयं जाच अधिकारी नहीं हो,
- (3) जाच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति के कारण संक्षेप में, यदि कोई हो, और यदि य दस्तावेज पहले से ही नहीं दिये गये हो,
- (4) लोक सेवा आयोग की सम्मति, और
- (5) आयोग की सम्मति स्वीकार नहीं करने के सक्षिप्त कारण, यदि ऐसा हो।

नियम 16 (12) का द्वितीय उपखण्ड अधिसूचना सख्या F-3 (13) नियुक्ति (ए III) 63 दि 16 जून, 1965 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यदि दोषी कर्मचारी को नियम 14 के खण्ड (i) से (iii) में निर्दिष्ट निम्नलिखितों में से कोई एक लघु शास्ति लागू करनी हो तो दोषी कर्मचारी को जाच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रति देनी आवश्यक नहीं होगी —

- (i) निन्दा,
- (ii) बतन वृद्धिया या पनोजति रोकना और
- (iii) किसी आर्थिक हानि को बतन से वसूल करना।

जब कि अनुशासनिक प्राधिकारी जाच अधिकारी के नतीजों से असहमत हो अथवा जब लोक सेवा आयोग का परामर्श अस्वीकार करे और कठोर शास्ति अधिरोपित करे, तो ऐसी असहमति का लिय कारण अनिवार्य रूप से देने होंगे। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट यदि कोई हो, की प्रति कर्मचारी का देनी चाहिये।¹

किसी सिविल कर्मचारी पर शास्ति लागू करने का आदेश "बोलता हुआ" होना चाहिये अर्थात् पूर्णतः कारण युक्त होना चाहिये। ऐसा आदेश सरसरी आज्ञा से भिन्न निष्कर्षों या नतीजों पर कारण व्यक्त करते हुए होना चाहिये।² ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि निगरानी या अपील में आदेश को चुनौती देने के लिये उपलब्ध उपचार लिखित कारणों के अभाव में केवल दिखावा मात्र (छलपूर्ण) रह जायेंगे।³ किसी व्यक्ति को दण्डित करने के लिये आदेश में अपने दृष्टिकोण के लिये

1 1970 आर एन डब्ल्यू 287—एस एन मिश्रा वि सरकार।

2 ए आई आर 1967 सु कोर्ट 1606—मगताराजा वि भारतीय सच।

3 1973 ए एस आर 442 हरमेन्द्र सिंह वि जनरल मेनेजर, उत्तरी रेलवे।

तथा महत्वपूर्ण आपत्तियों को नहीं मानने के कारण देते हुए, अर्थात् तर्कपूर्ण विवेचन करना चाहिए।¹ जब अध न्यायिक कार्यवाही होती है। अतः जबकि दोषी कर्मचारी के स्पष्टीकरण (प्रतिवेदन) पर विचार नहीं किया गया और उसे सेवा से हटाने के कारणों का भी उल्लेख नहीं किया गया तो, उक्त आदेश बेध नहीं माना जा सका क्योंकि वह 'बोलता हुआ' आदेश नहीं था।² आदेश स्वीकार्य सामग्री या साक्षी पर आधारित होना चाहिये अन्यथा वह अवैध होगा।³

इसके विपरीत, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जब अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो तो वह कारण व्यक्त करने के लिये बाध्य नहीं है। परन्तु यदि वह जब अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो तो उसे अपने स्वयं के निष्कर्षों के लिये कारण अभिव्यक्त करने होंगे।⁴

आदेश सूचना देने की तिथि से प्रभावशील होगा —

"5 अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश उस तीथि से लागू होगा जिस तीथि को वह सम्बन्धित राज्य कर्मचारी को सूचित किया जावे न कि उस तीथि से जिस दिन वह पारित हुआ।⁵ अन्य शब्दों में, आदेश उस तीथि से क्रियान्वित होगा जिस तीथि को उसे दोषी कर्मचारी ने प्राप्त किया।⁶ अतः, किसी आदेश को किसी पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता।⁷ जबकि वर्तमान की एक आदेश सेवा निवृत्त आयु से ठीक पहले पारित कर दिया गया और रेडियो प्रसारण द्वारा घोषित कर दिया गया और राजपत्र तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दिया गया, तो यह सूचना सही प्रकार से दी गई मानी गई क्योंकि उक्त नियम निदेशात्मक है न कि आदेशात्मक।⁸

17. छोटी शास्तियाँ लगाने की प्रक्रिया—(1) नियम 14 के खण्ड [1] से [3] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का तब तक आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि—

(क) सरकारी कर्मचारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव तथा ऐसे अभिकथनों की, जिन पर ऐसा किया जाना प्रस्तावित है, लिखित रूप में सूचना न दे दी गयी हो और उसको कोई अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, देने का अवसर न दे दिया गया हो,

(ख) ऐसे अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया हो।

1 (1974) 1 SLR 19, 1973 SLJ 834

2 (1975) Lab IC 1288 (कलकत्ता) जे पी बनर्जी वि भारतीय सघ। AIR 1974 मु बॉर्डे 87 भारतीय सघ वि एम एल. कपूर।

3 1976 Lab IC 1598 (पटना) शिवध्यान सिंह वि बिहार सरकार।

4 1977 S.C.C (L & S) 151 ताराचन्द सन्नी वि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देहली।

5 AIR 1966 मु. को 951 जीवरतन वि मद्रास सरकार।

6 AIR 1966 मु. को 1813, 1971 SLR 666.

7 AIR 1961 कलकत्ता 626—मुधिरजन वि प बगान सरकार।

8 1977 Lab IC (Noc) पञ्जाब तथा हरियाणा—पञ्जाब सरकार वि. परतार सिंह गरेवाल, 1976 SLWR 67।

* (ग) सरकारी कर्मचारी को, यदि वह चाहे तो, अपना मामला स्पष्ट करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(घ) उन मामलो में जिनमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, परामर्श कर लिया गया हो।

(2) ऐसे मामलो में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

[1] सरकारी कर्मचारी को, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रस्ताव की सूचना की प्रति,

[2] उसकी ससूचित अभिकथन विवरण की प्रति,

[3] उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो,

[4] आयोग की सलाह, यदि कोई हो, और

[5] मामले पर दिये गये आदेश, उनके कारण सहित।

राजस्थान सरकार के निर्देश

स्पष्टीकरण मांगने के पत्र का मसौदा बनाना और तामील करना—नियम 17.—जिस मामले में राजस्थान सिविल सेवा (बर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 के उप खण्ड (i) से (iii) में निर्दिष्ट कोई छाटी शास्ति लागू करना उचित प्रतीत हो, जब कि मामला मुख्यतः मौखिक साक्ष्य पर आधारित न हो, अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल एक पत्र दोषी कर्मचारी के नाम जारी कर देना चाहिए जिसमें प्रभावलोकन पर उसके विरुद्ध बन मामलो के आरोपों का उल्लेख करना चाहिए और उसे निर्धारित अवधि में, जैसे कि पन्द्रह दिन में, अपने आचरण को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस मेंमोरेण्डम में किसी प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिए क्योंकि खण्ड का निर्णय तो इस मेंमोरेण्डम (पत्र) के उत्तर में दोषी कर्मचारी से प्राप्त स्पष्टीकरण की जांच करने के पश्चात् करना है। उक्त मौमो पर अनुशासनिक प्राधिकारी को स्वयं हस्ताक्षर करना चाहिए न कि किसी अन्य प्राधिकारी को। उक्त प्राधिकारी को यह भी मुनि-यित करना चाहिए कि स्पष्टीकरण आमन्त्रित करने का पत्र कर्मचारी को (रजिस्टर्ड ए. डी डाक से या अन्यथा) अवश्य मिल जावे।

* 6 स्पष्टीकरण की जांच—

दोषी कर्मचारी से उसकी प्रतिरक्षा में प्राप्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, अथवा निर्दिष्ट अवधि में जैसी कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा समय समय (पर बढ़ाई गई हो) यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हो, तो उसके बिना अनुशासनिक प्राधिकारी, को, मामले के तथ्यों के आधार पर, किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए, उसकी जांच करनी चाहिए।

* अधिसूचना सं एफ 3 (9) कामिक/ए-III/78, जी एम आर 167 दिनांक 27 जनवरी, 1979 द्वारा जोड़ा गया जो राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दिनांक 8 फरवरी, 1979 को पृष्ठ 443 पर प्रकाशित हुआ।

"7 दोषी कर्मचारियों को दोष मुक्त करना या उनपर छोटी शास्तियां लागू करना—

(क) यदि मामले की जांच के परिणाम स्वरूप (जिसमें दोषी कर्मचारी का स्पष्टीकरण मांगा गया था, अनुशासनिक प्राधिकारी को तसल्ली हो जाए कि कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी को दोष मुक्त कर सकेगा। ऐसी दोषमुक्ति की सूचना कर्मचारी को लिखित में भेजी जाएगी।

(ख) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी इस सम्मति का हो कि मामले की जांच, स्पष्टीकरण सहित, कर्मचारी के विरुद्ध दोष सिद्ध होना दर्शाती है तो वह दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 14 के खण्ड (i) से (iii) में निर्दिष्ट छोटी शास्तियों में से कोई एक लागू कर सकेगा। छोटी शास्ति लागू करने में पहले दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना अवैध नहीं है और, इसलिए, टाला जाना चाहिए।

(ग) यदि दोषी कर्मचारी अपना दोष स्वीकार करते, तो निम्न लेने में सुविधा होगी, परन्तु यदि कोई ऐसा न करे, तो किम सीमा तक दोष साबित हुआ है, यह सारभूत अभिलेखों के सदर्भ में जांच करना होगा।

[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाहियों पर पुस्तिका, 1963 संस्करण अनुच्छेद 5, 6 तथा 7]

परिपत्र (सरस्यूसर)

नियुक्ति विभाग

स. F. 3 (7) App'ts A-III/70 दिनांक 23-5-1970.

"प्रतीत होता है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही में अनुसरणीय कार्य प्रणाली के विषय में कुछ गड़बड़ी है। एक गलत विचारधारा यह है कि नियम 17 के अधीन दिए गए नोटिस के उत्तर में दोषी अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात्, अनुशासनिक प्राधिकारी या तो स्वयं सारभूत अभिलेख के सदर्भ में दोषी कर्मचारी के अभिकथन की जांच करे या वह सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारी का आदेश दे कि वह रेकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के सदर्भ में प्रतिवेदन की जांच करे और तात्त्विक रिपोर्ट भेजे।

"सही प्रक्रिया यह है कि जब सी सी ए नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करनी हो, तो कोई औपचारिक आरोप (चार्ज) बनाना जरूरी नहीं है, और दोषी कर्मचारी को लिखित में सूचित करना है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है और वे आरोप बनाए जावे जिन पर कार्यवाही प्रस्तावित है। उसे प्रतिवेदन करने का अवसर, यदि वह चाह, तो दिया जावे, और यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे तो उस पर अनुशासनिक प्राधिकारी विचार करके उचित आदेश पारित करेगा। यह प्रक्रिया पालन करने में, प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी के पास रखे रेकॉर्ड के आधार पर जिस पर कि आरोप आधारित है, अपना मानम बनाएगा कि प्राया उक्त आरोप दोषी अधिकारी के विरुद्ध पर्याप्त रूप से साबित हैं, और यदि वे साबित होते हैं, तो किसी मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा नहीं है, और आदेश पारित किया जावे। यदि निर्दिष्ट अवधि में दोषी अधिकारी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करे, तो वह (अनुशासनिक प्राधिकारी) यह मान लेगा कि दोषी अधिकारी को कुछ नहीं कहना है और रेकॉर्ड के आधार पर मामले को, गुण-

दोषों पर निपटाने के लिए अग्रसर होगा। किन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दोषी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का मेमोरेण्डम या पत्र उसे प्राप्त हो गया है। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी यह अनुभव करे कि मामले में आग छानबीन करनी जरूरी है जिसमें प्रतिरिक्त दस्तावेजी या जबानी गवाहदत एवजित करनी आवश्यक है, अथवा प्रथमावलोकन से उन आरोपों पर कठोर शास्ति उपयुक्त होगी, तो नियम 17 के अधीन प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, परंतु उसे नियम 16 की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए और ताजा चार्जशीट और आरोपों का विवरण जारी करना चाहिये। यह तो केवल नियम 16 में ही है कि जिसमें या तो अनुशासनिक अधिकारी स्वयं जांच करे या राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और शरीर) नियमों के नियम 16 में निर्धारित तरीके से जांच संचालन करने के लिए किसी जांच अधिकारी की नियुक्ति करे। किन्तु यह अनुश नहीं है कि नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस का उत्तर प्राप्त होने के बाद जांच किसी अन्य अधिकारी से करवाई जावे।”

टिप्पणी

साधु शास्ति लागू करने की प्रक्रिया:— किसी सिविल कर्मचारी पर छोटी शास्ति लागू करने का आदेश पारित करने से पहले कुछ औपचारिकताओं का पालन करना होता है।

प्रथम तो, राज्य कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रस्तावित शास्ति के माध्यम से भेजने चाहियें, जिसमें उसको अवसर देना चाहिए कि यदि वह इस विषय में कोई स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) प्रस्तुत करना चाहे तो निर्दिष्ट अवधि में पेश करे।

द्वितीय में, जो अभ्यावेदन दोषी कर्मचारी से प्राप्त हो उस पर विचार करना चाहिए (यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हो)।

तृतीय में, जब भी इन नियमों के अधीन आवश्यक हो, तो लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए।

*चतुर्थ में एक नया प्रावधान हाल ही में जोड़ा गया है जिसके अनुसार दोषी कर्मचारी को यदि वह चाहे तो, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया जाना चाहिए।

अतः अंतिम आदेश अनुशासनिक प्राधिकारी तभी दे सकेगा जबकि उसने सम्बन्धित कर्मचारी के लिखित प्रतिवेदन पर विचार कर लिया हो, यदि प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो, और कर्मचारी को, यदि वह इच्छा प्रकट करे, तो उसे व्यक्तिगत रूप से सुन लिया गया हो।

राज्य सरकार ने मुख्यतः बल दिया है कि, पहले अनुशासनिक प्राधिकारी को केवल एक पत्र दोषी कर्मचारी के नाम जारी करना चाहिए जिसमें प्रथमावलोकन से जो आरोप उसके विरुद्ध बनते हो उनका उल्लेख होना चाहिए और कर्मचारी को इस विषय में अपना स्पष्टीकरण निर्दिष्ट समय, जैसे कि पन्द्रह दिन में प्रस्तुत करने का लिखा जाना चाहिए। इस पत्र में प्रस्तावित शास्ति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्ति का निर्णय तो दोषी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर

* अधिनूचना स एफ 3 (9) कामिग/ए III/78 जी एस. आर 167 दिनांक 27 जनवरी, 1979, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) (I) दिनांक 8 फरवरी, 1979 को पृष्ठ 443 पर प्रकाशित हुआ।

विचार करने के बाद तथा उस व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही किया जा जाता है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दोषी कर्मचारी को उक्त पत्र (जिस मीमांसा या मेमो-रान्ड भी कहा जाता है) रजिस्टर्ड डाक सेवा या अन्य तरीके से प्राप्त हो गया है।

अनुशासनिक प्राधिकारी को मामले पर विचार तब करना चाहिए जबकि दोषी कर्मचारी का स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हो या कर्मचारी न निर्धारित अवधि या समय समय पर बर्खास्त हो अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कोई स्पष्टीकरण पत्र नहीं दिया हो।

यदि दोषी कर्मचारी अपना दोष स्वीकार करले तो निर्णय लेना आसान होगी, परन्तु यदि वह दोष स्वीकार नहीं करे तो मामले की जांच कर्मचारी के लिखित स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक प्रतिवेदन पर विचार करते हुए की जानी चाहिए। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी को विश्वास हो जाए कि कोई दोष साबित नहीं होना, तो वह कर्मचारी को दोष मुक्त करेगा और इसकी लिखित सूचना उस कर्मचारी को देगा।

इसके विपरीत यदि अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्मचारी के स्पष्टीकरणों की जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि दोष साबित है, तो निम्नलिखितो में से कोई भी छोटी शास्ति जो वह मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझे लागू कर सकेगा, अर्थात्

(i) निन्दा, या

(ii) वेतन वृद्धि में रुकावट, या

(iii) पदोन्नति रोकना, या

(iv) कर्मचारी की लापरवाही के कारण, या किसी कानून या आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप सरकार को पहुँचाई गई आर्थिक हानि उसके वेतन से पूर्णतः या आंशिक रूप में बसूल करना।

लघु शास्तिया लागू करने के मामले में दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने तो आगे बढ़ कर यह चेतावनी दी है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को उक्त नोटिस देना टाल देना चाहिए, अर्थात् नहीं देना चाहिए।

यदि आरोप उपनय्य रेकॉर्ड के आधार पर साबित होता हो, तो किसी मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा नहीं है। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं करे, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को यह मान लेना चाहिए कि उसे कुछ भी नहीं कहना है और रेकॉर्ड के आधार पर मामले के गुण-धनगुणों पर फैसला देना चाहिए।

यदि प्रयोजनपूर्वक से मामला बँटोर शास्ति आरोपित करने योग्य प्रतीत हो तो ताजा नोटिस प्रादि देकर नियम 16 की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, किन्तु नियम 17 के अधीन दिए गए नोटिस के उत्तर में कर्मचारी का उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात्, किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाना अनुमति नहीं है।

प्रक्रिया में परिवर्तन —

"यद्यपि अनुशासन प्राधिकारी ने आरम्भ में नियम 16 के अधीन कार्यवाही शुरू की थी परन्तु बाद में वह छोटी शास्ति लागू करने के लिए नियम 17 के अधीन आगे कार्यवाही कर सकेगा, परन्तु, निरन्तर, यदि वह कार्य प्रणाली का नियम 16 से 17 में परिवर्तन करना चाहता है, तो नियम 17

की प्रक्रिया अपनाते से पहले, उसे सम्बन्धित व्यक्ति को स्पष्ट नोटिस देना चाहिए।¹ ऐसे नोटिस का अभाव शास्ति के आदेश को अवैध बना देता।² किन्तु यदि कोई जाच, नियम 16 के अधीन की जाती है और पूरी हो जाती है, तो अनुशासन प्राधिकारी को स्वतन्त्रता होगी कि वह दोषी कर्मचारी पर केवल कोई छोटी शास्ति आरोपित करदे।³ परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे विपरीत सम्मति प्रकट की और आई डी गुप्ता वि दिल्ली प्रज्ञामन⁴ में फंसला दिया कि, 'यदि आरम्भ में, नियम 14 (राजस्थान नियम 16) के अधीन ममोरेन्डम दिया गया हो और दोषी कर्मचारी का उत्तर प्राप्त होन के पश्चात् प्राधिकारी इस राय का हो कि कोई छोटी शास्ति ही उचित होगी तो प्राधिकारी, नियम 14 (राजस्थान नियम 16) की विस्तृत जाच प्रक्रिया पूरी किए बिना, लघु शास्ति लागू कर सकेगा।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय फतह सिंह सोडा वि राजस्थान सरकार⁵ में इस प्रकार दिया है — केवल इसी कारण से कि प्राची को पहले एक नोटिस 18 मई, 1964 को नियम 17 के अधीन जारी किया था, यह नहीं माना जा सकता कि जो ताजा अनुशासनिक कार्यवाही नियम 16 के अधीन, 29 अक्टूबर, 1964 को नोटिस देकर प्रारम्भ की गई, उस पर किसी प्रकार की रोक लगी हुई थी।⁶ इसी मामले में आगे यह कहा गया है कि, "जब तक कि किसी शोक सेवक के विरुद्ध कोई शास्ति लागू करने का आदेश, या उस पर लगाए गए आरोपों से उसे दोष मुक्त करने का आदेश किसी जाँच पर आधारित न हो, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उस शोक सेवक के विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी जिसमें उस पर शास्ति लागू करने की पहले की कार्यवाही बाद में निरस्त कर दी गई थी, सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध ताजा अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने पर तब तक कोई रुकावट नहीं होगी जब तक कि पहले की अनुशासनिक कार्यवाही को निरस्त करने के आदेश में इस विषय में कोई निर्देशन हो या यदि सम्बन्धित कर्मचारी को आरोप में दोष मुक्त कर दिया गया था।

"इस मामले में उन्ही तथ्यों के आधार पर और मूलतः उन्ही आरोपों पर पुन नई जाच करने पर कोई रुकावट नहीं थी और सक्षम प्राधिकारी को कानूनी अधिकार था कि प्राची को इन नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत नया नोटिस जारी करके वह नई जाच प्रारम्भ कर सके।"

लघु शास्तिया और बड़ी शक्तिया लागू करने की प्रक्रियाओं में अन्तर—

नियम 16 के अधीन बड़ी शास्तिया लागू करने तथा नियम 17 के अधीन छोटी शास्ति लागू करने की कार्य प्रणालियों में बहुत अन्तर है। नियम 16 के अन्तर्गत, जाच शीट और आरोपों का विवरण दोषी कर्मचारी को भेजना पड़ता है और उसके बाद नियमित जाच करनी पड़ती है जिसमें दोनों पक्षों की दस्तावेजी तथा मौखिक शहान्त ग्रहण करनी होती है, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को

1 I L R (1965) 15 राजस्थान 569—डा किशनसिंह वि राजस्थान सरकार: 1965 RLW 153 AIR 1966 राजस्थान 55

2 (1971) 1 SLR 40

3 AIR 1969 कलकत्ता 604—एम एम दत्ता वि भारतीय सघ। 1974 (2) SLR 602 (दिल्ली) के मिस्रल वि भारतीय सघ।

4 1973 (2) SLR 1

5 1977 WLN 421।

विरोधी पक्ष के गवाहों से जिरह करने का हक होता है और तत्पश्चात् वहस शुमार की जाती है। परन्तु छोटी (लघु) शास्तिओं के लिए, प्रक्रिया सरल बनाई गई है और नियम 17 के अनुसार किसी मौखिक साक्ष्य की जरूरत नहीं होती।

जब किसी कर्मचारी पर केवल निन्दा (परिनिन्दा) या वेतन वृद्धियां रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाती है तो न्योक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होता।

सी ए डी' सोजा वि. मध्य प्रदेश सरकार¹ में लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की कि परिनिन्दा पर्याप्त सजा होगी। अतः न्यायालय ने तय किया कि इन परिस्थितियों में अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं था कि कथित सचाह पर दोषी कर्मचारी को नोटिस जारी करके टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता।

'परिनिन्दा' की शास्ति किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) में केवल 'रिमाक' अंकित करने मात्र से भिन्न है। अमून्य रतन नायक वि. पश्चिम बंगाल सरकार² के विशेष लाक्षणिक मामले में, प्रार्थी ने उसकी सेवा पुस्तिका में अंकित निम्नलिखित टिप्पणी को हटवाने के लिए परमादेश की याचिका (Writ of mandamus) प्रस्तुत की,—“सदेहास्पद स्तयशीलता का ओवरसीयर” (An overseer of doubtful integrity)” अदालत ने तय किया कि उक्त 'रिमाक' केवल एक सम्मति थी और वह कोई 'परिनिन्दा' नहीं थी।

वेतन वृद्धि रोकने और वेतन रोकने में अन्तर—वेतन वृद्धियां रोकना नियम 14 के खण्ड (ii) में प्रावधानित एक छोटी शास्ति है, जबकि वेतन रोकना अनुज्ञ नहीं है और हमारे सविधान के सिद्धान्तों की अवहेलना है। उससे सविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होगा। सूरज नारायण वि. मध्य प्रदेश सरकार³ में पाठशालाओं के निरीक्षक ने एक अध्यापक को, असन्तोषजनक कार्य होने के आधार पर, वेतन वितरण करने से मना कर दिया। इसमें यह फैसला दिया गया कि किसी प्रादमी को काम करने के लिए कहना और बाद में उसका वेतन रोक लेना न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि सविधान की भावना के भी प्रतिकूल है। जब कि राज्य कर्मचारी ने अपना वेतन न कटौती स्वीकार नहीं की जिसके कारण उसका वेतन 18 महीनों तक रोक लिया गया और अन्ततः, उस सेवा से हटाने (discharge) का विकल्प दिया गया, तो निर्णय हुआ कि यदि देय वेतन कर्मचारी को नहीं दिया जावे तो वह निश्चय ही व्याज के रूप में या समुचित मुआवजा पाने का हकदार है जो प्रत्यक्ष उसको देय पूरे वेतन को रोकने से उत्पन्न हुआ।⁴

अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर—

जब किसी राज्य कर्मचारी पर केवल छोटी शास्ति लागू करनी हो, तो भी प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन (representation) पेश करने के लिए समुचित अवसर पाने का कर्मचारी हकदार होगा। अनुशासनिक प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले उसके अभ्यावेदन पर पूरा विचार करे। मामले पर अभ्यावेदन करने के लिए अवसर देने का तात्पर्य यह नहीं है कि कर्मचारी को गवाहों के बयानों की प्रतियां और दस्तावेजों की

1 AIR 1961 मध्य प्रदेश 261

2 AIR 1961 कलकत्ता 64

3 AIR 1960 मध्य प्रदेश 294।

4 AIR 1955 कलकत्ता 45—जैमिनी बान्ता दास वि. भारतीय सघ।

प्रतिया दी जावे और गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जावे। ऐसा करना नियम 17 की सीमा तथा परिधि में नहीं है।¹

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर—

पहले दोपी कर्मचारी केवल लिखित अभ्यावेदन दे सकता था और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अधिकार नहीं था। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। अब नियम 17 में खण्ड (ग) अधिमूल्यान स एफ 3 (9) कामिक/II/78 जी एस. आर 167 दिनांक 27 जनवरी 1979 द्वारा नया स्थापित किया गया है, जिसके अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी चाहे तो उसे अपना मामला स्पष्ट करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर बानूनन उपलब्ध है। अतः अब तो राज्य कर्मचारी स्वयं पर निर्भर है कि वह व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करे, जो अब उक्त नए प्रावधानानुसार अस्वीकृत नहीं की जा सकती।

उपयुक्त नये प्रावधान के पहले भी, डाक्टर विश्वनाथ सिंह वि. राजस्थान सरकार² में मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना आवश्यक समझा था। अभिव्यक्ति 'समुचित' या 'पर्याप्त' (adequate) अवसर से अभिप्राय सुनवाई का अवसर दिय जाने अथवा आरोपों के विरुद्ध कारण बताने से है।³

राज्य कर्मचारियों को मन्त्रणा—

राज्य कर्मचारी को जब नियम 17 के अधीन नोटिस तथा आरोपों का अभिकथन (statement of allegations) मिले, तो उसे पहले सम्बन्धित रेकार्ड और सामग्री, यदि कोई हो, का निरीक्षण करके अपनी याददास्त ताज़ा कर लेनी चाहिए। उसे ऐसा हक अधिकार स्वरूप उपलब्ध है। इसके लिए उसे लिखित में आवेदन करना चाहिए। कर्मचारी को उन सभी अखिलेश्वरी के उद्धरण ले लेने चाहिये जिन पर आरोप आधारित हैं और उनसे भी जिन पर उसको प्रतिरक्षा में आश्रय लेना है। उनके बाद उसे अपना अभ्यावेदन सावधानी से तथा प्रभावी तरीके से बनाना चाहिए जिससे उसका बचाव हो सके या उसका दोष कम से कम हल्का तो हो ही जावे। अभ्यावेदन का मसौदा बनाने के लिए कर्मचारी अपने से अधिक विद्वान या प्रतिभाशाली मित्र से सहायता ले सकता है। शांतमय रहे कि अभ्यावेदन विश्वास पैदा करने वाला तथा अपने आप में सम्पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि यही उसकी दाल तथा प्रतिरक्षा का बयन होगा। अपने मामले की दृष्टि में कर्मचारी अपने गवाहों के सत्यापित किये गये शपथ-पत्र (हलफनामे) या दस्तावेजों की नकलें पेश कर सकेगा। यदि आवश्यक हो, तो वह आवेदन करके अभ्यावेदन पेश करने की अवधि बढ़वा लेवे ताकि जल्दीवाजी के कु-परिणामों से बचकर सतुलित मानसिक स्थिति में सरलता पूर्वक अभ्यावेदन तैयार कर सके।

सब से जरूरी यह है कि कर्मचारी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को आवेदन अवश्य करे। नियम 17 के नए खण्ड (ग) के प्रावधानानुसार अब उसे व्यक्तिगत सुनवाई

1. 1977 Lab IC No C 28 (जम्मू तथा कश्मीर) यह फैसला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 1124 पर आधारित किया गया।
2. राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) (I) दिनांक 8 फरवरी, 1979 में पृष्ठ 443 पर प्रकाशित।
3. AIR 1966 राजस्थान 55 . 1965 RLW 153।
4. 1970 (2) ILR (पंजाब) 580 मलविन्दरजित सिंह वि. पंजाब सरकार और यह भी 1970 Lab. IC 170 (सुप्रीम कोर्ट) की डी गुप्ता वि. हरयाणा राज्य।

का कानूनी अधिकार मिल गया है और इसलिए अनुशासनिक प्राधिकारी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकता। व्यक्तिगत मुनवाई के समय कर्मचारी को धराना नहीं चाहिए और उसे अपना मन स्वतन्त्रता से, स्पष्टता से और हिम्मत से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि प्राधिकारी को तसल्ली या विश्वास हो जावे। अपनी दलीलों की पुष्टि में उसे आवश्यक दस्तावेजों को पढ़कर सुनाना चाहिए और कोई सामग्री हो तो दिखानी चाहिए ताकि उसके तर्क न्याय सगत और सही समझे जावें। अपना मामला जीतने के लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण निर्णय या नज़ीरे भी दृष्टान्त रूप से दे सकेगा।

2 शास्ति का आदेश कारण युक्त होना चाहिए—किमी सरकारी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने का आदेश 'बोलता हुआ' होना चाहिए, अथवा उसमें निष्कर्ष के औचित्य पर कारण व्यक्त करने चाहिए। दूसरे शब्दों में, उनमें अनुशासनिक प्राधिकारी का दिमाग यह बताते हुए प्रतिलिम्बित होना चाहिए कि जिससे उसने सम्बन्धित कर्मचारी को सजा देने का विचार किया।¹ एक अन्य मामले में, वेतन वृद्धि रोकने के आदेश में, सिविल कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर लिए गए निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किए गए। अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि शास्ति के आदेश में कारणों का अभाव होने में नियम 23 के अधीन प्रदत्त अपील का अधिकार केवल दिखावा मान हो जाएगा, अतः उक्त आदेश अवैध तथा शून्य था।² इसी प्रकार वेदपाल किशन धीर वि राजस्थान सरकार³ में पाया गया कि दोषी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश में कोई कारण नहीं दिए गए थे जिनके आधार पर उसके विरुद्ध बुराचरण का मामला स्थापित किया गया। अतः यह आदेश अवैध घोषित किया गया।

दोषी कर्मचारी के अभ्यावेदन पर विचार जरूरी—अनुशासनिक प्राधिकारी का यह आवश्यक कर्तव्य है कि दोषी कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर समुचित विचार करे। यह वैधता औपचारिकता मान नहीं है। आदेश में केवल एक संक्षिप्त वाक्य लिख देना कि "अभ्यावेदन पर" सावधानी से विचार कर लिया गया और वह सतोषप्रद नहीं पाया गया", कानून की अपेक्षताओं की पूर्ति नहीं करता। "जब कि नियम 8 (राजस्थान नियम 17) के अन्तर्गत वेतन वृद्धि रोकने की लघु शास्ति का आदेश यह नहीं दर्शाता कि दोषी अधिकारी के अभ्यावेदन पर विचार कर लिया गया है, तो ऐसा आदेश अवैध है क्योंकि वह 'बोलता हुआ' (कारण युक्त) आदेश नहीं है। आदेश में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त विचार किया जाना प्रतिबिम्बित होना चाहिए। विखण्डनीय आदेश में शब्द 'विचार किया (Considered)' का विराम लगाना मात्र, नियम 8 (राजस्थान नियम 17) की अपेक्षताओं के लिए पर्याप्त नहीं है और न ही यह प्राकृतिक न्याय की अपेक्षताओं की पूर्ति ही करता है। आदेश की भाषा में किसी प्रकार से ऐसा विचार किया जाना प्रदर्शित होना चाहिए।

"शास्ति का जो आदेश नियम 8 (राजस्थान नियम 17) के अधीन दिया गया है वह बिना नियमिन विभागीय जाच के जारी किया गया है और वह सर्व प्रथम आदेश है जिसमें किसी रूप में ऐसी सामग्री हानी चाहिए जो यह दर्शावे कि अभ्यावेदन पर विचार किया गया है।"⁴

- 1 (1977) SLR 809: 1978 Lab. IC Noc 85 (पंजाब तथा हरियाणा) पंजाब सरकार वि रामकिशन चौखटा। AIR 1972 मुंबई कोर्ट 2083 का अग्रथय लिया गया।
2. 1978 Lab. IC (41) कलकत्ता-टी और पाण्डे वि चीफ सी ए एन.
3. 1977 WLN UC 397
4. 1978 Lab IC Noc 85.

18 सयुक्त जांच—(1) जहाँ किसी मामले से दो या अधिक सरकारी कर्मचारी सबधित हों, सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारियों की सेवा से पदच्युत करने की शास्ति लगाने के लिए सक्षम हो, यह आदेश दे सकेगा कि उन सबके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक साथ की जाय।

(1) ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किए जायेंगे —

- [1] वह प्राधिकारी, जो उक्त एक साथ की जाने वाली कार्यवाही के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी होगा,
- [2] नियम 14 में विनिर्दिष्ट वे शास्तियाँ जिन्हें लगाने के लिए उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी समक्ष होगा, और
- [3] क्या कार्यवाही में नियम 16 में अवध 17 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय।

राजस्थान सरकार का निर्देश

सयुक्त जांच —जहाँ दो या अधिक राज्य कर्मचारी (राजपत्रित या अराजपत्रित, जो एक ही सेवा के हों या भिन्न भिन्न सेवाओं में) किसी मामले से सम्बन्धित हों, तो सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी जो उन सभी राज्य कर्मचारियों पर वर्तमान की शास्ति लागू करने के लिए समर्थ हो, यह आदेश दे सकेगा कि उन सब के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही एक ही सम्मिलित कार्यवाही के अन्तर्गत की जावे। ऐसे मामले में वरिष्ठतम दोषी कर्मचारी को वर्तान कर देने वाला प्राधिकारी सभी दोषी कर्मचारियों को चार्ज शीट जारी करेगा।

[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाहियाँ पर पुस्तिका (1963 संस्करण, अनुच्छेद 10)]

टिप्पणी

नियम 18—सयुक्त जांच —जब दो या दो से अधिक राज्य कर्मचारी एक ही घटना के कारण लिप्त हों, तो उन सब की जांच एक ही सम्मिलित कार्यवाही में की जा सकेगी। सयुक्त जांच के लिए स्वीकृति अपेक्षित है जो या तो राज्य सरकार की होगी या उन प्राधिकारियों की होनी चाहिए जो जाचप्रस्त सभी राज्य कर्मचारियों को सेवा से वर्तान करन की क्षमता रखता हो। उन सब के विरुद्ध सयुक्त जांच की कार्यवाही करने के आदेश में निम्नलिखित बात निर्दिष्ट की जाएगी —

- (1) प्राधिकारी का नाम और पद जो अनुशासनिक प्राधिकारी के कर्तव्य पालन करेगा,
- (2) शास्तियाँ जो उक्त अनुशासनिक प्राधिकारी लागू कर सकेगा।
- (3) आया जाच करने की कार्य प्रणाली नियम 16 में (कठोर शास्तियों के लिए) निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी, अथवा नियम 17 में लघु शास्तियों के लिए निर्धारित प्रावधानानुसार।

राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए एक ही जांच हो सकेगी, परन्तु उस सयुक्त जांच में नियुक्त अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जो कि प्रत्येक सम्बन्धित दोषियों से सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारियों में से वरिष्ठतम है जो कि प्रत्येक की सेवा से वर्तान करने की सजा देने के लिए सक्षम हो। अतः सभी को वर्तान करने की क्षमता प्राप्त प्राधिकारी ही सभी दोषियों को चार्ज शीट (आरोप-पत्र) जारी करेगा।

जबकि सरकार स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी हो और संयुक्त जांच का निदेशन दे, और अनुशासनिक प्राधिकारी के नियुक्ति आदेश में शास्ति या निदिष्ट न करे, तो कोई विशेष त्रुटि नहीं होगी। सरकार किसी व्यक्ति को संयुक्त जांच करने के लिए नियुक्त कर सकती है।¹

संयुक्त जांच के विरुद्ध में आपत्ति:—चार्ज शीट पाने वाला कोई भी एक या अधिक दोषी कर्मचारी, दूसरे कर्मचारियों के साथ साथ संयुक्त जांच किए जाने के विरोध में अपनी आपत्ति जांच अधिकारी के सम्मुख प्रेषित कर सकेगा। परन्तु जब तक यह नहीं बता दिया जावे कि संयुक्त जांच से आपत्तिकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तब तक ऐसी जांच दोषपूर्ण नहीं मानी जा सकती।² जब संयुक्त जांच से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो तो जांच अवैध नहीं होगी।³ विभागीय जांचों में संयुक्त फौजदारी मुकद्दमों से सम्बन्धित भारतीय दण्ड प्रक्रिया सग्रह (जान्ता फौजदारी) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।⁴

19. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया—नियम 16, 17 तथा 18 में किसी बात के होते हुए भी—

- [1] जहां, सरकारी कर्मचारी पर कोई शास्ति, ऐसे आचरण के आधार पर लगाई जाए जिसके कारण वह किसी फौजदारी आरोप पर सिद्ध दोष हुआ हो, या
- [2] जहां अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, समाधान हो जाय कि उक्त नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है, या
- [3] जहां राज्यपाल का समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करना समीचीन नहीं है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसे आदेश, जो वह उपयुक्त समझे, दे सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी मामले में, जिसमें आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, ऐसे आदेश देने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा।

टिप्पणियाँ—यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि किसी व्यक्ति को सविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के अशून कारण बताने का अवसर देना युक्तियुक्त रूप से साध्य है अथवा नहीं तो ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने, या हटाने या उसे पंक्ति में अवनत करने के लिए मध्यम प्राधिकारी के विनिश्चय की केवल एक ही अपील (उसमें) अगले उच्च प्राधिकारी को हो सकेगी।

1. 1978 Lab. I C 41 (बन्कत्ता) टी आर पाण्डे वि. चीफ नगीशनर ए एन ; AIR 1971 गुपीन कोर्ट 862 का आश्रय लिया गया।
2. 1975 (1) SLR 315 आर नरमिहा रेड्डी वि आन्ध्रप्रदेश सरकार।
3. AIR 1956 आन्ध्रप्रदेश 197—एम बी. जोगराव वि. आन्ध्रप्रदेश सरकार।
4. AIR 1955 आन्ध्रप्रदेश 168—ठाकुरजी वि. आन्ध्रप्रदेश सरकार।

राजस्थान सरकार का निर्देशन

निम्नलिखित मामलों में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और भर्ती) नियमों के नियम 16, 17 एवं 18 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना है—

- (i) जहाँ राज्य कर्मचारी पर कोई शास्ति, ऐसे आचरण के आधार पर लागू की जावे जिसके कारण वह किसी फौजदारी चार्ज पर सिद्ध दोष (conviction) हुआ हो, या
- (ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी को ऐसे कारणों से, जो लिखित में अभिलिखित किए जाएं, तसल्ली हो जाए कि कथित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है, उदाहरणार्थ, जबकि मुलजिम फरार हो, या किसी अन्य कारण से उसे सम्पर्क स्थापित करना साध्य नहीं हो, या
- (iii) जहाँ कि राज्यपाल को तसल्ली हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी प्रक्रिया अपनाना इष्टकर नहीं है,
- (iv) विध्वंसक गतिविधियों में लगे होने के कारण राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए अनुमरणीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा) नियम, 1954 (Rajasthan Civil Service (Safe-guarding of National Security) Rules, 1954) देखिए।

[राजस्थान सरकार की अनुशासनिक कार्यवाही पर प्रवृत्ति (1963), अनुच्छेद 18]

टिप्पणी

नियम 19, सन्निधान के अनुच्छेद 311 (3) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्धारित सिद्धान्त पर बनाया हुआ है। अनुच्छेद 311 (2) में लिखा है कि सिविल सेवा के किसी सदस्य को तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा अथवा पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी जाच, जिसमें उसे अपने खिलाफ दोषारोपों से अवगत करा दिया गया है और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिया गया है नहीं करती जानी।" परन्तु इस सिद्धान्त के तीन परन्तुक हैं जिन दिशाओं में उपर्युक्त प्रावधान (सिद्धान्त) लागू नहीं होगा, जो निम्नलिखित हैं:—

- “(क) जहाँ कि कोई व्यक्ति ऐसे आचार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया या पदच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड दोषारोप पर वह सिद्धदोष हुआ है या
- (ख) जहाँ कि किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पदच्युत करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लक्ष्य किया जायेगा, यह युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है कि ऐसी जाच की जाये, या
- (ग) जहाँ कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नहीं है कि ऐसी जाच की जाये।”

अतः नियम 19 प्रावधान करता है कि उपर्युक्त बताई गयी तीन प्रकार की परिस्थितियों में नियम 16, 17 तथा 18 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। इन नियमों का नियम 19 एक अपवाद है।

खण्ड (1)—आचरण जिसके आधार पर फौजदारी आरोप सिद्ध दोष हुआ.—जब किसी राज्य कर्मचारी को किसी फौजदारी मुकदमे में दोषी करार दिया गया हो तो उसके विरुद्ध कोई औपचारिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि कर्मचारी का अपराध नैतिक पतन का हो। इस खण्ड में शब्द 'आरोप (चार्ज)' से तात्पर्य दोषी पाये जाने से है, जो भारतीय दण्ड प्रक्रिया के माध्यम से शब्द 'चार्ज' के तकनीकी तात्पर्य से भिन्न है। न्यायालय के पीठाव्याप्त के विरुद्ध अपमानजनक कथन करने से न्यायालय अपमान सिद्ध दोष होने पर राज्य कर्मचारी को नियम 19 के खण्ड (1) के अधीन दण्डित करने के लिए पर्याप्त कारण है यद्यपि उक्त अपमान भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध नहीं है।¹ एक पुलिस कांस्टेबल को सार्वजनिक स्थान पर नशे की हालत में पाये जाने का अपराधी होने में उसे पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के अधीन सिद्ध दोष पाया गया। इस कारण से उसे सेवा से बिना किसी जांच किए बर्खास्त कर दिया गया। उसने दलील पेश की कि कथित अपराध नैतिक पतन की श्रेणी में नहीं आता। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सविधान के अनु. 311 (2) के परन्तुक (क) में यह बाहरी शब्द नहीं मिलाये जा सकते थे और अतः यह भी कि पुलिस अधिनियम की धारा 34 का अपराध नैतिक पतन बनता है।²

इसी प्रकार, दिनकर राव वि. मध्य प्रदेश सरकार³ में जबकि अपीलकर्ता के विरुद्ध फौजदारी अपराध सिद्ध हुआ, तो उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके विरुद्ध सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। अदालत ने इसे सविधान के अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (क) का उल्लंघन नहीं माना। दोष सिद्ध होने पर सरकारी कर्मचारी की सुनवाई करना तो आवश्यक नहीं है परन्तु उसे बर्खास्तगी का नोटिस देना जरूरी है, अन्यथा बिना जांच या बिना नोटिस के शास्ति का आदेश जारी करना अवैध होगा, जैसा कि टीका राम विन्दर वि. रजिस्ट्रार में निर्णित हुआ।⁴

अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (क) द्वारा अपवाद का प्रावधान करने के पीछे कारण स्पष्ट है। सिद्ध दोष होने की अवस्था से पहले, फौजदारी न्यायालय में न्यायिक जांच के दौरान, निम्नलिखित कर्मचारी को सुनवाई का तथा अपने आप की प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका होता है। इससे पारस्परिक विरोधी नतीजों की संभावना भी टलती है। यह परन्तुक, अनुशासनिक प्राधिकारी को पहले, आरोपों के सम्बन्ध में और तत्पश्चात्, प्रस्तावित शास्तियों के लिए, नोटिस जारी करने की आवश्यकता से भी मुक्त करता है।⁵

परन्तु जब कि एक राज्य कर्मचारी की भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 के अधीन विधि विरुद्ध जमाव (unlawful assembly) के रचनात्मक दायित्व (constructive liability) के लिए सिद्ध दोष किया गया और उस आधार पर उसे सेवा से हटा दिया गया, तो फंसला हुआ कि हटाये जाने का उक्त आदेश अवैध था, क्योंकि सजा कर्मचारी द्वारा वास्तविक भाग लेने पर ही आधारित होनी चाहिये।⁶

1. AIR 1946 मद्रास 375 वैक्टरामा Vs प्रोविन्स ऑफ मद्रास।
2. AIR 1957 पंजाब 97—दुर्गासिंह वि. पंजाब सरकार।
3. 1977 Lab I C 34 : AIR 1977 मध्य प्रदेश 13 (पूर्ण पीठ)
4. 1978 Lab. 16 NOC—13 (म. प्र.)—1975—Lab I C 1598 (मु. को.) का आश्रय लिया गया।
5. 1974 WLN 176; 1975 (1) SLR 792, कुनदीप सिंह वि. भारतीय सच।
6. 1967 Lab. IC 868 (हिमाचल प्रदेश) हरदयाल सिंह वि. हिमाचल प्रदेश सरकार।

एक अन्य मामले महोम्मद तैय्युम वि भारतीय सघ¹ में रिश्कत लेने के आरोप पर जाच करने की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और अभिलिखित कारण को “अग्राह्य, गलतफहमी तथा बिना सुसंगतता के और बिना कानूनी औचित्य” (Superficial, misconceived and irrelevant without any legal justification) के करार दिया गया। अतः न्यायालय न निर्णय दिया कि ऐसे मामले में जाच परित्याग नहीं की जा सकती।

यदि वाद में सिद्ध दोष (conviction) अपील में या अन्यथा निरस्त कर दिया जावे, तो वर्त्तमान के आदेश का प्रभाव समाप्त हो जायेगा और कर्मचारी को, जब तक कि वह सविधान के अनुच्छेद 311 (2) की पातना करते हुए सही तरीके से बर्खास्त नहीं किया जावे तब तक उसे दुरन्त पुनःस्थापित करना चाहिये और बर्खास्तगी की सीध से बकाया वेतन उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।²

सविधान के अनुच्छेद 311 (2), जो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियमन और अपील) नियम 1958 के नियम 19 का आधार है, पर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी पी वेरी और न्यायमूर्ति बी पी गुप्ता की खण्ड पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह पैमला कुलदीप सिंह तथा अन्य वि भारतीय सघ³ में घोषित किया गया है, जिसका पैरा 14 इस प्रकार है —

(1) यह भी दलील दी गयी कि दोष सिद्ध हो जाने के परिणाम स्वरूप रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्तगी से उसकी अयोग्यता (disqualification) बन गई। हम इससे सहमत होने में असमर्थ हैं। उसका आचरण जिसके आधार पर फौजदारी आरोप सिद्ध हुआ, बिनाय दावा पैदा करता है, ना कि सिद्ध दोष होना। सिद्ध दोष होने मान स कर्मचारी आवश्यक रूप से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जायेगा ना ही किया जाना चाहिये।”

(2) स्थिति जबकि राज्य कर्मचारी को प्रोवेशन अधिनियम का लाभ दिया जावे — प्रोवेशन अधिनियम की धारा 12 निम्न-लिखित है —

“धारा 12 सिद्ध दोष से सनन अयोग्यता का हटना,—

किसी अन्य कानून में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया जावे और उसके साथ धारा 3 या 4 का सलूक किया जावे तो वह किसी अनर्हता (disqualification), यदि कोई हो, का भागी नहीं होगा जो कि उक्त कानून के अधीन किसी अपराध में सिद्ध दोष होने पर लागू होती है।

परन्तु शर्त यह है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसे धारा 4 के अधीन छोड़ दिये जाने के पश्चात् मूल अपराध के लिये वाद में सजा दी जावे।”

यह धारा प्रावधान करती है कि यदि किसी कानून के अन्तर्गत सिद्ध दोष होने का तात्पर्य अनर्हता (disqualification) है, तो वह व्यक्ति जिसके साथ प्रोवेशन अधिनियम की धारा 3 या 4

1 1977 Lab IC 1590।

2 AIR 1961 मद्रास 486, भारतीय सघ वि अक्बर, AIR 1959 पंजाब 401 दिलवाग वि सभागीय अधीक्षक, AIR 1960 इलाहबाद 538 दास वि सभागीय अधीक्षक।

3. 1974 WLN 176

के अधीन व्यवहार किया गया हो ऐसी अनर्हता का भागी नहीं होगा। इस सम्बन्ध में न्यायालय ने निर्णय दिया कि, "सिद्ध दोष आवश्यक रूप से उसे सेवा में रखे रहने के लिये अनर्हता नहीं करता और इसके विपरीत, कर्मचारी को प्रवेशन अधिनियम का लाभ दिये जाने से अनुशासनिक कार्य-वाहियों से उसे उन्मुक्ति (Immunity) नहीं मिलेगी। जो बचाव धारा 12 प्रावधानित करती है, वह केवल अनर्हता (अयोग्यता) के विरुद्ध है यदि अनर्हता सिद्ध दोष से सम्बन्ध किसी कानून के अधीन लागू की गई हो, और वह दुराचरण के मामले से भिन्न है जिसमें वि नियोजन के सम्बन्ध में भिन्न परिणाम निकल सकते हैं।" "प्रवेशन अधिनियम की धारा 12 राज्य कर्मचारी को विभागीय कार्यवाहियों से उन्मुक्त नहीं करती।"

(3) जिस अपराध का अन्त सिद्ध दोष में हुआ उसकी प्रकृति से कोई शर्त सम्बन्ध नहीं है। अतः अनुच्छेद 311 (2) में सभी प्रकार के सिद्ध दोष समाविष्ट हैं।

अनुशासनिक प्राधिकारी न्यायिक तथा इमानदार होना चाहिये.—जब एक सिविल कर्मचारी को पौत्रदारी अशक्त ने बरी कर दिया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्राधिकारियों ने पहले से ही उस व्यक्ति को सजा देने का मानस बना लिया था और उसकी गैरहाजरी में क्षति की मात्रा तथा आरोपित भूलचूक का अनुमान लगा रहे थे। नियमों के अधीन या प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उसे कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि विभागीय अधिकारियों का पक्षपत रिकॉर्ड पर प्रत्यक्षनः स्पष्ट था। इसलिये उक्त आदेश खारिज किया गया।¹ प्राधिकारी को मामले की सभी परस्थितियों पर विचार करना चाहिए और विचार की कार्यवाही में सजा की मात्रा के विषय में दोरी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करके उसे साथ लेकर चलना चाहिए।²

खण्ड (11)—विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना मुक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है—जब अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रतीत हो कि निर्धारित प्रक्रिया उचित रूप से पालन करना अव्यवहार्य है और दोरी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस देना असाध्य है, तो इस तथ्य को वह लिखित में रिकॉर्ड पर रलेगा और उसके पश्चात् वह रिकॉर्ड से साबित तथ्यों के आधार पर शास्ति का आदेश पारित करने के लिये अग्रसर हो सकेगा। यह असाधारण प्रक्रिया बहुत ही अपवाद स्वरूप मामलों में ही काम में ली जानी चाहिये। किसी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त करने या हटाने का आदेश देने में पूर्व यह शास्तियाँ लागू करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को, अर्थात् नियुक्त प्राधिकारी या किसी अन्य उचित प्राधिकारी को स्वयं तत्सुची हो जानी चाहिये कि सामान्य निर्धारित प्रक्रिया अपनाया व्यवहारिक रूप से असाध्य है।³ जबकि प्राधिकारी ने उचित उच्चतर प्राधिकारी के आदेश का पालन किया और स्वयं ने स्थिति की जांच नहीं करते हुए सीधा कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया तो इस आदेश की बंधना 'केवल' इस आधार पर स्थिर नहीं रह सकेगी कि उसने नियम 19 के

1 1974 SLWR 407 दिल्ली: (1973) 2 SLR 331 1973 SLJ 918

2. AIR 1975 मुंबई कोर्ट 2216—डिविजनल परमोनल आफिसर—वि. टी. आर. चेंनापा—इससे विपरीत राय के लिए देखिए—AIR 1971 मुंबई कोर्ट 2004—बी. सी. दाम वि. प्रामाण सरकार।

3. (1975) SLR 800—भारतीय संघ वि. एन. के. चन्दा।

खण्ड (ii) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग किया था।¹ जो प्राधिकारी ऐसी बठोर शास्ति या लागू करने के लिये सक्षम है उसे कर्मचारी को नियम 16, 17 या 18 में प्रावधानित अवसर में बर्तन करने के लिये उचित कारण लिखित में रिकर्ड पर लगाने चाहिये। जब कोई आदेश निर्धारित प्रक्रिया को टालते हुए जारी किया गया हो और तत्पश्चात उसे चुनौती दी गयी हो, तो यह दलील नहीं दी जा सकती कि उक्त आदेश उपयुक्त खण्ड के कारण वैध है।²

जो प्राधिकारी बर्खास्तगी आदि की शास्ति लागू करने के लिये सक्षम हो उसे लिखित में यह अभिलिखित करना जरूरी है कि नियम 16, 17 या 18 की प्रक्रिया का अनुसरण करना "युक्तिपुक्त रूप से साध्य नहीं है" यह अभिव्यक्ति ऐसी परास्थिति के लिये है जबकि दोषी कर्मचारी उपलब्ध न हो, या फरार हो या जबकि उसे नोटिस देना सम्भव न हो।³

नि सन्देह, दण्ड देने वाले प्राधिकारी का यह गमिन (implied) कर्तव्य है कि वह "मामले की परस्थितियों पर न केवल उद्येष्ट्यपूर्ण विचार करें परन्तु यह भी आवश्यक है कि वह ऐसी प्रक्रिया में कर्मचारी को भी साथ रखा जावे। परन्तु इस प्रकार के ऐसे मामले में दोषी कर्मचारी को साथ रखना सर्वत्र सम्भव नहीं भी हो सकता है उदाहरणार्थ जबकि वह गायब हो या उस तक नहीं पहुँचा जा सकता हो या उसका पता नहीं लगाया जा सकता हो। अतः उनको उनका ही साथ रखा जा सकेगा जितना कि व्यवहार रूप से सम्भव हो।⁴ जो मामले खण्ड (ii) में आते हैं उनमें भी अनुशासनिक प्राधिकारी को सरसरी जांच करनी चाहिये जिसमें कर्मचारी को उनसे विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का अवसर देना चाहिये।⁵

आया युक्तिपुक्त रूप से साध्य नहीं है—नियम 19 के नीचे दी गयी टिप्पणी पीडित राज्य कर्मचारी को इस विषय पर केवल एक अपील अवसर उच्च प्राधिकारी के समक्ष करने का प्रावधान करती है इस प्रश्न के निर्णय हेतु कि आया सविधान के अनुच्छेद 311 के खण्ड (2) के अधीन कारण बताओ नोटिस देना युक्तिपुक्त रूप से साध्य नहीं था। यह दोषी अपराधी के पक्ष में एक कानूनी प्रावधान है, यद्यपि सविधान के अनुच्छेद 311 (3) के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करने, हटाने या पदावनत करने के लिये सक्षम प्राधिनारी द्वारा लिया गया निर्णय इस विषय में अन्तिम है।

चू कि नियम 19 के अधीन दिये गये आदेश की अपील हो सकती है और उसे रिट याचिका द्वारा भी चुनौती दी जा सकती है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि शास्ति आरोपित करने से पहले जांच नहीं करने के लिये आदेश में जांच नहीं करने के पूर्ण कारण दिये जाने चाहियें। प्रभावित

1. AIR 1965 आसाम 18—मुगीराम वि पुलिस अधीक्षक।

2. उपर्युक्तानुसार।

3. AIR 1965 जम्मू-कश्मीर 53—करणसिंह वि यानायात आयुक्त।

4. 1977 Lab IC 643 (दिल्ली)—आर. के मिश्रा वि जनरल मैनेजर उ लेलवे।

5. AIR 1975 सु कोर्ट 2216 डिविजनल परबनस ओफिसर वि टी. आर. चेलाप्पा का का आश्रय लिया गया।

के नियम यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसे कारणों की प्रतिनिधित्व के लिये आवेदन करे।¹

नियम 19 (iii) राज्य की सुरक्षा के हित में—सविधान के अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (ग) —जब कि राज्यपाल को समाधान (तत्सर्ली) हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में सामान्य न्याय का अनुसरण करना इष्टतर (उपयुक्त) नहीं है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की स्थितियों पर विचार करेगा और जैसा भी वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा। ऐसे मामले में राज्यपाल जाच करने से व यहाँ तक कि दोषी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस तक स मनाई कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें आरोप प्रकट करने से राज्य की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है। इस उप-खण्ड में अभिव्यक्ति “समाधान हो जाए” के साथ कोई भी लगी हुई नहीं है। अतः राज्यपाल के लिए आवश्यक नहीं है कि वह इस असामान्य कार्यवाही के लिए कारण प्रकट करे और इस विषय में राज्यपाल को कोई जाच करना आवश्यक नहीं है। अनुपविचम बंगाल सरकार कि नरेन्द्र नारायण में दिये गये हाल ही के एक फैसले के अनुसार, न्याय आदेश जारी करने से पहले सविधान के अनुच्छेद 311 (2) परन्तुक (ग) की अपेक्षताओं का पालन होना चाहिए, जो, नि सदेह, न्यायिक नजरमानी के अधीनस्थ है।² “आरोपों की जाच के भाव में, अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध सभी कारण नामों नोटिस नहीं देने का अभिप्राय यह लगाना चाहिए कि इसमें आरोपों की मत्पता की जाच और भी जाच के बाद प्रस्तावित शास्ति का इरादा भी शामिल है।”³

“अनुच्छेद 311 (2) का परन्तुक (ग), सरकार की मन्त्री मण्डल पद्धति के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल के व्यक्तिगत समाधान की अपेक्षा सर्वेधानिक अर्थ में नहीं करता। इसलिये अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन शक्तिन्या, अन्य कार्यकारिणी के कार्यों की तरह व्यवहार्य नियमों (Rules of Business) द्वारा किसी को सुपुर्द की जा सकती है और ऐसी दशा में, अनुच्छेद 166 (3) के अधीन बनाये गये व्यवहार्य नियमों के अधीन किसी मन्त्री या अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय राज्यपाल का निर्णय माना जाएगा। इस दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन दिया गया आदेश कार्यकारिणी द्वारा प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करना समझा जाएगा और इस प्रकार स शक्तियों का प्रयोग करना उसी प्रकार से न्यायिक नजरमानी के अधीनस्थ रहेगा जिस प्रकार से अन्य विभागीय आदेशों की जाच न्यायालय करत है।”⁴

सविधान के उपपुंक्त अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त कार्य-कारिणी का अधिकार स्वविवेकी (discretionary) है, और उसमें सोचागया समाधान अधिकरण

- 1 (1975) 1SLR 277 (गुजरात) भोलानाथ वि भारतीय सघ,
- 1977 Lab IC 105 (इनाहावाद) इन्द्रदेवसिंह वि भारतीय सघ,
- 1977 Lab IC 174 (पटना) रामचरित शर्मा वि भारतीय सघ।
- 2 ARI 1962 कलकत्ता 481।
- 3 1977 SLR 756—वी सी दास वि आसाम राज्य (AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1547—सर-दारीलाल के मामले में दिया गया फैसला उलट दिया गया।)
- 4 1977 Lab IC 628 (पूर्ण पीठा) मृन्तान कान्तिदास वि पश्चिम बंगाल सरकार। यह भी देखिए—AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 1249—एम. ए. रथोद वि केरल सरकार तथा AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 2192 जिसने AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1947 को विपक्षित किया।

सम्बन्धी (subjective) है।¹ परन्तु “किसी के व्यक्तिगत हित को सीधा प्रभावित करने वाले राजकीय प्राधिकार का प्रयोग किसी वैध बुनियाद पर आधारित होना चाहिए।² हैलिमबरी के “इंग्लैण्ड का कानून” चतुर्थ संस्करण की जिल्द के अनुच्छेद 20, 27, 61 और 62 के अनुसार, चू कि राज्यपाल, अनुच्छेद 311 (2) की अपेक्षाओं का परिचालन केवल तभी कर सकता है जब कि उसका समाधान हो जाये कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टतर नहीं है कि ऐसी जाच की जाए, इसलिए न्यायालय को यह अभिनियमित है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आया ऐसी कार्यवाहियों शक्ति के प्रयोग पर लागू शर्तों का पालन किया गया है। स्वाभाविक है, कि न्यायालय उन कारणा की परीक्षा करता की जाच नहीं करता जिन के आधार पर कार्यवाहियों की निदेशन शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रथम तो प्रदालत जाच कर सकती है कि आया ‘राष्ट्रपति या राज्यपाल या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त प्राधिकारी, न यदि कोई हो, अनुच्छेद 311 (2) के परन्तु (ग) की शर्तों के अनुसार वास्तव में कोई निर्णय लिया है। दूसरे में स्वविवेकी शक्ति के प्रयोग के लिए कतिपय शर्तों का पालन होना चाहिए, जो—(i) सद्भावना, (ii) सारभूत मामलों पर विचार और (iii) कार्यवाहियों द्वारा न्यायिक कार्यवाही करना है।

मुनालकातिदास वि पश्चिम बंगाल सरकार³ में यह निर्णय हुआ कि जब उच्च न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जो यह संकेत देती कि राज्य की सुरक्षा के विषय में राज्यपाल के पास कोई तथ्य उपस्थित थे तो सत्रिधान के अनुच्छेद 311 के उण्ड (2) के परन्तु (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रार्थी की वर्सास्तिगी का आदेश अवैध था।⁴

प्रशासनिक निर्णय यथोचित (reasonable) होना चाहिए। यथोचितता का प्रमाण (standard), यथोचितता के बार में न्यायालय की खुद की सम्मति की यथोचित क्या है में लगाकर इस इस मानदण्ड (निष्कर्ष) के बीच में रहना कि कोई भी न्यायोचित प्रशासनिक निकाय मामले में क्या निर्णय लेना। प्रदालत यह पता लगाएगी कि आया राम बनने से पहले की शर्तें वास्तविक बुनियाद पर टिकी हुई हैं या नहीं।⁵ किसी सरकारी कर्मचारी को हटाने से पहले सभी परिस्थितियों पर सचेष्ट विचार होना चाहिए। अन्यथा, लागू की गई राशि शास्ति कानूनन अवैध होगी।⁶

⁶[19 क-केन्द्रीय सरकार को या पब्लिक सेक्टर में किसी कम्पनी को या राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा सृजित स्वशासी निकाय को उधार दिये गये अधिकारियों के सम्बन्ध में उपबन्ध —

(1) जहाँ कि सरकारी कर्मचारी की सेवाये,—

[1] केन्द्रीय सरकार को

[11] कम्पनी अधिनियम, 1965 (1956 का अधिनियम 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत पब्लिक सेक्टर में किसी कम्पनी को, या

1 हैलिमबरी का “इंग्लैण्ड का कानून—चतुर्थ संस्करण जिल्द 1, पैरा 2।

2 1977 Lab IC 628 (पूर्ण पीठ)।

3 AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट—एम ए रशीद वि केरल राज्य।

4 1977 Lab IC (N O C) 75 (इलाहाबाद) भारतीय सच वि राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव।

5 अधिसूचना स F 3 (17) Appnts (A-III/67 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा जोड़ा गया।

[iii] राज्य या केन्द्रीय विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा सृजित सरकार के (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् उधारगृहीता प्राधिकारी कहा गया है) नियन्त्रण के अधीन किसी स्वशासित निकाय को उधार दी गई है, वहा उधारगृहीता प्राधिकारी को, उसे निलम्बित करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी की तथा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति होगी :

परन्तु "उधारगृहीता प्राधिकारी" उस प्राधिकारी को, जिसने उसकी सेवाएं उधार दी हैं (जिसे इस नियम में इससे पश्चात् "उधारदायी प्राधिकारी" कहा गया है), उसके (कर्मचारी के) निलम्बन या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के यथास्थिति आदेश दिये जाने की परिस्थितियों की तुरन्त सूचना देगा।

(2) सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए:—

[1] यदि उधारगृहीता प्राधिकारी का यह मत हो कि नियम 14 के खण्ड (1) से (iii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उधारदायी प्राधिकारी के परामर्श से, उस मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधारगृहीता प्राधिकारी तथा उधारदायी प्राधिकारी के मध्य मतभेद होने की दशा में, सरकारी कर्मचारी की सेवाएं वापस उधारदायी प्राधिकारी के अधीन कर दी जायेंगी।

[ii] यदि उधारगृहीता प्राधिकारी का यह मत हो कि नियम 14 के खण्ड (iv) से (vii) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उसकी सेवाएं पुनः उधारदायी प्राधिकारी के अधीन कर देगा तथा जाच की कार्यवाहिया भी भेज देगा और तब उधारदायी प्राधिकारी, यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी भी है, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे या यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है तो वह उस मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा जो ऐसे आदेश पारित करेगा जैसे वह आवश्यक समझे :

परन्तु अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे आदेश पारित करते समय नियम 16 के उप-नियम (10) तथा (11) के उपबन्धों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण:—अनुशासनिक प्राधिकारी उधारगृहीता प्राधिकारी द्वारा भेजे गये जाच अभिलेख पर इस खण्ड के अधीन या ऐसी और जाच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे आदेश दे सकेगा।]

टिप्पणी

नियम 19 (क) अधिसूचना स. एफ. 3 (17) नियुक्ति (ए-III)/67 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा जोड़ा गया है। यह नियम राजस्थान राज्य के उन कर्मचारियों के विषय में प्रावधान

करता है, जिनकी सेवाएँ केन्द्रीय सरकार का, या गावंजनिव क्षेत्र की किसी कम्पनी को या राज्य विधान मण्डल या केन्द्रीय विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा बनाई गई किसी स्वशासी निकाय (Autonomous body) को उधार दी गई हो। ऐसी दशा में उधार लेने वाले प्राधिकारी को, ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की शक्ति होगी। उधार लेने वाला प्राधिकारी, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग भी कर सकेगा, परन्तु इस शर्त के अधीन कि वह उधार देने वाले प्राधिकारी को, कर्मचारी को निलम्बित करने की या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिए जाने की यथास्थिति, परिस्थितियों से सुरन्त अवगत करावेगा।

अनुशासनिक कार्यवाहियों के नतीजों के आधार पर यदि उधार लेने वाला प्राधिकारी इस राय का हो कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध (नियम 14 के खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट) कोई छोटी शास्ति लागू की जाए, तो वह उधार देने वाले प्राधिकारी के परामर्श से, जैसा उचित समझे वैसे आदेश पारित कर सकेगा। यदि दोनों प्राधिकारियों के बीच मतभेद हो, तो राज्य कर्मचारी की सेवाएँ वापिस उसके मूल विभाग को लौटा दी जाएगी जहाँ से वह प्रनियुक्ति पर आया था। यदि उधार लेने वाले प्राधिकारी की राय हो कि ऐसे कर्मचारी पर (नियम 14 के खण्ड (iv) (v), (vi) और (vii) में निर्दिष्ट कोई कठोर शास्ति लागू की जाए, तो वह उस कर्मचारी की सेवाएँ वापिस उसके मूल विभाग को मुपुर्ण कर देगा और उससे सम्बन्धित जाच कार्यवाहियों का पूरा रेकॉर्ड उधार देने वाले प्राधिकारी के भेज देगा। ऐसी स्थिति में, उधार देने वाला प्राधिकारी, यदि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी है, तो जैसा वह उचित समझे वैसे आदेश पारित करेगा, और यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, मामला अनुशासनिक प्राधिकारी को यथोचित आदेश के लिए प्रेषित करेगा। कोई आदेश पारित करने से पहले, जब अनुशासनिक प्राधिकारी उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तदर्थ रूप में कोई कठोर शास्ति लागू करना चाहे, तो वह नियम 16 (10) के समस्त प्रावधानों का परिपालन करेगा और यदि किसी लघु (छोटी) शास्ति देना प्रस्तावित हो, तो नियम 16 (11) के प्रावधानों का अनुसरण करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा भेजे गए जाच प्रभिलेवो के आधार पर यथोचित आदेश पारित कर सकेगा। परन्तु यदि वह आवश्यक समझे, तो प्रागे जाच करने के लिए भी स्वतन्त्र है।

कठोर शास्ति या और लघु शास्ति लागू करने की कार्य प्रणालियों का विवेचन विस्तार से नियम 16 व 17 के अन्तर्गत ऊपर किया जा चुका है।

20 सरकार के अतिरिक्त, दूसरे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ सेवा तथा लिपिक वर्गीय सेवा के मामलों में पारित आदेश ¹[अपील प्राधिकारी] को समूचित किए जायेंगे तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अगले उच्च प्राधिकारी को समूचित किए जायेंगे।

टिप्पणी

नियम 20 में शब्द "अपील प्राधिकारी नीचे फुट नोट में दी गई दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 की विज्ञप्ति द्वारा जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी को और सरकार

1 [विज्ञप्ति सं F 3 (17) App'tts (A III) 67 दि 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा संशोधित तथा राजस्थान राज-पत्र दि 10 अक्टूबर, 1974 में प्रकाशित।]

को दोनों को दी जाएगी, सिवाय उन मामलों में जिनमें सरकार स्वयं ही अनुशासनिक प्राधिकारी हो, या जब कि संबंधित दोषी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य हो। चतुर्थ श्रेणी सेवा के मामले में, अनुशासनिक प्राधिकारी आदेश की सूचना अगले उच्च प्राधिकारी को देगा।

ऐसे आदेशों की सूचना उपर्युक्तानुसार नहीं भेजने से कार्यवाही दूषित नहीं होगी, क्योंकि यह नियम निदेशात्मक (Directory) है न कि आदेशात्मक (mandatory), और इसके कर्मचारी के किसी अधिकार का हनन नहीं होता। सरकार जब भी उचित समझे, तभी ऐसे आदेशों की नजरसानी (review) कर सकेगी।

भाग VI

अपील

21. सरकार द्वारा दिए गए आदेशों की अपील नहीं होगी:—इस भाग में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों से कोई शास्ति लगाने लाले सरकार द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

टिप्पणी

अनुशासनिक मामलों में जो भी आदेश राज्य सरकार किसी कर्मचारी के विरुद्ध नियम 14 में बताई गई कोई भी शास्ति लागू करने बाबत करे (चाहे शास्ति कठोर हो या लघु) और आदेश चाहे प्राथमिक हो या अपील के फैसले के रूप में, उसके विरुद्ध अपील दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है। नि सदेह, पीडित राज्य कर्मचारी, नियम 33 के अधीन सरकार को पुनर्विलोकन (नजरसानी) अर्थात् 'रिव्यू' के लिए प्रार्थना कर सकेगा। राज्य सरकार स्वेच्छा से भी किसी मामले में रेकार्ड पुनर्विलोकन के लिये मगवा सकती है। नियम 34 के अन्वयन राज्यपाल को भी ऐसे निर्णयों का पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। पुनर्विलोकन का अधिकार भी कानून की ही एक वृत्ति (creation of statute) है।¹ पीडित कर्मचारी भी राज्यपाल को पुनर्विलोकन (नजरसानी) के लिए प्रार्थना कर सकता है और उसमें विफल हो जाने की दशा में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकता है वगैरें कि उसके लिए कोई न्यायिक औचित्य हो। अनुच्छेद 226 के अधीन, उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार है कि वह इस बात की पृथक्ता (जाच) कर सके कि आया सरकार के निष्कर्ष की जिस पर शृङ्खला विवादग्रस्त आदेश आधारित है, किसी भी सबूत द्वारा कोई पुष्टि नहीं होती।² परन्तु ऐसी रिट याचिका में, उच्च न्यायालय सादय का पुनर्विलोकन किसी स्वतन्त्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नहीं कर सकता।³ सरकार द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा संचालित (विभागीय) जाच की अपील उच्च न्यायालय नहीं सुनेगा। यह न्यायालय अपील अदायत नहीं है परन्तु उसका सम्बन्ध यह तय करने के लिए है कि आया जाच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई और आया निर्धारित कार्य प्रणाली के अनुसार की गई और आया प्राकृतिक न्याय के नियमों का हनन नहीं हुआ है।³ नजरसानी (पुनर्विलोकन) के तरीके से विभागीय उपचार का उपभोग पहले

* 193 LAC 522।

1 AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 364 भारतीय सच वि एच सी गोयल।

2 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1723—आन्ध्र प्रदेश सरकार वि रामा राव।

3 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट 1723—आन्ध्र प्रदेश सरकार वि रामा राव।

ममाप्त हो जाना जरूरी है उसका बाद ही अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचना प्रस्तुत की जा सकती है अन्यथा वह चरन योग्य नहीं होगी।

पुनर्विलोकन की मयाद - पुनर्विलोकन का प्राथम्य-पत्र पेश करने दिए समय की अवधि संशोधन किए जाने के आदेश की तिथि से छ महीने की है।

22 निलवन के आदेशों के विरुद्ध अपील - कोई सरकारी कर्मचारी निलम्बन के आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसके ठीक अधीनस्थ वह प्राधिकारी हो जिसने आदेश दिया हो या जिसके द्वारा दिया गया समझा जाय।

टिप्पणियाँ

निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील निलम्बन का आदेश देने वाले अधिकारी से ठीक उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष की जा सकती है। अधीन प्राधिकारी को नियम 30 (1) के प्रावधानानुसार अपील पर उपयुक्त विचार करना चाहिए। अपील प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और तय करेगा कि आया -

(1) नियम 13 के प्रावधानों का परिपालन हुआ है और

(2) यह कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार निलम्बन का आदेश न्याय संगत है, और तत्पश्चात् वह या तो निलम्बन आदेश की पुष्टि करेगा या उसे रद्द कर देगा।

अपील पर विचार करना अब न्यायिक कर्तव्य है और इसमें अपील प्राधिकारी को अपना दिमाग सक्रियता और कर्तव्यनिष्ठा में लगाना चाहिए और उस पर फैसला करने से पहले, मामले के सभी पहलुओं पर अर्थात् उसके पक्ष तथा विपक्ष (pros and cons) पर विचार करना चाहिए।¹

23 शास्ति लगा देने के विरुद्ध अपील - पुलिस विभाग की अधीनस्थ सेवा, जिसमें आर ए सी सम्मिलित है, लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य उस पर नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जिसके ठीक अधीनस्थ शास्ति लगाने वाला प्राधिकारी हो जब तक कि सरकार किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कोई अन्य प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न करे

*परन्तु लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध आयुक्त विभागीय जाच द्वारा गवन की जाच के मामले के सम्बन्ध में, विभागाध्यक्ष के रूप में नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाय ता वह उस विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार को अपील कर सकेगा

परन्तु यह और है कि लिपिकवर्गीय सेवा या चतुर्थ श्रेणी सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध विशेषाधिकारी गवन जाच कार्य/महायक आयुक्त, विभागीय जाच द्वारा गवन की जाच के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष के रूप में, नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों

1 AIR 1975 गुजरात कोर्ट 2216-डिविजनल परसोनल ऑफिसर वि टि आर, चेलापा।

* अधिमूचना नं F 3 (3) नियुक्ति (A-II) 63 दिनांक 27-4-64 द्वारा जोड़ा गया और दिनांक 9-7-59 से प्रभावशील हुआ।

में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाय तो वह, आयुक्त, विभागीय जाच को अपील कर सकेगा।

(2) पुलिस विभाग, जिसमें आर ए सी सम्मिलित है, के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ सेवा का कोई सदस्य उस पर नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित को अपील कर सकेगा —

- (क) नियुक्ति प्राधिकारी को, उस आदेश के विरुद्ध जो उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो,
- (ख) सरकार को, नियुक्ति प्राधिकारी या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ न हो व जिसे नियमों के अधीन शास्तिया देने की शक्तिया सौंपी गई हो, द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध।

*परन्तु अधीनस्थ सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध गवन की जाच के मामला के सम्बन्ध में आयुक्त विभागीय जाच द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया जाए, तो वह उक्त विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार को अपील कर सकेगा।

*स्पष्टीकरण—जहां सरकार या विभागाध्यक्ष ने नियुक्ति की शक्तिया किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को सौंप दी हो तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, नियम 2 (क) (4) के नीचे शक्ति परन्तु के निबन्धना के अनुसार इस उपनियम के उपबन्धों के प्रयोजनाथ नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(3) राज्य सेवा का कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तिया में से कोई शास्ति लगाने का आदेश सरकार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध सरकार को अपील कर सकेगा।

परन्तु ¹ [राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा या] राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य जिसके विरुद्ध सेवा से पदच्युति करने या हटाने की शास्तियों के सिवाय नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का आदेश सरकार के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वह केवल ऐसी समिति को ही अपील कर सकेगा जिसमें ² [मुख्य न्यायाधीपति द्वारा नामजद राजस्थान उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का एक समिति होगी।]

*परन्तु यह और है कि राज्य सेवा का कोई सदस्य जिसके विरुद्ध आयुक्त विभागीय जाच द्वारा गवन के जाच के मामला में सौंपे गये प्राधिकारी के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने

अधिसूचना नं. F 3 (30) A-A-II/69 दिनांक 27-4-1970 द्वारा स्थानापन्न।

* अधिसूचना नं. F 3 (3) नियुक्ति (A-II)63 दिनांक 27-4-64 द्वारा स्थानापन्न।

1 [विनियम नं. G S R 27 एफ 3 (4) नियुक्ति (क-3) 72 दिनांक 24 सितम्बर 1963 द्वारा सम्बन्धित जो राजस्थान राज-पत्र दिनांक 17 अप्रैल 1975 में पृष्ठ नं. 30-31 पर प्रकाशित है।]

का आदेश दिया जाए तो वह उक्त विभाग से संबंधित प्रशासनिक विभाग से सरकार को अपील कर सकेगा।

²(4) उप-नियम [1] से [3] में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 18 के अधीन एक ही कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके ठीक अधीनस्थ उस कार्यवाही के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाला प्राधिकारी हो।

²(5) जहां इस नियम के अधीन की जाने वाली अपील सरकार की होती हो तो उस पर विनिश्चय, लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद, जहां वही ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:—इस नियम में अभिव्यक्ति 'सिविल सेवा का सदस्य' में वह व्यक्ति, जो उस सेवा का सदस्य नहीं रह गया हो, सम्मिलित है।

टिप्पणी

द्वितीय अपील निरस्त की गयी—जबकि सिविल कर्मचारियों पर अधिरोपित शास्तियों के सरकार के आदेशों के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियमों के अधीन नहीं है, (देखिये नियम 21) परन्तु अन्य मामलों में एवं अपील अनुसूचि है। पहले बठोर शास्तियों के मामले में पीड़ित राज्य कर्मचारियों को दो अपीलों का मौका उपलब्ध था, जिसमें अन्तिम अपील, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी। परन्तु अब नियम 23 का खण्ड (4) (जो दो अपीलों का प्रावधान करता था) जी एम आर 129 अधिसूचना सत्या F 3 (17) नियुक्ति (A-III)/67 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके कारण उप खण्डों का क्रमांक बढ़ा दिया गया है। नियम 23 में समय समय पर अनेक संशोधन हुए हैं जैसा कि फुटनोटों से विदित होगा।

विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में कौन-कौन से प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी वह निम्नांकित तालिकाओं से स्पष्ट होगा—

गहन के मामलों की जाच के अतिरिक्त अन्य मामलों में अपील प्राधिकारीगण

क्रमांक	सेवा की श्रेणी	शास्ति	शास्ति लागू करने वाला प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	नियम सत्या
1	2	3	4	5	6
1	चतुर्थ श्रेणी सेवाएं	नियम 14 में निर्दिष्ट सभी शास्तियां	अनुशासनिक प्राधिकारी	अगला उच्च प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष)	23 (1)
2	लिपिक वर्गीय सेवाएं	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6
3	अधीनस्थ सेवाएं जो पुलिस तथा आ ए. सी की नहीं हो	नियम 14 में निर्दिष्ट सभी शास्तिया	(क) नियुक्ति प्राधिकारी के नीचे का कोई अधिकारी (ख) नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी जो उसके अधीनस्थ न हो	नियुक्ति प्राधिकारी सरकार	23 (2) 23(2)(ख)
4	पुलिस विभाग की अधीनस्थ सेवाएं आर ए सी सहित	"	अनुशासनिक प्राधिकारी	अगला उच्च प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष)	23(1)
5	न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य राज्य सेवाएं	"	(क) सरकार (ख) सरकार के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी	कोई अपील नहीं, परन्तु नियम 33 तथा 34 के अधीन पुनर्विलोप सरकार	21 23 (3)
6	राजस्थान न्यायिक सेवाएं तथा उच्च-तर न्यायिक सेवाएं	"	(क) सरकार	कोई अपील नहीं, परन्तु नियम 33 तथा 34 के अधीन पुनर्विलोकन	21
	सिविल सेवा से हटाने या बर्खास्तगी के अन्य सभी शास्तिया	(ख) सरकार के अतिरिक्त कोई प्राधिकारी	मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत राजस्थान उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों में शक्ति संचित	23(3)	
7	नियम 18 के अधीन संयुक्त कार्यवाही	सभी शास्तिया	अनुशासनिक प्राधिकारी	अगला उच्च प्राधिकारी	23(4)

विधम 14 में निर्दिष्ट किसी भी शास्त्र के सम्बन्ध में गवर्न के मामलों में धर्मीय प्राधिकारीगण

क्रमांक	सेवा की श्रेणी	दण्ड देने वाला प्राधिकारी	धर्मीय प्राधिकारी	विधम
1.	धनुष श्रेणी सेवाएं	विभागाधीन गवर्न जांच या कार्यालयीय के रूप में महादक धर्मीय विभागीय जांच	धर्मीय विभागीय जांच	23(1)
2.	रिजिस्ट्रार धर्मीय सेवाएं	"	"	"
3.	धर्मीय सेवाएं	विभागाधीन के रूप में धर्मीय विभागीय जांच	विभाग में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग में सरकार	23(2)
4.	राज्य सेवाएं	"	"	23(3)

निर्दिष्ट सेवा का महत्व.—विधम 23 के नीचे दिए गए शब्दोंकरण के अनुसार, अभिव्यक्ति "निर्दिष्ट सेवा का महत्व" में यह ध्वनि भी सम्मिलित होगी जो अब उस सेवा का महत्व नहीं रहा है। यह निर्णय परिभाषा दण्डित प्राधिकारिता की गई है, ताकि जो महत्व सरकारी नौकरी में सम्मिलित कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो या अनिवार्यता से सेवा निवृत्त कर दिया गया हो, उस व्यक्ति के उस सेवा के विरुद्ध धर्मीय प्रत्युत्तर करने का अधिकार रहे।¹

विभागाधीन निवृत्ति प्राधिकारी होगा—अभिव्यक्ति "निवृत्ति प्राधिकारी" की परिभाषा विधम 2 (ए) में दी गई है जिसके नीचे एक परम्परा अभिगूचना न. F. 16 (2) निवृत्ति (A) 60 दण्ड 111 दिनांक 2-6-1960 द्वारा जोड़ा गया है जिसका प्रभाव यह है कि, जब सरकार ने या विभागाधीन ने अपनी शास्त्रियों किसी धर्मीय प्राधिकारी की प्रत्युत्तर (गुप्त) कर दी हो तो सम्बन्धित विभागाधीन विधम 23 (2) (ए) (ग) के प्रयोगकर्ता, यथा शास्त्रियों या प्रत्युत्तर के धर्मीय के विरुद्ध धर्मीय के प्रयोगकर्ता, "निवृत्ति प्राधिकारी" होगा।

नौकरी सेवा धर्मीय के वर्गों में—जब विधम 23 के धर्मीय कोई धर्मीय सरकार की प्रत्युत्तर की गई हो, तो सरकार उसका निर्णय नौकरी सेवा धर्मीय के वर्गों में देने के बाद करेगी यद्यपि कि ऐसा वर्गों में सेवा धर्मीय हो। इस प्रकार का वर्गों में सेवा उन मामलों में धर्मीय होता जबकि धर्मीय धर्मीयों राज्य धर्मीयों का महत्व हो और जब कि उसको निवृत्त करने का अधिकार किसी धर्मीय प्राधिकारी की प्रत्युत्तर दिया हुआ नहीं हो और जब कि प्रत्युत्तर शास्त्रियों, विधम 15 (2) के अनुसार "निवृत्ति" "और धर्मीय धर्मीयों के विरुद्ध कोई धर्मीय हो। धर्मीय जब धर्मीय धर्मीय धर्मीयों की गई हो, तो इस धर्मीयों का, इस धर्मीय देने के धर्मीय, और सेवा धर्मीय के वर्गों में देने की प्रत्युत्तर की है।

1. A.R. 1971 धर्मीय कोई 755-धर्मीय. धर्मीय वि. धर्मीय सरकार।

24 किसी अपीलनीय आदेश के मामलो में उक्त आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के अन्दर आदेश की एक प्रमाणित प्रति उस व्यक्ति को निःशुल्क देगा जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है।

टिप्पणी

आदेश की प्रमाणित प्रति मुफ्त देना.—इन नियमों के अधीन पारित किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति (Certified copy) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित दोषी कर्मचारी को मुफ्त दी जाएगी ताकि वह कथित आदेश के विरुद्ध सहज रूप में अपील पेश कर सके। यदि ऐसे आदेश की अपील नहीं हो सकती हो, उदाहरणार्थ, राज सरकार द्वारा पारित आदेश, तो जब तक कि सम्बन्धित दोषी कर्मचारी इसके लिए आग्रह नहीं करे तब तक उसे प्रमाणित प्रति देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तत्दीक्षुदा नकल बाजिव समय में देनी चाहिए, मसलन एक सप्ताह में। अपील पेश करने की मयाद, अपीलग्रस्त आदेश की प्रति अपीलकर्ता को प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की है।

25. अपील के लिए परिसीमा—इस भाग के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस दिन से तीन महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत नहीं कर दी जाए, जिस दिन अपीलकर्ता को उस आदेश की प्रति प्राप्त हुई हो जिसके विरुद्ध अपील करनी हो :

परन्तु अपील प्राधिकारी उपर्युक्त समय के समाप्त होने के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाए कि अपीलकर्ता के पास अपील को समय पर प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे।

टिप्पणी

अपील प्रस्तुत करने की मयाद.—नियम 25 प्रावधान करता है कि अपील करने की मयाद तीन महीने की है। यह अवधि उस तारीख से आरम्भ होगी मानी जाएगी जिस दिन अपीलकर्ता को उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त हो जिसके विरुद्ध उसे अपील पेश करनी है। विभागीय जाच में जिस प्राधिकारी ने दोषी कर्मचारी से सम्बन्धित आदेश पारित किया, उस प्राधिकारी से दोषी कर्मचारी उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है।

अपील पेश करने में विलम्ब, हो जाने की दशा में, यदि अधिकारी को तमल्ली हो जाए कि निर्धारित अवधि के भीतर अपील पेश नहीं कर सकने के पर्याप्त कारण हैं, तो वह कथित मयाद के बाद भी अपील सुनने के लिए ग्रहण कर सकेगा। फिर भी, दोषी कर्मचारी को सावधानी रख कर मयाद के भीतर अपील पेश कर देनी चाहिए और विलम्ब से पेश करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए अन्यथा, उक्त मयाद समाप्त होने की तिथि से लगाकर, अपील प्रस्तुत करने की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए विलम्ब का कारण स्पष्ट करना होगा। परन्तु, यदि यह पाया जावे कि उक्त पहले के समय में अपीलकर्ता लापरवाह और अकर्मण्य (निष्प्रय) रहा अथवा उसमें सद्भावना का अभाव (lacking in bonafides) था, तो अपील प्राधिकारी उसके पक्ष में अपने स्वविवेक का प्रयोग करने से इन्कार कर सकेगा।¹

1. AIR 1961 इनाहावाद 379—भगवत स्वरूप वि. रामगोपाल, AIR 1960 मुम्बई कोर्ट 260—सीताराम रामचरण वि. एम. एन. नागरसिंह।

अर्थात् वर्खास्तगी के विरुद्ध दोजानी वाद के लिए मयाद — अर्थात् वर्खास्तगी के विरुद्ध दोजानी दावा, या तो अधिधोपपणा वा वाद (declaratory suit) या वक़ाय़ा बेनन दिए जाने की प्रार्थना के साथ किया जाने वाला दवा प्रस्तुत करने की मयाद भारतीय मयाद अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 113 के अधीन, वर्खास्तगी की तारीख से तीन वर्ष की है।

अपील पुनर्विलोकन के उपचार का उपयोग खतम कर लेने के बाद ही, पीडित राज्य कर्मचारी सविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है, यदि उस ऐसी सलाह दी गई हो, और इस प्रयोजन के लिए कोई समय की मयाद निर्धारित नहीं है। फिर भी ऐसी रिट याचिका का अधिकार अजिन होने के बाद, जहाँ तक जल्दी संभव हो, वहाँ तक शीघ्र, रिट याचिका पेश कर देनी चाहिए।¹ परन्तु इसमें बिलम्ब करना घातक नहीं है। एक मामले में जब कि बिलम्ब डेढ़ वर्ष का था, फिर भी उसको नज़र अन्दाज़ (ignore) किया गया अर्थात् उपेक्षित किया गया।²

26. अपील का रूप तथा अन्तर्वस्तु—(1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथक् रूप से तथा अपने स्वयं के नाम से अपील करेगा।

(1) अपील उस प्राधिकारी को, जिसको अपील होनी हो, सम्बोधित होगी। उसमें समस्त सारवान विवरण तथा तर्क जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता हो अन्तर्विष्ट होंगे, उसमें कोई अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं होगा और वह स्वयं में पूर्ण होगी।

टिप्पणी

नियम 26 का आशय यह है कि यद्यपि विभागीय जाच धारा 18 के अन्तर्गत सयुक्त रूप से ही क्यों न की गई हो, फिर भी प्रत्येक दोषी कर्मचारी को अपने अपने नाम से अलग अलग अपील की दरखास्तें पेश करनी चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि सयुक्त जाच में भी, प्रत्येक कर्मचारी ने दुराचरण में बितना व क्या भाग लिया इसका खयाल रखते हुए प्रत्येक पर भिन्न भिन्न शास्तियाँ अधिरोपित की जा सकती हैं और उनमें से एक या अधिक को दोषयुक्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी की प्रतिरक्षा की रूप रेखा अलग अलग हो सकती है। अपील अपीलकर्ता कर्मचारी के छुद के नाम से होनी चाहिये, न कि उसके सहायक अधिकारी या वकील के माध्यम से। अपील नियम 23 द्वारा निर्धारित अपील प्राधिकारी को सम्बोधित की जानी चाहिये परन्तु उसे उचित माध्यम (Through proper Channel) के माध्यम प्रेषित करनी चाहिये।

अपील की दरखास्त अपने आप में पूर्ण (self Contained) होनी चाहिए, अर्थात् एक एक दोषारोपण, या चार्ज या आरोप पर वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और उस पर सम्बन्धित साक्ष्य, मौखिक तथा दस्तावेजी साहाय्य सहित, का तर्क पूर्ण विवेचन करे। वह अपनी लिखित कहस उन्हीं के आधार पर अपील में पेश करे। इस प्रकार से अपील की दस्तावेज़ अपने आप में पूर्ण होनी चाहिये। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, वह यह कि अपील की भाषा किसी भी व्यक्ति के प्रति अनादरपूर्ण या अभद्र अर्थात् अनुचित नहीं होनी चाहिये यद्यपि अपीलकर्ता, जाच से सम्बन्धित

1 AIR 1958 पंजाब 16—गुरेन्द्र नाथ वि चीफ कन्ज़रवेटर वन विभाग, AIR 1955 पंजाब 106 महेन्द्र सिंह वि पटियाला सरकार।

2 AIR 1958 जम्मू तथा काश्मीर 11—पंडित गोपीनाथ वि जम्मू और काश्मीर सरकार।

किमी भी व्यक्ति के दारे में प्रतिकूल तथ्य निर्भयता से रख सकेगा। इस प्रकार, किसी गवाह के अत्यन्त भापी होने या अविवशनीय होने के तथ्यों का उल्लेख किया जा सकेगा परन्तु उसकी भाषा उचित होगी, असोभनीय नहीं होगी। दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ अपील के माध्यम सलग्न की जा सकती हैं, परन्तु अपील प्राधिकारी ऐसे तथ्यों और दस्तावेजों का विचार के बिना अस्वीकार कर सकेगा, जब कि उनको, इस अन्तर्या में, विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई तर्क पूर्ण, तसल्लीबख्त कारण नहीं बनाया गया हो।

नियम 30 में किये गये एक इनाम ही के मशोधन¹ के अनुसार, अपीलकर्ता को अब यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह चाहे, तो अपना पक्ष निवेदन व्यक्तिगत सुनवाई के रूप में प्रस्तुत कर सकेगा। अपीलकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह यह अवसर नहीं छोके। व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ प्रत्येक उठावे और तर्कोंपूर्ण दलीलों के साथ निर्भयता से बहस करके और अपने हित के दस्तावेजों के तथा गवाहों के बयानों के सुमगन अंग पढ़कर सुनावें, जिसमें विजय थी मिल सके।

अपील करने वाले कर्मचारियों के लिये यह भी हितकर होगा कि वह अपनी अपील का मसौदा किसी वकील की सहायता से या कम से कम किसी अन्य अधिक विद्वान राज्य कर्मचारी की सहायता से तैयार करे, जिसके लिये सभ्यता: वह व्यक्ति अधिक लाभदायक सिद्ध होगा जो विभागीय जाच के दौरान उसका सहायक अधिकारी रहा था।

अपील दण्ड देने वाले अधिकारी के प्रति अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करना चाहिये, विशेषतः इस कारण से कि कर्मचारी को अपील उसी के माध्यम से और उसकी टिप्पणी के साथ आगे अपीलकर्ता तक पहुँचाई जायेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार या उसके मनियों की प्रतिष्ठा गिराने का प्रयास नहीं करना चाहिये, क्योंकि वे उसके मालिक (नियोजक) हैं, जो उसे इसी आधार पर सेवा से बर्खास्त कर सकते हैं।²

27. अपील प्रस्तुत करना—प्रत्येक अपील समुचित माध्यम से उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो।

परन्तु यदि ऐसा प्राधिकारी उस कार्यालय का अध्यक्ष नहीं है जिसमें अपीलकर्ता सेवा कर रहा हो, या यदि वह सेवा में न हो तो उस कार्यालय का, जिसमें वह अन्तिम बार सेवा कर रहा था, कार्यालयाध्यक्ष नहीं है या वह ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष का अधीनस्थ न हो, तो अपील, ऐसे कार्यालय के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे तुरत उक्त प्राधिकारी का अप्रोपित करेगा।

परन्तु यह और है कि अपील की प्रति अपील प्राधिकारी को सीधी प्रस्तुत की जा सकेगी।

टिप्पणी

अपीलों का प्रस्तुतिकरण—नियम 27 प्रावधान करता है कि इन नियमों के अधीन प्रत्येक

1. देखिए अधिसूचना स. F. 3 (7) (कामिक)/AA III/78 G.S.R. 168 दिनांक 27 जनवरी, 1979, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दिनांक 8 फरवरी, 1979 में पृष्ठ 445 पर हुआ।
2. AIR 1962 गुजरात 197—जगमोहनदास जगजीवनदास मोदी वि. गुजरात सरकार AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट 72

अपील उचित माध्यम से (Through proper Channel) पेश करनी चाहिये, यद्यपि अपील की एक प्रति सीधी अपील अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिये अपीलकर्ता स्वतन्त्र है। यह तो पीडित राज्य कर्मचारी के स्वयं के हित में है कि एक प्रति सीधी अपील प्राधिकारी को पेश कर दे, ताकि यदि मध्यस्थ अधिकारीगण अनुचित विलम्ब करें, तो अपील प्राधिकारी उनको शीघ्रता करने के लिए निर्देशन दे सके अथवा वह उचित माध्यम से अपील की दरखस्त प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना, अपील पर कार्यवाही आरम्भ कर दे। इसके अतिरिक्त यदि अपील, नियम 28 के अन्तर्गत अनुचित आधार पर रोकती जावे तो अपील प्राधिकारी रैकड मगवा सके और उस पर उचित कार्यवाही, जो वह उचित समझे कर सके।

अपीलकर्ता को चाहिये कि वह अपनी अपील अपील प्राधिकारी को सम्बोधित करे मगर उसे अपने मामले निश्चित उच्च अधिकारी को समर्पित करे जो उसे उस अधिकारी को अग्रसर करेगा जिसने अपील किया जाने वाला आदेश पारित किया था यदि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं था।

नियम 27 के नीचे दिया गया परन्तुक्त कहता है कि यदि शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी उस कार्यालय का कार्यालयाध्यक्ष नहीं है जिसमें कि दोषी अपीलकर्ता काम करता है या वह पिछली द्वार काम करता था, या वह उक्त कार्यालयाध्यक्ष का अधीनस्थ न हो, तो अपील की दस्तावेज ऐसे कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी, जो उस तुरन्त सजा देने वाले अनुशासनिक प्राधिकारी को भेज देगा। अतः यदि अधीनस्थ आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया था, जिसकी अपील जिलाधीश को होती है, तो दोषी-अपीलकर्ता अपील की दस्तावेज तहसीलदार को समर्पित करेगा जो उसे सम्बन्धित रैकड और अपनी टिप्पणी सहित जिलाधीश को अर्पित करेगा। यदि दोषी कर्मचारी का स्थानान्तर किसी अन्य तहसील में हो गया हो तो ऐसा अन्य तहसीलदार अपील को जिलाधीश के पास भेजेगा। जो दोषी अब सरकारी सेवा में ही नहीं रहा है वह अपनी अपील, उस कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को पेश करेगा जिसमें वह अन्तिम बार नौकरी करता था।

28 अपीलो की रोक रखना—(1) वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है अपील को रोक रख सकेगा यदि—

- [1] वह अपील ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध हो जिसकी कोई अपील न होती हो, या
- [2] उसमें नियम 26 के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन न किया गया हो, या
- [3] वह नियम 25 में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तुत न की गयी हो तथा विलम्ब का कोई कारण भी नहीं बताया गया हो, या
- [4] वह किसी पूर्व विनिश्चित अपील की पुनरावृत्ति हो और कोई नये तथ्य या परिस्थितियां नहीं बताई गयी हो -

परन्तु कोई अपील जो केवल इस आधार पर रोक ली गयी हो, कि उसमें नियम 26 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया हो तो वह अपीलकर्ता को लौटा दी जाएगी और यदि उसके लौटाये जाने के एक मास के अन्दर उपर्युक्त उपबन्धों का अनुपालन करने के बाद, वह पुनः प्रस्तुत की जाये तो रोक नहीं जाएगी।

(2) जहाँ कोई अपील रोकी जाए तो अपीलकर्ता को उस तथ्य तथा उसके कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा।

(3) किसी प्राधिकारी द्वारा पिछली तिमाही में रोकी गयी अपीलों की सूची, उनके रोकने के कारणों सहित, उस प्राधिकारी द्वारा, अपील प्राधिकारी को प्रत्येक तिमाही के प्रारम्भ में प्रस्तुत की जाएगी।

टिप्पणी

नियम 28—अपील अग्रप्रेषित करने के बजाय रोक लेना—वृत्ति कि नियम 27 के अधीन, अपील प्राधिकारी को सम्बोधित प्रत्येक अपील उचित माध्यम द्वारा (Through proper Channel) प्रेषित करने पर ध्यान देना है, इसलिए वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे अपील प्राधिकारी को भेजी जाती है। नियम 28 में कतिपय ऐसी परस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी अपील आगे नहीं भेजकर अपने पास ही रोक सकता है। प्रथम तो यह कि, यदि विलम्बपूर्ण आदेश की अपील नियमानुसार हो ही नहीं सकती हो, तो उसे आगे नहीं भेजा जाएगा ताकि अपील प्राधिकारी का मूल्यवान समय फालतू नष्ट न हो। उदाहरणतः यदि वह द्वितीय अपील हो या सरकार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गई हो, जो नहीं की जा सकती। अतः ऐसी अपीलों को आगे भेजना निरर्थक होगा जब तक कि वे नजरसानी (रिप्यू) के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई हों।

दूसरा यह कि अपील नियम 26 द्वारा प्रावधानित रूप में होगी चाहिये अर्थात् यदि अपील पीठित अपीलकर्ता के नाम से न हो, या अपील प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को सम्बोधित हो, या अपमानपूर्ण, अश्लेष या अनुचित भाषा में लिखी हुई हो, तो अनुशासनिक, प्राधिकारी उसे रोक सकेगा। परन्तु यदि उसे रोक रखने का एक मात्र यही कारण हो तो वह अपीलकर्ता को दुस्तगी (संशोधन) के लिए लौटा दी जाएगी। यदि लौटाए जाने की तिथि से एक महीने के भीतर अपीलकर्ता, नियम 26 का परिपालन करके, पुनः अपील प्रस्तुत करे तो उसे नहीं रोका जायेगा, जैसा कि उपर्युक्त नियम के खण्ड (1) के परन्तुक में प्रावधान है।

अपील रोक रखने का तीसरा कारण उसका मयाद बाहर होना है, जो नियम 25 के अनुसार विलम्बपूर्ण आदेश (जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है) की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की है। परन्तु यदि अपीलकर्ता न विलम्ब से अपील पेश करने के कारण का उल्लेख किया, हाँ तो वह नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि नियम 25 के परन्तुक के अनुसार यह निर्णय करने का अधिकार अपील प्राधिकारी को है न कि अनुशासनिक प्राधिकारी को, कि आया अपील मयाद के भीतर पेश नहीं करने का पर्याप्त कारण है।

अन्त में यह कि, यदि उक्त अपील पहले से निर्णीत अपील की पुनरावृत्ति हो और उसमें कोई नए तथ्य या परिस्थितियाँ नहीं बताई गई हों, तो शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी उसे रोक सकेगा।

नियम 27 का खण्ड (2) प्रावधान करता है कि यदि कोई अपील रोकी जाएगी तो उसकी सूचना अपीलकर्ता को, रोक रखने के कारणों सहित, अवश्य दी जाएगी।

न्यायिकता और पक्षपात हीनता की दृष्टि से, जब तक कि अपील रोक रखने के प्रबल कारण न हों तब तक वह नहीं रोकी जानी चाहिए, अन्यथा ऐसा करना शास्ति प्राधिकारी का पक्षपातपूर्ण भुभाव प्रदर्शित करेगा और इससे कर्मचारी को उच्च न्यायालय के सम्मुख रिट याचिका प्रस्तुत

करन का आधार मिल जाएगा। अपील करना एक कानूनी उपचार है, इसलिए सभ्य प्राधिकारी का उसे सुनने के लिए ग्रहण करना चाहिए।¹

29 अपीलो का परिपण—(1) वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है किसी वक्ते जा सकने वाले विलम्ब के बिना प्रत्येक अपील को जो नियम 28 के अधीन नहीं रोकी गयी हो उस पर अपनी टिप्पणी और संबंधित अभिलेखों के साथ अपील प्राधिकारी को पारेषित करेगा।

(2) वह प्राधिकारी जिसको अपील होती हो, नियम 28 के अधीन रोकी गई अपील को अपने पास पारेषित करने का निर्देश दे सकेगा और तदुपरान्त ऐसी अपील संबंधित अभिलेखों और अपील रोकने वाले प्राधिकारी की टिप्पणी के साथ उस प्राधिकारी को पारेषित कर दी जाएगी।

टिप्पणी

नियम 29—अपीलें आगे भेजना—नियम 29, अपीलें अपील प्राधिकारी को पहुंचान का प्रावधान करता है। जब कोई अपील नियम 28 के अन्तर्गत रोकी नहीं गई हो, तो उसे भारत अभिलेखों के साथ दण्ड देने वाला प्राधिकारी अपनी टिप्पणी सहित अपील प्राधिकारी को यथा संभव अविनाश भेजगा। नियम 29 के खण्ड (2) अपील प्राधिकारी को भी अधिकार प्रदत्त करता है कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश देकर रोकी गई अपील भगवा सके। इस प्रकार से मांगी जाने पर ऐसी अपील अपील रोक रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सारभूत अभिलेखों और उसकी स्वयं की टिप्पणी सहित अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी अर्थात् फिर रोकी नहीं जा सकेगी। यह प्रावधान अनुशासनिक (सजा देने वाले) प्राधिकारियों पर नियन्त्रण का कार्य करता है ताकि वे सरकारी कर्मचारियों की अपीलें पक्षपाती रख रखने के कारण रोक नहीं सकें। ऐसे भेजने वाले अधिकारी को अपनी टिप्पणी ईमानदारी से तथा न्यायिकता से अंकित करनी चाहिए और ऐसा टिप्पण नहीं करना चाहिए जो अपील प्राधिकारी के दिमग को प्रभावित कर।²

30, अपीलो पर विचार—(1) किसी निलवन आदेश के विरुद्ध की गयी किसी अपील के मामले में, अपील प्राधिकारी, विचार करेगा कि क्या नियम 13 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये तथा उस मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निलवन का आदेश न्याय संगत है या नहीं और तदनुसार आदेश को पुष्ट, या रद्द करेगा।

(2) नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने के आदेश के विरुद्ध की गई किसी अपील के मामले में, अपील प्राधिकारी निम्नांकित तथ्यों पर विचार करेगा कि—

- (क) क्या इन नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है और यदि नहीं, तो क्या ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप सन्निधान के बिन्ही उपबन्धों का अतिक्रमण हुआ है या न्याय नहीं हो पाया है,
- (ख) क्या वे तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था सिद्ध किये जा चके हैं,

1 1971 (2) SLR 695—सधोवहन गिरधारीलाल पटेल वि गुजरात सरकार।

2 1973 (2) SLR 430 (राजस्थान) भारतीय सघ वि बी एस मिश्रा।

- (ग) क्या मिट्ट तथ्यों के आधार पर कोई आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य है, और
- (घ) क्या लगाई गई शास्ति अत्यधिक है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है, ¹[और सरकारी कर्मचारी को, यदि वह ऐसा चाहे, अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्] और आयोग से परामर्श करने के बाद, यदि उस मामले में ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, तो—

- (i) उस शास्ति को अपास्त करने, कम करने, पुष्ट करने या बढ़ाने, या
- (ii) मामले को शास्ति लगाने वाले प्राधिकारी के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे निदेश के साथ जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, विप्रेषित करने का, आदेश देगा ।

परन्तु:—(i) अपील प्राधिकारी ऐसी कोई वर्धित शास्ति नहीं लगावेगा जिसको उस मामले में लगाने के लिए वह स्वयं या वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है, सक्षम न हो,

(ii) वर्धित शास्ति लगाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता को ऐसा कोई अभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया जाए,

(iii) यदि ऐसी वर्धित शास्ति, जिसके लगाने का अपील प्राधिकारी प्रस्ताव करे, नियम 14 के खण्ड [4] से [7] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई एक हो और मामले में नियम 16 के अधीन कोई जाच न की गई हो तो अपील प्राधिकारी नियम 18 *के उपबन्धों के अध्याधीन स्वयं ऐसी जाच करेगा या ऐसी जाच करने के निदेश देगा और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करने के बाद और अपीलकर्ता को ऐसा कोई अभ्यावेदन करने का जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, एक अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह उपयुक्त समझे ।

राजस्थान सरकार का निर्णय

इस विभाग की इसी सख्या के परिपत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 1962 पर, जिसमें मृत राज्य कर्मचारी के पीछे उसके वैध प्रतिनिधियों का अपील चालू रखने का अधिकार निर्धारित किया गया था जांच की गई है । इस परीक्षण के फलस्वरूप यह निष्पत्ति ली गयी है कि राजस्थान

1 अधिसूचना स F 3 (7) कामिक/A A-III/78 GSR 168 दिनांक 27 जनवरी, 1979 द्वारा जाड़ा गया और राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) I दिनांक 8-2-79 में पृष्ठ 445 पर प्रकाशित ।

* यहाँ नियम 16 होना चाहिए था ।

नियुक्ति (A III) विभाग की अधिसूचना स F 3 (5) नियुक्ति (A)/62 दिनांक 18-4-1963 द्वारा जोड़ा गया ।

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील (नियमों के अन्तर्गत, अपीलों के मामले में समाप्त करने या प्रतिस्थापन के हक का प्रश्न नहीं उठता और अपील प्राधिकारी को, राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भी, इन नियमों में निर्दिष्ट तरीके से, ऐसे मृत राज्य कर्मचारी के उत्तराधिकारियों या वंश प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाए बिना, अपील का निपटारा करना है।

अतः उपर्युक्त विभागीय परिपत्र को निरस्त करते हुए, यह तय किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में अपील प्राधिकारियों को अन्वेषण है कि वे राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भी, और उसके उत्तराधिकारियों या वंश प्रतिनिधियों के नाम रिकार्ड पर नहीं होने के बावजूद, परन्तु उक्त उत्तराधिकारियों/वंश प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाए बिना, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 30 में बताए गए तरीके से अपील का निपटारा करें। स्पष्ट है कि वस्तुस्थिति की प्रकृति से ही, मामलों को वापिस भेजने (रिमांड करने) या शास्ति बढाने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी।

टिप्पणी

नियम 30—अपीलो पर विचार—यह एक महत्वपूर्ण नियम है। इसका प्रथम लण्ड निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में है। निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारी से अगले उच्च अधिकारी को होगी, अर्थात् उस प्राधिकारी के पास जिसका निलम्बन की आज्ञा जारी करने वाला प्राधिकारी निवृत्ततम अधीनस्थ है, (देखिए नियम 22)।

किसी राज्य कर्मचारी को नियम 13 के प्रावधानों के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियों में निलम्बन में रखा जा सकता है,—

- (क) जब कि उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने का इरादा हो या ऐसी कार्यवाही चल रही हो, या
- (ख) जब किसी फौजदारी अपराध के सम्बन्ध में किसी मामले की तफ्तीश (अन्वेषण) या फौजदारी मुकद्दमा उसके विरुद्ध चल रहा हो।

निलम्बन का आदेश या तो नियुक्ति प्राधिकारी जारी कर सकता है, या इसका कोई अधीनस्थ अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए शक्ति प्रदान की हो। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना स एफ 3 (9) नियुक्ति (ए) 62 दिनांक 11 सितम्बर, 1962 के अधीन उन सभी अधिकारियों को, जो नियम 14 में निर्दिष्ट कोई छोटी शास्ति किसी कर्मचारी पर लागू करने के लिए सक्षम है उनको उक्त राज्य कर्मचारी को निलम्बन करने की शक्ति भी प्रदान की है। परन्तु यदि निलम्बन का आदेश जारी करने वाला अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे में स्तर का है, तो वह तुरन्त अपनी रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को देगा, जिसमें सम्बन्धित सिविल कर्मचारी को निलम्बित करने की परिस्थितियां दर्शाएंगी।

अतः अपील प्राधिकारी, जिसको किसी निलम्बन आदेश के विरुद्ध अपील पेश की गई हो, यह सुनिश्चित करेगा, आया ऐसा आदेश जारी करने वाला अपीतकर्ता को निलम्बित करने की क्षमता रखता था और यह भी कि आया मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसी कार्यवाही करना उचित था।

जब कोई निलम्बन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या अपील प्राधिकारी द्वारा खारिज कर

दिया जावे, तो ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी के लिए यह जरूरी है कि वह यह भी उल्लेख करे कि निलम्बन की अवधि किस रूप में व्यवहार्य होगी।

जब कि निम्बन के बाद केवा में पुनः स्थापन (re-instatement) किया जावे, तो राजस्थान केवा नियमों का नियम 54, नियुक्ति प्राधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह निलम्बन की अवधि के सम्बन्ध में वेतन, भत्ते आदि के विषय में उचित आदेश पारित करे।¹ यही सम्पत्ति राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने चन्दनमल जैन वि कलेक्टर, टोंक² में प्रकट की है। ट्रिब्यूनल का न्यून है कि आदेश यह नहीं बताता कि आया निलम्बन की अवधि नौकरी पर कार्यरत रहने के रूप में मानी जावे या नहीं। जब कि कलेक्टर ने एकाउन्टेंट जनरल (महालेखाकार) को सूचित कर दिया था कि यह अवधि ड्यूटी पर रहने के रूप में शुमार की जावे, परन्तु बाद में दिए गए आदेश में कलेक्टर ने, कर्मचारीयो को अपना पक्ष प्रनिवेदन करने का अवसर दिये बिना, यह तय किया कि यह अवधि ड्यूटी के रूप में शुमार नहीं की जा सकती। अतः, ट्रिब्यूनल ने कलेक्टर के इस आदेश को दूषित घोषित किया।

शास्ति के आदेशों के विरुद्ध अपीलों,—किसी भी शास्ति के आदेश के विरुद्ध, जो चाहे कठोर शास्ति लागू करने का हो या सघु शास्ति वा, अपील प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करना होगा कि आया अनुशासनिक प्राधिकारी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया या नहीं और यदि नहीं नहीं किया था, तो क्या उससे सविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन हुआ या न्याय का हनन हुआ। एक पुलिस कमचारी के विरुद्ध किये गये विभागीय मुकद्दमे में यह पाया गया कि जाच अधिकारी स्वयं ने जाच की कार्यवाही में गवाही दी थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्राकृतिक न्याय के नियमों की पूर्णतः अवहेलना की गई और पुलिस अधीक्षक का मुकद्दमे की कार्यवाही में पीठाव्यस बने रहने से न्यायिकता व पक्षपातहीनता के सिद्धान्तों का गंभीर रूप में उल्लंघन हुआ। अन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।³

नारायण मिथ्या वि उड़ीसा सरकार⁴ में जाच अधिकारी ने दोषी कर्मचारी को तीन आरोपों में दो आरोपों में दोषमुक्त कर दिया, परन्तु शास्ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ने उसको उन दो आरोपों में भी दोषी पाया। दण्ड देने से पहले, दोषी कर्मचारी का उन आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपनाई गई प्रक्रिया में पक्षपातहीनता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है। उक्त परिस्थितियों में दण्ड का आदेश निरस्त किया गया।

अपील प्राधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा, कि आया जिन तथ्यों पर आदेश पारित किया गया वे साबित हुए हैं या नहीं। यदि विश्वसनीय स्रोत द्वारा आरोप सिद्ध नहीं हुए हो, तो कोई मामला नहीं बनेगा और कमचारी दोष-मुक्त किए जाने का पात्र होगा।

तीसरा बिन्दु जिसे तय करना अपील प्राधिकारी का कर्तव्य है, वह यह है कि आया अभिलेख पर स्थापित अर्थात् साबित किए गये तथ्यों पर पर अपीलग्रस्त आदेश पारित करने का पर्याप्त भौतिक था।

1. RLT 78 Part IV 29—मदनलाल क्ल्ला वि राजस्थान सरकार।

2. RLT 78 Part IV 131।

3. 1958 SCR 595 यू. पी. सरकार वि मोहम्मद तूह AIR 1958 मुम्बई कीट 86।

4. 1969 SLR 657।

अन्त में, अपील प्राधिकारी यह भी तय करेगा कि आया अधिरोपित शास्ति अत्यधिक है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है और यदि वह न्यायिक तथा तथा उचित समझे तो आदेश में संशोधन करेगा।

पहले अपीलकर्ता राज्य कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं था। परन्तु अब नियम 30 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी गई है —

“और सरकारी कर्मचारी को यदि वह ऐसा चाहे, अपने मामले को स्पष्ट करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्”

राज्य कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त प्रावधान एक वरदान स्वरूप है और जरूरतमन्द व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ प्रकलमन्दी से उठाना चाहिए। अपीलकर्ता को चाहिए कि वह अपील प्राधिकारी को लिखित में आवेदन कर कि उस, अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए, नियम 30 (2) (घ) (संशोधित रूप) के अधीन, व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। उक्त संशोधन के अभाव में भी आसाम उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानूनी अपीलों में सुनवाई का अवसर अपील करने वाले को दिया जाना चाहिए।¹

अपील पर विचार — अपील प्राधिकारी का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि उनको प्रस्तुत की गई अपीलों पर पूरा तथा न्यायिकता से विचार करे। बिना स्वयं कष्ट उठाए और अपना मुँह का विभाग लगा कर स्वतंत्र निर्णय लेने के बजाय, अनुशासनिक प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि कर देना अन्यायपूर्ण होगा। अपील का निर्णय ‘बोलता हुआ’ आदेश होना चाहिए। अन्य शब्दों में, लिए गए निष्कर्षों की पुष्टि में कारण उल्लिखित करने जरूरी है। प्रावृत्तिक न्याय का यह सिद्धान्त, अर्ध-न्यायिक कार्य-प्रणाली पर भी लागू होना है और उसका अनुसरण वास्तव में किया जाना चाहिए न कि केवल दिखावे के रूप में। यदि किसी आदेश में, निष्कर्षों के कारण या आधार व्यक्त नहीं किए जावे, तो वह आदेश ‘अवैध और प्रभावहीन होगा।’²

जब कोई अपील खारिज की जावे, तो अपील प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना फैसला ‘बोलते हुए आदेश’ के रूप में लिखे, अर्थात् उसमें निर्णयों के आधार या कारण बनाए जाव। पहले के फैसलों में जिनमें प्रतिकूल सम्मति दी गई थी, अब उलट दिए गए हैं। देखिये—देवी दीन वि डिवीजनल ओपरेटिंग सुपिन्टेन्डेंट, उत्तरी रेलवे।³

राजस्थान उच्च न्यायालय के गजराज सिंह वि. राजस्थान सरकार में एक भिन्न मत प्रकट किया है। इस मामले में अपीलकर्ता ने दलील पेश की कि नियम 30 के अधीन, राज्य सरकार

* अधिनूचना स F 3 (7) कामिक/A A III 78 GSR 168 दिनांक 27 जनवरी, 1979 द्वारा जोड़ा गया, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) (I) दिनांक 8 फरवरी, 1979 में पृष्ठ 445 पर प्रकाशित हुआ।

1 AIR 1963 आसाम 183 डी एम बर्मन वि आसाम सरकार, AIR 1968 आसाम 52 (खण्ड पीठ) जी सी गोस्वामी वि ए के राय।

2 1977 Lab IC (Noc) 20 (इलाहाबाद) जी एन धीवास्तव वि भारतीय सघ: AIR 1976 मुंबई कीट 1785

3 AIR 1968 इलाहाबाद 355 (खण्ड पीठ)।

द्वारा अपील में दिए गए निर्णय को निरस्त करना चाहिए नतीक नियम 30 के उपबन्धों का पालन नहीं किया गया, और दूसरे में इस कारण से कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है अर्थात् उसमें निर्णय की पुष्टि में कारण व्यक्त नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए तय किया कि, 'जब अपील प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी और जब अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत हो, तो अपील प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपील खारिज करते समय विस्तार से कारण अभिव्यक्त करे।' न्यायालय ने सन्तुष्टि अनुभव की कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में कोई कमजोरी नहीं थी और यह कि जाच के समय अभिलिखित साक्ष्य प्रकाश्य थी और प्राप्ति, यह भी नहीं कहा जा सकता कि नियम 30 के उपबन्धों का अनुसरण नहीं किया गया, या यह कि राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश 'बोलता हुआ आदेश' नहीं था।

इसके विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि अपील प्राधिकारी, मूल प्राधिकारी के फैसले को स्थिर रखने के कारण नहीं बतावे, तो अपील प्राधिकारी का आदेश खारिज करने योग्य होगा।¹ जब तक कि कोई आदेश 'बोलता हुआ' आदेश नहीं हो तब तक अनुशासनिक प्राधिकारी के मूल्यांकन को कोई फैसला समझ सकेगा और साथ ही अपील प्राधिकारी के मस्तिष्क का और उन प्राधारों को भी कैसे समझ पाएगा जिन पर अपील-प्रस्त आदेश आधारित है।²

किन्तु निदेशक, डाक सेवाएं वि. दयानन्द³ में निर्णय हुआ कि, यदि अपील प्राधिकारी कोई अपील खारिज करे तो उसे दण्ड देने वाले प्राधिकारी के आदेश से सहमत होने से अधिक कारण उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सजा देने वाले प्राधिकारी के आदेश में पहले से ही कारण मौजूद हैं। परन्तु यदि किसी नई सामग्री पर अपील में बल दिया गया हो, तो अपील प्राधिकारी को नई सामग्री के मूल्यांकन के विषय में कारण अभिव्यक्त करने चाहिए, यद्यपि अन्तिम निर्णय में वह सजा देने वाले प्राधिकारी के फैसले को स्थिर रखे।

अनुशासनिक प्राधिकारी की असमता — जबकि अनुशासनिक प्राधिकारी की कानूनी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार ही नहीं हो तो, उसके द्वारा पारित फास्टि का आदेश शून्य (अभावहीन) होगा और अपील प्राधिकारी अपनी पुष्टि द्वारा उसे वैध आदेश के रूप में नहीं बदल सकता।⁴

लोक सेवा आयोग से परामर्श — अपीलों का तसखिया करने से पहले, उन मामलों में जिनमें लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक हो, अपील प्राधिकारी को भी आयोग से परामर्श लेना

1 1977 WLN 245.

2 1968 SLR 812; आई-सुवामनियम वि. सेक्टर, 1971 (1) SLR 720-विजय सिंह यादव वि. हरियाणा सरकार।

3 AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 1297-गुजरान राज्य वि. पटेल राघव नाथ, 1973 SLJ 834-सी एल का वि. भारतीय सच।

4 1972 SLR 325 (दिल्ली) डाइरेक्टर, पोस्टल सर्विसेज वि. दयानन्द।

5. 1975 Lab IC-1221, AIR 1925 सुप्रीम कोर्ट 1755-भारतीय सच वि. श्री रत्न बिस्वाम, 1978 Lab IC 41 बनवत्ता (खण्ड पीठ) टी प्रार पाण्डे वि. चीफ कमिशनर ए एण्ड एन।

चाहिए। यह परामर्श जरूरी है जबकि अपील प्राधिकारी राज्य सरकार हो। किन्तु फंसला करते समय राज्य सरकार आयोग की सम्मति से सहमत हो या नहीं भी हो।

अपील प्राधिकारी का निर्णय—अपील प्राधिकारी निम्नाविक्तों में से कोई भी निर्णय दे सकता है—यदि वह सजा देने वाले प्राधिकारी की सम्मति से असहमत हो और इस मत का हो कि दोषी वमंचरी, उसके विरुद्ध लगाये गए किसी भी आरोप का, रेकॉर्ड के आधार पर, दोषी नहीं है, तो वह सजा का आदेश रद्द कर सकेगा। परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का विचार हो कि मामले की परिस्थितियों में, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लागू की गई शास्ति क्रूर है और यह कि उससे हल्की शास्ति न्याय की दृष्टि से उपयुक्त होगी, तो जैसी भी वह उचित समझे वंसी कम सकती की शास्ति लागू कर सकेगा। यदि अपील प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों से तथा उसके द्वारा अधिरोपित शास्ति से भी सहमत हो तो वह मूल आदेश की पुष्टि कर सकेगा।

शास्ति में वृद्धि करना—यदि अपील प्राधिकारी यह अनुभव करे कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति बहुत हल्की है जिससे न्यायिक प्रयोजन का समाधान नहीं होगा, तो वह नियम, 30(2) के नीचे दिए गए परन्तुक (i), (ii) और (iii) के प्रावधानों की पूर्ति करने के पश्चात्, शास्ति में वृद्धि कर सकेगा। इसमें ध्यान रखने योग्य प्रथम शर्त तो यह है कि अपील प्राधिकारी बढ़ाई गई ऐसी कोई शास्ति लागू नहीं कर सकता जो उस मामले में वह स्वयं या मूल आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी लागू करने के लिए सक्षम नहीं था। द्वितीय में शास्ति में वृद्धि करने का आदेश जारी करने से पहले, अपील प्राधिकारी अपील कर्ता को प्रस्तावित बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगा। ऐसा करना नितान्त आवश्यक है।¹ जिन गवाहान ने अनुशासनिक कार्यवाहियों में, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध गवाही दी है, उनसे जिरह करने (cross-examination) का एक बहुत मूल्यवान अधिकारी दोषी कर्मचारी में निहित है, और यदि यह प्रतीत हो कि जिस गवाह के साक्ष्य का आश्रय लिया है उसका बयान कर्मचारी की उपस्थिति में नहीं लिए जाने के कारण, या अनुशासनिक जाँच के समय उसको जिरह करने के लिए उपलब्ध नहीं करने के कारण, कर्मचारी इस अधिकार का प्रभावपूर्ण प्रयोग नहीं कर सका था, तो इसका एक निश्चित परिणाम यह होगा कि जाच प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाना नहीं मानी जाएगी।

• • • गौरी शंकर का कथित बयान जो प्रार्थी के पीठ पीछे (अनुपस्थिति में) अनिलिखित किया गया था उनका आश्रय लेकर कलेक्टर, भीतवाड़ा द्वारा अधिरोपित शास्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती थी। इस मामले में राजस्व मण्डल ने, एक ऐसे गवाह के बयान का आधार लेकर शास्ति में वृद्धि कर दी जो प्रार्थी के विरुद्ध की गई विभागीय जाच में न तो गवाह के रूप में बुलाया गया था और न प्रार्थी को उससे जिरह करने का मौका मिला। अतः अपील के दौरान, शास्ति बढ़ाने की कार्यवाही दूषित करार दी जाकर, खारिज की गई।²

शास्ति में बढ़ोतरी करने पर एक प्रतिबन्ध और लगा हुआ है। नियम 30 (2) के नीचे दिए गये परन्तुक (iii) के अनुसार, यदि अपील प्राधिकारी किसी छोटी शास्ति को नियम 14 के खण्ड (iv) से (vii) में उल्लेखित किसी बड़े शास्ति में परिवर्तित करना प्रस्तावित करे और यदि नियम 16 के प्रावधानानुसार पहले से ही कार्यवाही नहीं हुई हो, तो अपील प्राधिकारी स्वयं ऐसी जाच करेगा या

1 AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 375-मैमूर सरकार वि शिवबासप्पा।

2 1975 WLN 8 हयन लाल वि राजस्थान सरकार।

ऐसी जांच करने का निर्देशन देगा, और तब नियम 16 के अनुसार की गई कार्यवाही पर विचार करने के बाद और अपीलकर्ता को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन पेश करने तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् जैसा उचित समझे वैसे आदेश पारित करेगा ।

अपील के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु—राजस्थान सरकार के दि. 18 अप्रैल 1963 के निर्णयानुसार (जो ऊपर दिया जा चुका है), अपीलकर्ता राज्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बावजूद, और उसके उत्तराधिकारियों या वंश प्रतिनिधियों की रेकॉर्ड से अनुपस्थिति में और मामले में उनको पक्षकार बनाए बिना, अपील चालू रहेगी। परन्तु ऐसे मामले को वापिस रिमांड करने या शास्ति में वृद्धि करने का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

मामला रिमांड करना—अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे, तो मामले को शास्ति प्रदान करने वाले अधिकारी के पास वापिस उपयुक्त निर्देशनों के साथ भेज सकता है। यदि अपील प्राधिकारी अनुशासनिक कार्यवाही में कोई खामी पावे, तो वह जांच अधिकारी को मामला रिमांड करने, दिए गए निर्देशनों की पालना करके पुनः तय करने के लिए भेज सकेगा ।

31. अपील में दिए गए आदेशों का कार्यान्वयन—वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

टिप्पणियाँ

जब किसी जांच का निपटारा अन्तिम रूप से अपील प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया हो, तो मूल आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को त्रिप्राव्यन्त करेगा, अर्थात् आदेश की तामील करवाएगा, उसी प्रकार जैसे कि दिवानी दावे अपील की अदालत द्वारा पारित फैसले की इजराय के लिए वापिस इजलास अदालत को भेज दिए जाते हैं। परन्तु एक बार जबकि विभागीय जांच पूरी हो चुकी हो, तो जब तक कि सेवा नियमों में कोई विशेष प्रावधान न हो, तब तक उसी कर्मचारी के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों पर दूसरी विभागीय जांच नहीं की जा सकती ।*

भाग VII

पुनरीक्षण एवं पुनर्विनिर्देशन (Revision & Review)

32. वह प्राधिकारी, जिसके पास नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील होनी हो और यदि उसकी कोई अपील न की गई हो तो वह स्वेच्छा से या अन्यथा, अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही में मामले के अभिलेख मगवा सकेगा तथा उनका परीक्षण कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो और अन्वेषण करने के बाद, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का परीक्षण कर सकेगा तथा आयोग से परामर्श करने के बाद जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो—

(क) आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या अपास्त कर सकेगा,

(ख) कोई शास्ति लगा सकेगा या आदेश द्वारा लगाई गई शास्ति को अपास्त, कम, पुष्ट या वर्धित कर सकेगा ।

(ग) मामले को उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया हो, या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी आगे कार्यवाही या जाच करने का निर्देश देते हुए जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, विप्रेषित कर सकेगा, या,

(घ) ऐसा आदेश जो वह उपयुक्त समझे पारित कर सकेगा :

परन्तु—

[1] किसी शास्ति को लगाने या वर्धित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को अभ्यावेदन करने का जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया गया हो,

[2] यदि अपील प्राधिकारी किसी ऐसे मामले जिसमें नियम 16 के अधीन कोई जाच नहीं की गयी हो नियम 14 के खण्ड [4] से [7] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करे तो वह, नियम 19 के उपबन्धों के अध्वधीन ऐसी जाच करने का निर्देश देगा और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करके तथा सम्बन्धित व्यक्ति को कोई अभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे,

[3] इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही का आरम्भ, पुनरीक्षित किये जाने वाले आदेश के दिनांक से 6 महिनो के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी

पहले इस परिच्छेद का शीर्षक “पुनरीक्षण (रिवीजन)” था । उसके बाद अधिसूचना स F- 10 (9) नियुक्ति, A/59 भूप II दिनांक 31-1-61 द्वारा बदल कर ‘पुनर्विलोकन (रिव्यू)’ कर दिया गया, और अब अधिसूचना स F 3 (17) नियुक्ति (A-111)/67 दिनांक 9 अक्टूबर, 1974 द्वारा पुन संशोधन किया जाकर “पुनरीक्षण एव पुनर्विलोकन (रिवीजन एण्ड रिव्यू)” रखा गया है, जो सही है ।

अपील प्राधिकारी को अधिकार है कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संचालित किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही के अभिलेख (रेकार्ड) या तो स्वेच्छा से अथवा पीडित राज्य नमंचारी के आवेदन पर मगवा कर, उनका परीक्षण कर सके । अपील प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो उनमें आगे अन्वेषण कर सकेगा और उसके बाद, मामले में पहले पारित आदेश का पुनरीक्षण (रिवीजन) कर सकेगा । किसी आदेश को पुनरीक्षण करने अर्थात् बदलने से पहले, यदि नियमानुसार आवश्यक हो तो लोक सेवा आयोग से भी परामर्श लेगा । पुनरीक्षण करते हुए, उक्त प्राधिकारी वह सभी कार्यवाही कर सकेगा जो अपील प्राधिकारी नियम 30 के अन्तर्गत अपील में करने के लिए सज्ज था और यदि उक्त प्राधिकारी शास्ति बढ़ाने का प्रस्ताव करे तो वह उनी प्रकार के प्रतिबन्धों के अधीनस्थ रह्या, अर्थात् जब तक दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित बड़ाई गई शास्ति के विरुद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, तब तक शास्ति में वृद्धि नहीं की जा सकेगी । और यह भी कि, यदि लघु शास्ति को कठोर शास्ति में परिवर्तित करने का इरादा हो और मूल जाच, नियम 16 के अनुबन्धों के अनुसार संचालित नहीं हुई हो, तो वह तदनुसार जाच करने का निर्देशन देगा और तत्पश्चात् वही जाच की कार्यवाहियों पर विचार

वर्द्धने और दोषी कर्मचारी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, जैसा भी वह उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकेगा।

पुनरीक्षण के लिए मयाद:—पुनरीक्षण (रिवीजन) की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए मयाद (समयावधि), पुनरीक्षण किए जाने वाले आदेश की तारीख से छ' महीने की है। परन्तु उक्त छ' महीने की अवधि में कारण बताओ नोटिस देना आवश्यक नहीं है, जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने विजयसिंह वि. राजस्थान सरकार में निर्णय किया है।¹ इस मामले में उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने रेकर्ड मगवाकर, उनका परीक्षण करने के पश्चात् यह तय किया कि पुलिस अधीक्षक ने अपने आदेश दिनांक 10 जून, 1965 द्वारा जो शास्ति दोषी कर्मचारी पर अधिरोपित की वह उदार थी और मामला शास्ति में वृद्धि करने हेतु कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त था। छ' महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई थी जब कि दिनांक 11 अक्टूबर, 1965 को, उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध शास्ति बढ़ाने के लिए आगे कार्यवाही करने कि सिफारिश का पत्र महा-निरीक्षक आरक्षी को भेजा क्योंकि वह कार्यवाही खुद नहीं करके महा-निरीक्षक से करवाना चाहता था, अन्यथा दोषी कर्मचारी को नोटिस वह स्वयं ही जारी कर देता। अतः न्यायमूर्ति श्री सिंगल ने तय किया कि उप-महानिरीक्षक आरक्षी ने शास्ति में वृद्धि करने की कार्यवाही नियम 32 में निर्धारित 6 महीने की मयाद के भीतर आरम्भ कर दी थी जब कि उसने 11 अक्टूबर, 1965 को महा-निरीक्षक आरक्षी के नाम पत्र भेजा। चूँकि महा-निरीक्षक आरक्षी के साथ पत्र व्यवहार करने में कुछ समय नष्ट हुआ, इसलिए कारण बताओ नोटिस विलम्ब से दिनांक 10 अप्रैल, 1966 को जारी किया गया, क्योंकि महा-निरीक्षक आरक्षी का मत था कि उप-महानिरीक्षक स्वयं आवश्यक कार्यवाही कर सकता था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसमें व्यक्त किया कि "आया नियम 32 के उप-नियम (3) के अधीन शास्ति में वृद्धि करने की कार्यवाही के लिए, निर्धारित छ' महीने की अवधि में कोई कार्यवाही आरम्भ की गई थी या नहीं उसमें तय करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना वास्तव में निर्णयात्मक नहीं माना जा सकता, क्योंकि नोटिस तो केवल तभी दिया जाता जब कि पुनरीक्षण प्राधिकारी शास्ति 'लाभू करना' या "बढ़ाना चाहता हो और न कि जब वह नियम 32 में उल्लेखित कोई अन्य आदेश देना प्रस्तावित करे।" * * * * * जब उक्त प्राधिकारी रेकर्ड मगवाए और उसका परीक्षण करे और यह तय करे कि लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर या अन्यथा पहले के आदेश को सशोधित या निरस्त करने के लिए वह मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, तब से ही उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसे मामले में कार्यवाही आरम्भ की जाना क्यों नहीं सम्भवा जाये इसका कोई कारण नहीं है। इसलिए, नोटिस जारी करना (या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया जाना) ही यह निश्चित करने के लिए एक मात्र निर्णयात्मक परीक्षा नहीं है कि आया नियम 32 (उप-नियम 3) के अधीन कार्यवाही आरम्भ हो गई है।"

उक्त न्यायालय ने उसी न्यायालय के मोहनलाल वि. राजस्थान सरकार² के फैसले का आश्रय लिया जिसमें अदालत ने यह मत व्यक्त किया था कि कार्यवाही तब से आरम्भ की जानी सम्भवी जावे 'जब ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तलबी का आदेश जारी हो अथवा जब प्राधिकारी कार्यवाही करने का मानस बनावे।' रमन कुट्टी वि. केरल सरकार³ का भी आश्रय लिया गया जिसमें यह तय हुआ था कि

1 1973 WLN 285।

2 1963 RLW 209।

3 1973 (1) SLR 408।

ऐसे मामले में वास्तविक प्रश्न यह है कि आया दोपी कमचारी के विरुद्ध सम्बन्धित कार्यवाही करने का निणय लिया गया है।

एक बार जब कोई मामला गुण दोपो के आधार पर निर्णित हो चुका हो, तो उसका पुनर्विलोकन करके शास्ति बढ़ाने के लिए सरकार सक्षम नहीं है, क्योंकि काई नए तथ्य प्रकाशित नहीं हुए हैं।¹ जब पुनर्विलोकन की शक्ति प्रयाग में काई जा चुकी हो और समाप्त हो गई हो, तो बारम्बार पुनर्विलोकन करके इस शक्ति का फिर से प्रयोग नहीं किया जा सकता।²

33 राज्य सेवाओं के सदस्यों के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक मामले में आदेशों का पुनर्विलोकन —सरकार स्वेच्छा से या अन्यथा, उस मामले के अभिलेखों को मगवा सकेगी जिसमें कि राज्य सेवाओं के किसी सदस्य पर नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने वाला आदेश दिया गया हो, ऐसे किसी मामले में पारित किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और आयोग से परामर्श करने के बाद जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो—

*[X X X]

*[(क) 'आदेश की पुष्टि, उसका सशोधन या उसको निरस्त कर सकेगी,

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित या निरस्त कर सकेगी या उसके द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति को कम कर सकेगी या बढ़ा सकेगी।"]

परन्तु किसी शास्ति को वर्धित करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को कोई अभ्यावेदन करने का जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे अवसर न दे दिया गया हो

परन्तु यह और है कि इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही का प्रारम्भ पुनर्विलो कित किये जाने वाले आदेश के दिनांक से तीन माहने से अधिक समय बाद नहीं किया जाएगा।

+ टिप्पणी —यह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध, सेवा से पदव्युति या हटाये जाने की शास्ति के अतिरिक्त नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का आदेश, प्रशासी न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिवक्ता द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो या जबकि आदेश न्यायालय की समिति द्वारा अपील में दिया गया हो।

1 1977 Lab IC (NOC) 74 (इलाहाबाद) भारतीय सघ वि राम अवतार शर्मा।

2 1977 Lab IC 1636 (दिल्ली) बशीधर वि भारतीय सघ।

* जी एस आर 129 विज्ञप्ति स F 3 (17) नियुक्ति (A-III) 67 दिनांक ३ अक्टूबर, 1974 द्वारा सशोधित, जिससे अभिव्यक्ति 'ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे लोपित की गई।

+ अधिसूचना स F 3 (I) A (A)/60, ग्रुप III दिनांक 16-2-1960 तथा 9-1-61 द्वारा सशोधित रूप में जोड़ी गई।

टिप्पणी

नियम 33 राजस्थान सरकार को शक्ति प्रदान करना है जिससे कि वह, राजस्थान न्यायिक सेवाओं के प्रतिरिक्त, अन्य राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन (रिव्यू) कर सके। राज्य सरकार या तो स्वेच्छा से ऐसे मामले का अभिलेख (रेकॉर्ड) बना सकेगी या सम्बन्धित होगी अधिकारी के आवेदन पर ऐसा कर सकेगी। पुनर्विलोकन की प्रक्रिया में राज्य सरकार, दोनों अधिकारी के विरुद्ध पारित शास्ति के आदेश की पुष्टि कर सकेगी या उसमें समोधन कर सकेगी या उसे तारिख कर सकेगी, अथवा सम्बन्धित अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् शास्ति में वृद्धि कर सकेगी। कोई भी आदेश जारी करने में राज्य सरकार लोक सेवा आयोग से उन तमाम मामलों में परामर्श लेगी जिनमें ऐसा करना नियम 5 (2) के अनुसार आवश्यक है जो निम्नांकित हैं:—

“राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जिनकी नियुक्ति करने की शक्ति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को दी गई है वह नहीं हो तो निम्ना और वेतन वृद्धियों को रोकने की शक्तियों के प्रतिरिक्त कोई अन्य शक्ति प्रविरोधित करने से पहले लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा।”

मयाद:—नियम 33 के द्वितीय परन्तुक् द्वारा पुनर्विलोकन की मयाद जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसकी तीसरी से तीन महीने की निश्चित की हुई है। अपीलों, पुनर्विलोकन या पुनर्विलोकन तथा पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने की मयाद निम्नानुसार है —

- | | |
|---|--|
| (1) नियम 30 अपील | जिस तीसरी को अपीलकर्ता अपीलप्रस्तुत आदेश की प्रति प्राप्त करे उस दिन से 3 महीने में (देखिये नियम 25) |
| (2) नियम 32 पुनरीक्षण | जिस आदेश का पुनरीक्षण करना है उस आदेश की तीसरी से 6 महीने में। |
| (3) नियम 33 सरकार द्वारा न्यायिक सेवाओं को छोड़ कर अन्य राज्य सेवाओं के सदस्यों के विरुद्ध आदेशों का पुनर्विलोकन, | जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसकी तीसरी से 3 महीने में। |
| (4) नियम 34 राज्यपाल द्वारा पुनर्विलोकन | जिस आदेश का पुनर्विलोकन करना है उसकी तीसरी से तीन वर्षों में। |

पीछित राज्य कर्मचारी को सामान्यतः अपना अपील करने का अधिकार का प्रयोग समाप्त करने के पश्चात् ही पुनर्विलोकन के लिये प्रार्थना करनी चाहिये। परन्तु कानूनन यह अनिवार्य नहीं है।

राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सदस्यों के सम्बन्ध में नियम 33 के नीचे दिये गये नोट का पालन करें।

34 राज्यपाल की पुनर्विलोकन सम्बन्धी शक्तियाँ:— इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल, स्वेच्छा से या अन्यथा, मामले के अभिलेखों को मगाने के बाद, किसी आदेश का जो इन नियमों या नियम 35 द्वारा निरसित नियमों

के अधीन दिया गया हो या अपीलनीय हो, पुनर्विलोकन कर सकेंगे और आयोग से परामर्श करने के बाद, जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो—

- (क) आदेश को पुष्ट, उपरान्तरित या अपास्त कर सकेंगे,
 - (ख) कोई भी शास्ति लगा सकेंगे या आदेश द्वारा लगाई गई शास्ति को अपास्त, कम या पुष्ट अथवा वर्धित कर सकेंगे,
 - (ग) मामले को, उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया हो, या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी अन्य कार्यवाही या जाच के निर्देश देते हुए, जैसा कि वे मामले की परिस्थितियों में उचित समझें, विप्रेक्षित कर सकेंगे, या
 - (घ) ऐसे अन्य आदेश जैसा वे उद्युक्त समझें, पारित कर सकेंगे :
- परंतु शर्त यह है कि:—

- (i) किसी शास्ति को लगाने या वर्धित करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति की अभ्यावेदन करने को, जो वह ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर न दे दिया गया हो ।
- (ii) यदि राज्यपाल किसी ऐसे मामले में जिसमें नियम 16 के अधीन कोई जाच नहीं की गई है, नियम 14 के खण्ड [4] से [7] में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का प्रस्ताव करें तो वे, नियम 19, के उपबंधों के अधीन ऐसी जाच करने का निर्देश देगे और उसके बाद ऐसी जाच की कार्यवाही पर विचार करने तथा सम्बन्धित व्यक्ति को ऐसा अभ्यावेदन करने का, जो वह ऐसी शास्ति के विरुद्ध करना चाहे, अवसर देने के बाद, ऐसा आदेश पारित करेंगे जो वे ठीक समझें ।

*[पुनर्विलोकन की जाने वाली आज्ञा के दिनांक से तीन वर्ष से अधिक के बाद इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जावेगी ।]

टिप्पणी:—वह नियम राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी ऐसे सदस्य के मामले में लागू नहीं होगा जिसके विरुद्ध सेवा से पदच्युति या हटाये जाने की शास्ति के अतिरिक्त नियम 14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति लगाने का आदेश प्रशासी न्यायाधीश द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामजद किसी न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो या जब कि आदेश न्यायालय की समिति द्वारा अपील में दिया गया हो ।

राजस्थान सरकार का निर्णय —“यह है कि आया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 34 के अन्तर्गत पीडित अधिकारियों द्वारा उन पर लागू की गई शास्ति के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये पुनर्विलोकन के प्रार्थना-पत्रों का फैसला करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना चाहिए । राजस्थान लोक सेवा (कार्यों की सीमा) विनियम 1951 के विनियम स 11 के साथ पठित सविधान के अनुच्छेद 320 (3) (ग) के परन्तुक के अनुसार, जब राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 14 में उप खण्ड (i) तथा (ii) में निर्दिष्ट शास्तियाँ सरकार लागू करे, तो आयोग

* [वि. स. 3(2) कामिक (क-3) 75 जी एस आर 29 दिनांक 25-7-75 द्वारा निविष्ट]

से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है। इस लिए ऊपर बनाए गई शास्तियों के विषय में आदेश या पुनर्विलोकन-प्राथना-पत्र पर आयोग का परामर्श लेना न ला ज़रूरी है और न आदेशानुसार। ऊपर बताई गई शास्तियों के अतिरिक्त अन्य शास्तियाँ लागू करने से सम्बन्धित अनुशासनिक मामलों में, इसी प्रकार पुनर्विलोकन प्राथना-पत्र के विषय में भी आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा।”

टिप्पणी

नियम 34-राज्यपाल की पुनर्विलोकन (रिब्यू) की शक्ति—इस नियम के अधीन राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी भी वर्ग के सिविल सेवा के सदस्य के विरुद्ध बनाए गए अनुशासनिक मामलों का पुनर्विलोकन कर सके। इसके विपरीत नियम 33 के अन्तर्गत राज्य सरकार, (राजस्थान न्यायिक सेवाओं को छोड़कर) केवल राज्य सेवाओं के सदस्यों से सम्बन्धित मामलों में ही पुनर्विलोकन कर सकती है। राजस्थान न्यायिक सेवाओं के सम्बन्ध में, नियम 34 के नीचे दी गई टिप्पणी देखिए। राज्यपाल यह कार्य स्वेच्छा से कर सकते हैं या ग्रामिन सरकारी कर्मचारी की प्राथना पर भी कर सकते हैं।

म्यादा;—पहले नियम 34 के अन्तर्गत कोई म्यादा निश्चित नहीं थी। परन्तु अब परन्तुक (ii) में निम्नांकित म्यादा छड़ा जोड़ा गया है।—

* “पुनर्विलोकन की जाने वाली आज्ञा के दिनांक से तीन वर्ष से अधिक के बाद इस नियम के अधीन कोई वाप्याही आरम्भ नहीं की जावेगी।”

सर्वोच्च न्यायालय ने मूझालान यादव वि. राजस्थान सरकार¹ में एक रोकथाम निर्णय दिया है। इस मामले में, पुलिस के एक सब-इन्स्पेक्टर को एक ऐसी विभागीय जांच करके सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जिसमें वह उपस्थित नहीं था। व्यापिन व्यक्ति ने राज्यपाल को पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने ग्रहण किया और आदेश दिया कि मामला पुनर्विलोकन (रिब्यू) के लिए उपयुक्त नहीं था। तत्पश्चात्, दो या तीन महीने के भीतर, उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की गई। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका मुस्यतः इस आधार पर खारिज कर दी कि राज्यपाल को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन-पत्र दो वर्ष की देरी के बाद पेश किया गया, जो उनकी सम्मति में अनुचित विलम्ब था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में उच्च न्यायालय का मूल्यांकन सही नहीं था। चूंकि राज्यपाल ने पुनर्विलोकन-आवेदन-पत्र विलम्ब के कारण खारिज नहीं किया था और उसे ग्रहण (entertain) करने के पश्चात् पुनर्विलोकन के लिए उपयुक्त नहीं माना, इस लिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह मन धारण किया कि राज्यपाल ने आवेदन-पत्र उमके गुण दोषों पर खारिज किया था। स्थिति उस प्रकार की होने से, उच्च न्यायालय के लिए यह सुना नहीं था कि उस दूरस्थ अवस्था में (remote stage) पुनर्विलोकन-आवेदन-पत्र के विलम्ब के आधार को पुनर्जीवित करता और उसे रिट याचिका खारिज करने का आधार बनाना। मतः अपील स्वीकार की गई और उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया गया और रिट याचिका वापिस भेजी जाकर उसका निपटारा कानून के अनुसार करने का आदेश दिया गया।

* अधिसूचना सं F. 3 (2) कायि (A-III) 75, G S R 29 दिनांक 25 जुलाई, 1975 द्वारा जोड़ा गया।

¹ AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2050-1970 Lab IC 1366,

संवैधानिक बिन्दु —अपील में या पुनर्विलोचन में उठाए जा सकते हैं। सरकार पुनर्विलोचन आवेदन पत्र इस आधार पर धारित नहीं कर सकती कि प्रार्थी की दलीलें ऐसी मर्मधानिन् पेची-दंगियों में सम्बन्धित हैं या उसमें ऐसे वातुनी बिन्दु हैं जिन पर नीचे के प्राधिकारीयों के समक्ष बन नहीं दिया गया था। सरकार भी उच्च न्यायालय के समान ही सविधान और कानून की मान्यता देने के लिए बाध्य है।¹

राज्यपाल की पुनर्विलोचन शक्ति—आया व्यक्तिगत है या मर्मधानिक मुक्तियाँ के रूप में —पहले, सर्वोच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय भी इस सम्मति के थे कि जो अधिकार किसी प्राधिकारी विशेष में निहित हो उसका प्रयोग वह केवल स्वयं ही कर सकता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि नियम 34 के अधीन पुनर्विलोचन का अधिकार केवल राज्यपाल द्वारा प्रयोग में लाया जाना चाहिए न कि सरकार द्वारा।² शमशेर सिंह वि पञ्जाब सरकार और ईश्वरचन्द धर्मपाल वि पञ्जाब सरकार³ में यह निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति/राज्यपाल एक मौलिक शक्ति के संवैधानिक मुखिया (Constitutional Head) है। यह सविधान का प्रावधानानुसार अपने मंत्रीपरिषद् के सामंजस्य से अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है। नियुक्तियाँ तथा व्यक्तिगत सेवा से हटाया जाना राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा कार्यकारीणी के संवैधानिक मुखिया (Constitutional Head) होने के नाते, और मंत्री परिषद् की सहायता तथा परामर्श से करते हैं। यही कारण है कि भारतीय सभ या राज्य के किसी कर्मचारी द्वारा नियुक्ति या बर्खास्तगी के विषय में लाया गया दावा भारतीय सभ या राज्य सरकार के विरुद्ध लाया जाता है न कि राष्ट्रपति/राज्यपाल के विरुद्ध।

इसी प्रकार का निर्णय भारतीय सभ वि श्री पति रजन विश्वास⁴ में दिया गया। इस मामले में घोषित किया गया कि किसी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति या बर्खास्तगी के क्षेत्राधिकार का प्रश्न, सचीव सरकार की दशा में राष्ट्रपति और राज्य की दशा में राज्यपाल के कार्यकारीणी बर्तनों की परिधि में आता है। अतः यह तथ्य कि अन्तिम आदेश स पहले या उसके साथ किसी मंत्री ने अधन्यायिक जांच की राष्ट्रपति के कर्तव्यों की विरुद्ध को प्रभावित नहीं करता जबकि भारत का सविधान उसे निश्चित रूप में संवैधानिक राष्ट्रपति मानता है, तो यह अनुज्ञ नहीं है न ऐसा इरादा ही किया गया कि राष्ट्रपति में इससे भिन्न शासनात्मक सत्ता का अधिकार निहित किया जावे। सविधान के अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति का कोई भी सदस्य उसके संवैधानिक मुखिया (Constitutional Head) के रूप में राष्ट्रपति स है जिसमें संवैधानिक कार्य-वाही करत हुए मंत्री परिषद् की सहायता और सेवा से कार्य करने का अभिप्राय है। केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम, 1957 के नियम 23 (2) के अनुसार मंत्री द्वारा किया गया अपील का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उचित और वातुनी निपटारा है जिसने बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि, मंत्री की सलाह पर कार्य करते हुए की है। ऐसे मामले में शक्ति की सुपुर्दगी (delegation of power) सम्मिलित नहीं है।

- 1 1975 Lab, IC 331 (जम्मू व काश्मीर) जी एस बोका वि जम्मू काश्मीर सरकार।
- 2 AIR 1961 सुप्रीमकोर्ट 751—यू पी सरकार वि बाबुराम उपाध्याय, AIR 1967 राजस्थान 414—लोगमल वि सरकार।
- 3 1974 सुप्रीम कोर्ट 2192, 1976 ASR 269
- 4 1976 ASR 87—AIR 1975 सुप्रीमकोर्ट 1255.

‘रिबी आदेश’,—अभिव्यक्ति ‘रिबी आदेश का जो इन नियमों या नियम 35 द्वारा निर्मित नियमों के अधीन दिया गया हो या अपीलनीय हो” राज्यपाल को पुनर्विलोकन की विस्तृत शक्ति प्रदान करती है और सिविल कर्मचारी को विस्तृत अवसर प्रदान करती है, क्योंकि अनुशासनिक कामवाहियों में न केवल अन्तिम आदेश बल्कि निलम्बन के आदेश या कोई मध्यवर्ती (interlocutory) आदेश भी पुनर्विलोकन के विषय हो सकते हैं। उदाहरणतः जाच अधिकारी की नियुक्ति, बनील रखने की अस्वीकृति किसी गवाह को सम्मन करने से इन्कार, किसी अभिलेख को ग्रहण करने से इन्कार किसी गवाह से जिरह करने की अस्वीकृति, इकतरफा आदेश निरस्त करने की अस्वीकृति, अभिलेख निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देना, नियम 18 के अधीन संयुक्त जाच आदि राज्यपाल द्वारा उसकी स्वेच्छा से या अन्यथा अर्थात् पीछित पक्षकार द्वारा आवेदन करने पर पुनर्विलोकन किये जा सकेंगे। राज्यपाल पर यह भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिससे कि वह पुनर्विलोकन के फलस्वरूप दिये गये स्वयं के आदेशों का पुनर्विलोकन नहीं कर सके। यह केन्द्रीय सरकार ने एम एच एफेयर्स के आदेश, सीमो सत्या F-39/1/69 Esst (A) दिनांक 16 अप्रैल 1969 के समक्ष है।

पुनर्विलोकन आदेश एक बोलता हुआ आदेश होता है—जो प्राधिकारी अपील पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का फैसला करें उनको अपने निष्कर्ष कानून के अनुसार निबालने चाहिये और उनकी अपने निर्णय की धृष्टि में कारण उल्लेखित करने चाहिये। ऐसा करना आवश्यक है, “ताकि उच्च न्यायालय (जिसे अपने सर्वप्रधानिक कर्तव्यों का पालन रिट याचिकाओं पर करना होता है) इस स्थिति में हों कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि आया निर्णय न्यायिकता से और निष्पक्षता से और सम्बन्धित विषय के तथ्यों और कानून पर उचित विचार करके और नीति या अधिष्ठान के बाह्य प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए किया गया था। यह भी ध्यान देन योग्य है कि कारण अभिलिखित करना इस लिये भी आवश्यक है क्योंकि इससे मामले को स्पष्टीकरण मिलता है मनमाना आचरण का मौका कम होता है, आम जनता के मस्तिष्क में विश्वास पैदा होता है, जिस पक्षकार के विरुद्ध आदेश दिया गया है उसे सतुष्टि होनी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिये समर्थ होकर न्यायाधिकरणों और कार्यकारणी को अपनी सीमा के भीतर रहने के लिये बाध्य कर सकता है।¹

रूप उपचार—जब कोई सरकारी कर्मचारी अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के माध्यम से विफल हो जाये तो, वह उस पर अधिगोपित शास्ति के विरुद्ध राज्यपाल को मेमोरियल याचिका पेश कर सकता है जो कि एक प्रकार में वीजदारी भुक्तम में सजा दिये जाने पर किसी अभिव्यक्ति की क्षमा याचना के समान है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को क्षमादान करने या सजा कम करने की शक्ति है। परन्तु न्यायालय रिट याचिका प्रस्तुत करने में विलम्ब को माफ करने के लिये कार्यकारणी प्राधिकारियों को आवेदन करने तथा मेमोरियल प्रस्तुत करने में व्यतीत किया गया समय नहीं गिनेगी।²

भाग VIII

प्रकीर्ण तथा अस्थाई

35 निरसन तथा व्यावृत्ति:—(1) राजस्थान सिविल सेवा (सर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1950 और ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन जारी की गई अधिसूचना

1. 1976 Lab IC 1979 (जम्मू कश्मीर) पूर्ण पीठ) एम शरीफूद्दीन वि जम्मू-कश्मीर सरकार, (1973) 1 SLR 1168 (जम्मू कश्मीर) हकीज-उल्ला वि जम्मू-कश्मीर सरकार।
- 2 AIR 1954 बम्बई 202।

और दिए गए आदेश उस सीमा तक, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं, जहां तक कि वे उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं जिन पर ये नियम लागू होते हैं, और जहां तक वे अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिविल सेवाओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित हो अथवा जहां तक वे नियुक्तियां करने, शास्ति या लगाने या अपील ग्रहण करने की शक्तियां प्रदान करते हैं :

परन्तु :—

- (क) ऐसा निरसन उक्त नियमों, अधिसूचनाओं और आदेशों अथवा तद्दीन पहले की गई किसी बात या कार्यवाही के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा,
- (ख) उक्त नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन कोई कार्यवाहियां जो इन नियमों के प्रारम्भ के समय लम्बित थी चालू रहेंगी और यथा सम्भव इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार निपटाई जाएगी।

(2) इन नियमों में कोई भी बात, ऐसे व्यक्ति को, जिस पर कि ये नियम लागू होते हों, अपील करने के उस अखबार से वंचित करने का प्रभाव नहीं रखेगी जो कि इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में उसको उप नियम (1) द्वारा निरसित नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन प्रोद्भूत हो चुका था।

(3) इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय लम्बित या बाद में की गई अपील पर जो किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध हो जो इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व दिया गया था, *इन नियमों के अनुसार विचार किया जाकर उस पर आदेश पारित किए जाएंगे।

टिप्पणी

नियम 35 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1950 तथा उसके अधीन जारी की गयी अधिसूचनाओं तथा आदेशों को निरस्त करता है। यह निरसन उस सीमा तक होता है जहां तक कि वे उन व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जिन पर यह नये नियम लागू होते हैं। परन्तु उपनियम 1 के नीचे दिया गया परन्तुक्त कहता है कि ऐसा निरसन पहले के कानून के अधीन की गई कार्यवाहियों को प्रभावहीन नहीं करता अर्थात् यह कि उनके अन्तर्गत जो भी कार्यवाही की गयी वह बँध रहेगी। परन्तु पहले के प्रावधानों के अधीन की गयी कार्यवाही जो इन नियमों के चालू होने के समय विचाराधीन चल रही थी वे जारी रहेंगी और, जहाँ तक सम्भव हो वह इन (नये) नियमों के अनुसार शासित होंगी। अतः कोई भी की गयी कार्यवाही या पारित किया गया आदेश बँध रहेगा और प्रभावशील बना रहेगा। किन्तु जो आदेश पहले भी शून्य या वह अब भी अर्बन्ध रहेगा।

परन्तु उपनियम (2) में राज्य कर्मचारियों के लिये एक सरक्षण का उपबन्ध किया गया है जिसके अनुसार नये नियम राज्य कर्मचारियों को निरस्त किये गये नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन पहले से प्राप्त किसी अधिकार से वंचित नहीं सकते, जो कि 1958 में इन नियमों के लागू होने से पहले अर्जित हो चुके थे। परन्तु उपनियम (2) पर एवं प्रतिबन्ध उपबन्ध (3) द्वारा प्रावधानित किया गया है, वह यह है कि जो अपील इन नये नियमों के लागू होने से पहले विचाराधीन थी या जो इन नियमों के लागू होने से पूर्व पारित आदेशों के विरुद्ध है परन्तु नये नियम लागू होने के पश्चात

नियुक्त की गयी है वह इन नये नियमों के प्रावधानानुसार विचारणीय होगी और उसी के अनुसार तय की जायेगी। 1950 के पहले के नियमों में अपील प्राधिकारी को शास्ति में वृद्धि करने का अधिकार नहीं था, परन्तु अब 1958 के नियमों में नियम 30 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी को शास्ति में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान की गयी है। एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि क्या कथित सशोधन आगे के लिये है या भूतकाल से प्रभावशील है। मोहन लाल वि राजस्थान सरकार¹ में राजस्व मण्डल के प्रार्थी की पदावनति कर दी और आदेश दिया कि तीन वर्षों के लिये उसे किसी उच्च पद पर स्थाना-पन्न रूप से कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाए। प्रार्थी ने शास्ति के इस आदेश के विरुद्ध अपील की जो लगभग 6 वर्षों तक अनिर्णीत रही और उसके दरम्यान 1958 के नये नियम प्रभावशील हो गये और तत्पश्चात् सरकार ने, अपील तय करते हुए, नियम 30 के अधीन अपील प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रार्थी की शास्ति में वृद्धि करते हुए उसे सेवा से वखास्त कर दिया। प्रार्थी प्राधिकारी के इस निर्णय को प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें निर्णय हुआ कि नियम 35 के उपनियम (3) में किया गया सशोधन आगे के लिये (Prospective) प्रभावशील था न कि भूतकालिक प्रभाव से (Retrospective)। अतः प्रार्थी की शास्ति में वृद्धि करने की सरकार की शक्ति अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है। इस प्रावधान का अर्थ यह लगाना व्यापक नहीं होगा कि प्रार्थी प्राधिकारी को ऐसा शक्ति प्रदत्त हो गयी है कि वह पहले से ही विचाराधीन अपील, नये नियमों के नियम 30 में निर्धारित तरीके से तय करे और शास्ति में वृद्धि कर दे।

36. सदेहों का निराकरण:—जहाँ कोई सदेह उत्पन्न हो कि किसी कार्यालय का अध्यक्ष कौन है या कोई प्राधिकारी किसी दूसरे प्राधिकारी के अधीनस्थ है या उसमें उच्चतर है या इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्धों के निर्वचन में या उनकी प्रयोग्यता में सदेह हो, तो मामला सरकार को नियुक्ति विभाग में निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

37. कतिपय अधिकारियों के लिये विशेष उपबन्ध —जहाँ कोई अधिकारी एकी-करण की योजनाओं में से किसी योजना में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह राजस्थान में सम्मिलित सभी इकाई के उस पर लागू होने वाले नियमों से जिसमें उसने अनिमित्त नियुक्ति धारण की हो, शासित होता रहेगा।

राजस्थान सिविल सेवा
[वर्गीकरण, नियन्त्रण और अवील] नियम 1958

अनुसूचियां

- (क) 1. सूची विभागाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी
2. सूची विभागाध्यक्ष-प्रथम श्रेणी के प्रतिरिक्त
- (ख) कार्यालयाध्यक्ष
- (1) राज्य सेवाएं
- (2) अधीनस्थ सेवाएं
- (3) लिपिक वर्गीय सेवाएं
- (4) चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

अनुसूची (क)

(1) विभागाध्यक्षों (प्रथम श्रेणी) की सूची

- 1 महाधिवक्ता
- 2 अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
- 3 मुख्य वन संरक्षक
- 4 विलोपित
- 5 मुख्य अभियन्ता, भवन एवं पथ
6. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
7. नगर आयुक्त, राजस्थान
8. निदेशक, उद्योग एवं रसद विभाग
- 9 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- 10 मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार
- 11 आयुक्त, आबकारी विभाग
- 12 निदेशक शिक्षा विभाग
13. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
- 14 निदेशक खान एवं भूगर्भ विभाग
15. निदेशक कृषि एवं खाद्य आयुक्त
16. समुक्त विकास आयुक्त
17. विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव
18. महानिरीक्षक पुलिस
- 19 महानिरीक्षक, कारागार (निदेशक, सुधार सेवाओं के अधीन विषयो को छोड़कर¹)
- 20 निरीक्षक पंजीयन एवं स्टाम्प
- 21 जागीर आयुक्त
22. श्रम आयुक्त
- 23 विधि परामर्शी
- 24 न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायाधिकरण
- 25 पंजीयक सहायरी समिति
- 26 बन्दोबस्त आयुक्त
- 27 परिवहन आयुक्त
- 46 विशेषाधिकारी, जल गृह (परिवहन) विभाग (ऐसी अनुयासिनिक कायवाहियों के सम्बन्ध में जो किसी सरकारी कमचारी द्वारा उसके भूतपूर्व राजस्थान स्टेट रोडवेज डिपार्टमेंट में सेवा काल के दरमियान या राजस्थान राज्य सड़क परिवहन नियम में प्रतिनिधित्व के दौरान किए गए किन्हीं कामों के सम्बन्ध में अथवा किन्हीं कामों में की गई किन्हीं गलतियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित हो या पुन स्थापित की जाती हो।)
- 47 आयुक्त, विभागीय जल
- 48 अपर आयुक्त वाणिज्य कर एवं पदेन प्रधानाचार्य, वाणिज्य कर प्रशिक्षणालय
- 27A प्रतिरिक्त परिवहन आयुक्त²
- 28 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन मामलों (उस तारीख से जिससे राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी उस पद को धारण करे।)
- 29 अपर निदेशक शिक्षा विभाग
- 30 निदेशक तकनीकी शिक्षा
- 31 निदेशक बीमा विभाग
- 32 देशस्थान, आयुक्त
- 33 निदेशक, चक्कन्दी जल
- 34 प्रधानाचार्य, अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय
- 35 मुख्य लेखा अधिकारी, चम्बल परियोजना
- 36 निदेशक, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन
- 37 अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मण्डल
38. अध्यक्ष, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल
- 39 अपर महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग³
- 40 मुख्य अभियन्ता, राजस्थान नहर परि-याजना
- 41 द्वितीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई
- 42 निदेशक, रोजगार
- 43 सहायता आयुक्त
- 44 निदेशक, सघु ब्रचत एवं लोटरोज⁴
- 45 उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर परियोजना बीकानेर⁵
- 1 विज्ञप्ति सख्या एक 3 (3) कामिक (क-3) 77 दि० 14-2-77 द्वारा निविष्ट ।
- 2 विज्ञप्ति सख्या एक 3 (20) कामिक (क-3) 75 दि० 22-12-75 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 3 विज्ञप्ति सख्या एक 3 (1) कामिक (क-3) 77 दिनांक 2-2-77 द्वारा पुन निविष्ट ।
- 4 विज्ञप्ति सख्या 3 (6) कामिक (क-3) 77 दिनांक 19-5-77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
- 5 विज्ञप्ति सख्या एक 3 (9) कामिक (क-3) 75 दिनांक 28-1-76 द्वारा प्रतिस्थापित ।

49 निदेशक भेड व ऊन विभाग	60 आयुक्त, महस्थल विकास आयुक्त राज-स्थान जोधपुर ²
50 निदेशक, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर	61 निदेशक, नागरिक रक्षा एव गृहसमा-रेष्ट्रा, गृह रक्षक ³
51 ग्रन्थन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण	62 निदेशक, नगर भूमिया, राजस्थान जयपुर ⁴
52 परीक्षक, स्थानीय निधि अन्वेषण	63 निदेशक, अभियोजन ⁵
53 निदेशक, जिला गजेटियर	64 ग्रन्थन, राजस्थान विविध सेवा प्रपील अधिकरण, राजस्थान ⁶
54 मुख्य नगर आयोजक	65 अपर महानिरीक्षक (पुलिस सतर्ता) ⁷
55 मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	66 निदेशक, सुधार सेवार्थ जेल विभाग, जयपुर ⁸
56 निदेशक भाषा विभाग	
57 महत्त्व राज्य परिवहन प्रपील अधिकरण	
58 निदेशक चमत्त्व विकास	
59 निदेशक, दुग्धशाला विकास एव अपर पत्नीयक, सहकारी समितिया ¹	

(2) विभागाध्यक्षों (प्रथम अंशों के अतिरिक्त) की सूची

1 अपर जागीर कमिशनर	9 आफिमर कमांडिंग, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यूनिट
2 निदेशक, अर्थ विज्ञान एव माह्यवी	10 निदेशक, आयुर्वेद विभाग
3 निदेशक पुरातत्व एव संग्रहालय	11 निदेशक, स्थानीय निवास
4 विलोपित	12 निदेशक, जन सम्पर्क कार्यालय
5 अध्यक्ष आयुर्वेदिक एव यूनानी पद्धति औषधि प्रजीयन मण्डल	13 निदेशक, समाज कल्याण विभाग
6 सतम अधिकारी (निष्क्रान्त सम्पति) बनवर	14 विलोपित
7 विलोपित	15 जिला एव सत्र न्यायाधीशरण
8 जिनो के क्लेक्टर	16 विलोपित
9 अध्यक्ष, आयुर्वेदिक फार्मसी	17 अध्यक्ष, पुरातत्व मंदिर का
10 प्रधानाचार्य, स्नातक एव स्नातकोत्तर महाविद्यालय	
11 प्रधानाचार्य, फोर्ड फाउण्डेशन प्रशिक्षण केन्द्र, छत्रपुरा (कोटा)	
12 प्रधानाचार्य, मंगतीराम बागड मैमोरियल इन्जीनियरिंग कालेज, जोधपुर	
13 पत्नीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय	
14 मन्थन नगर विकास	
15 विभिष्ट अधिकारी नगर विकास एव शासन सचिव	
16 सचिव, लोक सेवा आयोग	
17 उप निदेशक भेड एव ऊन	
18 विलोपित	
19 अध्यक्ष, आयुर्वेद अध्ययन	

1 वि स एफ 3 (15) कामिक (क-3) 75 दि० 9-1-76 द्वारा निविष्ट ।
2 वि स एफ 3 (17) कामिक (क-3) 75 दि० 28-1-76 द्वारा निविष्ट ।
3 वि स एफ 3 (18) कामिक (क-3) 75 दि० 17-2-76 द्वारा निविष्ट ।
4 वि स एफ 3 (6) कामिक (क-3) 76 दि० 24-5-76 द्वारा निविष्ट ।
5 वि स एफ 3 (12) कामिक (क-3) 76 दि० 15-7-76 द्वारा निविष्ट ।
6 वि स एफ 3 (16) कामिक (क-3) 76 दि० 6-8-76 द्वारा निविष्ट ।
7 वि स एफ 3 (19) कामिक (क-3) 77 दि० 18-1-77 द्वारा निविष्ट ।
8 वि स एफ 3 (3) कामिक (क-3) 77 दि० 14-2-77 द्वारा निविष्ट ।

- 29 प्रधानाचार्य, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर
30. प्रधानाचार्य, श्री करण नरेन्द्र दृषि महाविद्यालय, जोबनेर
- 31 राजकीय विद्युत् निरीक्षक, वित्त विभाग के आदेश सरया एफ 18 (11) एफ 11/15, दिनांक 13 अक्टूबर 1956 में वर्णित पदों के लिए।
- 32 विलोपित
- 33 विशेषाधिकारी, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर जैसे अधिकार प्रधानाचार्य पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर को दिये गये हैं, ये अधिकार किसी प्रधानाचार्य के बायभार सभालने तक के होंगे।
- 34 निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट शिक्षा अधिकारी, योजना -
(क) बहुउद्देशीय विद्यालय तथा उच्चतर माध्यमिक शालाएँ
(ख) केन्द्रीय सभागीय एवं जिला पुस्तकालय
(ग) समाज शिक्षा
- 35 राजस्थान के महाविद्यालयों के विशेषाधिकारी
- 36 उप-आयुक्त, उपनिवेशन, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर
37. आयुक्त, उपनिवेशन, चम्बल परियोजना कोटा
- 38 विलोपित
- 39 यूनिट अभिलेख कार्यालयों के लिए उप-सचिव निर्दिष्ट विभाग
- 40 वक्ता आयुक्त
- 41 सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल
- 42 प्रधानाचार्य, पोलोटैकनिक (बहुतकनीकी)
- 43 प्रधानाचार्य अतिरिक्त प्रसार प्रशिक्षण कैम्प सुमेरपुर
- 44 निदेशक, सहायता एवं पुनर्वास
- 45 निदेशक, संस्कृत शिक्षा
- 46 विलोपित
- 47 निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री
- 48 अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्य कर एवं पदेन प्रधानाचार्य वाणिज्य कर प्रशिक्षणालय
- 49 भारसाधक अभियंता और सचिव, भू-जन मण्डल, जोधपुर
- 50 मुख्य लेखा अधिकारी
- 51 निदेशक, पर्यटन विभाग
- 52 उप-महानिरीक्षक, पुलिस, अष्टाचार निरोधक विभाग
- 53 मुख्य निरीक्षक, फौजदारी एवं बायलस, *
- 54 अपर उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान नहर योजना, बीकानेर¹
- 55 सचिव, मरुस्थल विकास आयुक्त, राजस्थान, जोधपुर²
- 56 अपर बन्दोबस्त आयुक्त (1-4-1974 से)³
- 57 पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा शपील अधिकरण⁴
- 58 निदेशक, सतर्कता, जन विभाग, राजस्थान, जयपुर⁵

- 1 वि स एफ 3 (9) कामिक (क-3)/75 दि० 28-1-1976 द्वारा निविष्ट
- 2 वि स एफ 3 (17) कामिक (क-3)/75 दि० 28-1-1976 द्वारा निविष्ट
- 3 वि स एफ 3 (3) कामिक (क-3)/75 दि० 31-1-1976 द्वारा निविष्ट
- 4 वि स. एफ 3 (16) कामिक (क-3)/76 दि० 6-8-1976 द्वारा निविष्ट
- 5 वि स एफ 3 (13) कामिक (क-3)/77 दि० 6-8-1977 द्वारा निविष्ट

1	2	3	4	5	6
(ग) पशु चिकित्सा	कार्यालय, उप-निदेशक	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	निदेशक	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	निदेशक
	प्रादेशिक कार्यालय	सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी)	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी)	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)
	पशु चिकित्सालय या औषधालय	(क) जयपुर (ख) ओधपुर भारवाधक पशु चिकित्सक	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)	सम्बन्धित प्रादेशिक अधिकारी (द्वितीय वर्ग अधिकारी)	उप-निदेशक (पशु चिकित्सा)
2 उद्भूत विमान विभाग	केन्द्रीय कार्यालय कार्यालय कोटा	स्थल अभियन्ता स्थल अभियन्ता, कोटा	मुख्य विमान चालक	स्थल अभियन्ता स्थल अभियन्ता, कोटा	मुख्य विमान चालक
3 आयुर्वेद विभाग	मुख्यालय कार्यालय आयुर्वेदिक विभाग	उप-निदेशक आयुर्वेद विभाग	निदेशक, आयुर्वेद विभाग	निदेशक, आयुर्वेद विभाग	निदेशक, आयुर्वेद विभाग
	*क्षेत्रीय कार्यालय महारिवालय एव आयुर्वेद संस्थान	क्षेत्रीय उप-निदेशक प्रवक्ताचार्यगण	अपर निदेशक निदेशक, आयुर्वेद विभाग	क्षेत्रीय उप-निदेशक प्रवक्ताचार्य	अपर निदेशक निदेशक, आयुर्वेद विभाग
	औषध निर्माणशालाए औषधालय 'ए' वर्ग औषधालय 'ए' वर्ग	प्रभारी वैद्य प्रभारी वैद्य	मैजेर उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग	मैजेर प्रभारी वैद्य	मैजेर निदेशक, आयुर्वेद विभाग
	सूतानी दवाखाना 'ए' वर्ग औषधालय 'बो' गोन 'सी' सूतानी दवाखाना 'बो' मोर 'सो'	प्रभारी हकीम निरीक्षक	— उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग	प्रभारी हकीम निरीक्षक	— निदेशक आयुर्वेद विभाग

* वि. स. एक (11) कामिक (क-3) 75 दि 22-12-75 द्वारा निविष्ट ।

6

5

4

3

2

1

कार्यालय सहायक पजीयक
कार्यालय शिक्षा अधिकारी
प्रचार कार्यालय
निरीक्षक, सहायक निरीक्षक
एवं प्रक्षेपक कर्मचारीगण

सहायक पजीयक
शिक्षा अधिकारी
प्रचार अधिकारी
सहायक पजीयक

सम्बन्धित उप पजीयक

सहायक पजीयक
शिक्षा अधिकारी
प्रचार अधिकारी
सहायक पजीयक

सम्बन्धित उप पजीयक

9 (क) बाणिज्य

कर विभाग

प्रशासन अधिकारी

अपर आयुक्त

प्रशासनिक अधिकारी

अपर आयुक्त

उपायुक्त (प्रशासन) कार्यालय
उपायुक्त (प्रपील का कार्यालय)
उपायुक्त (अपील)

उपायुक्त (प्रशासन)
उपायुक्त (प्रपील)

अपर आयुक्त

बाणिज्य कर अधिकारिगण/
सहायक बाणिज्य कर अधि-
कारिगण के कार्यालय

उपायुक्त (प्रशासन)

उपायुक्त (प्रशासन)

ऐसे बाणिज्य कर अधि-
कारीगण/सहायक बाणि-
ज्य कर अधिकारीगण
जिनके कार्यालय बाणिज्य कर अधिकारी के मुख्यालय के प्रतिरिक्त हैं।

कार्य

बाणिज्य कर प्रशिक्षण स्कूल

उप प्रधानाचार्य

अपर आयुक्त

उप प्रधानाचार्य

अपर आयुक्त, पदेन
प्रधानाचार्य

पटताल वीकिन्दा (बैंक पोस्ट)
उडन दस्ते

उपायुक्त (प्रशासन)

उपायुक्त (प्रशासन)

9 (ख) आवकारी

विभाग

प्रशासनिक अधिकारी

आयुक्त

आयुक्त

उपायुक्त कार्यालय (माबकारी)
उपायुक्त कार्यालय
निवारक

उपायुक्त (माबकारी)
उपायुक्त (निवारक)

"

राजकीय इंटरमिडियेट महाविद्यालय अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्या- लय, बीकानेर और सादुल पनिसक स्कूल बीकानेर नार्मल एंव प्रशिक्षण विद्यालय हाई स्कूल इसी प्रवर्ग के या निम्नतर प्रवर्ग के अन्य शिक्षा संस्थान । मुख्यालय कार्यालय, आयुर्वेदिक अध्ययन राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय] 'ए' श्रेणी के पुस्तकालय अन्य पुस्तकालय पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल मुख्यालय कार्यालय जिला कार्यालय निर्वाचन पजीयन अधिकारी कार्यालय	"	निदेशक शिक्षा विभाग	"	निदेशक, शिक्षा विभाग
"	"	उप निदेशक (रैंज) निरीक्षक	"	उप निदेशक (रैंज) निरीक्षक
"	"	शासन सचिव	अधीक्षक	शासन सचिव
अधीक्षक	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेदिक	प्रधानाचार्य	अधीक्षक, आयुर्वेदिक अध्ययन निदेशक, शिक्षा विभाग
पुस्तकालय का भारसायक अधिकारी	प्रोड शिक्षा अधिकारी	उप-निदेशक (रैंज) शिक्षा सचिव	प्रोड शिक्षा अधिकारी सचिव, पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण मण्डल	उप निदेशक (रैंज) शिक्षा सचिव
महायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
जिला कार्यालय	जिला अधीक्षक	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व मण्डल का सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व मण्डल का सदस्य	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व मण्डल का सदस्य
निर्वाचन पजीयन अधिकारी कार्यालय	निर्वाचन पजीयन अधिकारी	जिला अधीक्षक	जिला अधीक्षक	

12 निर्वाचन
विभाग

मुख्यालय कार्यालय

13 विद्युत

निरीक्षणालय

सम्भाग कार्यालय

केन्द्रीय कार्यालय

14 निष्कास

सम्पत्ति

(प्रशासन)

विभाग

उप-परिक्षक कार्यालय

सहायक परिक्षक

मुख्यालय कार्यालय

15 खाद्य आयुक्त

विभाग

सम्भाग खाद्य सहायक कार्या-

ला पोष रक्षण शाखा

मुख्यालय कार्यालय

16 (1) वन

परिमण्डल कार्यालय

सम्भाग कार्यालय

उप-सम्भाग कार्यालय

रेजर या उप-रेजर

के भार के प्रचीन रेज

या अन्य भनुभाग

वन विद्यालय, कोटा

वन्य जीव परिक्षण

शाखा

सहायक विद्युत निरीक्षक शासन विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय)

सहायक विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षक

प्रशासन का भारसाधक परिक्षक

सहायक परिक्षक

उप-परिक्षक

सहायक परिक्षक

विशिष्ट अधिकारी खाद्य

खाद्य सहायक

पोष रक्षण अधिकारी

मुख्य वन सरक्षक ना

तकनीकी सहायक

सरक्षक

सम्भाग वन अधिकारी

उप-सम्भाग वन अधिकारी

रेजर

उप-सम्भाग वन अधिकारी

निदेशक

भ्रातृभारसाधक

अधिकारी तथा आखेट

सरक्षक (गेम वार्डन), सहायक भ्रातृ सरक्षक,

सहायक विद्युत निरीक्षक शासन विद्युत निरीक्षक (मुख्यालय)

सहायक विद्युत निरीक्षक शासन विद्युत निरीक्षक

प्रशासन का भारसाधक परिक्षक

सहायक परिक्षक

उप-परिक्षक

सहायक परिक्षक

विशिष्ट अधिकारी खाद्य

पोष रक्षण अधिकारी

मुख्य वन सरक्षक ना

तकनीकी सहायक

सरक्षक

सम्भाग वन अधिकारी

उप-सम्भाग वन अधिकारी

मुख्य वन सरक्षक

सम्भाग वन सरक्षक

उप-सम्भाग वन अधिकारी

रेजर

उप-सम्भाग वन अधिकारी

निदेशक

सम्युक्त परिमण्डल का

सरक्षक

मुख्य वन सरक्षक

सम्युक्त परिमण्डल का सरक्षक

उप-सम्भाग वन अधिकारी

मुख्य वन सरक्षक

1	2	3	4	5	6
	अधीक्षको के अधीन चिकित्सालय	अधीक्षक	उप-निदेशक, मंडिकल स्टोर तथा चिकित्सालय	अधीक्षक	उप-निदेशक, मंडिकल स्टोर तथा चिकित्सालय
	सभाग कार्यालय तथा जोन के सामान भण्डार	सभाग के सहायक निदेशक सबंध स्वास्थ्य अधिकारी या सहायक स्वास्थ्य अधिकारी	सभाग के सहायक निदेशक	सभाग के सहायक निदेशक	उप-निदेशक (जन स्वास्थ्य तथा ग्राम चिकित्सा सहायता)
	जिला प्रांतीय	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	उप-निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (प्रशासन)	जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी	उप-निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (प्रशासन)
	चिकित्सालय, दवाखाना या इसी प्रकार के चिकित्सा या स्वास्थ्य संस्थान जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं।	भारताधिक अधिकारी	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	भारताधिक अधिकारी	जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
	टी पी क्लिनिक	प्रान्तीय टी पी अधिकारी	उप-निदेशक (जन स्वास्थ्य एवं ग्राम चिकित्सा सहायता)	प्रान्तीय टी. पी. अधिकारी	उप-निदेशक (जन स्वास्थ्य एवं ग्राम चिकित्सा अधिकारी)
	केन्द्रीय जन स्वास्थ्य उपयोगिता सभाग प्रयोगशालाएं	मुख्य लोक विश्लेषक सभाग का सहायक निदेशक	" " "	मुख्य लोक विश्लेषक सभाग का सहायक निदेशक	" " "
	स्वास्थ्य विद्यालय	अधीक्षक	सभाग का सहायक निदेशक	"	"

विभाग	व्यवस्थापक	प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक	प्रशासनाध्यक्ष	निदेशक
राज्य प. नि. मयूरा	राज्य प. नि. मयूरा	प्रशासनिक अधिकारी	राज्य प. नि. अधिकारी	प्रशासन अधिकारी	रा. प. नि. म.
विभा. प. नि. मयूरा	विभा. प. नि. मयूरा	उप मुख्य अधिकारी	"	उप मुख्य अधिकारी	"
महोदय परिवार नियोजन	महोदय परिवार नियोजन	प्रभारी, अस्पताल/मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	वि. प. नि. अधिकारी	प्रभारी	वि. प. नि. म.
आरोग्य प. नि. केन्द्र	आरोग्य प. नि. केन्द्र	प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/हिले.	"	प्रभारी	"
क्षेत्रीय प. नि. अधिकारी	क्षेत्रीय प. नि. अधिकारी	प्राचार्य, क्षेत्रीय प. नि. प्र. केन्द्र	राज्य प. नि. अधिकारी	प्राचार्य	राज्य प. नि. म.
मृत शल्य केन्द्र	मृत शल्य केन्द्र	निदेशक मृत शल्य	"	निदेशक मृत शल्य	"
स्वास्थ्य परिवहन संगठन	स्वास्थ्य परिवहन संगठन	मुख्य परिवहन अधिकारी	"	मुख्य परिवहन अधिकारी	"
मुख्य स्वास्थ्य कार्यालय	मुख्य स्वास्थ्य कार्यालय	संयुक्त निदेशक	निदेशक	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	निदेशक
नगर कार्यलय	नगर कार्यलय	मान्य अभियन्ता	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	मान्य अभियन्ता	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
उप-नगर कार्यलय	उप-नगर कार्यलय	सहायक मान्य अभियन्ता	मान्य अभियन्ता	सहायक मान्य अभियन्ता	मान्य अभियन्ता
नगराधीन कोयला खान, बीकानेर	नगराधीन कोयला खान, बीकानेर	मान्य मैनेजर	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	मान्य मैनेजर	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
जन स्वास्थ्य विभाग	जन स्वास्थ्य विभाग	सहायक निदेशक	प्रभार निदेशक	सहायक निदेशक	प्रभार निदेशक
		(केवल कनिष्ठ लिपिकों के लिए)			
		(केवल कनिष्ठ लिपिकों से ऊपर की पेशियों के लिए)			

1	2	3	4	5	6
अधीनस्थ कार्यालय	अनु सम्पन्न अधिकारी तथा सूचना केन्द्रों के भारसाधक अधिकारी			(i) अनु सम्पन्न अधिकारी (किस कनिष्ठ लिपिकों के लिए) (ii) सूचना केन्द्रों के भारसाधक अधिकारी (केवल कनिष्ठ लिपिकों के लिए) (iii) अपर निदेशक (कनिष्ठ लिपिक में ऊपर की थोड़ी के लिए)	अपर निदेशक अपर निदेशक
मुख्यालय कार्यालय	मुख्य अधिकारी (बस)	मुख्य अधिकारी (बस)	मुख्य अधिकारी (बस)	मुख्य अधिकारी (बस)	मुख्य अधिकारी (बस)
रेज	अपर महानिरीक्षक	अपर महानिरीक्षक	अपर महानिरीक्षक, पुलिस	अपर महानिरीक्षक, पुलिस	अपर महानिरीक्षक, पुलिस
अधीक्षकों के भारसाधन के अधीन जिला जाला पुलिस स्टाने	अधीक्षक	अधीक्षक	अपर महानिरीक्षक, पुलिस, रेज	अधीक्षक	अपर महानिरीक्षक, पुलिस, रेज
अपर-अधीक्षक या निरोधक के भारसाधन के अधीन परिमण्डल	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अपर महानिरीक्षक, पुलिस, रेज
पाने तथा चौकिया	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अपर महानिरीक्षक, पुलिस, रेज
सुफिया पुलिस विभाग तथा मुस्त बातों द्यूरो (क) मुख्यालय (ख) जेल	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अधीक्षक	अपर महानिरीक्षक, पुलिस, रेज

नियुक्ति (बल)

उप महानिरीक्षक
पुलिस रेंज
अपर महानिरीक्षक
पुलिस (बल)
सहायक महानिरीक्षक
पुलिस, (बल)
महानिरीक्षक

पुलिस (बल)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
रेंज
अपर महानिरीक्षक
पुलिस, बल
सहायक महानिरीक्षक
पुलिस, बल,
महानिरीक्षक
*उप महानिरीक्षक

31 रजिस्ट्रीकरण
स्थाय विभाग

महान्याय कार्यालय (अपर *उप महानिरीक्षक
महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण
तथा सहायक, राजस्थान,
जयपुर

रजिस्ट्रीकरण

परमिटर निरीक्षक कार्या- निरीक्षक
लय सहायक रजिस्ट्रीकरण
कोषाधिकारी

*उप महानिरीक्षक

"
" कोषाधिकारी

"
"

*उप महानिरीक्षक

अध्यक्ष
राज्य सरकार

स्टाम्प

32 राजस्व विभाग

(1) राजस्व
विभाग

कार्यालय राजस्व बोर्ड
जिला

अध्यक्ष

अध्यक्ष द्वारा नामजद
राजस्व बोर्ड का सहाय
राजस्व बोर्ड का सहाय

रजिस्ट्रार

(1) कार्यालय अध्यक्ष प्रथम श्री श्री एवं आधुनिक द्वितीय श्री श्री के लिए
जिनको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, झुंझर एवं बीकानेर में
नियुक्त किया गया है।

(11) अपने कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्ष, प्रथम
और आधुनिक द्वितीय श्री श्री के पद धारण
करने वालों के लिए केवल छोटी शास्ति के लिए

(111) अन्य कर्मचारियों द्वारा कर्मचारी लिपिक, वरिष्ठ
लिपिक आदि के लिये।

अध्यक्ष द्वारा नामजद
राजस्व बोर्ड का
सहाय

"

कलेक्टर

"

1	2	3	4	5	6
	जिला कर्मचारी बगै, सहायक लेखाधिकारी प्रसवर (पुनर्वास) प्रसवर प्रसवर के प्रसावा जिला कलेक्टर (पुनर्वास) कर्मचारी बगै			सहायक लेखाधिकारी (पुनर्वास) प्रसवर कलेक्टर (पुनर्वास)	" "
34 सचिवालय	—	(क) सम्युक्त विभाग/ प्रकोष्ठ/कार्यकास के शासन उपसचिव/ सहायक शासन सचिव/पुनर्भाग अधिकारी और तत्समान हैसियत के प्र य अधिकारी, ऐसे चणुय श्रेणी कर्मचारियों को परिनिम्दा एव एक वेतन बद्धि रोक्ने की शक्ति लगाने के लिए जिनके विभाग/पुनर्भाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय से उक्त कर्मचारी प्रभुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय मन्दबन्ध से	(1) शासन सचिव, जहाँ (क) विभाग/प्रकोष्ठ/ विभाग/प्रकोष्ठ/कार्यालय से शासन उप सचिव, नियुक्त का उप सचिव कार्यसिद्धा सचिव या तत्समान व्यव है हैसियत का कोई यदि (2) शासन उप सचिव जारी और जहाँ गता नियुक्ति (ग) विभाग, कोई प्रचारी उपसचिव प्र य समस्त मामला के नहीं हो, पुनर्भाग अधिक- मन्त्र-य म कारो ग प्र मुख मन्त्रवाहक की छोड़कर अपने प्रचीन कार्य करने जाने निक वर्गीय कर्मचारियों के सम्यग से उप-अधिक नियुक्ति (ग) विभाग उन कमियों के लिए जो पदीय कृतव का निर्वाह करने में की गई हो, परिनिम्दा और एक वेतन वृद्धि रोक्ने की शक्ति लगाने के सम्यग प्र	(ग) उपयुक्त विविध वर्गीय कर्मचारियों के मन्त्र प्र से सम्यग प्र य	विनिष्ठ शासन सचिव, नियुक्ति विभाग
		(क) सहायक शासन सचिव कार्यक (ग-2) विभाग	शासन उप सचिव नियुक्ति विभाग		

भुवनेश्वरी (ख)

अनुशासन एवं राज्य कर्मचारी

मासलों के बिन्दे और मुख्य सचिव/शासन सचिव/विनिष्ट शासन सचिव/मुख्य सचिव/मन्त्री/उप सचिव/संसदीय सचिव के कार्यालय से सम्बद्ध ऐसे अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में, शासन उप सचिव, नियुक्ति (ख) विभाग

(ग) अनुभाग अधिकारी और मुख्य अनुवादक के सचिव में, विनिष्ट शासन सचिव, नियुक्त विभाग सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड + सचिव, जिला सैनिक बोर्ड

(क) जिला सैनिक बोर्ड - सचिव, जिला सैनिक बोर्ड

(ख) राज्य सैनिक बोर्ड - सचिव राज्य सैनिक बोर्ड

+ [प्रशासनिक कार्यकारी धारण करने के समय उनके विभाग से सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक वर्ग तथा कल्याण-संगठनकर्ता (बेलवेयर गार्डनर्स) को परिनिम्ना, एक वेतन वृद्धि रोकने तथा वेतन में से वसूली के दण्ड देने की शक्तियाँ सचिव, जिला सैनिक मण्डल ने निहित होनी ।]

निदेशक उप-निदेशक निदेशक

भारसाधक सहायक निदेशक निदेशक

सांख्यिक सचिव परीक्षक उप-सांख्यिक

परिवहन उप-सांख्यिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

परिवहन उप-सांख्यिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

परिवहन उप-सांख्यिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

5. सैनिक बोर्ड

36. राज्य बीमा विभाग

37. निदेशालय

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग

1	2	3	4	5	6
	जिला परिवहन कार्यालय	जिला परिवहन अधिकारी	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी	जिला परिवहन अधिकारी	प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
39 कोलार	कोलार उप कोलार	कोषाधिकारी सहनीलदार	कोलेक्टर सौपाधिकारी	कोषाधिकारी	कोलेक्टर
40. राज्यपाल	राज्यपाल का सचिवालय	राज्यपाल का सचिव	शासन सचिव	राज्यपाल का सचिव	मुख्य सचिव
क सचिवालय					
41 विधि विभाग	(1) महाप्रबलता कार्यालय	महाप्रबलता	शासन सचिव, विधि	महाप्रबलता	शासन सचिव, विधि विभाग
	(2) सरकारी प्रबलता	उप-सरकारी प्रबलता	सरकारी प्रबलता	सरकारी प्रबलता	विधि परामर्श
42 विकास	मुख्य कार्यालय	उप-विकास आयुक्त	अनुकूल विकास आयुक्त (पचायत)	उप विकास आयुक्त (पचायत)	अनुकूल विकास आयुक्त पचायत
इव पचा-यत					
विभाग (पचायत कक्ष)					
	कलेक्टर के कार्यालय	उप-जिला विकास अधिकारी	कलेक्टर के लिए	कलेक्टर	अध्यक्ष द्वारा नामजद राजस्व बोर्ड का सदस्य
			वरिष्ठ लिपिका के लिए	उप-विकास आयुक्त (पचायत)	"
			पचायत समितियों में प्रतिनियुक्त सेलालिपिको पर परिनिम्दा तथा बिना प्राकलित प्रभाव के दो धेतन दृष्टियां रोक रखने की प्राप्तिवां रगाने के सम्बन्ध में सम्पुल्ल कलेक्टर		अपर विकास आयुक्त

1	2	3	4	5	6
	भौदोलिक प्रक्षिप्त स्थान नागौर, खेतड़ी, पाटो सीकर भोववाडा रतनगढ गगानगर	सम्पूक्त औद्योगिक प्रक्षि- प्त गम्भान के अधीनक		सम्पूक्त औद्योगिक प्रक्षि- प्त गम्भान के अधीनक	
(अ) शिक्षा विभाग	मुख्यालय कार्यालय चौदित्तिलक स्थान	सहायक निदेशक तत्त्वनीकी विभाग		सहायक निदेशक सीसी शिक्षा	
(ग)	तत्त्वनीकी शिक्षा बाड कार्यालय	पञ्जीयन	सचिव	पञ्जीयन	सचिव
60	भारवा विभाग निदेशाचार	सहायक निदेशक	निदेशक	सहायक निदेशक	निदेशक
61	निरीक्षणार्थ सम्बन्धार्थार्थ पंचद्वी तथा बायनर	पंचद्वी तथा बायनर निरीक्षण (मुख्यालय) और मुख्य निरीक्षण पंचद्वी तथा बायनर के तत्त्वनीकी सहायक	मुख्य निरीक्षण तथा बायनर	पंचद्वी तथा बायनर निरीक्षण (मुख्यालय) और मुख्य निरीक्षण पंचद्वी तथा बायनर तत्त्वनीकी सहायक	मुख्य निरीक्षण पंचद्वी तथा बायनर
	मुख्यालय पर वदस्थापित पंचद्वी तथा बायनर निरीक्षण जो अभिहित करने हुए वरिष्ठ निरीक्षण पंचद्वी तथा बायनर	वरिष्ठ निरीक्षण पंचद्वी तथा बायनर		वरिष्ठ निरीक्षण पंचद्वी तथा बायनर	
	जिजा स्थित पंचद्वी तथा बायनर निरीक्षण	पंचद्वी तथा बायनर निरीक्षण		पंचद्वी तथा बायनर निरीक्षण	

अनुसूची-1-राज्यसेवाएं (State Services)

1 निम्नलिखित सेवाओं में सम्मिलित पदों के धारक—

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1 [राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा | 2 राजस्थान प्रशासनिक सेवा |
| 3 राजस्थान न्यायिक सेवा | 4 राजस्थान पुलिस सेवा |
| 5 राजस्थान लेख सेवा | 6 राजस्थान सचिवालय सेवा] |

नोट राजस्थान पुलिस सेवा व पद धारकों के सम्बन्ध में परिनिदा और वेतन-वृद्धि रोक रखने की शास्तिया रगान की शास्तिया यह निगलक्ष पुनिस म निहित हागी ।

2 नीचे प्रगणित अन्य पदों के धारक -

नोट—नीचे प्रगणित पदा के धारका के सम्बन्ध म भाग 3 और नियम 15 के उप नियम (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया जो विभागाध्यक्ष में प्रत्यायाजित प्राधिकार के अधीन निहित हैं, वे सरकार द्वारा आयुक्त, विभागीय जाच को सौंपे गए विभिन्न विभागा से संबंधित 50/- रु या इससे अधिक राशि के गबन की जाच के मामलों के संबध मे आयुक्त विभागीय जाच मे निहित होगी ।

कृषि विभाग

क-कृषि अनुभाग

1 निदेशक, कृषि विभाग, 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 प्रशासन सहायक 5 अप सहायक निदेशक, 6 कृषि रसायनज्ञ, 7 बीट विज्ञानी, 8 खेक विज्ञानी, (माइक्रोबैक्टीरियल) 9, सौंख्यिक 10 कृषि अभियंता 11 सहायक कृषि अभियंता, 12 जल वैज्ञानिक, 13 अधीक्षक बुनियादी कृषि विद्यालय, 14 जिला कृषि अधिकारी, 15 फन विज्ञेपज्ञ, 16 सभागीय पशु चिकित्सा अधिकारी 17 पशुपालन अधिकारी, 18 दुग्धशाला अधिकारी, 19 प्रधानाचार्य, राजस्थान पशु चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर 20 जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, 21, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, 22 सहायक भूमि मरक्षण अधिकारी, 23 भागसाधक अधिकारी, कनिष्ठ कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र ।

नोट — मद 14 के पदा के धारकों के संबध मे भाग 3 तथा नियम 15 (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया, उनमे अन्तर्विष्ट उपबधा के अध्यक्षीन निदेशक, कृषि विभाग मे निहित होगी ।

ख-पशुधन अनुभाग

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 उप-निदेशक | 2 सहायक निदेशक, पशुचिकित्सा विभाग |
| 3 अधिकारी, प्रथम श्रेणी | 4 अधिकारी, द्वितीय श्रेणी |
| 5 मोशाला विकास अधिकारी | 6 पशुधन विकास अधिकारी |
| 7 अधीक्षक, पशु प्रजनन प्रयोगशाला | 8 सहायक मजन पशु चिकित्सा |

नोट.— मद 4 तथा 7 के पदों के धारकों के संबध मे भाग 3 तथा नियम 15 (1) मे विनिर्दिष्ट शक्तिया, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यक्षीन निदेशक कृषि विभाग म निहित होगी ।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

1 मुख्य अधीक्षक 2 अधीक्षक 3 संग्रहालयाध्यक्ष 4 पुरातत्व रसायनज्ञ 5 गवेषक एवं खुदाई अधिकारी 6 मुद्रा-शास्त्रज्ञ ।

1 वि स 3 (4) नियुक्ति (क-3) 72 दि 24-9-1973, जा राजपत्र म दि 17-4-75 को प्रकाशित हुआ, द्वारा प्रतिस्थापित ।

उद्घटन विभाग

- 1 मुख्य पायलट 2 पायलट 3 ग्राउन्ड अभियंता 4 रेडियो वासक ।

आयुर्वेद विभाग

- 1 निदेशक, आयुर्वेद विभाग 2 प्रभारी मैनेजर, औषध निर्माणशाला 3 प्राचार्य
तुर्क पदविद्यालय 4 उप-निदेशक ।

जनगणना विभाग (लोपित)

सर्किट हाउस

- 1 मधीलक, राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर 2 भण्डार निरीक्षक ।

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

- 1 जिला रसद अधिकारी 2 विशिष्ट लक्षा अधिकारी 3 लेखा अधिकारी 4 सहायक
प्रभारिता 5 साक्षिक ।

सहकारी विभाग

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1 अपर पञ्जीयक | 2 प्रादेशिक समुक्त पञ्जीयक |
| 3 उप-पञ्जीयक | 4 मुख्य (आडिटर) प्रकेशक |
| 5 सहायक पञ्जीयक | 6 विशिष्ट प्रकेशक |
| 7 निष्ठा अधिकारी | 8 प्रचार अधिकारी |

नोट — सहायक पञ्जीयक, सहकारी समितियों के लिए परनिन्दा तथा दा बेतनवृद्धियां रोकने
के लिए शक्तियां पञ्जीयक, सहकारी समितियों में निहित होंगी । [वि स एफ 3 (5)
पृष्ठ (क-3) 76 S O 85 दि 13-5-76]

वाणिज्यिक कर विभाग

- | | |
|--|------------------------|
| 1 उप आयुक्त, (प्रशासन) | 2 उप-आयुक्त, (अधीन) |
| 3 प्रशासन अधिकारी | 4 वाणिज्यिक कर अधिकारी |
| 5 उप-प्रधानाचार्य, वाणिज्यिक कर प्रशिक्षण विद्यालय | |
| 6 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी | |
| 7 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (निवारक दल) | |
| 8 साम्यिक अधिकारी | |

नोट — क्रमांक 6 और 7 के पदों के धारकों को अर्थात् सहायक वाणिज्यिक कर
और सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (निवारक दल) और वाणिज्यिक कर अधिकारी
[वि स एफ 4] जो रा प्र से के नहीं हैं वो परनिन्दा और बेतनवृद्धि रोक रखने की शक्तियां लग
सर्वी शक्तियां, कर आयुक्त, राजस्थान में निहित होंगी ।

आवकारी विभाग

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1 उप-आयुक्त (आवकारी) | 2 प्रशासन अधिकारी |
| 3 जिला आवकारी अधिकारी | 4 सहायक आवकारी अधिकारी |
| 5 मुख्य अभियोजन निरीक्षक | 6 उप आयुक्त (निवारक दल) |
| 7 सहायक आवकारी अधिकारी [निवारक दल] | |

- 9 लेखा अधिकारी 10 उद्यान विशेषज्ञ 11 उद्यान अधीक्षक 12 रसायनज्ञ (जल प्रदाय विभाग)
13 विशेष अधिकारी ग्राम जल-प्रदाय (जल प्रणाली विभाग)।

जेल विभाग

- 1 महानिरीक्षक, कारागार 2 उप-महानिरीक्षक, कारागार 3 अधीक्षक, केन्द्रीय जेल
4 अधीक्षक, जिला जेल 5 उप-अधीक्षक, केन्द्रीय एवं जिला जेल 6 निदेशक, जेल उद्योग
7 चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन, प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी।

नोट—सद 5 के पद धारको के सम्बन्ध में भाग (3) तथा नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां उनमें अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अन्वये महानिरीक्षक कारागार में निहित होंगी।

श्रम विभाग

- 1 श्रम आयुक्त 2 संयुक्त श्रम आयुक्त 3 उप श्रम आयुक्त 4 सहायक श्रम आयुक्त
5 कार्मिक अधिकारी 6 श्रम कल्याण अधिकारी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

क - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग

- 1 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा 2 उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
3 सहायक निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा 4 मुख्य उपचर्या अधीक्षक 5 प्रान्तीय टी० बी०
अधिकारी 6 जन्म मरण गणना अधिकारी 7 लेखा अधिकारी 8 प्रधान चिकित्सा अधिकारी
9 चिकित्सालय अधीक्षक 10 बरिष्ठ सर्जन 11 बरिष्ठ भ्रूण 12 बरिष्ठ स्त्री रोग चिकित्सक
13 बरिष्ठ नर चिकित्सक 14 सर्जन 15 भ्रूण 16 स्त्री रोग चिकित्सक 17 नेत्र चिकित्सक
18 रश्मि विद 19 दन्त चिकित्सक 20 जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 21 सहायक
सिविल सर्जन, प्रथम श्रेणी (चार दन्त चिकित्सकों को सम्मिलित करते हुए) 22 उपचर्या अधीक्षक
23 मातृका (मैट्रन) 24 स्वास्थ्य अधिकारी (एम बी बी एस) 25 अधीक्षक, स्वास्थ्य
विद्यालय 26 औषध रसायनज्ञ 27 जवागु विज्ञानी 28 मुख्य सरकारी विश्लेषक 29 रसायन
परीक्षक 30 मैनेजर सेंट्रल मैट्रिकल स्टोर 31 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रथम श्रेणी
(सलेक्शन श्रेणी) 32 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, प्रथम श्रेणी 33 राजस्थान चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य सेवा द्वितीय श्रेणी (वरिष्ठ वेतनमान) 34 राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा
द्वितीय श्रेणी (कनिष्ठ वेतनमान) 35 सहायक स्वास्थ्य अधिकारी 36 सचिव सामान्य सगठन
37 प्रशामन अधिकारी 38 निदर्शक 39 आहार विद 40 सरकारी विश्लेषक * [41 एन्टोमो-
लोजिस्ट 42 बरिष्ठ ड्रग निरीक्षक 43 ड्रग निरीक्षक 44 ड्रग विश्लेषक 45 सहायक ड्रग विश्लेषक
46 ड्रग निरीक्षक (आयुर्वेद) 47 विधि अधिकारी, आयुर्वेद 48 रेडियो-फिजिस्ट]

ख - सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

- 1 प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय 2 (क) आचार्य, शरीर त्रिया
विज्ञान (ख) आचार्य, शरीर रचना विज्ञान (ग) आचार्य, औषधि प्रभाव विज्ञान (घ) आचार्य,
विज्ञान विज्ञान 3 (च) उपाचार्य, विकृति विज्ञान (ख) उपचार्य, मैडीसन (क्लीनिकल) (ग)
उपाचार्य जीव रसायन 4 (क) सहायक आचार्य, शरीर त्रिया विज्ञान (ख) सहायक आचार्य, शरीर

* वि स एफ 3 (15) कांमि (क 3) 76 जो एन नंर 62 दि 2-8-76) द्वारा निविष्ट]

ज्ञान 5 (क) वरिष्ठ निदेशक, शरीर क्रिया विज्ञान (ख) वरिष्ठ निदेशक, शरीर रचना ज्ञान (ग) वरिष्ठ निदेशक, औषध प्रभाव विज्ञान (घ) वरिष्ठ निदेशक, विकृति विज्ञान प्रयोगशाला।

ग—आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

- 1 पुस्तकाध्यक्ष (375-850 के वेतनमान में)
- 2 ध्यायन शिक्षक (375-850 के वेतनमान में)

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

- 1 निदेशक 2 सयुक्त निदेशक, प्रशामन 3 खान अभियन्ता 4 सहायक खान अभियन्ता 5 रसायन एवं सिरेमिक औद्योगिकी विज्ञ 6 खान मैनेजर 7 सहायक खान मैनेजर 8 उप बेधक अभियन्ता 9 रसायनज्ञ 10 सिरेमिक सहायक 11 सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) 12 मैनेजर, रात परियोजना 13 श्रमिक कल्याण अधिकारी 14 वरिष्ठ भू विज्ञान 15 वरिष्ठ भू विज्ञानी 16 रसायन एवं सिरेमिक अभियन्ता।

पुलिस विभाग

- 1 पुलिस बाह्य अधिकारी 2 निदेशक श्याय (फोरमेन्सिक) विज्ञान प्रयोगशाला 3 सहायक निदेशक, फो वि प्रयोगशाला 4 वैज्ञानिक अधिकारी, फो वि प्र।
- टिप्पणी—पद 1, 3 व 4 को परिनिन्दा व वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देने की शक्तियां बढ़ानिरीक्षक, भारत में निहित होगी।]

जन सम्पर्क निदेशालय

- 1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 सवीक्षा अधिकारी 5 वरिष्ठ फोटो ग्राफर 6 सहायक सम्पादक 7 सम्पर्क अधिकारी 8 जन सम्पर्क अधिकारी 9 पूछताछ अधिकारी।

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

- 1 द्वितीय मलाहकार 2 ग्रहण अधिकारी

समाज कल्याण विभाग

- 1 निदेशक 2 सहायक निदेशक 3 कल्याण अधिकारी 4 अनुसन्धान अधिकारी 5 प्रचार अधिकारी 6 विशेष अधिकारी (पुनर्वास) 7 चिकित्सा अधिकारी 8 अधीक्षक गृह 9 मुख्य परि कीर्णा अधिकारी 10 प्रधानाचार्य 11 प्राध्यापक 12 जन जाति कल्याण एवं सुधार कार्य प्रशासन क प्राध्यापक।

निर्वाचन विभाग

- 1 मुख्य निर्वाचन पर्यवेक्षक

पर्यटन निदेशालय

- 1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 मैनेजर।

पञ्जीयन एवं स्टाम्प विभाग

- 1 निरीक्षक

राजस्व एवं भू अभिलेख विभाग (सोपित)

नाविक, सैनिक तथा सौमनिक सन्दर्भ

- 1 मधिय

सचिवालय

- 1 सहायक शासन सचिव 2 व्यवस्था एवं पद्धति अधिकारी 3 निजी सचिव 4 सचिव
5 ¹[6 सक्शन अधिकारी] ।

राज्य बीमा

- 1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक

अथ विज्ञान एवं सांख्यिकी निदेशालय

- 1 निदेशक अथ विज्ञान एवं सांख्यिकी 2 सांख्यिकी 3 उप निदेशक 4 सहायक निदेशक ।

स्वायत्त शासन (स्थानीय निकाय)

- 1 प्रादेशिक निरीक्षक 2 सभागीय पंचायत अधिकारी ।

विकास विभाग

- 1 विकास अधिकारी 2 पशुपालन अधिकारी 3 कृषि प्रसार अधिकारी 4 सम्पादन,

राजस्थान ग्राम विकास 5 प्रधानाचार्य ग्राम सचिव व ड्र ।

²विकास अधिकारी पर शान्ति अधिरोपित करने का अधिकार—

- (1) सम्बन्धित कलेक्टर (जिला विकास अधिकारी) को परिनिर्दिष्ट तथ्याधारी प्रभाव से दो तक वसत बढ़िया रोकने का हिय ।

- (2) अन्य लघु शान्ति का लिए—निदेशक सामुदायिक विकास ।

- (3) कलेक्टर के द्वारा दी गई शान्ति के आदेश की धरिल—निदेशक सामुदायिक विकास ।
उप निदेशन विभाग ××× (सोपित दि० 28 1 76 स)

राजस्थान उच्च न्यायालय

- 1 उप-परीक्षक (प्रशासन) 2 सहायक परीक्षक एवं मुख्य न्यायाधिपति के सचिव

3 पुस्तकाध्यक्ष (375-850 का वतनमान से)

विधि एवं न्याय विभाग

- 1 पूर्वाकालिक लोक अभियोजक 2 सक्कारी अधिवक्ता ।

पंचायत विभाग

- 1 सहायक निदेशक 2 वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा अन्य प्रशिक्षक 3 जिला पंचायत अधिकारी ।

अल्प वचत सगठन

- 1 विशेष अधिकारी अल्प वचत 2 सभागीय अधिकारी अल्प वचत ।

रोजगार निदेशालय

- 1 निदेशक 2 उप निदेशक 3 सहायक निदेशक 4 उप प्रादेशिक रोजगार अधिकारी

5 सहायक रोजगार अधिकारी 6 जिला रोजगार अधिकारी ।

चकबंदी विभाग

- 1 चकबंदी अधिकारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग (विलोपित)

अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय, जयपुर

- 1 प्रशासन अधिकारी

1 स० एफ 3(11) कामिक/क 3/75 दि 28 1 76 द्वारा बोडा गया ।

स० ए० 9 (18) कामिक/क III/77 दि० 10 1 78 ।

मूल्यांकन समूह

- 1 प्रादेशिक मूल्यांकन अधिकारी 2 अन्वेषण अधिकारी

राजस्थान नहर परियोजना

- 1 महायव नगर आयोजक

राजस्थान भू-गर्भ जल विभाग

- 1 भारमायव अभियन्ता एवं सचिव 2 अधिशासी अभियन्ता (वेधन) 3 अधिशासी अभियन्ता (रिस्फोटक) 4 भू-गर्भ जल वैज्ञानिक 5 महायव अभियन्ता 6 कनिष्ठ भू विज्ञानी 7 रसायनज्ञ 8 वेधन फोरमैन [9 कनिष्ठ जल वैज्ञानिक 10 कनिष्ठ भौतिकीक 11 कनिष्ठ रसायनज्ञ]

जिला मजिस्ट्रेट्स निर्देशालय

- 1 अनुसंधान अधिकारी

निर्देशालय पुरालेख

- 1 निदेशक पुरालेख 2 सहायक निदेशक पुरालेख

नागरिक सुरक्षा विभाग

- 2 [1 निदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं कमांडेंट जनरल, होमगार्ड्स 2 उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं डिप्टी कमांडेंट जनरल 3 वटानियन कमांडेंट 4 उरिण्ट स्टॉफ अधिकारी नागरिक सुरक्षा 5 वरिण्ट स्टॉफ अधिकारी, होमगार्ड 6 अप कमांडेंट, नगर होमगार्ड 7 वटानियन में द्वितीय कमांडेंट 8 कनिष्ठ स्टॉफ अधिकारी 9 लेखाधिकारी]

टिप्पणी—पद सं० 3 से 9 को 'परिनिन्दा' तथा दो स अनधिक वेतन वृद्धिया सचयी प्रभाव से रोकने की शक्तियां निदेशक में निहित होगी ।]

नगर आयोजना विभाग

- 1 मुख्य नगर आयोजक एवं वास्तुशिल्प सलाहकार 2 वरिष्ठ नगर आयोजक 3 उप-नगर आयोजक 4 उप नगर आयोजक (सिविल सर्वेक्षण) 5 सहायक नगर आयोजक (तकनीकी सहायक को सम्मिलित करत हुए) 6 सहायक अभियन्ता (सर्वेक्षण) 7 सामान्य 8 अनुसंधान अधिकारी ।

तकनीकी शिक्षा निर्देशालय

- 1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा 2 अध्यक्ष, तकनीकी शिक्षा बोर्ड 3 समुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा 4 सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड 5 प्रशिक्षण एवं काम दिलाने वाला अधिकारी 6 प्रधानाचार्य, पोलिटैक्निक 7 सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा 8 अध्यक्ष, अभियांत्रिक विभाग 9 प्राध्यापक, तकनीकी 10 प्राध्यापक, गैर तकनीकी 11 अधीक्षक, वर्कशाप 12 उप-निदेशक, प्रशिक्षण 13 राज्य उप शिक्षता सलाहकार 14 सहायक निदेशक, प्रशिक्षण 15 राज्य महायव शिक्षता सलाहकार 16 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 17 अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 18 परीक्षक तकनीकी शिक्षा बोर्ड [19 उपनिदेशक 20 रीडर 21 पाठ्यक्रम विकास का अध्यक्ष 22 मैथेरिक अधिकारी 23 सहायक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी] ।

भाषा विभाग

1. निदेशक 2. सहायक निदेशक 3. जिना भाषा अधिकारी

1 सं० एक 9 (55) कांमि/क-3/76 GSR 128 दि० 27-6-77 द्वारा बोडे गये ।

2 सं० 3 (2) कांमि/क-3/76 दि० 29-3-1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।

• दि० ३०-३-७८ कांमि/क-३/७६ दि० २८-७८ द्वारा प्लेसमेंट

निरीक्षणालय केंद्र तथा बायलर

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 मुख्य निरीक्षक | 3 निरीक्षक |
| 2 वरिष्ठ निरीक्षक | 4 चिकित्सा निरीक्षक |

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- 1 मुख्य अभियन्ता 2 अधीक्षक अभियन्ता 3 अधिशासी अभियन्ता 4 सहायक अभियन्ता
5 वरिष्ठ रसायनज्ञ 6 वनिष्ठ रसायनज्ञ ।

भेड एव ऊन विभाग

- 1 उप-निदेशक (विपणन) 2 उप-निदेशक (प्रसार) 3 प्रधानाध्याय भेड एव ऊन प्रशिक्षण सस्थान 4 सहायक निदेशक (विपणन) 5 सहायक निदेशक (प्रशा०) 6 जिला भेड एव ऊन अधि 7 ऊन श्रेणीकरण अधिकारी 8 कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी 9 प्रयोगशाला अधिकारी (ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला) 10 अधीक्षक, भेड प्रजनन म थान 11 मुख्य कतन अधिकारी 12 प्राध्यपक, भेड एव ऊन प्रशिक्षण सस्थान 13 सहायक कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी 14 भेड एव ऊन प्रसार अधिकारी ।

प्राथमिक निधि (प्रोविडेंट फण्ड) विभाग¹

- 1 निदेशक प्राथमिक निधि 2 लेखाधिकारी

दुग्धशाला विकास विभाग²

- 1 निदेशक, दुग्धशाला विकास एव अपर पजीयक सहकारी समितिया 2 अपर निदेशक (दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम) 3 मयुक्त निदेशक (दुग्धशाला अभियांत्रिकी) 4 उप निदेशक (कायकारी अभियन्ता, सिविल) 5 उप निदेशक (कार्पोरेशन) 6 उप निदेशक (मानव शक्ति विकास) 7 उप निदेशक (विपणन व क्रय) 8 उप निदेशक (पशु प्रजनन) 9 सहायक निदेशक (पशुपालन एव चारा विकास) 10 सहायक निदेशक (सर्वेक्षण) ।

अभियोजन विभाग³

राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक

विश्व स्तर कार्यक्रम परियोजना विभाग⁴

- 1 प्रोजेक्ट प्रबंधक 2 सहायक प्रोजेक्ट प्रबंधक

अल्प बजट एव लौटरी विभाग⁵

- 1 उप निदेशक 2 सहायक निदेशक

-
- 1 स एफ 3(16) नि (क-3) 75 दि 28-1-76 द्वारा जोड़ा गया ।
2 स एफ 3(15) कामिक/क 3/75 दि 9-1-76 द्वारा जोड़ा गया ।
3 स एफ 3(12) कामिक/क-3/76 दि 15-7-76 द्वारा जोड़ा गया ।
4 स एफ 3(12) नियुक्ति (क-3)/71 दि 4-9-76 द्वारा जोड़ा गया ।
5 स एफ 3 (6) कामिक व-3/77 GSR 68 दि 19-5-77 द्वारा जोड़ा गया ।

अनुसूची (2) अधीनस्थ सेवाएं

निम्नलिखित पद या इसी प्रकार के पदों के धारक

वित्त विभाग लेखा एवं विनिर्माण/राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्य

नोट—विभागों/कार्यालयों में सम्बद्ध लेखाकारों [तथा कनिष्ठ लेखाकारों] के सम्बन्ध में जो शक्तियाँ लगाने की शक्तियाँ विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में भी निहित हैं।

कृषि विभाग

(6) कृषि अनुभाग

1. बोरिंग सुपरवाइजर्स 2. बोरिंग करने वाला 3. सगणक 4. ओवरसियरगण 5. नक्शा-ग्रीड 6. नक्शाकार 7. तकनीशियन 8. डिस्वी 9. बरमा चालक 10. प्रयोगशाला सहायक 11. कृषि सहायक 12. क्षेत्र सहायक 13. सहायक तकनीशियन 14. प्रक्षेत्र मिस्त्री 15. कृषि अभ्यापक 16. उद्यान पर्यवेक्षक 17. प्रशिक्षक 18. यांत्रिक 19. कपास निरीक्षक 20. पीप सारक्षक सहायक 21. सहायक जिला कृषि अधिकारी 22. ट्रैक्टर फौरमैन 23. प्रक्षेत्र मैनेजर 24. अनुसंधान सहायक 25. इपि प्रसार अधिकारी 26. डिजाइनर, कृषि निर्माणशाला 27. कृषि फोल्डमैन।

(क) पशुधन शाखा

1. शालिहोत्री 2. टीका लगाने वाला 3. मुख्य पशुपाल एवं पशुपाल 4. पशुधन निरीक्षक 5. मत्स्य क्षेत्र पर्यवेक्षक 6. कम्पाउण्डर पशु चिकित्सालय 7. कुक्कुट पालन निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा सहायक 8. प्रयोगशाला सहायक 9. सहायक अधीक्षक, पशु प्रजनन प्रक्षेत्र 10. पशुपालन प्रसार अधिकारी और भेड एवं ऊन प्रसार अधिकारी।

नोट :—पशुपालक प्रसार अधिकारियों के सम्बन्ध में “परिनिन्दा” करने और बिना आकलित प्रभाव से दो से अनधिक “चेतन बृद्धियाँ रोक रखने” की शक्तियाँ सपाने की शक्तियाँ राजपत्रित कोटि के अधिकारियों के सम्बन्ध में सम्पूक्त उप-निदेशक, पशुपालन विभाग में निहित होंगी और अराजपत्रित कोटि के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्पूक्त जिला पशुपालन अधिकारी में निहित होंगी। कृषि प्रसार अधिकारियों एवं भेड तथा ऊन विकास अधिकारियों के विषय में उक्त शक्तियाँ क्रमशः सम्पूक्त जिला इपि अधिकारी और जिला पशुपालन अधिकारियों के पास होंगी।

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग

1. परिरक्षक 2. सरदार सहायक 3. पर्यवेक्षक, खगोल वैद्यशाला, जयपुर 4. फोटोग्राफर 5. नक्शानवीस 6. नक्शाकार 7. पुस्तकाध्यक्ष 8. पर्यवेक्षक, विज्ञान एवं वंशज 9. प्रयोगशाला सहायक 10. निगानेबाज 11. मुख्य फोटोग्राफर 12. बड़ई।

आयुर्वेद विभाग

1. निरीक्षक, आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालय 2. वैद्य एवं सहायक वैद्य, औषध निर्माणशाला 3. वैद्य एवं हवैस, औषधालय 4. कम्पाउण्डरगण 5. नर्स 6. अभ्यापक, आयुर्वेद महाविद्यालय 7. वजीमक, भारतीय मैडिकल मण्डल।

सर्विट हाउस

1. भारमापक पर्यवेक्षक, सर्विट हाउस, प्रथम श्रेणी 2. पर्यवेक्षक, राजकीय प्रवास भवन,

3 वरिष्ठ स्वागतकर्त्ता 4 कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता 5 मैनेजर, सविट हाउस 6 महायक अधीक्षक, राजस्थान राज्य होटल, जयपुर 7 मैनेजर, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।

नागरिक उद्बोधन विभाग

1 यात्रिक (मैकेनिक्स)

साल पूति विभाग

1 क्षेत्रीय रसद अधिकारी 2 प्रवर्तन अधिकारी 3 गोदाम अधिकारीगण 4 सहायक जिला पूति अधिकारी 5 प्रवर्तन निरीक्षकगण ।

ग्राम पुनर्निर्माण सहायक विभाग

1 निरीक्षक 2 सहायक निरीक्षक 3 क्षेत्रीय प्रचार सहायक 4 चालक 5 ग्रामस्थक 6 अध्यापक, ग्राम पुनर्निर्माण विभाग 7 बैंक 8 प्रबन्धक नाट्य दल 9 कलाकार, नाट्य दल 10 अभिनेता, नाट्य दल 11. संगीतज्ञ, नाट्य दल 12 सहायक प्रसार अधिकारी ।

1 [टिप्पणी — (1) इन नियमों के नियम 14 में वर्णित समस्त शास्तिया निरीक्षक अधिशासी तथा सहायक निरीक्षकों के लिए देने की सम्पूर्ण शक्तिया अपर पञ्जीयक में निहित होगी ।

(2) निरीक्षक (आडिटर) पर समस्त शास्तिया देने की सम्पूर्ण शक्तिया मुख्य आडिटर में निहित होगी ।

(3) नियम 14 में वर्णित (i), (ii) व (iii) साधारण दण्ड देने की शक्तिया निरीक्षक (अधिशासी) मय सहायक प्रसार अधिकारी, सहायक निरीक्षकों के जो सम्बन्धित अधिकारिता में है । उस क्षेत्र के क्षेत्रीय एवं संयुक्त/उप पञ्जीयकों में निहित होगी ।

(4) उनके अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे निरीक्षक (अधिशासी) मय सहायक प्रसार अधिकारी, सहायक निरीक्षकों पर परिनिन्दा या दो से अधिक वेतन वृद्धि बिना सचयी प्रभाव से रोकने के साधारण दण्ड देने की शक्तिया सहायक पञ्जीयक में निहित होगी जो तदर्थ (एडवाक) या पूर्णतः अस्थाई रूप से यह पद धारण नहीं करते हैं ।

(5) उनके अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे निरीक्षक (आडिटर) पर परिनिन्दा या दो से अधिक वेतन वृद्धि बिना सचयी प्रभाव से रोकने की शक्तिया विशिष्ट आडिटर में निहित होगी, जो तदर्थ या पूर्णतः अस्थाई रूप से यह पद धारण नहीं करते हैं ।]

वाणिज्यिक कर विभाग

1 विवि महायक 2 निरीक्षक, प्रथम श्रेणी 3 निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी 4 निरीक्षक, तृतीय श्रेणी 5 गश्त अधिकारी 6 जमादार 7 सिपाही 8 ड्राइवर ।

नोट.—(1) क्रमांक 2 से 4 पुनः संयोजित पदों के सम्बन्ध में अर्थात् निरीक्षक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय पर 'परिनिन्दा' और बिना आवलित प्रभाव के दो से अधिक वेतन वृद्धि गेक रखने की शास्तिया लगाने की शक्तिया वाणिज्यिक कर अधिकारियों में निहित होगी ।

(2) क्रमांक 7 और 8 के पदा अर्थात् सिपाही और डाइवरा पर परिनिन्दा की शास्ति लगाने की शक्तिया सहायक वाणिज्यिक वर अधिकारिया (निवायक दल) में निहित होगी।

() क्रमांक 2 से 11 तक के पदा के सम्बन्ध में समस्त छोटी शास्तिया, जैसा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधील) नियम 1958 के नियम, 14[1], [2] और [3] में विहित है, लगाने की शक्तिया उप-प्रायुक्त, वाणिज्यिक वर (प्रशासन) का होगी।

आवकारी विभाग

1 निरीक्षक, प्रथम श्रेणी 2 निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी 3 निरीक्षक, तृतीय श्रेणी 4 परिमोजन निरीक्षक 5 गश्त अधीक्षक, (निवारक दल) 6 गश्त अधिकारी, प्रथम श्रेणी (निरोधक दल) 7 गश्त अधिकारी, द्वितीय श्रेणी (निरोधक दल) 8. जमादार (निरोधक दल) 9 सिपाही और सवार (निरोधक दल)।

नोट — (1) क्रमांक 1 से 4 तक के पदा के सम्बन्ध में परिनिन्दा और बिना आकलित प्रभाव के दो से अधिक वेतन बढ़िया रोक रखने की शक्तिया लगाने की शक्तिया सहायक आवकारी, अधिकारी, जिला आवकारी अधिकारी को होगी।

(2) क्रमांक 8 तथा 9 के पदों के सम्बन्ध में परिनिन्दा की शास्ति लगाने की शक्तिया सहायक आवकारी अधिकारी (निरोधक दल), जिला आवकारी अधिकारी (निरोधक दल) को होगी।

(3) क्रमांक 1 से 4 तक के पदों के सम्बन्ध में समस्त छोटी शास्तिया, जैसा कि उपर्युक्त नियमों के नियम 14[1], [2] तथा [3] के अधीन विहित है, लगाने की शक्तिया उप-प्रायुक्त, आवकारी में और क्रमांक 5 से 9 तक के पदों के सम्बन्ध में उप-प्रायुक्त (निरोधक दल) को होगी।

धर्मार्थ विभाग

1 निरीक्षक 2 सहायक निरीक्षक

शिक्षा विभाग

1 उप-सहायक निरीक्षक

2 हाई स्कूलों तथा वैसे ही शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकगण।

3 भारसाधक पुस्तकाध्यक्ष, महाराजा मार्वजनिष्ठ पुस्तकालय, जयपुर। विजयार्जुन पंचम रजन जयन्ती पुस्तकालय, बीकानेर और सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय, जोधपुर।

4 समस्त राजकीय संस्थाओं के अध्यापक 5 अधीक्षक शारीरिक शिक्षा 6 चिकित्सा अधिकारी 7 समाज शिक्षा आयोजक 8 ओवरसीयर 9 उप-प्रधानाचार्य, कला संस्थान, जयपुर 10 शारीरिक शिक्षक 11 प्रयोगशाला सहायक 12 निदेशक 13 मानुलिपि शिक्षक 14 चप प्रसाधक 15 कलाकार 16 उद्यान पर्यवेक्षक 17 महापाल 18 मैसमेन 19 संवशन बटन 20 संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक 21 शिक्षा प्रसार अधिकारी 22 सहायक शारीरिक शिक्षक 23 संगीत एवं नृत्य शिक्षक 24 बालविनोदक 25 तबला शिक्षक 26 बस डाइवर 27 मैट्रन 28 यात्रिक और मिस्त्री 29 इन तक महाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष 30 सहायक सामर्थ्यक 31 सहायक 32 प्रवक्त अधिकारी 33 सहायक प्रवक्त अधिकारी 34 हानरी अधिकारी 35 मन्नागीय पुस्तकाध्यक्ष 36 मैट्रन 37 प्रूफ रीडर।

- नोट — (1) वेसिव बरिष्ठ अध्यापक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण विद्यालय के सहायक अध्यापको को सम्मिलित करते हुए अप्रशिक्षित स्नातक, प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड के अध्यापक के पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 तथा नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में अध्ययन उप-निदेशक शिक्षा विभाग को होगी।
- (2) मैट्रिक प्रशिक्षित मैट्रिक, अप्रशिक्षित इन्टर और प्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापको से पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 तथा नियम 15 (1) में निर्दिष्ट शक्तियां, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन, विद्यालय निरीक्षको में (जिना भारसाधक विद्यालय उप-निरीक्षको को सम्मिलित करते हुए) होगी।
- (3) कन्या विद्यालयों के अप्रशिक्षित तथा प्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापको के पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 तथा नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन सहायक निदेशक शिक्षा विभाग (महिला) में निहित होगी।
- (4) कन्या विद्यालयों के मैट्रिक और प्रशिक्षित मैट्रिक ग्रेड के अध्यापको के पदधारको के विषय में भाग 3 तथा नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन विद्यालय उप-निरीक्षका को होगी।
- (5) शिक्षा प्रसार अधिकारियों के पदधारको पर परिनिष्ठा और बिना प्राप्ति प्रभाव के दो से धनपिष वेतन बढ़िया रोक रखने की शक्तियां लगाने की शक्तियां सम्पूर्ण विद्यालय निरीक्षको को होगी।
- अनुसूची 3 में शिक्षा विभाग शीर्षक के अधीन मद 4 को लागू कर देना चाहिये।

- नोट — (1) प्रशिक्षित इन्टर, अप्रशिक्षित स्नातक और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापको के पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 में विनिर्दिष्ट शक्तियां उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन उप-निदेशक, शिक्षा विभाग को होगी।
- (2) मिडिल, प्रशिक्षित मिडिल, मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक और अप्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापको के पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 में निर्दिष्ट, शक्तियां, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन, विद्यालय निरीक्षको में (जिना भारसाधक विद्यालय उप निरीक्षको को सम्मिलित करते हुए) होगी।
- (3) कन्या विद्यालयों में मैट्रिक, प्रशिक्षित मैट्रिक और अप्रशिक्षित इन्टर ग्रेड के अध्यापको के पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 में निर्दिष्ट शक्तियां, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन, सहायक निदेशक शिक्षा विभाग (महिला वर्ग) को होगी।
- (4) कन्या विद्यालयों में मिडिल और प्रशिक्षित मिडिल ग्रेड के अध्यापको के पदधारको के सम्बन्ध में भाग 3 में निर्दिष्ट शक्तियां, उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्ययन, विद्यालय उप निरीक्षको को होगी।

पुरातत्व मन्दिर (राजस्थान ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट)

- 1 कनिष्ठ अनुसंधान सहायक 2 सर्वेक्षक
वन विभाग

1. सीमांकन रेंजर तथा उप-रेंजर, घास प्रक्षेत्र को सम्मिलित करने हुए रेंजिंग 2 उप-रेंजर 3 प्रशिक्षक, कोटा वन विद्यालय 4 गुरग रक्षक 5 हवलदार 6 वनपाल 7 नाकेदार सर्वेक्षक 10 नवशान्ती 11 अमीन 12 ओवरसियर।

गैरेज विभाग

1. ड्राइवर महायक ड्राइवर, मोटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर को सम्मिलित करते हुए 2 फोरमैन 3 बिजलीवाना 4 यांत्रिक 5 फिटर 6 यांत्रिक निरीक्षक

नोट—(1) इन सबो का वर्गीकरण अन्य विभाग के वैसे ही पद धारकों पर लागू होगा।

नोट—(2) (1) यांत्रिक, (2) फिटरों, (3) बिजली वानों, (4) ड्राइवरों को नियुक्त करने और निनिन्दा एवं उनकी वेतन वृद्धियां रोक रखने की शक्तियां लगाने की शक्तियां मुख्य अधीक्षक, मोटर गैरेज जयपुर को होंगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई)

1 महायक क्षेत्र अभियन्ता 2 सहायक 3 प्राक्कलनकार 4 नक्शानवीस, मुख्य नक्शानवीस, वरिष्ठ नक्शानवीस, वनिष्ठ नक्शानवीस और सहायक नक्शानवीस को सम्मिलित करते हुए 5 अनु-रेखक 6 ओवरसीयर 7 सर्वेक्षक वरिष्ठ एवं वनिष्ठ सर्वेक्षक को सम्मिलित करते हुए 8 पर्यवेक्षक 9 आयोजना अभिलेखापाम 10 फॉरो मुद्रक एवं फोरमैन 11 सविस् फोरमैन 12 यांत्रिक फोरमैन 13 प्रशिक्षक 14 मुख्य सकेतकार तथा सकेतकार 15 जिलेदार तथा नायब जिलेदार 16 डिप्टी कलेक्टर 17 यांत्रिक एवं विद्युत ओवरसीयर 18 अनुसंधान सहायक 19 मुख्य प्रयोगशाला सहायक 20 प्रयोगशाला सहायक 21 ओवरसीयर 22 नहर सहसीनदार 23 क्षेत्र सहायक 24 मिट्टी विश्लेषक 25 प्रेक्षक 26 मिस्त्री 27 श्रमिक कल्याण निरीक्षक।

नोट (1) ओवरसीयर के पद के धारकों पर परिनिन्दा और बिना आकलित प्रभाव के दो से अधिक वेतन वृद्धियां रोक रखने की शक्तियां लगाने की शक्तियां समुक्त अधिशामो अभियन्ता, सिंचाई को होंगी।

(2) भाग 3 और नियम 15 (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियां, अपर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई के प्रभाराधीन परिमण्डलों के अधीनस्थ सेवाओं के पदों के सम्बन्ध में, अपर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई को होंगी।

सहायता एवं पुनर्वास विभाग

1 सहसीनदार 2 सहायक ग्राम पुनर्वास अधिकारी 3 श्रृणु निरीक्षक 4 पर्यन्त निरीक्षक 5 नायब सहसीनदार 6 विक्रय निरीक्षक।

समाज कल्याण विभाग

1 सहायक अनुसंधानाधिकारी 2 सहायक प्रचारिकाधिकारी 3 सहायक सांख्यिक अधिकारी 4 फोटोग्राफर एवं कलाकार 5 कल्याण एवं पुनर्वास निरीक्षक 6 सेल निरीक्षक 7 प्रचार सहायक 8 कल्याण कर्मी 9 कल्याण कर्मिणी 10 ओवरसीयर एवं नक्शानवीस 11 प्रचारक 12 बालक 13 मुख्य निरीक्षक 14 वरिष्ठ गृह निर्माण निरीक्षक 15 उद्योग निरीक्षक 16 विद्यालय पर्यवेक्षक 17 गृह निर्माण निरीक्षक 18 ग्रूप निरीक्षक 19 बैद्य 20 कम्पाउण्डर 21 छात्रावास अधीक्षक 22 छात्रावास अधीक्षिका 23 सिलाई शिक्षक 24 बर्डिंगिरी शिक्षक 25 जूता निर्माण निरीक्षक 26 बास एवं वेंट निर्माण शिक्षक 27 वृषि शिक्षक 28 लोहारगिरी शिक्षक 29 बुनियादी प्रशिक्षक (बुनियादी विद्यालय) 30 शिल्प विद्यालय अध्यापक 31 अध्यापक 32 सहायक अधीक्षक 33 महिला कल्याण अधिकारी 34 जिना समाज कल्याण अधिकारी 35 प्रत्येक (क्षेत्र सर्वेक्षण) 36 परिवीक्षा अधिकारी 37 सहायक महिला कल्याण अधिकारी 38 अधीक्षक, परवर्ती सेवा गृह/उद्धारगृह/मिश्रगृह और वृद्ध एवं अशक्तता 39 प्रधानाध्यापक, सर्वोकाइड स्कूल 40 सहक अधीक्षक, परवर्ती सेवा गृह उद्धारगृह/मिश्रगृह/जिना अशक्तता और अनाथालय 41 सहायक परिवीक्षा अधिकारी 42 कल्याण अधिकारी (कारावास) 43 अवपणकर्ता (गृह)।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (अवन एवं सड़क)

1 अभियांत्रिक अधीनस्थ, वरिष्ठ एवं वनिष्ठ 2 प्राक्कलनकार 3 सहायक 4 नक्शानवीस, मुख्य नक्शानवीस, वरिष्ठ नक्शानवीस, वनिष्ठ नक्शानवीस और सहायक नक्शानवीस को सम्मिलित करते हुए 5 फॉरमैन 6 कारखाना पर्यवेक्षक 7 कारखाना फोरमैन 8 जल निरीक्षक 9 मोटर निरीक्षक 10 मोटर पढ़ने वाला 11 प्रयोगशाला सहायक 12 फिल्टर एटेन्डेंट 13 पम्प एटेन्डेंट

14 अनुसूचक 15 उद्याना के निरीक्षक 16 सहायक उद्यान निरीक्षक 17 वानुमी महायक 18 महायक वानुविद 19 सहायक सारियक 20 मिश्री 21 एम्प चालक ¹[22 भौतिक वैज्ञानिक 23 रसायनिक वैज्ञानिक 24 प्रयोगशाला चालक]।

नोट ओवरसिपर के पदधारको पर परिनिन्दा और बिना अवलित प्रभाव के दो स घन-विक बतन बढिया रोक रखन की शास्तिया उगान की शक्तिया सपूवन प्राविशामी अभियन्ता (लाक निर्माण विभाग, भवन एवं सडक) सशक्त हामें।

अभ विभाग

1 निरीक्षक 2 अन्वेषक 3 सारियक सहायक 4 संगणक 5 नक्शानवीम 6 शिक्षक, प्रौढ़ शिक्षा ²[7 महिला दर्जी]।

जेल विभाग

1 जेलर 2 उर जेलर 3 नायब जेलर 4 मुख्य महाप्रहरी 5 सर्टन 6 मुख्य प्रहरी 7 कारखाना मैनेजर 8 सहायक फौज्दी मैनेजर 9 अध्यापक 10 मुख्य कम्पाउण्डर 11 कम्पाउण्डर 12 मुद्रक 13 निरीक्षक जेल एवं बन्दीगृह 14 कम्पाउण्डर 15 नर्स दार्ड ³[16 वार्डर 17 डायर (रगरेज) 18 खानी (कारपेण्टर) 19 लोहार 20 चर्म शिक्षक 21 दर्जी]।

राजस्व, उपनिधेशन, बन्दोबस्त एम भू अभिलेख विभाग

1 नायब तहसीलदार

नोट—इन पदों के धारका के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष अपने अपने जिले के जिनाधीश ⁴[तथा उपनिधेश विभाग में उपनिधेश आयुक्त] हामें।

2 सहायक भू अभिलेख अधिकारी

नोट— इन पदों के धारका के सम्बन्ध में कार्यालय अध्यक्ष निदेशक भू-अभिलेख होगा।

3 बन्दोबस्त विभाग के कार्यालय में निरीक्षक या पडतालक

4 निरीक्षक भू-अभिलेख विभाग

5 मुख्य नक्शानवीम तथा नक्शानवीस

6 सीमा निरीक्षक

7 सदर कानूनगो, सहायक सदर कानूनगो तथा कार्यालय कानूनगो

⁴8 [सदर मुसरिम]

9 महायक कार्यालय कानूनगो 10 वरिष्ठ सीमा निरीक्षक 11 राजस्व लेखा निरीक्षक

12 अनुसूचक 13 फोरमैन 14 तहसीलदार 15 सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (रा त से)

टिप्पणी—तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के पदों को धारण करन वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में “परिनिन्दा तथा बतन बढिया रोक रखने” सम्बन्धी शास्तिया लगाने की शक्तिया सम्बद्ध जिलो जहा कि बहु घटना घटी हो, जिसके सम्बन्ध में शिकायत की गई हो, के क्लेक्टरो की होगी।

रजिस्ट्रेशन एम स्टाम्प विभाग

1 उप रजिस्ट्रार

स्थानीय निकाय निर्वेक्षणालय

1 सहायक प्रादेशिक निरीक्षक

चिकित्सा एम जन स्वास्थ्य विभाग

(क) चिकित्सा एम जन स्वास्थ्य विभाग

1 सहायक अध्यापक, चिकित्सालय 2 सहायक औषध रसायनज्ञ 3 सहायक परिचारिकाए

4 सिस्टर और जूनियर सिस्टर 5 नर्स तथा नर्सदार्ड दार्ड जिनमें मेल नर्स सम्मिलित है 6. कम्पाउण्डर

1 ॥ एफ 3(18) कामिक/क-3/दिनांक 26 11-76 द्वारा जोडे गये।

2 स एफ 3(14) कामिक/क-3/75 दि० 28-1-1976 द्वारा जोडा गया।

3 F 3(1) Per (A III) 75 दि० 10 3-75 द्वारा जोडे गये।

4 स० 3 (9) कामिक/क-3/75 दि० 28 1-1976 द्वारा सशोधित।

7 औपचारिक 8 तबनीशन 9 एक्स र सहायक 10 प्रचार सहायक 11 कलाकार 12 महिला स्वास्थ्य अधिकारी 13 प्रयोगशाला सहायक 14 मिडीया मैनेज 15 स्वास्थ्य निरीक्षक 16 सफाई निरीक्षक 17 मलेरिया सर्वेक्षक 18 स्वास्थ्य वीक्षक 19 टीका लगान वाला 20 मिस्त्री 21 बिजली वाला 22 मिस्टर टयूबर 23 स्टाफ नर्स 24 मिडवाइफ 25 पशु गृहपाल 26 फोटोग्राफर 27 व्यावसायिक रीपारिस्ट 28 प्रतिमान कार 29 व्यायाम शिक्षक 30 मोटर मिस्त्री 31 यूनिट ग्रहणी मन्त्रिय ।

(ख) सवाई भा सिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय

1 कनिष्ठ निदेशक 2 महाप्राध्यापक 3 पुस्तकालय 4 व्यायाम शिक्षक

नोट —सवाई निरीक्षक के पदधारका पर ' परिनिदा और बिना आवलित प्रभाव के दो स अधिक वनन वृद्धियां रोक रखने ' की शास्त्रिया नगान की शक्तिया सपूत जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को हामी ।

'परिवार नियोजन विभाग

1 परिवार नियोजन शिक्षा एवं प्रचार अधिकारी 2 स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्रसार अधिकारी 3 स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक 4 सामाजिक विज्ञान प्रशिक्षक 5 जन स्वास्थ्य नर्स प्रशिक्षक 6 प नि गहरी प्रसार शिक्षक 7 प नि स्वास्थ्य प्रसार शिक्षक 8 परिचर्या मिस्टर 9 स्टाफ नर्स 10 कम्पाउण्डर 11 महिला स्वास्थ्य विनिटर 12 क्षेत्र शिक्षक 13 फोटोग्राफर 14 कलाकार एवं फोटोग्राफर 15 कैमरामैन 16 कम्पोजिटर ग्रेड I (प्रचारयोजक) 17 कम्पोजिटर ग्रेड II 18 ग्राफिक्स मशीन चालक 19 सहायक आफसेट मशीन चालक 20 फोटो कलाकार ग्राफिक्स प्रेस 21 हैबियो आफसेटर 22 डेवनपर 23 कैमरा फोटो कलाकार 24 कलाकार एवं कैमरामैन 25 प्रोजेक्शनिस्ट 26 मैकेनिक थ्रे I 27 मैकेनिक थ्रे II 28 चालक एवं यात्रिकी 29 चालक 30 सहायक परिचारिका हाई 31 प नि स्वा सहायक 32 प नि कल्याण कार्यकर्ता 33 प नि क्षेत्र कार्यकर्ता 34 फोरमैन थ्रे I 35 फोरमैन थ्रे II 36 बिजली वाला 37 54 2

2[टिप्पणी—परिनिदा की शास्त्रि अधिकारित करने घोर मद स 1 स 54 व सम्मुख बताये गये पदधारका के सम्बन्ध में असन्तुष्टी प्रभाव के दो से अधिक वैननवृद्धियां नोकन की शक्तिया सवधित विभाग के कार्यालय प्रध्यक्ष का हामी ।]

जनित एम भू विज्ञान विभाग

1 सर्वेक्षक 2 बिजली वाला 3 सहायक सहायक 4 रसायनिक सहायक 5 ग्रहणक 6 यात्रिक 7 भाकडी पटिटरों की खान व मैनेजर 8 कम्पेसर चालक 9 पूर्वोक्त एवं वक्षक 10 ग्रहण चालक 11 जेनेरेटर चालक 12 चट्टानवरमा चालक 13 वक्षक सहायक 14 रिगमैन 15 सर्वेक्षण कटर 16 अनुसंधान 17 कम्पेसर ड्राइवर 18 वक्षक प्रथम श्रेणी 19 वक्षक द्वितीय श्रेणी 20 सहायक वक्षक 21 खान सर्वेक्षक 22 साम्यिक सहायक 23 सहायक 24 खान फोरमैन प्रथम श्रेणी 25 खान फोरमैन द्वितीय श्रेणी 26 नवशानवीस प्रथम श्रेणी 27 नवशानवीस द्वितीय श्रेणी 28 क्षेत्र सहायक प्रथम श्रेणी 29 क्षेत्र सहायक द्वितीय श्रेणी 30 वरिष्ठ निगरा 31 कनिष्ठ निगरा 32 वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 33 कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 34 करखाने का यात्रिक 35 बरमा यात्रिक 36 फिक्टर द्वितीय श्रेणी 37 जीप टंक एवं ट्रैक्टर ड्राइवर ।

पुलिस विभाग

3[1 निरीक्षक/कम्पनी प्रदेशक 8 पुलिस फोटोग्राफर
2 उपनिरीक्षक S I /मुपरवाइजर 9 फोरमैन साइंस लैबोरेटरी में फोटोग्राफर/ वैज्ञानिक सहायक ।
3 उपनिरीक्षक/प्लाटून आदेशक 10 तकनीकी सहायक
4 सहायक उपनिरीक्षक (A S I) 11 कनिष्ठ तकनीकी सहायक
5 मुख आरक्षी (H C) 12 मैकेनिक
6 आरक्षी (कास्टबिल) 13 प्रयोगशाला सहायक अक्षक
7 चालक (ड्राइवर) 14 प्रयोगशाला एन्डेंट ।

1 वि स 3(11) नि (क 3) 71 दि० 27 3 1973

2 [वि स 3(1) कामिक (क 3) 75 दि० 21 7 75]

3 स 3(12) कामिक/क 3/77/GSR-162 दि० 6 8 77 तख

टिप्पणियाँ—नियम 15(1) में वर्णित शक्तियाँ—

- (1) पद सख्या 2 3 व 8 के लिए—निदेशक राज्य पुलिस बेतार/उप महानिरीक्षक को होगी ।
- (2) पद सख्या 4 5,6 7 के लिए—पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष पदाधिकारी या निदेशक, राज्य पुलिस बेतार को होगी ।
- (3) पद सख्या 12,13,14 के लिए—निदेशक पुलिस फोरसेनिक् प्रयोगशाला का होगी ।
- (4) दण्ड सख्या (1) ; (II) व (III) देने की शक्तियाँ—

पद सख्या 1 के लिए—उपमहानिरीक्षक/निदेशक राज्य पुलिस बेतार में पद सख्या 2,3,8 लिये पुलिस अधीक्षक या समान पदाधिकारी में पद सख्या 9,10,11 के लिये निदेशक, पुलिस फोरसेनिक् साइन्स प्रयोगशाला में तथा पद सख्या 13 [4 के लिए सहायक निदेशक पुलिस फो बि प्रयोगशाला को होगी ।

- (5) पद स 5 को निम्न थोड़ी, बेतनमान आदि में पदावत करने तथा पद स 4,5, 6, 7 को सड स (1) , (II) व (III) देने की शक्तियाँ अपर पुलिस अधीक्षक (Ad.S P) को होगी ।

- (6) पद सख्या 4, 5, 6 व 7 को परिनिष्ठा का दण्ड देने की शक्तियाँ उप अधीक्षक पुलिस/अपर अधीक्षक सहायक कमांडेंट/एजुटेन्ट को होगी ।

- (7) अपर टिप्पणी 2 व 4 में सहायक महानिरीक्षक, कमांडेंट/पाचारन, प्रशिक्षण सख्यान भी सम्मिलित होंगे ।

[अपर पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता रेल्वे एंव पुलिस मुख्यालय) राजस्थान की नियम 23 के अन्तगत पुलिस उपनिरीक्षकों एवं प्लाटुन कमांडरो की अविले निर्णित करने के अधिकार दिये गये हैं ।]¹

जन सम्पर्क निर्देशालय

- 1 फोटोग्राफर 2 डाक रूम सहायक 3 कसाकार 4 यांत्रिक एंव चालक 5 चालक 6 मिस्त्री ।

²अर्थ विज्ञान एवं सांख्यिकी विभाग

- 1 अधीनस्थ साम्यकी सेवा के सदस्य 2 पुस्तकाध्यक्ष 3 मुख्य कसाकार 4 परिष्क कसाकार ³5 फोटोनिथो चालक 6 कनिष्ठ कसाकार 7 मिस्त्री ।

टिप्पणी—विभिन्न विभागों के साथ सबन्ध अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के सदस्यों को साधारण दण्ड देने के अधिकार सम्बन्धित विभागाध्यक्षों में भी निहित होंगे ।

यातायात विभाग

- ⁴[1 सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी] 2 परिवहन निरीक्षक 3 परिवहन उप-निरीक्षक 4 सगैलण निरीक्षक 5 फोरमैन 6 ड्राइवर 7 यन्त्र निरीक्षक ।

1 वि० सं० एफ 1(क)(48) गृह (गृ-1) 77 दि० 25-8 78

2 [वि सं० एफ 3(13) नि क-3/72 दि० 28-1-76]

3 उपराक्त क स 5 को वि स 3(13) नि (क 3) 72 G3R 19 (48) दि० 25-5-76 द्वारा हटा दिया ।

4 वि स एफ 3(9) कार्मिक (क 3) 74 दि० 27-2-75 द्वारा जोड़ा गया ।

विकास विभाग

1. महवारी एव पचायत अधिकारी 2. समाज शिक्षा अधिकारी 3. ओवरसियर
4. ड्रावर 5 महिला आहार प्रसार अधिकारी ।

पचायत विभाग

- 1 पचायत प्रसार अधिकारी, प्रथम श्रेणी
2 पचायत प्रसार अधिकारी, द्वितीय श्रेणी

पर्यटक सुविधायें विभाग

- 1 पर्यटन सहायक 2 बरिष्ठ स्वागतकर्ता 3 ड्राइवर 4 कण्डक्टर ।

चक्रवन्दी विभाग

- 1 सहायक चक्रवन्दी अधिकारी 2 मुन्सरिम 3 निरीक्षक ।

उद्योग विभाग

- 1 जिला उद्योग अधिकारी 2 सूचना अधिकारी (जिला उद्योग अधिकारी के रैंक में)
3 अधीक्षक एव डिजाइनर आर्टिस्ट 4 तकनीकी अधिकारी 5 तकनीकी व्यवस्थापक 6 प्राध्यापक,
चम 7 विश्लेषक, रसायनिक प्रयोगशाला 8 व्यवस्थापक औद्योगिक सम्पदा 9 प्रशिक्षक, बड़ईगिरी
10 आर्थिक अनुसंधानकर्ता 11 सार्वजनिक सहायक 12 सर्वोत्तम अधिकारी 13 डिजाइनर
हस्तशिल्पकला 14 अधीक्षक लवण 15 उद्योग निरीक्षक 16 व्यवस्थापक, औद्योगिक सम्पदा
जयपुर को छोड़ कर 17 निरीक्षण लवण 18 पर्यवेक्षक, कोटि धकन 19 पर्यवेक्षक, चर्म
20 निरीक्षक, हस्तशिल्पकला 21 विद्युत कर्षा प्रशिक्षक 22 होजरी मास्टर 23 ऊन बुनाई
24 रगई मास्टर 25 डिजाइनर, हस्तशिल्पकला विकास केन्द्र 26 फिनिशिंग मास्टर
27 रसायनिक (शोरा) 28 उद्योग विस्तार अधिकारी 29 निरीक्षक बाट और माप
30 नक्शानवीस, शोरा 31 निरीक्षक, कोटि धकन 32 भस्मतकार बाट और माप 33 प्रशिक्षक,
चर्म जूता 34 सहायक निरीक्षक, बाट और माप 35 प्रयोगशाला सहायक 36 मिस्त्री चर्म संस्थान
37 मिस्त्री/पात्रिक रंगरेज एव मुद्रक 38 बुनाई प्रशिक्षक कुटीर उद्योग संस्थान 39 सहायक
बुनाई प्रशिक्षक, कुटीर उद्योग संस्थान 40 दक्ष जुलाहा 41 यात्रिक 42 रंगरेज 43 मिलर
44 प्रशिक्षक, मुद्रा एव बाण 45 प्रशिक्षक, मुद्रा वर्तन निर्माण 46 मिस्त्री 47 ड्राइवर
48 बड़ई ।

टिप्पणी—उद्योग प्रसार अधिकारियों को परिनिन्दा तथा दो से अधिक वेतन वृद्धि रोकने का इण्ड
देने की शक्तिया जिला उद्योग अधिकारी को निहित होगी ।

मूल्यांकन सगठन

- 1 अनुसंधान सहायक 2 अनुसंधानकर्ता 3 गणनाकार ।

अधिकारी प्रशिक्षण विद्यालय

- 1 व्यायाम एव खेल-कूद प्रशिक्षक

राजस्थान नहर मण्डल

- 1 स्टोर अधीक्षक

* अधिमूचना स एफ 3(8) डी ओ पी /ए-III/78, जो एस भार 173 दि० 31 जनवरी, 79
द्वारा जोड़ा गया (राज० राज-पत्र भाग 4 (ग) (I) दि० 8-2-1979 में पृष्ठ 451 पर
प्रकाशित ।

भेड एव ऊन विभाग

1 सहायक जिला भेड तथा ऊन अधिकारी 2 प्रगति सहायक 3 कृषि सहायक 4 अनुसंधान सहायक 5 बिन निरीक्षक 6 प्रशिक्षक (वर्तन/श्रेणीवरसु) 7 पयवशक 8 घोवरमियर 9 नक्शानवीस 10 प्रक्षेत्र सहायक 11 श्रेणीकर्ता 12 पशुपाल सहायक 13 पशुपान 14 यात्रिक 15 चालक 16 ड्राइवर 17 मास्टर वर्तव ।

दुग्धशाला विकास विभाग¹

1 तकनीकी सहायक 2 दुग्धशाला विकास अधिकारी 3 पशुपानन प्रसार अधिकारी 4 कृषि प्रचार अधिकारी 5 सहकारी इन्सपेक्टर ।

अभियोजन विभाग²

1 सहायक जन अभियोक्ता थोली (2)

टिप्पणी—उपरोक्त पदाधिकारियों को परिनिन्दा तथा वेतन वृद्धि रोकने के दण्ड देने के अधिकार सम्बन्धित डिस्टीक्ट मजिस्ट्रेट में निहित हाने ।

2 सहायक जन अभियोक्ता (श्रेणी प्रथम) अभियोजन विभाग के लिए नियम 14 में वर्णित परिनिन्दा तथा वेतनवृद्धि रोकने के दण्ड देने की शक्तिया निदेशक, अभियोजन राजस्थान को प्राप्त की गई है³ ।

आयोजना (गैजेटयर्स) अनुसंधानकर्ता विभाग⁴

1 शोध सहायक (वरिष्ठ) 2 गुप्त सदेशक (डीसाइफरिस्ट) 3 शोध सहायक 4 कनिष्ठ शोध सहायक 5 अनुसंधानकर्ता (फील्ड इन्वेस्टिगेटर) ।

भूमि एवं भवन कर विभाग⁵ 1 विधिक सहायक 2 कनिष्ठ अभियन्ता/अधिदशक 3 वरिष्ठ प्रासपकार 4 निरीक्षक श्रे 2 5 ट्रेसर (रेखाचित्र) 6 वाहन चालक 7 फोरमैन ।

टिप्पणी—क स 2 व 4 के सम्बन्ध में परिनिन्दा, दो वेतन बढ़िया तक बिना सचयी प्रभाव से रोकने, सरकार को किसी कानून या आज्ञा की अवहेलना या लापरवाही से हुई हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन में से बसूली करने के दण्ड देने की शक्तिया 'सहायक निदेशक' में निहित होगी ।

अल्प वयस्क एवं साठरी विभाग⁶

1 प्रचार सहायक 2 ड्राइवर 3 आपरेटर (प्रचालक)

“राजस्थान लोकसेवा आयोग”⁷

1 चालक ।

1 स एफ 3 (15) कामिक/क-3/75 दि 9-1-76 द्वारा जोड़ा गया ।

2 [वि स एफ 3 (12) का (क-3) 76 G S R 41 दि 15-7-76]

3 [वि स एफ 3(4) कामिक/क-3/77 एस ओ 35 दि 5-4-77 द्वारा, जो राजपत्र में दि. 21-4-77 को पृ 29 पर प्रकाशित हुई]

4 एफ 3 (13) कामिक/क-3/76 दि 15-7-76

5 [वि स एफ 3 (14) का (क-3) 76 G S R 46 दि 23-7-76]

6 एफ 3 (6) कामिक/क-3/77 G S R दि 19-5-77

7 एफ 3 (9) कामिक/क-3/77 G S R 119 दि 16-6-77

अनुसूची (3) लिपिक वर्गीय सेवाएं

समस्त विभागों में निम्नलिखित प्रवर्गों के पदधारन करने वाले जैसे :—

1. जिला राजस्व लेखाकार और सहजीव राजस्व लेखाकार 2. ग्रहलमद, वरिष्ठ, कनिष्ठ अथवा सहायक ग्रहलमद 3. लेखालिपिक और कनिष्ठ लेखा लिपिक 4. लेखा संकलनकर्ता 5. सहायक विमले राजस्व सहायक, न्यायिक सहायक, स्थापना सहायक, विविध सहायक एवं आयोजना सहायक सम्मिलित हैं 6. अवेधा, चिट्ठियात लिपिक 7. अवेधा लिपिक 8. सभागीय अवेधक को सम्मिलित करने हुए अवेधक 9. विम लिपिक 10. विष्दी लिपिक 11. जिल्दसाज 12. गजान्ची एवं सहायक गजान्ची 13. लिपिक जिममें दोबानो लिपिक, फौजदारी लिपिक, विविध लिपिक, धपोल लिपिक, निगानी लिपिक, अयेजी लिपिक सम्मिलित हैं। 14. गणना यंत्र चालक 15. शिबिर लिपिक 16. सूचीकार 17. संकलनकर्ता जिममें निदेशक जिला एजेंटियम के मुख्य संकलनकर्ता भी सम्मिलित हैं 18. ग्रंथ लिपिक 19. नकलनवीस 20. कोर नोयि लिपिक 21. पटल लिपिक 22. डाक लिपिक 23. प्रेषण लिपिक 24. डाकरी लिपिक 25. मन्त्र लिपिक 26. स्थापना लिपिक 27. आवाकारी लिपिक 28. प्रक्षेत्र लिपिक 29. विलोपिन 30. क्षेत्र सहायक 31. सैन्य लिपिक 32. फौज लिपिक 33. गजधर 34. राज-यंत्र लिपिक 35. मुख्य लिपिक 36. जनगणना विभाग में निरीक्षक 37. सुक्रिया निरीक्षक, बुंगी एवं आवाकारी विभाग के उप-निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक 38. उपकरण लिपिक 39. कनिष्ठ लिपिक 40. खाता जमाखर्ची लिपिक 41. अभिलेख लिपिक 42. नदान एवं प्रेदण लिपिक 43. कार्यालयों के पुस्तकाध्यक्ष या पुस्तकालय लिपिक 44. अनुसूची (1) या (2) में वर्णित पुस्तकालयों के अतिरिक्त पुस्तकालयों के पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, शाखा पुस्तकाध्यक्ष, सदर्थ पुस्तकाध्यक्ष 45. छुट्टी आरक्षित लिपिक 46. सदर मुसरिम को सम्मिलित करने हुए मुसरिम 47. मुशी एवं मुख्य मुशी 48. मोहूरर 49. मुकद्दम 50. नावेदार 51. ताजिर 52. कागज विशेषज्ञ, सहकारी विभाग का 53. पासव लिपिक 54. पटवारी 55. बेतन लिपिक 56. पेंशन लिपिक 57. विभागाध्यक्षों अथवा कार्यालयाध्यक्षों के निजी सहायक जो विभाग के स्वयं से सवधित नहीं हैं।

नोट:—मद 57 के पद धारकों के सवध में कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होगा।

58. पेशकार और कनिष्ठ अथवा सहायक पेशकार 59. याचिका लिपिक 60. दूकरीहर 61. जनसम्पर्क निदेशावय में निम्नलिखित पद — जाच अधिकारी समाचार सम्पादक, समाचार सहायक, पत्रकार, संवीक्षक, उत्पादन अधिकारी, व्याख्याता 62. पेशकार एवं मुख्य पेशकार 63. प्राप्ति लिपिक 64. अभिलेखपाल सहायक अभिलेखपाल तथा अभिलेख लिपिक 65. प्रत्यक्ष लिपिक 66. रोजनामचा लिपिक 67. शाखा प्रभारी और शाखा लिपिक 68. वरिष्ठ लिपिक जिसमें जागीर विभाग के निरीक्षक सम्मिलित हैं 69. लेखन सामग्री लिपिक 70. मासिकी लिपिक 71. प्राधु लिपिक 72. माल पढतालिया 73. मण्डारी तथा सहायक मण्डारी 74. उपमभाग लिपिक 75. अधीक्षक महा अधीक्षक, अनुभाग अधीक्षक, जिसमें कार्यालय अधीक्षक एवं पञ्जीयक मंगनीगम बांगड इजीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर सम्मिलित हैं। 76. पर्यवेक्षकगण 77. बारखीकार 78. समय-पान और सहायक समयपाल 79. कार्यालयों के अनुवादक 80. यात्राध्यय लिपिक 81. कार्यालयों के कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष तथा कनिष्ठ कोषाध्यक्ष 82. टक्ककर्ता 83. भत्ता लिपिक 84

वैद्यक 85 ग्राम सेवक 86 मुहाफिजान 87 उप पजीयक, विभागीय परीक्षाएँ लापित 88 टिन्ट
वायू एवं कण्डक्टर, राजकीय परिवहन सेवा, सिरौही 89 देव यान विभाग के मैनेजर प्रथम तथा
द्वितीय थ्रेणो *90 दारोगा, प्रथम तथा द्वितीय थ्रेणो 91 ओहदेदार, प्रथम तथा द्वितीय थ्रेणो
92 महन्त, प्रथम तथा द्वितीय थ्रेणो 93 मुखिया, प्रथम तथा द्वितीय थ्रेणो 94 पुजाी प्रथम
तथा द्वितीय थ्रेणो 95 गोस्वामी प्रथम तथा द्वितीय थ्रेणो 96 महायक म।दक 97 मवाददाना
98 बरिष्ट प्रूफरीडर 99 निदेशक, कृषि विभाग व निजी सहायक 100 भण्डार पयवक्षक 101
खेन-कूद पर्यवेक्षक एवं सहायक 102 पयवक्षिका 103 महिला दर्जी 104 निरीक्षक, भण्डार एवं
लेखा 105 अमीन 106 टेलीफोन चालक 107 चकबन्दी विभाग के मर्र्छक 108 मार्गदर्शक
109, कनिष्ठ स्वामश्वर्त्ता 110 कारिदा 111 सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा प्रायोग
कार्यालयों के शाखा अधिकारी 112 लखा निरीक्षक 113 अभिलेख सहायक 114 अग्नेयक
115 रिकार्ड अटेंडेंट 116 छटाईकर्त्ता 117 परिरक्षण सहायक 118 प्रयोगशाला सहायक
119 मुख्य अनुवादक सचिवालय 120 लोक निर्माण (भवन एवं सडक) विभाग में प्रशासन
सहायक 121 भेड ऊन कार्यालय में मास्टर क्लर्क 122 प्रशासनिक सहायक 123 मुख्य अनुवादक
124 सहायक मुख्य अनुवादक 125 साक्षर अटेंडेंट + 126 देखभालकर्त्ता ।

*91 से 96 देवस्थान विभाग के पद हैं ।

+ [दि. 16.10.78 को जोड़ा गया]

अनुसूची (4) चतुर्थ श्रेणी सेवाएं

अनुसूची—(3)

गमल विभागों में निम्न लिखित श्रेणियों के पदधारण करने वाले, जैसे—

- 1 शिल्पकार (लोहार, बढई, मलवाईगर, खगदी, रगमाज आदि) 2 अटेंडेंट जिसमें गैलेरी प्रोटेक्टर, वाई अटेंडेंट, असमल अटेंडेंट रिपेयर अटेंडेंट, मज स्टेशन अटेंडेंट सम्मिलित है 3 नाई 4 मारकदार 5 मिस्त्री 6 जिल्दमाज तथा सहायक जिल्दमाज 7 चोहरिया 8 बाग जिसमें गार्डनी बाग, टेनीफोन बाग व हं बाग, पैट्रोल बाग सम्मिलित हैं 9 बडल उठाने वाला 10 बर्तनगर 11 गाड़ीवान 12 गाड़ी चालक 13 चकालिया 14 चौकीदार 15 करीबी 16 सिनेमा कमचारी 17 क्लीनर 18 मसाइया 19 कुत्ता 20, डफेंदार 21 दफतरी 22 दाई या मिड बाइफ 23 डक ले जाने वाला 24 ड्रैसर 25 फर्राज 26 फिल्टर चालक 27 माली (हाली, माली, चौकी आदि) 28 गैंगमैन और गैंगमन 29 गेट पास चेंजर 30, द्वारगल एव गेट सार्जेंट 31 पहरेदार जिसमें कोप रक्षक वन रक्षक, आयेट रक्षक तथा रिजर्व रक्षक सम्मिलित हैं 32 हरकारा 33 मददगार 34 हाथपाक 35 जमादार 36 कावडिया 37 खलासी 38 श्रमिक जिसमें स्थायी श्रमिक तथा कृशल श्रमिक सम्मिलित हैं 39 निश्चयन 40 लाइन बेलदार 41 गेट एव हैटमेट 42 गोपित 43 भोजिया 44 निगरा और निगरानेदार जिसमें सहायक निगरा तथा निगरानेदार सम्मिलित हैं 45 प्रद्वनी 46 वेष्टक 47 पैदल 48 प्रहरी 49 चपरासी 50 बस्ताबरदार 51 गण जमादार 52 शहना 53 शिकारी 54 सवार जस साईक्ल सवार ऊट सवार, सुतर मवार, पुष्ट मवार डाक सवार 55 मेहनत 56 सईस 57 दर्जी 58 टर्नकी एव सहायक टर्नक 59 प्रहरी 60 वाइमेट 61 घोली 62 जनचारी 63 किसान 64 परवाहा 65 चील 66 मूर्ता 67 भण्डारी 68 बटर 69 मशालची 70 कोठारी 71 स्टीवड या खानसामा 72 बाबदार 73 शकरची 74 धकर 75 बरा 76 बलदार 77 बागतर अटेंडेंट 78 भोजित 79 धन रक्षक 80 बापीगा 81 लापित 82 पहरायती 83 सरवण 84 टिनमैन 85 गोपित 8 कोठार सेवक 8 गद्दी बनाने वाला 88 मोची 89, गोपित 90 लक्षर 91 मवाई पयबधक 92 सिनेमा चालक 93 नटर ड्योडी 94 नाडर लिहवी 95 दरवान 96 हजारी 97 नेबगन 98 भण्डार वर्मचारी 99 गाडी निर्माता 100 माचानर 101, बल्लेमाइनर 102 कलईसाज 103, वेंटरिमैन 104 मोची 105 रगमाज * [106 कोष्ठाधी 107 भण्डारी 108 राखडिया 109 तोपखानी 110 अभिषेकी 111 वारभोगी 112 शुभचिन्तक 113 रसोड्या 114 टहलवा 115 भापटिया 116 बीर्ननिया 117 चोबलर 118 हरकारा 119, पोशाकी 120 जनधडिया 121 धवधाता 122 कर वसूल करने वाला 123 सहायक भण्डारी 124 वनपान 125 प्रयोत्र सेवक 126 मुख्य हनवाला 127 हनवाला 128 मशवा 129 हैडमैन (देवागा) 130 घोली 131 आदेशिका वाहक 132 गोपित 133 गोपित 134 महायक बुनाई मास्टर, पगिसज्जक, मृत बुनाई सहायक बॉयनगर्भन 135 चमडेवाला 136 सुलाग 137 प्रोजेक्ट वालक 138 गैर रीडर 139 प्रयोगशाला सहायक (गिशा विभाग) 140 प्रयोगशाला सेवक (गिशा विभाग) 141 लोहार 142 गोपित 143 मगदी 144 बाबावाला 145 मारगिवा

* 106 से 120 तथा 144 से 155 वेकेशन विभाग के पद हैं ।

146 पखावजिया 147 बाडदार 148 भुविया 149 पुजारी 150 भीतरिया 151 भापटिया
 152 देश का पोशवान 153 नयारची 154 प्रचारक 155 शहनायची] 156 साह परिचारक
 157 खाला तथा हल्ली 158 सहायक गेसमैन 159 मेनुअल सहायक 160 मानचित्र पाठ
 161 फौरोमैन 162 डिजल बॉय 163 भारिक 164 लश्कर 165 प्रयोगशाला बॉय 166 मडर
 (मरम्मत करने वाला) 167 नौकापाल 168 एलममैन 169 की मैन 170 वाट कीपर 171
 बाइलर मैन ★ 172 वॉच एण्ड वार्ड स ।

* अधिसूचना स एफ 3 (10) कार्मिक/ए-111/78, जो एस. आर 174 दि 31 जनवरी, 1979 द्वारा जोड़ा गया, (राज राज-पत्र भाग 4 (ग) (1) दि 8-2-1979 म पृष्ठ 452 पर प्रकाशित ।

परिशिष्ट—क

विभागीय जाचों के लिये आदेश प्रपत्र

प्रपत्र स 1

[नियम 13 (1) (क) के अन्तर्गत निलम्बन आज्ञा]

राजस्थान सरकार

विभाग

भाज्ञा

क्रमांक

दिनांक

चू कि

[राज्य कमचारी का नाम तथा पद]

के विरुद्ध एक अनुशासन कार्यवाही करने का विचार है/चल रही है

2 अतः अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवाएँ (बर्गीकरण नियमण और अपील) नियम के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद।

प्रतिलिपि श्री

— (निलम्बित कमचारी का नाम तथा पद)

को प्रेषित। निलम्बन की अवधि में उनको वेप निर्वाह भत्ते के विषय में पृथक आदेश जारी किया जायेगा।

अनुशासन प्राधिकारी।

प्रपत्र स० 2

[नियम 13 (1) (ख) के अन्तर्गत निलम्बन आज्ञा]

राजस्थान सरकार

विभाग

भाज्ञा

क्रमांक

दिनांक

चू कि श्री

— (राज्य कमचारी का नाम तथा पद)

के विरुद्ध फौजदारी दोषारोपण के विषय में मामला प्रन्वेपण/विचारण हो रहा है।

अतः, अब राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता राजस्थान सिविल सेवाएँ (बर्गीकरण नियमण और अपील) नियम, के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कथित श्री को तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हैं।

अनुशासन प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं पद।

पृष्ठांकन ऊपर लिखे अनुसार

* निम्नवत वापिस लेने के कारण निम्नलिखित है :—

प्रतः प्रय राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा कथित निम्नवत आदेश को तत्कालिक प्रभाव से वापिस लेते हैं।

हस्ताक्षर.....

* यही संक्षेप में कारण लिखिए।

प्रतिलिपि श्री..... (निलम्बित अधिकारी का नाम तथा पद) को प्रेषित।

अनुशासन प्राधिकारी

प्रपत्र संख्या 7

[नियम 16 (4) के अन्तर्गत जाच अधिकारी की नियुक्ति]

राजस्थान सरकार

..... विभाग

आज्ञा

क्रमांक.....

दिनांक.....

चूं कि राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और मपील) नियम, 1958 नियम 16 के अन्तर्गत जाच थी.....के विरुद्ध की जा रही है।

(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

2. और चूं कि राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता का विचार है कि उसके विरुद्ध आरोपित आरोपो की जाच करने के लिए एक जाच अधिकारी/जाच मण्डल नियुक्ति किया जाना चाहिये।

3. अतः, अब, राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा श्री.....
...../सर्वे श्री.....

का (जाच अधिकारी/जाच मण्डल के सदस्यगणों के नाम तथा पद) को जाच अधिकारी/जाच मण्डल कथित श्री..... के विरुद्ध आरोपो की जाच करने के लिए नियुक्त करते हैं/करता है।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:—

1. श्री.....

(जाच अधिकारी का नाम तथा पद)

2. श्री.....

(राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद)

3. अन्य सम्बन्धित, यदि कोई हो।

प्रश्न सं० 8

[नियम 18 के अन्तर्गत जांच अधिकारी की नियुक्ति]

राजस्थान सरकार

.....विभाग

क्रमांक.....

दिनांक.....

वृत्ति सर्व श्री (कर्मचारियों के नाम एवं पद) के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और प्रवीण) नियम, 1958 के अन्तर्गत जांच की गयी है।

2. और वृत्ति राज्यपाल/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विचार में उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये।

3. अतः, अब, राज्यपाल निम्न/हस्ताक्षरकर्ता, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियन्त्रण और प्रवीण) नियम, 1958 के नियम 18 के अन्तर्गत श्री (जांच अधिकारी का नाम तथा पद) को उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों की संयुक्त जांच करने के लिए नियुक्त करते हैं/करता है। कार्यवाही में कथित नियमों के नियम 16 द्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जावे।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि प्रेषित है :—

1. श्री को
(जांच अधिकारी का नाम तथा पद)
2. श्री को
(राज्य कर्मचारियों के नाम तथा पद)
3. अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को, यदि कोई हो।

प्रश्न सं० 9

(दिल्ले जांच अधिकारी के स्थान पर नए जांच अधिकारी की नियुक्ति)

राजस्थान सरकार

.....विभाग

आज्ञा

क्रमांक.....

दिनांक.....

आज्ञा/आज्ञाओं क्रमांक..... दिनांक.....

के मिनसिले में राज्यपाल प्रसन्न होकर/निम्न हस्ताक्षरकर्ता श्री (नाम एवं पद) को में सम्बन्धित मामलों/मामलों की जांच करने के लिए जांच प्राधिकारी नियुक्ति करते हैं/करता है, जो गतकालिक जांच प्राधिकारी श्री द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था।

कोई अभिवेदन करें तो उस पर, प्रस्तावित कायवाही करने से पूर्व, उनके द्वारा विचार किया जायगा ऐसा अभिवेदन, यदि कोई हो तो लिखित में हो और आप द्वारा इस पत्र की प्राप्ति से पन्द्रह दिन में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को मिल जाना चाहिये।

3 इस पत्र की पट्टी च भेजें।

अनुशासन प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

प्रपत्र 13

(देलिए नियम 16 (12))

राजस्थान सरकार

विभाग

लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अंतिम आदेश

सं०

दिनांक

श्री

(नाम तथा पद) के विरुद्ध कतिपय आग्र वा के आधार पर

निम्न लिखित आज बनाए गए थे।

नामाथ —

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन उक्त अभियोगों की समुचित जांच के पश्चात्, राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, राज्यपाल महोदय ने तदनुसार निश्चय किया है कि आपको (यह शास्ति लिखिए) से दण्डित किया जावे।

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र की प्रति (जिसमें उन्होंने अपनी सम्मति मिली है, आपके सूचनाथ चलाने है।

श्री

को निवेदन है कि यह इस पत्र की पट्टी च भेजें।

अनुशासन प्राधिकारी

प्रपत्र 14

[भारतीय दण्ड विधान एवं अष्टाचार विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी पर फौजदारी मुकदमा चलाने की स्वीकृति]

को कृत्य करने हुए थी

का साजिश में गकड

(नाम तथा पद)

बहिन (बेहनुम) में गलत तथा फर्जी प्रविष्टियाँ द्वारा विभिन्न अनुरागियों को विभिन्न व्यक्तियों तथा
संस्थाओं के नाम वितरण करना दर्शाया जो वास्तव में वितरित नहीं की गई थी एवं कुल धनगांश
२० जो इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं को फर्जी वितरित की जाना बताई गई वह
नविक अधिकारी द्वारा अपराधिन अपहरण (दुरुपयोग) की गई और कतिपय व्यय थी न
भी गलत प्रमाणित किये हैं और

2. कि राजस्थान सरकार/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के यह भी ध्यान में लाया गया है कि
एसे " जो श्री स्टेट बैंक आफ इंडिया से दिनांक " को प्राप्त किये वे न तो
रोक नहीं में जमा हैं न उनका सही व्यक्ति को भ्रष्टाचार पद मुक्त करन वाल अधिकारी को भुगतान
हो किया गया है और इस राजि का भी कथित अधिकारियों ने अपहरण किया हैं और

3. कि अभिलेख के आन्वीकन से तथा मामले के सब तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार
करने के पश्चात्, सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्ता को तसल्ली हो गई कि कथित श्री " और
श्री " ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा के साथ पटित भारतीय
दण्ड विधान की धारा के अंतर्गत अपराध किये हैं और ।

4. इसलिये, अब आता फौजदारी की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी
अधिनियम की धारा का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार/निम्न हस्ताक्षर कर्ता
एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान करने हैं कि श्री " के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान
की धारा तथा भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा " में भारतीय दण्ड
विधान की धारा का पठ्य करने हुए एवं सक्षम क्षत्राधिकार रखन वाली न्यायानय
में कोई अन्य अपराध बने तो उसके अंतर्गत फौजदारी मुकदमा चलाया जाव ।

अनुशासन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद

मुखर

दिनांक

दिनांक

प्रतिनिर्दिष्ट समस्त सम्बन्धिता का सिवाय उन राजकीय कर्मचारियों के जो इस मामले में
सम्बन्धित हो ।

प्रपत्र सं 15

(अपील/नज़रतानी के मामलों के लिए प्रपत्र)

अपिपति

श्री मचिद,

राजस्थान लोक सेवा आयोग धनपुर ।

1. राज्य कर्मचारी का नाम

2. शांति सं पृष्ठ पद

- 3 शास्ति के बाद का पद
- 4 आया यह प्रथम अपील है या द्वितीय अथवा रिवाजन या रिज्यू
- 5 अनुशासनिक प्राधिकारी
- 6 अपील प्राधिकारी
- 7 शास्ति की तारीख
- 8 दिनांक जिस दिन अपील/रिज्यू/रिवीजन प्रस्तुत की गई।

9 (क) यह प्रमाणित किया जाता है कि (प्राधिकारी का पद) ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के अधीन नियमित विभागीय जाच का आदेश दिया था और उक्त प्राधिकारी ऐसा आदेश देने और नियम 16 (4) के अंतर्गत जाच अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम था। नियमित विभागीय जाच का आदेश फाइल स में पृष्ठ पर है।

(ख) सक्षम प्राधिकारी के आदेशाधीन जाच और भाग्यो का विवरण दोषी अधिकारी/कर्मचारी पर तामील कराए गए और ये फाइल स में पृष्ठ पर उपलब्ध हैं।

(ग) राज्य कर्मचारी को आवेदित सरकारी रेकाड का निरीक्षण करने तथा उनसे उद्धरण लेने की अनुमति दी गई थी जिसका निम्नलिखित दस्तावेज के जिनके कारण निम्नलिखित है -

(घ) जाच अधिकारी प्रारम्भिक जाच करने वाले से भिन्न व्यक्ति था।

(ङ) अधिकारी/कर्मचारी का लिखित प्रतिवेदन उसको तैयार करने हेतु पर्याप्त और समुचित समय दिये जाने के बाद यथोचित प्राप्त हो गई, और फाइल स के पृष्ठ पर है। उक्तकी उपस्थिति में लिए गए गवाहों के बयान फाईल स में पृष्ठ पर है। जाच अधिकारी ने अधिकारी/कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया।

(च) अधिकारी/कर्मचारी का तथा उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के गवाहों के बयान फाइल स में पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। जाच अधिकारी की रिपोर्ट फाइल स में पृष्ठ पर उपलब्ध है।

(छ) राज्य कर्मचारी पर दण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किया गया और जारी किया गया आदेश राज्य कर्मचारी को भेज दिया गया।

(ज) अपील/रिवीजन भयाद के भीतर है, अथवा यदि भयाद बाहर है तो विनम्ब राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 25 के अधीन आदेश दिनांक पृष्ठ द्वारा समा कर दिया गया है।

जब कठोर शास्ति अधिरोपित की गई हो तो पूरक बिन्दु

(1) जाच अधिकारी के रिपोर्ट की प्रति अनुशासनिक प्राधिकारी की टिप्पणी सहित, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम के नियम 16 (10) (ग) के कारण बताओ नोटिस के साथ सविधान के अनुच्छेद 311 (2) की प्रपक्षानुसार, राज्य को दिए जा चुके हैं जो फाइल स में पृष्ठ पर है।

(2) जब कि यनुशासनिक अधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत था, तो असहमति के कारण भरोसे में सूचित कर दिए थे, फाइल स - शृङ्खला..... ।

विधि :

(क) राज्य कर्मचारी को सूचित कर दिया गया है कि उसकी सेवा के पिछला रिकार्ड पर जो उसके पत्र में नहीं है, सजा भी माया तय करने लिए, विचार किया जाएगा ।

(ख) राज्य कर्मचारी के ऐसे कृत्यों या कमियों के लिए जो चार्ज-शीट में उल्लिखित नहीं हैं कोई शक्ति नहीं दी गई है ।

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित रिकार्ड एकत्रित कर लिया गया है और संबंधित मामलों में फाइलें तैयार करवाके, समस्त सारभूत कागजात, अपील/रिक्ल्यू/रिवीजन के प्रार्यता-पत्र के साथ राजस्वपान ग्रेव सेवा आयोग को सम्मति हेतु भेजे जा रहे हैं ।

परिशिष्ट—ख

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया
(गवाहों का ब्राह्मण तथा प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण)

अधिनियम, 1959¹

(अधिनियम क्रमांक 28, मग 1959 का)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 24 मई, 1959 को प्राप्त हुई)

एक

अधिनियम

राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित मावजनिक सेवाओं तथा पदा पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में गवाहों की उपस्थिति बाध्य करने एवं प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान निर्मित करने हेतु ।

राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा गणराज्य के दसवें वर्ष में निम्न रूपेण अधिनियमित किया जाता है ।

1 सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ — (1) यह अधिनियम राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया (गवाहों का ब्राह्मण तथा प्रलेखों का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, 1959 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रभाव में आयेगा ।

2 अधिनियम का लागू होना — यह अधिनियम राजस्थान राज्य के कार्यों से सम्बन्धित मावजनिक सेवाओं तथा पदा पर नियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त विभागीय जाचों पर लागू होगा ।

3 परिभाषायें — इस अधिनियम में, जब तक कि प्रमग तथा विषय द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "विभागीय जाच" स अधिप्राय उन जाच से है जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न बधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बताये गये किसी कानून अथवा नियमों के अथवा अनुच्छेद 313 के अन्तर्गत जारी किए गये किसी नियमों के अन्तर्गत या उनके अनुसार की गई हो, और

(ख) "जाच प्राधिकारी" से तात्पर्य उस पदाधिकारी अथवा प्राधिकारी से है जो किसी व्यक्ति के अन्वेषण की विभागीय जाच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो और इसमें वह पदाधिकारी या प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं जिसे जाच करने का अधिकार किसी और प्रकार से हो ।

4. गवाहों की उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की जांच प्राधिकारी की शक्तियाँ—(1) जांच प्राधिकारी को गवाहों को ग्राह्वान करने, एवं उनकी उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा प्रलेखों का प्रस्तुत करने के लिए विवश करने का वह समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो किसी वाद को सुनवाई करते समय, जाय्ता दीवानी, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम पंचम सन 1908) के अन्तर्गत किसी दिवानी न्यायालय की अधिकृत है।

(2) ऐसे जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये गवाहों की उपस्थिति के लिए भयवा प्रेषों को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने के सब आदेश-पत्रों की तामील उस सब न्यायाधीश के माध्यम से होगी जिसके क्षेत्राधिकार में गवाह भयवा कोई अन्य व्यक्ति जिस पर आदेश-पत्र तामील होनी है, निर्दोष करता है।

5. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियाश्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

परिशिष्ट-ग

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया

(गवाहा का आव्हान एवं प्रलेखा का प्रस्तुतिकरण)

नियम, 1960¹

राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया (गवाहा का आव्हान एवं प्रलेखा का प्रस्तुतिकरण) अधिनियम, 1959 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा —

नियम

1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ —(1) ये नियम राजस्थान अनुशासनात्मक कार्यवाहिया (गवाहा का आव्हान एवं प्रलेखा का प्रस्तुतिकरण) नियम, 1960 कहलायेंगे।

(2) ये नियम तुरन्त प्रभाव में आयेंगे।

2 सम्मन एवं आदेश-पत्र —(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी गवाही में जांच प्राधिकारी किसी पक्ष को आदेश दे सकता है कि वह सम्मन के छोड़कर प्रपत्र या प्रतीतो में देश-नागरी लिपि में, सिवाय उपस्थिति पेशी का दिनांक/तथा सम्मन/नोटिस (सूचना पत्र) के जारी होने के दिन के विषयों को पूरी तरह भर कर उन गवाहों पर सामीप्य कराने के लिए प्रस्तुत करे जिनका वह अपने पक्ष में माध्यम पेश करना चाहता है।

(2) सम्मन एवं सूचना पत्रों में उपस्थिति/पेशी का दिनांक एवं जारी होने का दिनांक जांच प्राधिकारी के कार्यालय में भरे आयेंगे तथा जांच प्राधिकारी अथवा उसका कार्यालय अधीक्षक अथवा निजी सहायक अथवा कमचारी वगैरह का कोई अन्य सदस्य जिसको ऐसा प्राधिकार प्रत्यापुक्त किया गया हो, सम्मन/सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करेगा एवं हस्ताक्षर करने का दिनांक भी अंकित करेगा।

(3) प्रपत्र तब तक स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे बड़े स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य अक्षरों में नहीं भरे गए हों। वह पक्ष उस प्रपत्र पर नीचे के बाएँ हाथ के कोने पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस प्रपत्र में प्रविष्टित वस्तु की सत्यता का उतरदायी होगा।

(4) जांच प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक आदेश-पत्र या आज्ञा में, जारी करने वाले या देने वाले अधिकारी का नाम सबसे ऊपर स्पष्ट अक्षरों में लिखा जायेगा।

सब दशाओं में जांच प्राधिकारी या उसका कार्यालय अधीक्षक, या निजी सहायक या उपरोक्त नियम 2 (2) में निर्दिष्ट कर्मचारी वर्ग का अन्य सदस्य अपने नाम के हस्ताक्षर साफ साफ एवं पढ़ने योग्य अक्षरों में करेगा। ऐसा कोई हस्ताक्षर मुद्रा (स्टाम्प) द्वारा नहीं किया जायेगा।

(5) प्रपत्र अथवा आदेश-पत्र, आवश्यक परिवर्तनों तथा संशोधनों सहित वही होगा जो राजस्थान के दीवानी यायालयों के लिए सामान्य नियम (सिविल) 1952 के अन्तर्गत निर्धारित है।

(6) आदेश-पत्र जारी करने से पूर्व जारी करने वाला अधिकारी इस बात की तसल्ली करा कि जिस व्यक्ति को आदेश-पत्र भेजना हो अथवा जिस व्यक्ति के विषय में अथवा जिस सम्पत्ति के विषय में यह जारी किया जा रहा है उसके वर्णन की प्रविष्टियाँ ऐसी हैं जिनमें तामील हुक्म को ऐसे व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को पहिचानने में गति करने का खतरा नहीं रहे। आदेश तब नाम पितृ का नाम, व्यवसाय, जिला, मोहल्ला (यदि कोई हो) ग्राम या नगर दर्ज किये जायेंगे। जब कि आज अधिकारी को निवेदन करने वाले व्यक्ति के आवेदन-पत्र में इस प्रकार का सुनिश्चय दृष्टा नहीं हो तो, जारी करने वाले अधिकारी को तुरन्त आज अधिकारी की आज्ञा पालन करनी चाहिए।

(7) जब कोई सम्पत्ति किसी सैनिक, नाविक, वायु सैनिक अथवा मावजनिन कर्मचारी को दी किया जाना हो तो यथा सम्भव गवाही के आश्रय नया प्रलेखो हस्त, मावा-नियम (सिविल) 152 के अध्याय 3 में दिये गये प्रावधानों का उपयोग किया जावेगा।

(8) साधारणतया सम्पत्ति आदेश-पत्र तामील हेतु उस जिला एवं सत्र व्यापारी के मालिक में भेजे जावेग जिसका उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार है जिसमें उक्त गवाह निवास करता हो या जिसके मरहम से प्रलेख प्रस्तुत कर्नाता हो।

(एफ 23 (93) ए/58/प्र.प तृतीय दिनांक 21-10-1960)

1 'प्रथम अंश टी टकर नायक' के हवाज पर, निर्वाचित (ग-तृतीय) विभाग के प्रमाण एफ 23 (93) ए/58 प्र.प तृतीय दिनांक 15 दन 1961 द्वारा लिखा गया।

राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971

बी एम प्रा. 29—भारतीय मंत्रिपरिषद् 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, प्रमन्न होकर एम.डी. द्वारा राजस्थान राज्य में और वनके कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित राज्य कर्मचारियों के आचरण को नियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रयोग—

(1) ये नियम राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त लागू होंगे।

(3) जब तक इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित नहीं किया गया हो, वे ऐसे व्यक्तियों पर लागू होंगे जो कि राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त हों।

परन्तु शर्त यह है कि जब कोई राज्य कर्मचारी किसी अन्य राज्य-सरकार या केन्द्रीय-सरकार में प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) पर रखा गया हो तो वह प्रतिनियुक्ति की अवधि में, इन नियमों के प्रावधान (exclusion) में उधार लेने वाली सरकार के आचरण नियमों द्वारा उस सीमा तक शासित होगा।

परन्तु आगे शर्त यह है कि राज्यपाल यात्री साधारण या विशिष्ट आज्ञा द्वारा ऐसे राज्य कर्मचारियों को जो किसी विशेष वर्गीकरण के हों, जो इन नियमों से पूर्णतः या आंशिक रूप में भाग्य होने से मुक्त कर सकेंगे।

परन्तु और शर्त यह भी है कि उन नियमों का कोई अंश उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि अखिल भारतीय सेवानो के सदस्य हैं और जो अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 के अधीनस्थ हैं।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(अ) 'नियुक्ति-अधिकारी' से अभिप्राय वही होगा जो कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अधीन) नियम, 1958 में दिया गया है :

(आ) "सरकार" से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।

(इ) "सरकार कर्मचारी" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो कि राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त हो, और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल होगा जिसकी सेवाएं अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति पर उधार ली गई हों।

(ई) "परिवार के सदस्य" में सरकारी-कर्मचारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

1. [राजस्थान सरकार के कार्यात्मक विभाग (ग्रुप II-III) की विनियमि ४० एफ. 4

(3) कानून (III-II)/65 दि. 4 अक्टूबर 1972 द्वारा राजस्थान राज पत्र भाषा-4 III (1) आचारण दि. 18-8-1972 में प्रकाशित।]

(1) कर्मचारी की पत्नि या पति, यथा स्थिति, चाहे वह कर्मचारी के साथ निवास करता/करती हो या नहीं, लेकिन ऐसी पत्नी या पति, जैसा भी हो, शामिल नहीं होंगे जो किसी डिप्टी या स्टेशन-मैजिस्ट्रेट की डिप्टी या अज्ञात द्वारा सरकारी कर्मचारी से जुड़ा कर दिया गया/दी गई हो।

(2) कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री, जो कि कर्मचारी पर प्राप्त आश्रित हो, लेकिन ऐसा बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं होगा जो अब किसी प्रकार भी सरकारी कर्मचारी पर आश्रित न हो या फिर कानून के अन्तर्गत कर्मचारी को उसके सरक्षण में बचिा कर दिया गया हो।

(3) अन्य व्यक्ति जो रक्त से या विवाह से कर्मचारी की पत्नि या पति में सम्बन्धित हो और कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो।

3 सामान्य.

(1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सदैव

(i) पूर्णतः ईमानदार रहेगा और

(ii) वतव्य निष्ठा और कार्यालय की गरिमा बनाए रखेगा।

(2) (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, जो कि पर्यवेक्षीय पद (supervisory post) पर हो एक सुब बद्धम उठावेगा जिसमें कि उसके नियन्त्रण और प्राधिकार में काम कर रहे समस्त कर्मचारियों की ईमानदारी और कार्यनिष्ठा सुनिश्चित हो गई।

(ii) सरकारी कार्य करते समय प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए कोई कर्मचारी अपने उत्तम-निर्णय का अथवा कोई कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह किसी निर्देश के अन्तर्गत कार्य न कर रहा हो और उस निर्देश को जहाँ तक सम्भव हो लिखित रूप में प्राप्त करेगा और जहाँ लिखित निर्देश प्राप्त करना सम्भव न हो, वहाँ कार्य के शीघ्र पश्चात् तथा सम्भव शीघ्र वह निर्देश को लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण.—उप नियम (2) के खण्ड (ii) में किसी का भी अर्थ ऐसा नहीं लगाया जावेगा जिससे कि सरकारी कर्मचारी को अपना उत्तरदायित्व टाकन हटाने अपने उच्च अधिकारी या प्राधिकारी से निर्देश या स्वीकृति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जबकि शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों की आवंटन योजना (Scheme of distribution of powers & responsibility) के अन्तर्गत ऐसी आवश्यकता नहीं हो।

4 अनुचित तथा अयोग्य आचरण (Improper and Unbecoming Conduct).—

कोई भी सरकारी कर्मचारी जो—

(1) कर्मस्थ करते समय या अथवा किसी ऐसी अवस्था का दोषी बनकर दिया गया है जिससे नैतिक पतन (moral turpitude) शामिल हो।

(2) जनता के बीच ऐसे खेदग प्रचार में व्यवहार करे जो कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसके पद के लिए असोमनीय हो।

(3) यह सिद्ध हो जावे कि उसने किसी प्राधिकारी को बेनाय से या झूठे नाम से कोई धमिका (प्रार्थना पत्र) भेजा है।

(4) अनेक जीवन व्यतीत करता हो, वह अनुशासित कार्यवाही किए जाने का विरोध करता हो।

स्थापित सम्कार को ठलटने में लगी हो, उसमें भाग लेने, चन्दा देने या अन्य प्रकार से सहायता करने से रोकने का भरसक प्रयत्न कर और जहाँ मन्वारी कर्मचारी अपने परिवार के सब य की ऐसी कार्यवाही, गतिविधि सहाय्यतायें चन्दा देने, अथवा अन्य प्रकार से सहायता देने में रोकने में असमर्थ हो, तो उक्त सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरकार को देगा।

(3) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई दन राजनैतिक दल है, या कोई सस्था राजनीति में भाग लेती है या कोई गतिविधि या कार्यवाही उपनियम (2) के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है या नहीं तो उस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी विधान मण्डल या स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) के चुनाव के सम्बन्ध में न तो मत (vote) देने प्रभाव डालेगा, न अन्य प्रकार से दखल देगा और न उसमें भाग लेगा।

परन्तु शर्त यह है कि—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी जो ऐसे चुनाव में मत (vote) देने के योग्य है अपना मत देने के अधिकार का प्रयोग कर सकेगा और जहाँ ऐसा करेगा, वह ऐसा कोई सवेत नहीं देगा कि उसका किसी के पक्ष में वोट देने का प्रस्ताव है या वोट दिया है,

(2) कोई सरकारी कर्मचारी जिसको कि किसी कानून, जो कि तत् समय लागू हो, के अन्तर्गत चुनाव सम्पादन करने का काम दिया गया है और वह यदि ये चुनाव सम्पादन करवाता है तो यह नहीं समझा जावेगा कि उसने इस नियम के प्रावधान का उल्लंघन किया है।

स्पष्टीकरण—किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं के वाहन या निवास स्थान पर किसी चुनाव चिन्ह के प्रदर्शन करने का अर्थ उसके द्वारा चुनाव के सम्बन्ध में अपने प्रभाव का, इस उप-नियम के अर्थ में प्रयोग करना समझा जायगा।

टिप्पणी—किसी सरकारी कर्मचारी को यदि संकायण ऐसा विश्वास हो कि उसके अधिकारी या उपर वाले व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे कि इस नियम के प्रावधान का उल्लंघन होगा तो वह ये तथ्य राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेगा।

(2) चुनाव में किसी उम्मीदवार का नामांकन प्रस्ताव या अनुमोदन करना या पोलिंग एजेंट के रूप में कार्य करना, चुनाव में सक्रिय भाग लेना समझा जायगा।

8 सरकारी कर्मचारी द्वारा सघों में सम्मिलित होना—

कोई सरकारी कर्मचारी न तो किसी ऐसे सघ (association) में सम्मिलित होगा न उसके सदस्य के रूप में ही बना रहेगा जिसके उद्देश्य और गतिविधियाँ भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता के हित या लोक व्यवस्था और नैतिकता के प्रतिकूल हों।

9 प्रदर्शन तथा हड़तालें—

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन में नहीं लगेगा और न भाग ही लेगा या भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मिली सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित के प्रतिकूल हों, ता जिनसे न्यायालय का अपमान या क्षति हो या जिनसे किसी व्यपराय को प्रोत्साहन मिलता हो।

(2) अपनी सेवा या श्रम सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों में न तो किसी प्रकार की हस्तक्षेप या माध्यम अपनावेगा और न हस्तक्षेप को किसी प्रकार प्रोत्साहन देगा।
10 प्रेस या रेडियो से सम्बन्ध —

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र या समाचारिका प्रकाशन का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसका सम्पादन या प्रकाश ही करेगा, न उसमें भाग लेगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी—

(अ) किसी रेडियो प्रसारण में, सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना भाग नहीं लेगा, या

(आ) किसी समाचार पत्र या पत्रिका में नियुक्ति अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई लेख या पत्र लेखन या स्वयं के नाम से या अन्य किसी नाम से प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं करेगा—

परन्तु शर्त यह है कि यदि ऐसा प्रसारण या लेख, जो शुद्ध रूप में माहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो और उसमें ऐसा कोई भागना नहीं हो जिसे किसी कानून, नियम या पर्याप्त के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रकट करना निषेध हो, तो ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

और यह, कि यदि उन प्रसारण या लेख में सरकारी कर्मचारी के विषय में सम्बन्धित होने वाले (चाहे वे सरकारी श्रोत से तैयार किये हों या नहीं) को तो कर्मचारी द्वारा जो चीज भी जाती वही भी जावेगी और वह सरकारी कर्मचारी उस चीज से अधिक वसूल नहीं करेगा जो किसी सरकारी व्यक्ति को ऐसे प्रसारण या लेख पर देय होती हो।

1. सरकार की आलोचना —

कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने रेडियो प्रसारण या दस्तावेज में जो कि उसके नाम से नाम या वर्णित नाम या अन्य के नाम से प्रकाशित हो, या प्रेस को दिये जाने वाले पत्र व्यवहार या सार्वजनिक रूप में किये बयानों या विचारों में निम्न प्रकार की बातें नहीं करेगा—

(1) जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के वर्तमान या ह्रास हो की नीति या कार्यवाही पर प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव पड़ेगा।

(2) जो केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार के मध्य सम्बन्धों में उत्पन्न ईर्ष्या कर सकते हों।

(3) जो केन्द्रीय सरकार और किसी मित्र विदेशी सरकार के मध्य सम्बन्धों में उत्पन्न ईर्ष्या कर सकते हों।

परन्तु शर्त यह है, कि इस नियम का कुछ भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये ऐसे बयानों या उगने द्वारा प्रकट किये ऐसे विचारों पर लागू नहीं होगा जो कि अपने सरकारी पद की हेतुना से या अपने निर्धारित कर्तव्यों का समुचित ध्यान करते हुए दिया हो।

12 किसी समिति या अन्य अधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना—

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी उप नियम (3) में दिये शब्दों के प्रतिष्ठित अपने नियुक्ति अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति समिति (कमेटी) या प्राधिकारी द्वारा की जा रही जांच में साक्ष्य (बयान) नहीं देगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) ने अधीन कोई स्वीकृति दी गई हो, वहाँ कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी माहय देने समय राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकार की नीति या कोई स्वीकृति की खालोचना नहीं करेगा।

(3) इस नियम में कुछ भी निम्न लिखितो पर लागू नहीं होगा—

(घ) सरकार, ससद या राज्यीय विधान मण्डल नियुक्त कि गये प्राधिकारी के समक्ष जाच के सम्बन्ध में दी गई साक्ष्य या

(आ) न्यायिक जाच में दी गई साक्ष्य, या

(इ) ऐसी विभागीय जाच में दी गई साक्ष्य जो सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से की जा रही हो।

13 अनधिकृत सूचना का आदान प्रदान —

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार की सामान्य या विशेष आज्ञा या या निर्धारित कर्तव्यों का सद्भावनापूर्वक पालन करने के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग सरकारी कर्मचारी को परोप या अपरोप रूप में कोई दस्तावेज या सूचना जो कि उसके द्वारा कर्तव्य करने के दौरान या सरकारी स्त्रोत या अन्य प्रकार से तैयार या मकलन की गई हो, नहीं देगा।

परन्तु यहाँ यह है कि, इस नियम का कुछ भी उक्त अधिकारी को जिसका कर्तव्य सरकार की गतिविधियाँ का सरकार के सामान्य या विशिष्ट निर्देशानुसार प्रचार करना हो, प्रेस (समाचार पत्र) के साथ संचार करने में नहीं रोकेगा।

परन्तु यह और है कि, इस नियम का कुछ भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा पुलिस आचार विधी विभाग) को कोई सूचना या दस्तावेज दान से वञ्चित नहीं माना जावेगा जब कि उसे ईमान के साथ ऐसा विश्वास हो कि उक्त सूचना अप्रचार या अन्य दुराचार रोकने या रणधियाँ का पता लगाने या उन्हें दण्ड देने में सहायक होगी।

14 धरें—

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार या निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति या आज्ञा के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए न तो वह यावेगा न स्वीकार करेगा, तथा अन्य प्रकार से कोई राजि या वस्तुओं के एक्जीक्यूशन में या अन्य प्रकार में अपने आप को सम्मिलित नहीं करेगा।

15 उपहार —

(1) इन नियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार का उपहार न तो स्वयं स्वीकार करेगा न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने की अनुमति देगा।

स्पष्टीकरण—व्यक्ति 'उपहार' में निम्नलिखित यातायात आवास भोजन या अन्य सवाये या अन्य आर्थिक लाभ सम्मिलित है जिन्हें किसी एम व्यक्ति ने उपलब्ध किये हों जो कर्मचारी का निरुप सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र जिसका उसके सरकारी ध्यवहार में कोई सम्बन्ध होने के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हो।

नोट:—(1) कभी कभी (Casual) भोजन, सवारी या अन्य सामाजिक आर्थिक उपहार नहीं माने जाते हैं।

नोट: (ii) सरकारी कर्मचारी, ऐसे व्यक्ति से, जिसका सरकार में काम काज है या जो औद्योगिक वाणिज्यिक फर्म या संस्थाएं आदि हैं, से खर्चीले आतिथ्य या बार बार आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

(2) ऐसे अवसरों जैसे कि विवाह-वापिकोरमव, मृत्यु या धार्मिकोत्सवों पर जिनमें कि उपहार देना, धार्मिक या सामाजिक परम्परा के अनुकूल है, सरकारी कर्मचारी अपने निकट सम्बन्धियों से उपहार स्वीकार कर सकेगा, लेकिन उसे इसकी सूचना सरकार को देनी होगी, यदि ऐसे उपहार का मूल्य—

(i) रु० 500.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी कि राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा का पद धारण करता हो।

(ii) रु० 200.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी कि धीर मन्त्रालयिक (मिनिस्टेरियल) सेवा का पद धारण करता हो;

(iii) रु० 100.00 से अधिक हो ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद पर धारण करता हो।

(3) ऐसे अवसरों पर जो कि उपनियम (2) में स्पष्ट किये गये हैं, कोई सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मित्रों जिनका सरकार में काम काज है, से उपहार स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसकी सूचना सरकार को देनी होगी यदि ऐसे उपहार का मूल्य:—

(1) रु० 200.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा का पद धारण करता हो।

(2) रु० 100.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मन्त्रालयिक (Ministerial) सेवा का पद धारण करता हो; धीर

(3) रु० 50.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो चतुर्थ श्रेणी सेवा का पद धारण करता हो।

(4) किसी अन्य मामले में, सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, यदि उसका मूल्य:—

(i) रु० 75.00 से अधिक है, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो किसी राज्य सेवा या अधीनस्थ सेवा का पद धारण करता हो; धीर

(ii) रु० 25.00 से अधिक हो, ऐसे सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में जो मन्त्रालयिक (Ministerial) या चतुर्थ श्रेणी सेवा का पद धारण करता हो।

16 सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में लोक प्रदर्शन:—

कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति के बिना स्वयं के सम्मान में दिया गया कोई अभिनन्दन स्वस्तिवाचन या प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करेगा तथा उसके सम्मान में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में की गई सभा या मनीरंजन में उपस्थित नहीं रहेगा।

परन्तु इस नियम का कुछ भी निम्नांकितों पर लागू नहीं होगा—

(i) स्वयं सरकारी कर्मचारी के या अन्य सरकारी कर्मचारी के सम्मान में उसकी सेवा-निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर, या ऐसे अन्य व्यक्ति के सम्मान में दिया गया विदाई समारोह जिसने कि हाल ही में सरकारी सेवा छोड़ी हो, या

(ii) स्थानीय निकायों (local bodies) या संस्थाओं द्वारा दिए गए साधारण अल्प व्यय के मनोरंजन को स्वीकार करना।

नोट :—किसी सरकारी कर्मचारी को किसी विदाई समारोह के लिए चाहे वह मुख्यतः व्यक्तिगत या घनीपचारिक हो चन्दा देने के लिए दबाव डालना या प्रभावित करना और मन्त्रालयिक (मिनिस्टेरियल) या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से किन्हीं परिस्थितियों में, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु चन्दा इकट्ठा करना वर्जित है जो कि मन्त्रालयिक (मिनिस्टेरियल) या चतुर्थ श्रेणी सेवा के न हो।

17 शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने या उपस्थित न होने पर प्रतिबन्ध :—

किसी सरकारी कर्मचारी को जब तक कि वह सरकारी सेवा में है अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पूर्ण अनुमति बिना, मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षा हेतु तैयारी करने हेतु या परीक्षा में बैठने हेतु किसी शिक्षण संस्था में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

परन्तु, शर्त यह है कि—

(i) इन नियमों का कुछ भी उप सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा जिसने कि राजस्थान सेवा नियमों के अधीन देय अवकाश हेतु आवेदन दिया है और जो स्वीकृत हुआ है ताकि वह उस विद्यालय या महाविद्यालय के पूर्ण सत्र की अवधि में सम्मिलित हो सके जिसके लिए वह अपने स्वयं को तैयार करता है,

(ii) सरकारी कर्मचारी जिसने कि (वर्ष 1955 में या उससे पहले) कोई परीक्षा का प्रथम खण्ड पास कर लिया है, उसका कार्यालय समय के अलावा समय में नियुक्ति प्रति अधिकारी द्वारा पूर्व की परीक्षा के पश्चात अन्तिम परीक्षा की तैयारी करने या बैठने हेतु, किसी शिक्षण संस्था में उपस्थित होने या सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को कार्यालय समय के पश्चात किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा या अन्य परीक्षा जो कि किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है की तैयारी करने और बैठने हेतु कोई शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने या उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा।

(iv) किसी अध्यापक या पुस्तकालय अध्यापक की शिक्षा विभाग के नियमों तथा उपनियमों के अधीन और पुरातत्व राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एच पुरातत्व की सेवा और (आर-बीओलोजिकल) विभाग के सदस्यों को नियुक्त प्राधिकारी, उन्हें मैट्रिकुलेशन परीक्षा से उच्च शिक्षा हेतु किसी मान्य बोर्ड या विश्वविद्यालय या उसके समक्ष घोषित परीक्षा की तैयारी करने या उसमें बैठने की कार्यालय समय के पश्चात अनुमति दे सकेगा।

(v) विभागीय नियमों के अधीनस्थ किसी तकनीकी अधिकारी को भी, उसके कार्यालय समय के अलावा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा बढ़ाने और तकनीकी परीक्षा में बैठने हेतु कोई तृतीय श्रेणी से प्रवेश लेने और उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

स्मार्टकरण —(ख) अभिव्यक्ति 'प्रथम खण्ड परीक्षा' का अर्थ उस परीक्षा से है जो कि माध्यमिक या स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षाओं की अन्तिम परीक्षा के ठीक पहले होती है।

(अ) अभिवृत्ति "तकनीकी अधिकारी" का अर्थ उन अधिकारियों में है जो राजस्थान राज्य या अन्य राज्य के चिरिरता और स्वास्थ्य वृष्टि पशु-पालन, वन, सार्वजनिक निर्माण और सैनिक एवं भू विभागों में तकनीकी पदों पर अधीन हैं; या राज्य क सशक्तता वाले कारखानों या राज्य के उद्योग विभाग के अधीनस्थ या उसके नियन्त्रणाधीन उत्पादन केन्द्रों में पदासीन हैं।

(इ) ऐसी, हिन्दी परीक्षाएँ जैसे विशारद, साहित्य-रत्न आदि जो कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा ली जाती है, इस नियम के क्षेत्र में नहीं आती।

18 निजी व्यापार या नियोजन —

(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, किसी व्यापार, वाणिज्य में नहीं लगेगा या अन्य प्रकार की संस्था में नियोजन स्वीकार नहीं करेगा परन्तु सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अवैतनिक (honorary) कार्य जो सामाजिक या पुण्यात्मक (Charitable) प्रकार का हो या साहित्यिक या वैज्ञानिक या सामायिक (occasional) हो वह कर सकेगा बशर्त कि ऐसा करने से उसके राज कार्य पर वैज्ञानिक प्रकार प्रतिफल प्रभाव नहीं पड़ता हो, लेकिन वह ऐसे कार्य को स्वीकार नहीं करेगा और उसे छोड़ देगा, यदि राज्य सरकार उसे ऐसा करने का निर्देश दे।

स्पष्टीकरण — (1) सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी बीमा-एजेंसी, कमीशन एजेंसी या इसी प्रकार के वाणिज्यिक कार्य का प्रचार करना जिस पर उसको पत्नी या परिवार किसी अन्य सदस्य का स्वामित्व या प्रबंध हो, इस नियम का उल्लंघन करना समझा जाएगा।

(2) यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी व्यापार या वाणिज्य में लगा हुआ है या वह किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का स्वामी या प्रबन्धक है तो सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना राज्य सरकार को देगा।

(3) कोई सरकारी कर्मचारी, सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बिना, अपने राजकाय के अतिरिक्त, किसी बैंक के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) विकास या व्यवस्था कार्य में या अन्य कम्पनी अधिनियम 1956 का (1956 का 9) या अन्य कानून जो उस समय लागू हो, के अधीन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) आवश्यक है या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन की सहायरी संस्था के कार्य में भाग नहीं लेगा।

परन्तु शर्त यह है कि सरकारी कर्मचारी, किसी सहायरी संस्था जो मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ हो, के पंजीयन, विकास या व्यवस्था जो कि राजस्थान सहायरी संस्था अधिनियम, 1965 या अन्य कानून जो तत्समय लागू हों के अन्तर्गत पंजीकृत है, या जो साहित्यिक, वैज्ञानिक या पुण्यात्मक संस्थाएँ हैं जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1890 (1890 का 21) या अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत (registered) है, में भाग ले सकेगा।

19 विनियोजन (Investment), ऋण का लेन देन.—

(1) कोई सरकारी कर्मचारी स्टॉक, शेयर या अन्य प्रकार के विनियोजन (Investment) में सट्टा (स्पेकुलेट) नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.—शेयर, सिन्डिकेटेड या अन्य प्रकार के विनियोग (इन्वेस्टमेंट) का बार-बार क्रय, विक्रय या दोनों कार्यवाही करना, इस उप-नियम के अधीन सट्टा (स्पेकुलेशन) करना समझा जाएगा।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी न तो स्वयं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या ऐसे व्यक्ति को जो कर्मचारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हो, इस प्रकार के

(Investment) की अनुमति नहीं देगा जिससे कि उसे राजकीय कर्तव्यों के पालन में उलभन या प्रभाव में आना पड़े।

(3) यदि, यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कि आया कोई कार्य, उप-नियम, (1), और (2) में बतलाये प्रकार का है तो इस मामले में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) कोई भी सरकारी कर्मचारी, किसी बैंक या प्रतिष्ठित फर्म जिसे कि बैंकिंग-कार्य करने का अधिकार हो के साथ बैंकिंग के साधारण कार्य के अतिरिक्त, न तो स्वयं और न अपने परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा जो कि कर्मचारी की ओर से कार्य करता हो वो निम्न कार्य नहीं करेगा —

(प्र) स्वामी (Principal) या प्रतिनिधि के रूप में कोई सरकारी कर्मचारी अपने स्थानीय सीमा में किसी ऐसे व्यक्ति से ऋण की लन-देन नहीं करेगा जिसमें कि कर्मचारी का राज-राज में सम्पर्क होता हो या उस पर किसी अन्य प्रकार से कोई वित्तीय भार पड़ता हो,

(पा) किसी भी व्यक्ति को कोई रकमान तो व्याज पर और इस प्रकार से उधार देगा जिसमें कि रोकट या वस्तु के रूप में भगवान प्राप्त होती हो।

परन्तु, सरकारी कर्मचारी अपने किसी सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र के साथ छोटी राशि का केवल अस्थायी ऋण, व्याज या बिना ग्यारंज पर आद न-प्रदान कर सकेगा या किसी सद्भावी व्यापारी के साथ उधार खाता रह सकेगा या अपने निजी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन दे सकेगा।

जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति या स्थानान्तरण ऐसे या उस प्रकार के पद पर हो जहाँ उप नियम (2) या उप नियम (4) के प्रावधानों का उल्लंघन हो, तो वह कर्मचारी अनुरक्त अपने निर्धारित प्राधिकारी को उक्त परिस्थितियों की सूचना देगा और अनुपस्थात् अपने प्राधिकारी द्वारा दिये गए आदेश के अनुसार कार्यवाही करेगा।

20 दिवालियापन और आवतन कर्मचारी —

(1) सरकारी कर्मचारी आवतन कर्मचारी स्वाभाविक कारण प्रसूता से दूर रहेगा।

(2) जब भी कोई सरकारी कर्मचारी दिवालिया करार या घोषित कर दिया जावे या जब उसके वेतन का आधा भाग लगातार कर्ज हो रहा, या दो वर्षों से अधिक अवधि तक वेतन लगातार कुर्क किया जा रहा हो या जो इतनी राशि के लिए कुर्क हो रही है जिसका कि साधारण परिस्थितियों में कर्मचारी दाय दो वर्षों में भुगतान नहीं हो सकता हो तो उसे राज्य सेवा से बर्खास्त होने योग्य समझा जावेगा।

(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की स्वीकृति के बिना राज्य सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सके लेकिन वह दिवालिया घोषित है और उसके वेतन का आधा भाग कुर्क है तो इसकी सूचना सरकार को प्रेषित की जावेगी।

(4) ऐसे अन्य सरकारी कर्मचारी का मामला उसके कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को जिसके अधीन वह सेवा-युक्त है भेजना चाहिये।

(5) जब किसी अधिकारी के वेतन का आधा भाग जप्त हो तो प्रतिवेदन में यह दर्शाया जाना चाहिये कि कर्ज का उसके वेतन से क्या अनुगत है और उसके सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसकी कार्य दक्षता कहा तब कम करता है, आया ऋणों की स्थिति असाध्य है और आया मामले की उन परिस्थितियों में उसे अपने पद या अन्य सरकारी पद पर रखा जाना आवश्यक है जबकि यह मामला सूचित कर दिया गया था।

(6) इस नियम के हर मामले में यह निश्चित करना कर्जदार पर भार होगा कि उसका दिवा-
नियामन या ऋण प्रस्तुतता, ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप है जिनका सामान्य उद्यम से पूर्वाभास नहीं
हो सकता या और जिन पर उसका नियंत्रण नहीं था और यह उसके खर्चों या दुराचारी स्वभाव
के फलस्वरूप नहीं है।

21. चल प्रपत्र तथा मृत्युवान सम्पत्ति,--

(1), प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, किसी सेवा प्रा. पद, पर नियुक्त होते ही या तत्पश्चात् ऐसे
प्राप्तियों (इंटरवल) में जैसा कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जावे, अपनी सम्पत्ति और दायित्वों
(Liabilities) का प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि सरकार निर्दिष्ट करे, प्रेषित करेगा जिसमें
निम्न विषयक पूर्ण विवरण होगा—

(अ) प्रचल सम्पत्ति, जो इसने उत्तराधिकार में प्राप्त की हो, या जिस पर उसका स्वामित्व
हो, या जिसे उसे प्राप्त किया हो, या जो होज या रहने से उसके अधिकार में आई हो; चाहे वह
कर्मचारी के स्वयं के नाम या उसके परिवार किसी सदस्य के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम हो,
(आ) होयइ, द्विवेशस और रोकड, बज्जक, डिपोजिट को सम्मिलित, करते हुए, जो उसने
उत्तराधिकार रूप में प्राप्त की हो, या इसी प्रकार उस पर स्वामित्व प्राप्त किया हो, या जो ग्रहण
की गई हो या जिस पर उसका कब्जा हो,

(इ) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे उत्तराधिकार रूप में प्राप्त हुई हो, या इसी प्रकार उस पर
स्वामित्व प्राप्त किया हो, या जो ग्रहण की गई हो या उस पर उसके द्वारा धारण की हुई हो, और
(ई) और अन्य देनदारियाँ जो उसने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ग्रहण की हो।

नोट (I).— उपनियम (1) सामान्यतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
लेकिन सरकार यह निर्देश दे सकती कि वह किसी अमुक सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारियों
की अमुक श्रेणी पर लागू होगा।

नोट (II).— समस्त प्रतिवेदनों में, प्रचल सम्पत्ति के प्रॉर्टिमेंटों, जिनका मूल्य रु० 1000/-
से कम हो का योग कर एक मुक्त बतलाये जावे। दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे, कपड़ा,
बर्तन, चीनी के बर्तन, पुस्तकें आदि का मूल्य उक्त प्रतिवेदन में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।

नोट III.— प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के दिन सेवा में था,
इस उप-नियम के अधीन अपना प्रतिवेदन, सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि या उसके पूर्व पेश करेगा।

(2) कोई भी सरकारी कर्मचारी, निर्धारित प्राधिकारी के पहले सूचना दिए बिना कोई
अचल सम्पत्ति लीज, रेंट, ब्रय, विक्रय, उपहार या अन्य प्रकार से अपने या अपने परिवार के किसी
सदस्य के नाम न तो प्राप्त करेगा और न देगा।

परन्तु शर्त यह है कि, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त
की जावेगी, यदि कोई व्यवहार

(1) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित हो, जिसका सरकारी कर्मचारी से राजकाज में सम्पर्क होता
हो, या

(2) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी व्यक्ति के अतिरिक्त, धन्य से सम्बन्धित हो,

(3) ऐसा सरकारी कर्मचारी जो राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा के किसी पद पर हों और
सम्पत्ति का मूल्य रु० 1000 से अधिक हो या ऐसा कर्मचारी जो मंत्रालय (ministerial) सेवा
और चतुर्थ श्रेणी सेवा के किसी पद पर हो, और सम्पत्ति का मूल्य रु० 500 है, अपने निर्धारित

प्राधिकारी को ऐसी चल सम्पत्ति से सम्बन्धित हर मामले की सूचना देनी होगी जिस पर उसके स्वयं के नाम से या परिवार के किसी सदस्य के नाम से लेन देन हुआ हो।

परन्तु शर्त यह है कि निर्धारित अधिकारी को पूर्व स्वीकृति ली जावेगी, यदि कोई व्यवहार

(1) ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित हो जिसका सरकारी कर्मचारी तो राज काज में सम्पन्न होता हो,

(2) जो नियमित या प्रतिष्ठित व्यापारी के प्रतिरिक्त अन्य से सम्बन्धित हो।

(3) सरकार या निर्धारित प्राधिकारी किसी भी समय सामान्य या विशिष्ट आज्ञा द्वारा सरकारी कर्मचारी से ऐसी चल या अचल सम्पत्ति जो उसके अधिकार में है, या प्राप्त की गई है या उसके स्वयं के द्वारा या उसके नाम पर परिवार के किसी सदस्य के द्वारा प्राप्त की गई है का पूर्ण विवरण में निदिष्ट अवधि में माँग सकते हैं। यदि सरकार या निर्धारित अधिकारी ऐसा चाहेंगे तो उक्त विवरण में यह भी सम्मिलित किया जावेगा कि सम्पत्ति किस प्रकार एवं किस स्रोत से प्राप्त की गई।

(4) सरकार किसी को अधीनस्थ सेव और चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के किसी वर्ग को इन नियमों के किसी प्रावधान, उपनियम (4) के प्रतिरिक्त से मुक्त कर सकती है। ऐसी छूट किसी हालत में नियुक्ति (A-III) विभाग की सहमति के बिना नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'चल सम्पत्ति' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(अ) जवाहरात, और बीमा-पालीसिया, जिनका वार्षिक प्रीमियम रु० 1000/- से अधिक हो, या सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक परिलभो रु० 116 से अधिक हो, जो भी इन दोनों में से कम हो, और शेयर, सिक्योरिटिया और डिबेंचर्स।

(आ) ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिये गये भ्रष्टाचार काहे प्रतिभूत पर हो या नहीं,

(इ) मोटर गाडिया, मोटर साइकिलें, मकान, या अन्य प्रकार की गाडिया, और

(ई) रेफरीजरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम

(2) "निर्धारित प्राधिकारी" का अर्थ है :—

(अ) (1) सरकार, उम सरकारी कर्मचारी के मामले में जो ऐसे पद पर हो जो पद राज्य सेवा में सम्मिलित हो सिवाय उसके जब सरकार द्वारा कोई निम्न प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट हो,

(2) विभागाध्यक्ष, उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अधीनस्थ सेवा का कोई पद धारण करता हो,

(3) कार्यालय अध्यक्ष, उस सरकारी कर्मचारी के मामले में जो मजालय (मिनिस्टेरियल) सेवा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाओं में कोई पद धारण करता हो,

(आ) ऐसे सरकारी कर्मचारी के विषय में जो बौदेशिक सेवा या केन्द्रीय-सरकार, निगम, राजकीय उपक्रम या अन्य ऐसी जगह पर प्रति नियुक्ति पर हो तो उसका प्रत्यक्ष विभाग जिसके कंडर पर उक्त सरकारी कर्मचारी है।

22. सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिवेदन :—

कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकार को या अन्य अधीनस्थ प्राधिकारित जो कि नियमों, आदेशों आदि जैसा कि सरकार सप्रस-समय

में प्रतिवेदन

23 सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्य और चरित्र को न्याय संगत बनाने हेतु प्रतिशोध :-

कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऐसे सरकारी कार्य जिस पर मफीज या प्रतिकूल चर्चा हुई हो को न्याय संगत ऋताने हेतु किसी न्यायालय या समाचार पत्र का साधन नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम का कुछ भी, सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कार्य या चरित्र को (न्याय संगत) ठहराने के अधिकार को न तो सीमित और या न अन्य प्रकार से प्रभावित करेगा।

नोट—सरकार किसी को न्यायालय या समाचार पत्र का साधन लेने की स्वीकृति देने के पूर्व, प्रत्येक मामले में यह निर्णय लेगी कि सरकार स्वयं न्यायालय की कार्यवाही का खर्चा वहन करेगी या कर्मचारी अपने स्वयं के खर्चे पर न्यायालय कार्यवाही धारण करेगा, और यदि ऐसा है तो प्राया कर्मचारी के हक में निर्णय हो जाने पर सरकार उसे पूर्ण या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करेगी।

24 सरासरी एवं अन्य प्रकार के प्रभाव डालना :-

कोई सरकारी कर्मचारी किसी उच्च अधिकारी पर ऐसे भावनाओं में जो राज्य सेवा से सम्बन्धित हो किसी प्रकार का राजनैतिक या धार्मिक प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा।

25 दूतता विवाह -

(1) कोई सरकारी कर्मचारी जिसके एक पति जीवित है सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना दूसरा विवाह करने का हक नहीं करेगा, चाहे इस प्रकार के पुनर्विवाह की उसने व्यक्तिगत कानून जो तत्कालीन काल है, के अंतर्गत अनुमति है।

(2) कोई स्त्री सरकारी कर्मचारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके पति जीवित हैं विवाह नहीं करेगी।

+25-ब कोई भी सरकारी कर्मचारी -

(1) कोई दहेज न देगा न लेगा और न किसी को इसके लिए नहीं उकसाएगा, या

(ii) किसी घर या वस्तु, या स्थिति के माता पिता या मरुतक में प्रवेश या परोपन रूप में किसी दहेज की मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'दहेज' में तात्पर्य नहीं है जो दहेज निवारण अधिनियम, 1961 (सन् 1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में दिया हुआ है।

×25 ग [विमृण 1]

26 नशीले पेय या औषधि का प्रयोग :-

(1) कोई सरकारी कर्मचारी :-

(क) नशीले पेय और पदार्थ सम्बंधी कानून, जो उस क्षेत्र पर लागू हो महा कर्मचारी तत्काल मोतूद हो का बहोला से पासन करेगा,

●(ग) अपने कर्तव्य पासन के समय किसी मादक पेय या औषधि के नशे में नहीं रहना और इसकी भी उचित सावधानी करने का कि किसी भी कथन टक्का कथन पासन ऐसी मादक पेय या औषधि से किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, न वह ऐसे समय के निष्पत्ति से पेय या औषधि का

+ अधिमूचना स. एन 4 (2) कामिक/ए-3/76 दि 5-1-1977 द्वारा जोड़ा गया।

× अधिमूचना स. एन 4 (3) कामिक/ए-3/76 दि 23-1-1977 द्वारा निरस्त किया।

● बिजलि स. एन 5 (34) कामिक/ए-3/73 दि 1-1-1977 द्वारा निरस्त किया।

सेवन करेगा जब उसे नौकरी पर उपस्थित होना हो और तब उसके मुख की दुर्गन्ध या व्यवहार दूसरी को ऐसा प्रतीत हो कि उसने कोई मादक पेय या औषधि सेवन की है।]

(ग) मादक द्रव्य या औषधि के नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएगा।

(घ) किसी प्रकार के नशीले पेय और पदार्थ का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करेगा।

27 अधिकारीगण द्वारा विदेशी सुविदायुक्त फर्मों में यात्रा व्यय एवं आतिथ्य स्वीकार करना —

यदि इस प्रकार की सुविधायें देने हेतु विदेशी सुविदा वाली फर्म, परीक्षा या अपरीक्षा रूप में हो और अधिकारीगण कि न तो वे स्वयं, विदेश जाने हेतु यात्रा व्यय और वहां निशुभोजन एवं ठहरने की सुविधायें स्वीकार करेंगे और न उनका किसी को अनुमति देंगे। इसका अपवाद केवल उनके सम्बन्ध में होगा जो सुविधायें विदेशी फर्म विदेश में शिक्षण हेतु प्रदान करती है और एवं में वे विदेशी सरकारी कर्मचारी से सहायता-कार्यक्रम के प्रश्न के रूप में, सुगतान प्राप्त करती हैं।

28. अधीनस्थ कर्मचारियों से दौरे पर आतिथ्य स्वीकार करना :—

सरकारी कर्मचारी जब दौरे पर जावे तो अपने भोजन एवं ठहरने के स्थान का स्वयं प्रबंध करेंगे, और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का न तो आतिथ्य स्वीकार करेंगे और न ही अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों को इस प्रकार का आतिथ्य करने को कहेंगे।

29. सेवा के मामलों में कानूनी आश्रय :—

कोई सरकारी कर्मचारी पहले सामान्य शासकीय प्रणाली का उपाय या सहारा लिए बिना सेवा या सेवा की शर्तों के मामलों में उत्पन्न विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय का निर्णय प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा ऐसे मामलों में भी जिनमें कि न्यायिक कार्यवाही का उसे अधिकार है।

30. व्याख्या —

यदि इन नियमों के सम्बन्ध में व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उत्पन्न हो, तो सरकार के कार्यात्मक विभाग को मामले में लिखा जावेगा जिसका उस पर निर्णय प्रारंभ होगा।

31 शक्तियों का प्रत्यापोजन (Delegation) :—

सरकार किसी सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकेगी कि सरकार या किसी विभागाध्यक्ष की इन नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां (इस नियम और नियम (30) के अतिरिक्त) और आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते यदि कोई भी, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी जो कि आदेश में बतलाये जावेंगे, प्रयोग कर सकेंगे।

32 निरस्तन और व्यावृत्ति (Repeal & Saving) :—

(1) राजस्थान राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स आचरण नियम 1950, जो इस समय लागू है और कोई विज्ञप्ति और आदेश जो ऐसे किसी नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये हो, उस सीमा तक जहां वे उक्त व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जिन पर कि ये नियम लागू हैं एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि—

(i) उक्त निरस्तन वधित नियमों, विज्ञप्ति और आज्ञाओं के पूर्व-प्रभाव को या उनके अन्तर्गत की गई किसी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा,

(ii) उन नियमों के अन्तर्गत की गई कोई कार्यवाही, विज्ञप्ति या आज्ञाएं जो कि इन नियमों के प्रारम्भ के समस्त विचाराधीन थी या नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, शुरू की गई थी, जारी रखी जावेगी और उन पर जहां तक हो सकेगा इनके अनुसार निपटाई जाएंगी।

(2) इन नियमों में कुछ भी किसी व्यक्ति को जिस पर ये नियम लागू हैं, किसी ऐसे अधिकार से वधित नहीं करेगा जो उसे उप-नियम (1) द्वारा निरस्तन-नियमों, अधिसूचनाओं या आदेशों के अन्तर्गत इन नियमों के प्रारम्भ होने से पहले प्रदान किए हुए किसी आदेश से अर्जित हो गए थे।

